हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

06 अगस्त, 2019

खण्ड–2, अंक–3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 06 अगस्त, 2019

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

डिवाइन पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा, जिला कुरूक्षेत्र तथा डी.ए.वी. महाविद्यालय, नन्यौला, अम्बाला शहर के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम–15 के अधीन प्रस्ताव

नियम–16 के अधीन प्रस्ताव

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

सदस्यों द्वारा विभिन्न मांगों को उठाना

हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव व हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

सदस्यों द्वारा विभिन्न मांगों को उठाना (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों के इस्तीफा की घोषणा

सदस्यों द्वारा विभिन्न मांगों को उठाना (पुनरारम्भ)

पंजाब विधान सभा के सदस्यों का अभिनन्दन

सदस्यों द्वारा विभिन्न मांगों को उठाना (पुनरारम्भ)

पंजाब विधान सभा के सदस्य एवं पंजाब विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता का अभिनन्दन

सदस्यों द्वारा विभिन्न मांगों को उठाना (पुनरारम्भ)

शून्यकाल तथा विभिन्न मांगों के दौरान सदस्यगण द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण–

श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. द्वारा

शून्यकाल तथा विभिन्न मांगों के दौरान सदस्यगण द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर (पुनारारम्भ)

वाक आउट

शून्यकाल तथा विभिन्न मांगों के दौरान सदस्यगण द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर (पुनारारम्भ)

वाक आउट

शून्यकाल तथा विभिन्न मांगों के दौरान सदस्यगण द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर (पुनारारम्भ)

वाक आउट

शून्यकाल तथा विभिन्न मांगों के दौरान सदस्यगण द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर (पुनारारम्भ)

विधान कार्य–

(i) दि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बिल, 2019

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(ii) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नंबर 3) बिल, 2019
(iii) दि हरियाणा गोवंश संरक्षण एण्ड गोसंवर्धन (अमैंडमैंट) बिल, 2019
(iv) दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2019
(v) दि हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2019
(vi) दि हरियाणा ग्रुप डी इम्प्लॉईज (रिक्रूटमैंट एण्ड कंडीशंज़ ऑफ सर्विस) अमैंडमैंट बिल, 2019

(vii) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2019

(viii) दि पंजाब इलैक्ट्रिसिटी (एमरजेंसी पॉवर्स) हरियाणा रिपील बिल, 2019

(ix) दि हरियाणा कंट्रोल ऑफ आर्गेनाईज्ड क्राइम बिल, 2019

(x) दि मोटर व्हीकल्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2019

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा हरियाणा विधान सभा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मानदेय के रूप में एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने के सम्बन्ध में दिया गया सुझाव

हरियाणा के मृतक एम.एल.एलज. की पत्नियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का मामला उठाना

संसदीय कार्य मंत्री, श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार 06 अगस्त, 2019

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

Construction of Bye Pass

***3090. Smt. Geeta Bhukkal**: Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bye Pass of village Chhuchakwas in Jhajjar constituency; if so, the time by which it is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) हां, श्रीमान जी,

(ख) भूमि अधिग्रहण के पूर्ण होने के उपरांत अतिशीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा जोकि 15 महीने में पूरा कर दिया जाएगा।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण होने के बाद बहुत ही जल्दी बाईपास बनाने का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा, परन्तु यह बहुत लम्बा प्रोसैस है। छुछकवास का बाईपास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उस एरिया में बहुत से एजूकेशनल इंस्टीच्यूशंज हैं। इसके अतिरिक्त झाड़ली थर्मल पॉवर प्लांट और बहुत सी दूसरी इंडस्ट्रीज भी हैं जिसके कारण झज्जर और दादरी से ओवरलोडिड वाहन सामान लेकर आते जाते रहते हैं। मैंने स्वयं देखा है संबंधित एरिया में एक्सीडैंट्स होते रहते हैं इसलिए इस बाईपास को बनाया जाना बहुत जरूरी है ताकि जान–माल का नुकसान होने से बचा जा सके। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में भी संबंधित बाईपास बनाने के लिए पूरा प्रयास किया था। सैक्शन 4 और 6 के नोटिसिज इशू हो चुके थे और सैक्शन 9 के लिए कॉल कर रहे थे परन्तु उस समय लैंड लेने के लिए लोगों के साथ सहमति नहीं बन पायी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने संबंधित बाईपास बनाने के लिए 'हां' तो भरी है। लेकिन after on going land acquisition process के बाद कहा है। यह बाईपास बनवाने का काम जल्दी पूरा करवाया जाना चाहिए और यह माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अनाउंसमैंट है। संबंधित एरिया में बाईपास न होने के कारण ट्रैफिक जाम होता रहता है और नम्बर ऑफ इंसिडैंट्स भी बढ़ रहे हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या सही बात कह रही हैं। मैंने मौके का मुआयना भी किया था। मैं झज्जर जिले की ग्रीवेंसिज कमेटी का चेयरमैंन भी

हूं। इसमें 2 गांवों के कुल 229 लोगों की जमीन है जिसमें से 74.2 प्रतिशत लोगों ने अपनी जमीन देने के लिए कन्सैंट दे दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि यह काम जल्दी पूरा करवा दिया जाएगा और यह सी.एम. अनाउंसमैंट भी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस काम को जल्दी ही पूरा करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्षः ठीक है। संबंधित लोगों से जमीन दिलवाने में माननीय सदस्या भी सहयोग करेंगी।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले पांच सालों से सभी सैशंज में लगातार यह सवाल लगाती रही हूं। इसमें 74.2 प्रतिशत लोगों ने अपनी जमीन दे दी है और माननीय मंत्री जी ने संबंधित बाईपास को बनवाने का आश्वासन भी दिया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह सवाल पहली बार आया है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि संबंधित बाईपास बनवाने का मामला पहले जीरो ऑवर में उठाती रही हूं और पिछले पांच सालों से लगातार उठाती रही हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, विभाग बिना सवाल के भी संबंधित बाईपास बनवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके लिए माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं।

श्री ओम प्रकाश बरवाः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के लोहारू के लोहारू ब्लॉक में ढ़िघावा जाटान एक कस्बा है और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा हुई थी। इस जनसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि ढ़िघावा जाटान का बाईपास बनवाया जाएगा।

श्री अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, आप जो बात कह रहे हैं, वह अलग विषय है।

श्री ओम प्रकाश बरवाः अध्यक्ष महोदय, मैं बाईपास बनाने के बारे में ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, माननीय मंत्री जी बिना पूर्व सूचना के हरियाणा के सभी बाईपासों की जानकारी कैसे दे सकते हैं ? माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा था, यह बात उससे जुड़ी हुई नहीं है।

श्री ओम प्रकाश बरवाः अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मंत्री जी से सिर्फ यही बात पूछना चाहता हूं कि संबंधित बाईपास का स्टेट्स क्या है ?

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मेरे पास इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्रीमती प्रेम लताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि उंचाना के बाईपास का क्या स्टेट्स है ?

श्री अध्यक्षः प्रेमलता जी, माननीय मंत्री जी बिना पूर्व सूचना के सभी बाईपासों की जानकारी कैसे दे सकते हैं ?

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूगा कि संबंधित बाईपास की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दी जा चुकी है और जल्दी ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। संबंधित जिले के डी.सी. ने रिपोर्ट दे दी है कि ई–भूमि पोर्टल पर जमीन की डिमांड की जा रही है। इस बाईपास के लिए 57.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है और जल्द ही काम शुरू करवा दिया जाएगा।

श्रीमती प्रेमलताः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि विभाग द्वारा टैंडर कब तक लगवा दिया जाएगा ?

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि संबंधित काम के लिए जल्दी ही टैंडर लगवा दिया जाएगा।

श्री बिक्रम सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2015 में कोसली का बाईपास बनाने की घोषणा की गयी थी, परन्तु बाईपास बनवाने का कार्य शुरू नहीं करवाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि संबंधित बाईपास बनाने का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्षः बिक्रम जी, आपकी बात पूरी हो गयी है। प्लीज, आप बैठ जाएं। इस प्रश्न पर पहले ही बहुत ज्यादा स्पलीमैंटरी पूछी जा चुकी हैं। बिना पूर्व सूचना के मंत्री जी द्वारा इसका जवाब दिया जाना संभव नहीं है। अब माननीय सदस्य श्री अनूप धानक जी अपना प्रश्न पूछेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी विषय पर एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक बार–बार सवाल पूछने के लिए खड़े हो जाते हैं। इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार के 10 साल के शासन काल के दौरान इन्होंने अपने हल्के की कोई सड़के नहीं बनवायी और हमारी सरकार के समय में आज ही सभी सड़के बनवाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन के दौरान माननीय मंत्री जी ने मेरे द्वारा पूछे गये सवाल के बारे में आश्वासन दिया था कि गोहाना का पश्चिमी बाईपास बनवा दिया जाएगा, परन्तु वह अभी तक नहीं बनवाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सैशन के दौरान भी माननीय सदस्य को आश्वासन दिया था कि संबंधित बाईपास बनवा दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जगबीर सिंह जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक जी जो भी बात कहें, उसको रिकार्ड न किया जाए।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, ****

To Line The Unlined Water Courses

***3099**. **Shri Anoop Dhanak** : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to line the unlined water courses of the fields of Uklana Constituency, if so, the time by which the said water courses are likely to be lined?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हॉ, श्रीमान जी, 11 कच्चे खालों में से 7 खाले BCC-III परियोजना में शामिल हैं जो कि भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं । भारत सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद 6 महीने में इनका कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा ।

श्री अनूप धानकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये जिन 11 खालों को पक्का करने की बात कर रहे हैं, वह मेरा प्रश्न

.....

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया।**

नहीं है। मेरा प्रश्न कुछ और है और माननीय मंत्री जी जवाब कुछ और ही दे रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उकलाना निर्वाचन क्षेत्र के खेतों में जो कच्चे खाले हैं, उनमें से मैंने करीब 11 खालों को डिप्टी कमिश्नर के द्वारा डी–प्लान के तहत पक्का बनवा दिया है, इसके अलावा भी वहां पर बहुत सारे खाले कच्चे पड़े हुये हैं। मैं तो इन खालों की बात कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं माननीय मंत्री जी किन 11 खालों की बात कर रहे हैं, वहां पर तो बहुत ज्यादा खाले कच्चे पड़े हुये हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि उकलाना निर्वाचन क्षेत्र में 358 खाले हैं और जिनमें से केवल 11 खाले ही कच्चे हैं। इनमें से 283 खाले ऐसे हैं, जिनको बने हुए लगभग 20 साल से कम का समय हो गया है और 64 खाले ऐसे हैं, जिनको बने हुए लगभग 20 साल से ज्यादा का समय हो गया है। अध्यक्ष महोदय, यदि हमें इनकी जानकारी मिलेगी कि इन खालों की कंडीशन खराब है तो हम इनकी मरम्मत और पुननिर्माण जरूर करवायेंगे, क्योंकि सरकार के पास इन खालों की मरम्मत करने के लिए एक प्रॉविजन भी है। सरकार ने इससे संबंधित एक अच्छी पॉलिसी बनाई हुई है। पहले कमांडिंग एरिया प्रति एकड़ 24 फीट होता था, जोकि अब बढ़ाकर 40 फीट प्रति एकड़ कर दिया गया है। अगर माननीय सदस्य के पास इस संबंध में अतिरिक्त कोई जानकारी है तो ये हमें दे दें, हम अवश्य उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जो ये 11 खाले हैं, अगर इनके लिए भारत सरकार से फंड आने में देरी भी होगी तो हम स्टेट फंड से खाले पक्का करवाने का काम करवा देंगे।

श्री अनूप धनकः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को उन खालों की लिस्ट दे दूंगा और मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि हमारी खालों को जल्दी से जल्दी पक्का करवाया जाये।

श्री मूल चंद शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे बल्लभगढ़ विधान सभा क्षेत्र से एक खाला निकलता है, जो रजबाहा से होता हुआ पृथला विधान सभा तक जाता है, इसके साथ ही साथ वह खाला सैक्टर 3, 2, 64 और 65 से होता हुआ निकलता है। वह खाला बिल्कुल ही कच्चा पड़ा हुआ है, जिसके कारण कभी–कभी सैक्टरों में पानी भर जाता है और

कभी–कभी सैक्टरों की ग्रीन बैल्ट भर जाती है। इन खालों को पक्का करने के लिए एस्टीमेट्स भी आये हुये हैं। मैंने पिछले सैशन में भी इस सदन में यह मुद्दा उठाया था कि इन खालों से सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले कीड़े–मकोड़े भी निकलते हैं और कई बार तो पानी का फ्लो इतना तेज होता है कि पानी सैक्टरों में घुस जाता है, घरों में पानी चला जाता है और उससे पेड़–पौधों को भी नुकसान होता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये खाल केवल 2 किलोमीटर के ही है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि क्या यह खाल खेतों में सिंचाई के काम आता है या नहीं ?

श्री मूल चंद शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह खाल खेतों में सिंचाई के काम आता है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि हम इन खालों को पक्का करवा देंगे।

Details of Construction Works in Palwal

***3080. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) the ward wise details of all the construction works of roads/pavements of streets/construction of drains in all the Municipal wards of Municipal Council of Palwal from the year 2015 to 2018;

(b) whetherany complaint has been received by the Government in respect of the construction of roads/pavements of streets/construction of drains as mentioned in 'a' above; and

(c) if so, the details of the contents of the complaints togetherwith the action taken by the Government on such complaints?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविताजैन) : श्रीमानजी,

(क) वर्ष 2015 से 2018 तक के नगर परिषद, पलवल के सभी वार्डो में सडकों/गलियों के फुठपाथ/नालियोंके समस्त निर्माण कार्यो का वार्ड अनुसार ब्यौरा अनुलग्नक–"A" पर सलग्नहै।

(ख) हां, ऐसी 20 शिकायतें प्राप्त हुईहै।

(ग) विवरण अनुलग्नक–"B" पर सलग्नहै।

Municipal Council Palwal

List of Work (2018-19)
Annexure - A

Sr. No	Name of work	Ward No	Amount (In Rs)
1	Const of road and drain by interlcking tiles rakesh to om parkash to bhim	1	245424
2	Repair of various street	1	401807
3	Const of drain outer firni village firozepur	1	127067
4	const. of road & drain Rakesh to Omparkash,Bhagat singh to bhim	1	514043
5	Const. Of road & drain Water firni vill. Firojpur	1	717236
6	Repair and completion of harijan Chopal Firojpur	1	423567
7	Const. of road & drain h/o Mittal to Rajiv in W.No.1	1	941986
8	Const. of Harijan Choupal in Ward no 01 Vill Agwanpur	1	1114300
9	Repair of variou street	2	419673
10	Renovation of harijan chaupal in naya gaov	2	939030
11	Const. of road by interlocking tile & drain H/o Jagdish Sastri to H/o Bhoodev Sharma	2	287725
12	Const. of road & drain by interlocking tiles M35 grade H/o Hanraj to Prem Singh in W.No.2	2	891348
13	Const. of road by 80 mm thick interlocking tiles M35 Grade & drain from SM School to SM School in ward no 02	2	378315
14	Const of road and drain ashok baghel to ashok advocate	3	1088531
15	Const of road and drain IPB H/O to manoj mangla h/o manoj	3	843488
16	Const of road and drain kishan to naresh gautam prakash colony	3	880115
17	Const. of road & drain from Sunil Inspector	3	504605
18	Const. of road & drain from Sugar Singh to Manhor	3	556000
19	Const. of road & drain H//o Dr. Balbir to Samunder Akhara near H/o Budhi to Ram Chand	3	443099
20	Const. of road & drain H/o Sarup Parshad to Sodan	3	1081995
21	Const. of road & Drain H/o Kishan to Naresh Gotam Prakash Colony	3	151350
22	Const. of road by interlocking tiles M35 Garde & drain H/o Babu to Sumer Village Kithwari in ward no 3	3	234480
23	Const. of ILPB road & drain Kallu Parjapat to Balbir W.No.3	3	909068
24	Const. of road and drain by interlocking tiles M35 grade from H/o Gyani Gujjer to H/o Pappu in ward no 04	4	754820
25	Const. of road and drain by interlocking tiles M35 grade from H/o Harveer to Satpal in ward no 04	4	948880
26	Const of road and drain deep dhol wali gali in kailash nagar	4	585245

27	Const of road and drain house chunni to house nahar	4	524018
28	Const. of road and drain from Rop Singhj to Bhawar Singh	4	254737
29	Const.of Road & drain Khursid to Kewal	4	993967
30	Const of road & drain by interlocking tiles of m-35 grade in deep dhol wali gali ward no 4 mc Palwal	4	929671
31	Construction of road & drain by interlocking tiles of m-35 grade from h/o Brijlal to H/o Attar Singh Ward no 4	4	850699
32	Const. of road & drain from IPB M35 grade H/o Mahesh to Girraj W.No.4	4	175369
33	Const. of road by interlocking tiles M35 Grade & drain H/o Vijay Subedar to Khajan in ward no 4	4	442247
34	Const of road and drain h/o Dharamvir to Punit Chouadary and punit Virmani and Ghanshyam Goyal	5	600017
35	Const of road and drain Babbli to Sugar Singh to than Singh	5	1148340
36	RE-Const of road and drain from saini to kurshid	5	914841
37	Const of road bhola to babu lal	5	362050
38	Const. of road & drain by interlocking tiles from H/o Dinesh to H/o Satbir	5	760063
39	Const. of road and drain from Pahlad to Mandir	5	100005
40	Const. of road by interlocking tiles m35 grade & drain Bhola to Babu ram	5	515373
41	Raising of re-const. of street road by ILPB m35 grade Sanju to Khurshid W.No.5	5	401985
42	Const. of road by interlocking tiles M35 Grade and drain From H/o Charan to H/o Ram Kumar	6	1178537
43	Const of road and drain From Laxman to raghuveer	6	699670
44	Const of RMC road and drain Amar singh to Raju Panchal	6	2410034
45	Const. of road and drain by interlocking tiles M35 grade from H/o Bhan Singh to Pappu H/o Jitender to Ashok in ward no 6	6	465158
46	Const of RMC Rood from Maithal Dharamshala to Krishan Tailor to Mukesh Panchal in Ward No	6	2300759
47	Const. of road & drain interlocing tiles H/o Hari Master	6	769405
48	Const. of road & drain interlocking tiles H/o Manoj to Gopal	6	770084
49	Const. of road & drain by interlocking tiles M35 grade H/o Netarpal to Naresh H/o Jagdish W.No.6	6	322541
50	Const. of road by interlocking tiles M35 Grade and drain From H/o Umesh to H/o Subodh	7	238314
51	Const. of Road & drain by Interlocking tiles of M35 grade from H/o Ram Chand Fuji to Prem Chand W.No.7	7	1062593
52	Const. of road by interlocking tiles M35 Grade and drain From Saleem to H/o Om Parkash	8	992948
53	Const. of road by interlocking tiles M35 Grade and drain From H/o Dr. Manohar to H/o Balbir	8	667432
54	Const of road by ICPB tile of m-35 dr mannu house to balbir	8	126263

55	Const of shamshan ghat and fixing of RCC	8	1047147
56	Const. Of road & drain Girraj to Pritam	8	939907
57	Const. of road & drain from H/o Rampal to Naresh	8	769529
58	Const. of drain by IPB from H/o of Vinod Bsinla to hari nagar and Samsham ghat to H/o Samsu near Hari nagar Ward no 8	8	4156058
59	Const. of road by interlocking tiles M35 Garde & drain H/o Radhey Shyam to Subash in ward no 08	8	260988
60	Const. of road and drain by interlocking tiles of M-35 grade H/o Janardan to H/o Sahtri in ward no 08	8	232955
61	const. of shed in Ronija Village in Shamshan Ghat in ward no 09	9	919090
62	Const. Of road & drain Suresh to Ajit to jagram	9	265150
63	Const. Of road & drain Bir singh to Sukhram Holi dehan wali gali	9	263373
64	Repair and renovation of Jaat Choupal in Ward no 09	9	408150
65	Repair and renovation of beach wali choupal (near H/o Hukkam Singh) village Lohagarh W.No.9	9	923215
66	Repair road and drain sarrouding mandir to Sabal Vihar	10	409346
67	RE-Const of road with IPB kheda devat wali gali kuslipur	10	939878
68	Const of road and drain shri chand to babu subedar village kuslipur	10	618787
69	const. of road & drain Ranjeet to Subedar to Satbir	11	943133
70	Const. of road & drain H/o Manish Balmiki wali gali	11	192824
71	Const. of road & drain from Vijender Kabari wale to Kumar pal W.No.11	11	1324881
72	Const of renovation of Sahid Madan Lal Community center	12	23703614
73	Const. of road & drain from Gurudyal Ahuja to Super Market	12	850860
74	const. of drain mata mandir to silai center	12	116159
75	Providing & fixing retro reflective sign board (Welcome gate) Sahid Madan Lal Dhingra Near Devi Lal Park road MC Palwal	12	294951
76	Const. of rood and drain Ganda Nala to Sunder Das	12	1047416
77	Repair of various street with 80mm thick interlocking tiles m35 grade & drain	12	1494744
78	P/L B.M. with BC paith work various road in New colony	13	485324
79	Const of road and drain 80 mm thcik H/o Sardanand park to PWD Chowk	13	1135169
80	Const of road burm with 80 mm thick tile subhash chug to pwd chowk	13	1097727
81	Repair of road side gandhi park	13	685651
82	Re-Const.of DD Makkad wali gali	13	1313977
83	Maintenance & renovation of shardananad Park, Tikona Park in MC Palwal	13	574934
84	Maintenance & renovation of D Park, Mahatma Gandhi Park, Bhuragir Park in MC Palwal	13	486689

85	Maintenance & renovation of Balmiki Park, Bhagat Singh Park, Mini Park, Sastri Park, Rajput Park in MC Palwal	13	539451
86	Providing & laying RMC on D Park wali road New Colony	13	703805
87	Repair of Road in front and Side Gandhi Park in ward no 13	13	317201
88	Const. of ILPB road and drain from H/o Bane Singh to Sukhpal in MC Palwal	14	528841
89	Const. of ILPB road and drain from H/o Maan Singh to Lekraj in MC Palwal	14	1013628
90	Const of road and drain visham to jagdish	14	1075947
91	Const of road burm with thick tile bhati to ice factory wali gali	14	542192
92	const. of road & drain Vikram to Jeetram to Satish chabra	14	764777
93	Const. of road & drain h/o Hosiyar to Gulabad wali gali	14	983015
94	Const. of road & drain Bhagat Singh to Rattan	14	611006
95	Const. of raod & drain Arya Samaj Mandir to Tula Ram W.no.14	14	395482
96	Const. and repair of road and drain with 80mm thick IPB in W.No.14 Pandit Parsuram to Bhagirath Gaya Ram Dhudhola to Ratan Sorot	14	178191
97	Const. of road and drain 80 MM thick tile M-35 Grade with H/o Rajendera Bainsla Wali Gali in ward no 14	14	951182
98	Repair of various street by 80 mm thick interlocking tile and drain	15	556427
99	Const. of road & drain by interloking tiles 80 mm M 35 grade From h/o vikki nai to sankar bania	15	1136733
100	Const. of road & drain in gali 15	15	436400
101	Repair of various streets by 80mm thick interlocking tile & drain in W.no.15	15	463640
102	Raising of road & drain const. of IPB road H/o Rosan to Mangli wali gali	16	481493
103	Const. of road by 80mm thick interlocking tiles of M35 grade with drain H/o teji to Smt. Bimla Tandur	16	457961
104	Const of road and drain Dr. Parbhu dayal to Chamila Chowk to Shiv Ram	17	322418
105	Const of road and drain Suman to Omparkash to Seeta Ram	17	772262
106	Const of road and drain ram chand and mahesh to nai wali gali	17	100497
107	Repair of various street	17	641589
108	Const. of road and drain from H/o Rohtash Aroda wali in ward no 17	17	774880
109	Const. and repair of road by 80mm thick IPB H/o Jivan Jyti School to Master Kailash in W.No.17	17	1537752
110	Const. of ILPB road and drain from H/o Kamal to Govind in MC Palwal	18	1055552
111	Const. of road & drain H/o Bhusan Baniya to Bhudram to H/o Parbhu and Dharamvir to Govind in ward no 18	18	927040
112	Const. of road by 80 mm thick interlocking tiles m 35 Grade with drain from Shivdatt wali gali PWD 18	18	764077

113	Repair of various street in interlocking tiles m 35 garde with drain in ward no 18	18	480973
114	Const of road and drain in Daya Basti	19	36627
115	Const of road and drain master chintaram to pardeep to mandir	19	821271
116	const. of road & drain bhagirath police wala to NH 2	19	860729
117	const. of road & drain Sanjay to Lal chand	19	152415
118	Const. of rood and drain Master Chinta Ram to Pardeep	19	828020
119	Repair of various street 80 mm thick tiles with drain	20	509386
120	Repair of Balbhawan Park	20	983905
121	Const. of Guru Balmki Shed, Footh path & Yaga Shed Bal Bhawan Park in W.No.20 in MC Palwal	20	937601
122	Const. of RCC drain from Bus stand to Nala near Lakhpat Tyre wala MC Palwal	20	4850518
123	Const. of berm & drain by interlocking tiles Minar Gate to Railway road in MC Palwal	20	2219541
124	Const. of Seniour citizen old GT Road in MC Palwal	20	1185886
125	Const. Of Brim & drain Interlocking tiles Hamdia hostipal to Rasulpur chowk NH 2	21	3611154
126	Const of road and drain shiv mandir to suraj hwaldar	22	903580
127	Completion of Baghel Chopal	22	536779
128	Const. of road and drain from shop Ashu to Bagehal Choupal and Number Home in Shekpura in ward no 22	22	524147
129	Const of road and drain Dr. Sardana to Back side muthiood finance	23	3517397
130	Const. of road & drain H/o Goyal Beej Bhandar to dhyam Appartment and h/o Devi Ram Saini to Kanheya W.No.23	23	1074502
131	Const. of road & drain NH-2 to Madan Thanedar	23	349179
132	Const of toilet in media centerin Old Court Palwal	24	527935
133	Const. of road & drain from Janki Parshad to Puran to Ashok	24	737122
134	Const. of road & drain H/o ASI Omprakash to Pani Line	24	894674
135	Const. Of road & drain Satyaparkash to Pokhar Kashipur	24	937642
136	Const. of Toilet in Panchwati colony	24	423496
137	Const. of drain from H/o Kishan Diraver to H/o Dali Banchari Civil Line Ward No 24	24	300648
138	Const. of road by 80 mm thick interlocking tiles M35 Grade & drain H/o Raju Pandit & Bijender H/o Narender Sharma in ward no 24	24	850615
139	Const. of road by 80 mm thick interlocking tiles M35 Grade & drain H/o Naresh to Gyani to H/o Bharti Panchwati Colony in ward no 24	24	955769
140	Const of road and drain 80 mm thcik H/o Devan Adv. To Mahesh Thakur to Rattu wali gali	25	361525

141	Const of road and drain deven advocate to mahesh thakur to om parkash saini to rattu wali gali	25	338673
142	Const of road and drain dharam chaudhary and punit virmani and shyam charan wali gali	25	439718
143	Const of road and drain girraj singh wali gali ekta nagar and kalra colony	25	903643
144	Const. of rood and drain H/o Ghanshyam to amar singh Thakur shop of jivan Thakur to amar singh thakur to holika ward no 25	25	458836
145	Const of road and drain Dhan singh to Bhurvi	26	397902
146	Const. of road & drain from H/o Megh Singh to Jai and Tillu to Laxman	26	1003565
147	Const. of road & drain H/o Jawahar to Deep Chand and Deo Chand to Sodan	26	1167583
148	Const of road and drain Ganeshi to Mangal	27	27070
149	Const of boundary wall in khara no 27 dumpinh yard in Vill Meghpur	27	789456
150	Febrication and insallation in welcome Gate in Hathin road vill. Raipur	27	206004
151	Febrication and insallation in welcome Gate in Sohna road in meghpur Village	27	200490
152	Febrication and insallation in welcome Gate in Nuh raod	27	204927
153	Const. of ILPB road and drain from Peer Baba Wali gali in MC Palwal	27	720559
154	Const of road and drain Ram Singh to Mahipal to Bharat	27	146599
155	Const of road and Lawn in Shamshan Ghat to Near Tizo wala mandir	27	971813
156	Const of road and drain Chandi to Amar Sohna road	27	243111
157	Const. of road & drain Dhan Singh to Patram	27	1453401
158	Const. of Dumpling Station of Solid waste transfer station in Meghpur	27	7184737
159	Providing & fixing retro reflective sign board (Welcome gate) at Sohna road MC Palwal	27	345131
160	Const. of road & drain Bisan Singh Sarpanch to Prem Raj & infront of Dhan Singh Sarpanch village raipur	27	256441
161	Const. of repair of road Baghel Chopal to main puliya	27	217950
162	Const. of road & drain Harijan Mandir to Satbir W.No.27	27	810377
163	Const of road and drain Bhawan Kunad to Aheriya Chupal	28	6791598
164	Const of road and drain H/o Satpal Tewatia wali gali in Bhatia Colony	29	1094984
165	Const of road and drain by interlcking tiles Tulsi niketah to rampal in Bhatia colony	29	1087739
166	Const of road and drain H/o Ratiram to Sabu to Azad in Dulriya Mohalla	29	980301
167	Repair of Sanjay Park	29	352897
168	Const. of road & drain Dayanand School to Devi Satte wali	29	1114979
169	Const of road and drain Mandir to School village Alhapur	30	315593
170	Complitatiion of brahaman chaupal in alhapur	30	865711

171	Const. of road & drain h/o Daya Chand to Kishan Dukriya Mohalla	30	1111382
172	Const. of road & drain from Roop Chand to Kishan & H/o Gopal in W.No.30	30	238487
173	Const. of road & drain from Balmiki Samshan & Ramesh in W.No.30	30	1095593
174	Const of road and drain H/o Raju Katik to Kamal Singh	31	845659
175	Const of road and drain rohit pardhan wali gali	31	248648
176	Const. of road & drain by interlocking tiles from H/o Raju Thakur to Mahesh Pandit	31	1062757
177	const. of road & drain atul mangla to sonia mittal	31	772404
178	const. of road & drain Khemchand to Raju	31	1108189
179	Completion of Arya Samaj Mandir Khyali Enclave	31	1122688
180	Const. of road & drain by 80mm interlocking tiles m35 grade with drain from Rahit Pardhan wali gali W.No.31	31	424120
181	Intallation of Open Gym item in deffrent places in MC Palwal Parks	31	3232576

ANNEXURE – "B"

Detail of complaint received from the year 2015 to 2018: -

Sr. No.	Dated	Name of Complainant	Complaint	Action Taken report
1	13-01-15	Sh. Pawan Bhadana	Regarding construction of street.	Redressal of complaint done. About which complainant has submitted in writing.
2	04-04-16	Sh. Ramkishan	Regarding misuse of public money by contractor by collusion with Govt. Officers and negligence during construction of road work.	Redressal of complaint done. About which complainant has submitted in writing.
3	03-04-17	Smt. Dayawati	Regarding illegal construction of road on the land of complainant.	Redressal of complaint done. About which complainant has submitted in writing.
4	20-04-17	Smt. Poonam Sharma	Regarding water logging and dirt around the house of complainant.	Redressal of complaint done
5	30-05-17	Sh. Davender Kumar	Regarding construction of road without leveling of street.	Redressal of complaint done
6	13-06-17	Smt. Neelam Sharma	Regarding overflow of drains	Redressal of complaint done. About which complainant has submitted in writing.
7	08-09-17	Sh. Deepak	Problems be faced due to work done by MC.	Redressal of complaint done. About which complainant has submitted in writing.

8	23-08-17	Sh. Dhaniram	Regarding deposition of construction material by contractor in front of complainant house.	Redressal of complaint done. About which complainant has submitted in writing.
9	11-09-17	Sh. Lalit Kumar	Regarding non construction of Puliya over drain while construction of road and inferior construction material.	Redressal of complaint done. About which complainant has submitted in writing.
10	02-11-17	Sh. Sarwan Kumar	Regarding construction of road in Harinagar, W. no. 8.	Redressal of complaint done
11	28-11-17	Sh. Parmod Kumar	Regarding to get enquiry from CM Flyingfor the road work executed by Sh. Satyabhan contractor.	Redressal of complaint done
12	06-12-17	Sh. Rahul	Bricks are dismantle Due to not properly construction of drain and street in new colony palwal.	Redressal of complaint done
13	19-01-18	Sh. Lakhan Singh	Corruption in construction of road from Mohan nagar, W. no. 4 in front of mosque.	Redressal of complaint done
14	09-02-18	Sh. Giriraj Singh	Regarding appropriate action.	Redressal of complaint done
15	16-03-18	Sh. JitenderPuri	No action being taken on the complaint given regarding construction of road.	Redressal of complaint done
16	20-03-18	Sh. Naveen Sherawat	Regarding use of inferior quality of material for construction of road from the house of kuldeepsherawat to Dhani ram daggar.	Redressal of complaint done. About which complainant has submitted in writing.
17	21-05-18	Sh. Giriraj Singh	Regarding raising of level of street and drains	Redressal of complaint done. About which complainant has submitted in writing.
18	29-06-18	Sh. Lalit Kumar	Regarding construction of drain.	Redressal of complaint done. About which complainant has submitted in writing.
19	25-10-18	Sh. BhagwanShaye	Regarding conducting enquiry for negligence and irregularity done by contractor.	Redressal of complaint done. About which Residents of colony have submitted in writing.
20	18-12-18	Sh. Satish Kumar	Regarding not proper construction of road and drain in vasant vihar colony, palwal.	Redressal of complaint done

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नगर परिषद् पलवल के अलग–अलग वार्डों में जो विकास

कार्य किए जा रहे हैं जैसे चाहे वह पैव्मेंट ऑफ स्ट्रीट हैं और चाहे वह ड्रेन की कंस्ट्रक्शन है, इन सभी विकास कार्यों को करवाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसे किसी तरह का कोई भी टैंडर निकाला जाता है तो बाकायदा उसकी एडर्वटाइजमैंट समाचार–पत्रों के माध्यम से की जाती है, ताकि टैंडर मांगे जा सकें। क्या माननीया मंत्री जी बतायेंगी कि सरकार द्वारा वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2018 तक नगर परिषद् पलवल के सभी वार्डों में कितने विकास कार्य करवाये गये और टैंडर की बिडिंग किस प्रक्रिया के तहत करवाई गई है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि टैंडर की बिडिंग कौन–कौन से समाचार–पत्रों में प्रकाशित हुई और टैंडर अलॉट करने में किस सार्वजनिक सिस्टम को अपनाया गया? अध्यक्ष महोदय, माननीया मंत्री जी ने अपने उत्तर में भी इस बात को माना है कि सरकार के ध्यान में पलवल जिले के नगर परिषद् की 20 शिकायतें हैं अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि इन 20 शिकायतों की जांच क्या हरियाणा के विजिलैंस डिपार्टमैंट से करवाई जायेगी या इसके अलावा जो पलवल जिले के डिप्टी कमिश्नर है, उनकी निगरानी में इसकी जांच करवायेगी?

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी को बताना चाहूंगी कि नगर परिषद् पलवल के अलग–अलग वार्डों में वर्ष 2015 से 2018 के बीच में जो विकास कार्य हुए हैं उनका विवरण इस प्रकार है। वर्ष 2015 में 134 विकास कार्य हुए, वर्ष 2016 में 152 विकास कार्य हुए, वर्ष 2017 में 131 विकास कार्य हुए और वर्ष 2018 में 181 विकास विकास हुए। अगर हम इन चार वर्षों का टोटल देखें तो सरकार द्वारा 598 विकास कार्य कर चुकी है। जिसके लिए सरकार ने वहां पर 2650.39 लाख रुपये खर्च भी किए हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा सैप्लीमैंट्री क्वैश्चन पूछा था कि टैंडर की प्रक्रिया क्या अपनाई गई और इसके साथ ही साथ इन्होंने यह भी पूछा था कि क्या टैंडर मैनुअली दिए गए? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है, जिसने जीरों टॉलेरेंस करप्शन की नीति को अपनाया है। जहां तक अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमैंट की बात है तो इसमें 50 हजार रुपये के ऊपर का कोई भी काम बिना टैंडर के अलॉट नहीं किया जाता है और जब कोई व्यक्ति डिपार्टमैंट में टैंडर अप्लाई करता है तो ऑनलाईन के माध्यम से ही करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि टैंडर

की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाती है। माननीय सदस्य ने कहा कि 20 शिकायतें प्राप्त हुईं तो मैं उन 20 शिकायतों का विवरण क्रमवाइज माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, पहली शिकायत दिनांक 13.01.2015 को श्री पवन भडाना द्वारा प्राप्त हुई जोकि regarding construction of street है। इसकी शिकायत नगर परिषद् को दी और मेरे पास इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी है। हमने उस सड़क को बनवा दिया है और इसकी रिड्रैसल भी कंपलेनैंट से राईटिंग में ले ली है। दूसरी शिकायत दिनांक 04.04.2016 को श्री राम कृष्ण द्वारा प्राप्त हुई regarding misuse of public money by contractor in collusion with Government officers and negligence during construction of road work इस शिकायत के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट में बता दिया है कि इसका भी रिड्रैसल कर दिया गया है। Redressal of complaint done. About which complainant has submitted it in writing. तीसरी शिकायत दिनांक 03.04.2017 को श्रीमती दयावती के द्वारा प्राप्त हुई regarding illegal construction of road on the land of complainant. इसका भी रिड्रैसल कर दिया गया है और कंपलेनैंट से राईटिंग में ले ली है। चौथी शिकायत दिनांक 20.04.2017 को श्रीमती पूनम शर्मा से प्राप्त हुई regarding water-logging and dirt around the house of complainant. कंपलेनैंट ने दिनांक 03.05.2017 को इसके बारे में जवाब मांगा था कि मेरी शिकायत पर क्या एक्शन हुआ। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि इसको भी रिड्रैसल कर दिया गया है और कंपलेनैंट से रिड्रैसल को राईटिंग में भी ले लिया गया है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने 20 शिकायतों के बारे में पूछा है। मैं उन्हीं के बारे में इनको बता रही हूं कि उसमें क्या जांच हुई है और सरकार ने इसमें क्या कार्रवाई की है। यही हमारे माननीय सदस्य द्वारा पूछा भी गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : श्री करण सिंह दलाल जी, आपको तो माननीया मंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए। (विघ्न) प्लीज आप बैठ जाईये। मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी कि किसी दूसरे सदस्य की बातों को भी सुनने की पेशेंस होनी चाहिए। मैं इनको इनकी ही 20 शिकायतों के बारे में बता रही हूं कि नगर परिषद् पलवल ने इन 20 शिकायतों का क्या समाधान किया है? हमारी सरकार का यह

दायित्व है कि माननीय सदस्य को इनकी 20 शिकायतों के बारे में पता भी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा में माननीय सदस्य कुछ वर्ष पहले विधायक भी नहीं थे, तब भी इनका रुतबा किसी विधायक से कम नहीं था। माननीय सदस्य को इस बारे में पता होना चाहिए कि खुद की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इन्होंने पलवल क्षेत्र में कितने विकास कार्य करवायें और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इन 5 सालों में कितने विकास कार्य हुए? अध्यक्ष महोदय, मैं इन 20 शिकायतों के बारे में पहले पढ़ दूं। उसके बाद माननीय सदस्य को यह भी बता दिया जायेगा कि किस सरकार में कितने विकास कार्य हुए हैं और किस सरकार में कितने विकास कार्य नहीं हुए हैं?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कविता जैन जी, मेरे ख्याल से श्री करण सिंह दलाल जी आपकी बातों से सहमत हो गए हैं। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इनकी पांचवी शिकायत के बारे में बताना चाहती हूं जोकि दिनांक 30.05.2017 को श्री देवेन्द्र कुमार के द्वारा प्राप्त हुई regarding construction of road without leveling of street. इसका भी रिड्रैसल कर दिया गया है और रिड्रैसल भी कंपलेनैंट से राईटिंग में ले ली है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज, आप बैठ जाईये। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप माननीया मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी कि अगर ये इस महान सदन में इसी तरह से व्यवहार करते रहे तो भविष्य में इनके द्वारा लगाये गये किसी भी प्रश्न का जवाब इस महान सदन में नहीं दिया जायेगा। जब माननीय सदस्य अपने ही सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है तो भविष्य में हमें इनका बहिष्कार करने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इसी प्रकार से कम्पलेंट नम्बर 6 है जो कि श्रीमती नीलम शर्मा द्वारा 13.06.2017 को दी गई थी जो कि Overflow of drains के बारे में थी। इस कम्पलेंट के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट है कि Redressal of complaint done, about which complainant has submitted in writing. ऐसे ही कम्पलेंट नम्बर 7 है जो कि श्री दीपक द्वारा

08.09.2017 को दी गई थी जो कि problems be faced due to work done by MC के बारे में थी। इस कम्पलेंट के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट है कि Redressal of complaint done, about which complainant has submitted in writing. इसी प्रकार से कम्पलेंट नम्बर 8 है जो कि श्री धनी राम द्वारा दिनांक 23.08.2017 को दी गई थी जो कि Deposition of construction material by contractor in front of complainant house के बारे में थी। इस कम्पलेंट के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट है कि Redressal of complaint done, about which complainant has submitted in writing. इससे आगे कम्पलेंट नम्बर 9 है जो कि श्री ललित कुमार द्वारा 11.09.2017 को दी गई थी जो कि non-construction of Puliya over drain while construction of road and inferior construction material के बारे में थी। इस कम्पलेंट के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट यह है कि Redressal of complaint done, about which complainant has submitted in writing. इससे नैक्सट कम्पलेंट नम्बर 10 है जो कि श्री सरवन कुमार द्वारा दिनांक 02.11.2017 को दी गई थी जो कि Construction of road in Harinagar, Ward No.8 के बारे में थी। इस कम्पलेंट के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट यह है कि Redressal of complaint done. कम्पलेंट नम्बर 11 श्री प्रमोद कुमार द्वारा दिनांक 28.11.2017 को दी गई थी जो कि to get enquiry from CM Flying for the road work executed by Shri Satyabhan, Contractor के बारे में थी। इस कम्पलेंट के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट यह है कि Redressal of complaint done, about which complainant has submitted in writing. कम्पलेंट नम्बर 12 श्री राहुल द्वारा दिनांक 06.12.2017 को दी गई थी जो कि bricks are dismantle due to not properly construction of drain and street in new colony Palwal के बारे में थी। इस कम्पलेंट के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट यह है कि Redressal of complaint done, about which complainant has submitted in writing.

श्री अध्यक्ष : कविता जी, दलाल साहब आपके जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हैं इसलिए अब आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : सर, मैं इन सभी 20 कम्पलेंट्स के बारे में अपना रिप्लाई सबमिट करवा दूंगी। (विघ्न) स्पीकर सर, इसके अलावा मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की सरकार द्वारा अपने पांच साल के शासनकाल के दौरान पलवल के विकास के लिए सिर्फ 30 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गई जबकि हमारी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल के दौरान पलवल के विकास के लिए 126 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है। वहां पर जितने भी ड्रेनेज के काम थे, जितने भी नालों के काम थे और जितने भी गलियों के काम थे उन सबको हमारी सरकार द्वारा प्राथमिकता के तौर पर करवाया गया है। हमारी सरकार के प्रयासों से ही पलवल से गुजरने वाला एलीवेटिड हाईवे अपने आप में एक मास्टरपीस बनने जा रहा है। इसी प्रकार से पलवल में फाटक पार पांच करोड़ रूपये की राशि से शहीद मदन लाल ढ़ींगड़ा के नाम से एक कम्युनिटी सैंटर बना है। ऐसे ही सवा दो करोड़ रूपये की लागत से वहां पर एक पार्क का निर्माण भी करवाया गया है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगी कि पलवल में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना काम हमारी सरकार ने किया है उतना पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया है। मैं यह समझती हूं कि माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी भी इस फर्क को महसूस करेंगे।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, माननीय मंत्री महोदया ने जितना लम्बा उत्तर देने की कोशिश की है और जो मेरे सवाल के एवज़ में जो इन्होंने जानकारी दी है उसमें इन्होंने खुद माना है कि उसके अंदर 20 शिकायतें हैं। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि शिकायतें सिर्फ 20 नहीं बल्कि हज़ारों हैं। यह मैं मानता हूं कि यह माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा है कि पलवल में विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए पैसा जा रहा है लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय का एक पॉलिटिकल सैक्रेटरी जो वहां पर होने वाले तमाम कामों में दखल देता है। जो वहां पर म्युनिसिपल बॉडी की महिला चेयरपर्सन है उनका बेटा फाइल्स निकालने में उनकी वैसे ही मदद करता है जैसे माननीय मंत्री जी के पति इनकी मदद करते हैं। स्पष्ट तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर सभी कामों में बहुत बड़ी धांधली हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मैं यह बात स्पष्ट करना चाहती हूं कि चाहे कोई भी हो उसको एक सलाहकार की जरूरत होती है। मेरे पति मेरे सलाहकार हैं। मुझे यहां पर इस बात को कहने से कोई गुरेज नहीं है। वो मेरे गुरू भी हैं मुझे

इस बात को स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। जब मुझे घर में ही शिक्षा मिल रही है तो मुझे बाहर से शिक्षा लेने की क्या आवश्कता है?

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, पलवल में विकास कार्यों के लिए पैसा जा रहा है इससे मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूं लेकिन इसके साथ मेरा यह कहना है कि वह पैसा पलवल के विकास में न लग करके भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेताओं की जेबों में जा रहा है। वहां पर किसी काम के लिए कोई प्रॉपर टैण्डर प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना है कि अगर ये कोई जांच करवाना चाहते हैं तो उस बारे में ये पुख्ता सबूतों के साथ हमें लिखकर दें। उसके बाद हम उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अगर आप किसी मामले की जांच करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कम्पलीट इनफर्मेशन मंत्री जी को लिखित रूप में दे दें।

.....

डिवाइन पब्लिक स्कूल शाहबाद मारकंडा जिला कुरूक्षेत्र तथा डी.ए.वी. महाविद्यालय नन्यौला, अम्बाला शहर के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, डिवाइन पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा के विद्यार्थी और अध्यापकगण, सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका हार्दिक अभिनन्दन करता है। इसी प्रकार से डी.ए.वी. कॉलेज नन्यौला के प्राध्यापक और विद्यार्थी भी सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका भी हार्दिक अभिनन्दन करता है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री करण सिह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगी? नगर परिषद् में पैसा तो जा रहा है लेकिन वह विकास कार्यों में न लग कर ** जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल जी ने जो ** शब्द कहे हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्षः ठीक है, श्री करण सिंह दलाल जी ने जो ** शब्द कहे हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इसकी विजिलैंस जांच करवायेंगी?

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, विजिलैंस जांच की जरूरत नहीं है। मंत्री जी ने इसका विस्तृत जवाब सदन में दे दिया है।

.....

Policy of Cash Award to players

***3100. Shri Jagbir Singh Malik:** Will the Sports and Youth Affairs Minister be pleased to state the policy of the Government to give cash award to medalists of Olympics, Asian, Commonwealth, National and other games togetherwith the details of the games included in the above said policy ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : महोदय, खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार देने के संबंध में नीति संलग्न है।

नीति

I. ELIGIBILITY OF SPORTS PERSON:

(i) Domicile/resident of Haryana;

(ii) Did not play for a State/UT other than Haryana; and

(iii) Plays for Haryana State at the National level.

However, in case of medal winners in Olympics, Paralympics, Asian Games, Para Asian Games, Youth Olympics, Commonwealth Games, Youth Asian Games and World Cup/Championship (held once in 4 years cycle), the sub-condition at (iii) above will be relaxed in case thesportsperson plays for any central organization due to employment or sports training.

II. RESTRICTION ON SPORTS DISCIPLINES ELIGIBLE FOR CASH AWARDS:

In respect of the following tournaments, cash awards will be restricted to the following sports disciplines: -

A. In the case of World Cup/Championship, World University Games/Championship, Asian Cup/Championship, Commonwealth Cup/Championship, SAF Games, National Championship and All India Inter-University Tournaments/Championship: -

(i) Sports disciplines included in Olympic Gamesor Asian Games or Commonwealth Games.

(ii) Chess.

B. In the case of Para World Games/Championship and Para National Championship: -

(i) Sports disciplines included in Paralympic Games or Asian Para Games or Commonwealth Games (Para-Sports).

(ii) Chess.

The word, "sports disciplines" appearing in this Para shall be construed as "sports events".

III. CASH AWARDS FOR TEAMEVENTS:

I. Cash award will be admissible to a member of the team provided he has played at least one game in the tournament.

II. In certain games, individual scores are aggregated to form the team score. In such cases, cash award will be admissible in either individual event or team event, but not both.

III. Cash award per member in case of team events will be admissible as under:-

Team of 2 members: 75% of award in individual event

Team of 3 or more members: 50% of award in individual event

IV. **CASH AWARDS TO SPORTSPERSONS IN INDIVIDUAL EVENTS:**

The cash awards to eligible sportspersons in individual events will be governed as per the Table below. In case a sportsperson wins more than one medal during a financial year, he/she will receive full award money for the highest medal and at 50% of the award money for the second and subsequent medals.

Sr. No.	Tournament	Medal	Award Money (Rs.)
1.	Olympics/Paralympic Games	Gold Silver Bronze Participation	6,00,00,000 4,00,00,000 2,50,00,000 15,00,000
2.	Asian/Para Asian Games	Gold Silver Bronze Participation	3,00,00,000 1,50,00,000 75,00,000 7,50,000
3.	Youth Olympic Games	Gold Silver Bronze Participation	1,00,00,000 65,00,000 40,00,000 2,50,000
4.	Commonwealth Games/ Para Commonwealth Games	Gold Silver Bronze Participation	1,50,00,000 75,00,000 50,00,000 7,50,000
5.	World Cup/Championship (once in 4 years)	Gold Silver Bronze Participation	1,50,00,000 75,00,000 50,00,000 7,50,000
6.	Para World Games/Para World Championship (once in 4 years cycle)	Gold Silver Bronze Participation	1,50,00,000 75,00,000 50,00,000 7,50,000
7.	Deaflympics	Gold Silver Bronze Participation	1,20,00,000 80,00,000 40,00,000 2,50,000
8.	Youth Commonwealth Games	Gold Silver Bronze	25,00,000 12,50,000 8,00,000
9.	World Cup/Championship, Para World Cup/Para World Championship	Gold Silver Bronze	40,00,000 30,00,000 20,00,000

	(once in 2 years cycle)	Participation	5,00,000
10.	World Cup/World Championship/ Para World Game/Para World Championship (annual)	Gold Silver Bronze Participation	20,00,000 15,00,000 10,00,000 3,00,000
11.	IBSA World Games	Gold Silver Bronze Participation	20,00,000 15,00,000 10,00,000 2,00,000
12.	World Junior Cup/Championship, Junior Para World Cup/Championship (once in 4 years cycle)	Gold Silver Bronze Participation	20,00,000 15,00,000 10,00,000 3,00,000
13.	Special Olympics-World Games for mentally challenged	Gold Silver Bronze Participation	20,00,000 15,00,000 10,00,000 2,00,000
14.	World Cup/Championship, Para World Cup/Para World Championship (2 or more times in a year)	Gold Silver Bronze	10,00,000 7,50,000 5,00,000
15.	World Junior Cup/Championship, Junior Para World Cup/Championship (once in 1 or 2 years cycle)	Gold Silver Bronze Participation	10,00,000 7,50,000 5,00,000 1,50,000
16.	World University Games/Championship	Gold Silver Bronze	7,00,000 5,00,000 3,00,000
17.	Asian/Commonwealth Championship/Cup	Gold Silver Bronze	5,00,000 4,00,000 3,00,000
18.	SAF Games	Gold Silver Bronze	5,00,000 3,00,000 2,00,000
19.	National Games/Para National Games	Gold Silver Bronze	5,00,000 3,00,000 2,00,000
20.	World Junior Cup/Championship, Junior Para World Cup/Championship (2 or more times in a year)	Gold Silver Bronze	5,00,000 3,00,000 1,00,000
21.	World Sub-Junior Cup/Championship, Sub-Junior Para World Cup/Championship (once in 1, 2 or 4 years cycle)	Gold Silver Bronze	5,00,000 3,00,000 1,00,000
22.	4-year Blind Cricket World Cup	Gold Silver Bronze Participation	5,00,000 3,00,000 2,00,000 1,00,000
23.	National Championship/Para National Championship	Gold Silver Bronze	3,00,000 2,00,000 1,00,000
24.	World Marathon for mentally/Physically Challenged	Gold Silver Bronze Participation	3,00,000 2,00,000 1,00,000 50,000
25.	Asian/Commonwealth Junior Championship/Cup	Gold Silver Bronze	3,00,000 2,00,000 1,00,000
26.	Asian/Commonwealth Sub-Junior Championship/Cup	Gold Silver Bronze	1,50,000 1,00,000 50,000
27.	SAF Junior Games	Gold Silver Bronze	1,50,000 1,00,000 50,000
28.	International Veteran (Master) Athletics Championship (in all age groups)	Gold Silver Bronze	1,00,000 60,000 40,000
29.	National Veteran (Master) Athletics Championship (in all age groups)	Gold Silver Bronze	75,000 50,000 30,000
30.	Khelo India Games	Gold Silver	50,000 30,000

		Bronze	20,000
31.	National School Games	Gold Silver Bronze	50,000 30,000 20,000
32.	All India Inter University Tournament/Championship	Gold Silver Bronze	50,000 30,000 20,000
33.	National Women Sports Festival	Gold Silver Bronze	50,000 30,000 20,000
34.	All India Rural Sports Tournament	Gold Silver Bronze	50,000 30,000 20,000
35.	Special Olympics (National) for mentally challenged	Gold Silver Bronze	50,000 30,000 20,000
36.	National Junior Championship/Junior Para National Championship	Gold Silver Bronze	50,000 30,000 20,000
37.	National Sub-Junior Championship/Sub-Junior Para National Championship	Gold Silver Bronze	25,000 15,000 10,000

V. CHESS:

Cash awards will also be given for winning a title given by FIDE (International Chess Federation), Provided the sportsperson wins the title before the age of twenty years

(i) International Grand Master Rs. 5,00,000

(ii) International Master / International Women Master: Rs. 2,00,000

VI. PARTICIPATION MONEY:

Participation money will be paid to eligible sportspersons, wherever applicable, before the commencement of tournament after confirmation of selection by the Ministry of Youth Affairs and Sports.

VII. VERIFICATION OF CASH AWARD APPLICATION BYNATIONALSPORTSFEDERATION:

Cash award application will be verified by the National Sports Federations (NSF) under the signature of President or Secretary General of the NSF. The amount will be credited into the Bank account of sportspersons/coaches. Copies of all documents enclosed in support of the application will be self-attested by the sportsperson/coach.

VIII. GENERALCONDITIONS:

(i) The international sports competitions should have been conducted by the international sports body recognized by International Olympic Committee (IOC), International Paralympic Committee (IPC), Olympic Council of Asia (OCA), World Chess Federation (FIDE), International Sports Committee for the Deaf (ICSD), International Blind Sports Federation (IBSA) or Special Olympics International, as the case may be.

(ii) There may be some ambiguity in determining as to which official World/Asian/Commonwealth championship should be eligible for the cash awards, as there may be many kinds of tournaments, cups or championships all organized officially but only one and the best of them may be listed as theofficial World / Asian / Commonwealth Championships in each eligible discipline for the purpose of these cash awards. The Government of Haryana will have the right to decide as to which event will be eligible for the cash award.

(iii) Application by the eligible sportsperson will be made in the prescribed proforma to the concerned District Sports and Youth Affairs Officer. False information or concealment of

material information in the application form by the sportsperson will render him/her ineligible in future for cash award; appointment under the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018 and issue of Sports Gradation Certificate.

(iv) Cash awards will not be given to sportspersons in following cases:-

(a) Sportspersons who made wrong claims earlier on the basis of false information or concealment of material information. In case any such proceeding is pending against a sportsperson, the cash award will be withheld till finalization of the pending proceeding.

(b) In the case of any sports related misconduct.

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में खिलाड़ियों को कितनी राशि किस वर्ग में दी गई है? जूनियर कुश्ती चैम्पियनशिप के लिए पिछली सरकार ने 3 लाख, 2 लाख तथा 1 लाख रुपये की इनाम राशि का प्रावधान किया था। क्या सरकार ने उसको घटा कर 50 हजार, 30 हजार तथा 20 हजार रुपये कर दिया है? तीसरा सवाल यह है कि खिलाड़ियों को बार–बार सम्मानित करने के लिए समारोह कितनी बार घोषित किये गये और कितनी बार रद्द किये गये हैं? बजरंग पूनिया तथा विनेश फौगाट ने भी विरोध किया था कि सरकार खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि कम कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह राशि कम कर दी है या कम करने जा रही है?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मै माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने वर्ष 2014–15 में 1759 खिलाड़ियों को 29 करोड़ रुपये ईनाम राशि के रूप में दिये हैं । वर्ष 2015–16 में 3415 खिलाड़ियों को 89 करोड़ 90 लाख रुपये ईनाम राशि के रूप में दिये हैं । वर्ष 2016–17 में 1862 खिलाड़ियों को 48 करोड़ 88 लाख रुपये ईनाम राशि के रूप में दिया है । वर्ष 2017–18 में 160 खिलाड़ियों को 41 करोड़ 73 लाख रुपये ईनाम राशि के रूप में दिया है । वर्ष 2018–19 में 1166 खिलाड़ियों को 33 करोड़ 31 लाख रुपये ईनाम राशि के रूप में दिया है । वर्ष 2019–20 में 2930 खिलाड़ियों को 92 करोड़ 49 लाख रुपये ईनाम राशि के रूप में दिया है । सर, हमने अपने कार्यकाल में लगभग 425 करोड़ रुपये की राशि खिलाड़ियों को ईनाम के रूप में दी है । जैसा कि माननीय विधायक ने बात की है कि कोई भी तारीख रख कर खिलाड़ियों के खातों में ईनाम राशि डाल दी गई है । हम सोच रहे थे कि हम खिलाड़ियों को बुलाकर एक बड़ा सा कार्यक्रम करें । जैसे पिछली बार हमने 15 अगस्त को जोकि नैशनल डे होता है और हिन्दुस्तान के

अन्दर उससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता । उस दिन हमने सभी खिलाड़ियों को हर जिले में बुलाकर ईनाम दिया था । इस बार क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी जैसा कि मैंने बताया 2930 खिलाड़ी थे । उस समय अगर एक खिलाड़ी पर पांच मिनट भी लगाएं तो लगभग 15000 मिनट लगते थे जोकि मुमकिन नहीं था और हम इसको डिले नहीं करना चाहते थे इसलिए हमने सभी खिलाड़ियों की ईनाम की राशि उनके खाते में डाल दी थी। इसके साथ हमने उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दे दिया था । उसके साथ ही हमने यह भी कहा कि अगर किसी खिलाड़ी की राशि में कोई त्रुटि हो तो वह हमें बता सकता है । सर, हमारे पास 3000 खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी की भी आपत्ति नहीं आई । अगर किसी और सदस्य के पास आई हो तो हमें उसका पता नहीं है । जहां तक इन 2930 खिलाड़ियों को सम्मानित करने की बात है उसके लिए हम सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स को कह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को 15 अगस्त के दिन अपने–अपने जिलों में बुलाकर सम्मानित किया जाए ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, सब–जूनियर गेम्स में पिछली सरकार के समय में गोल्ड मैडल के लिए 3 लाख रुपये, सिल्वर मैडल के लिए 2 लाख रुपये और कांस्य पदक के लिए 1 लाख रुपये की राशि ईनाम के रूप में निर्धारित की गई थी । अब ये राशि 50 हजार, 30 हजार और 20 हजार रुपये कर दी गई है । मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि सरकार ने इस ईनाम की राशि को कम क्यों किया है ? दूसरा मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि मेरे हल्के से एक खिलाड़ी प्रवीन मलिक है जो वर्ष 2017 में सब–जूनियर गेम्स में गोल्ड मैडलिस्ट था जिसकी इनाम की राशि 2 लाख रुपये बनती है । वर्ष 2018 में अण्डर 23 नैशनल में गोल्ड मैडल था जिसकी इनाम की राशि 3 लाख रुपये बनती है । वर्ष 2018 में खेलो इण्डिया में गोल्ड मैडलिस्ट था और वर्ष 2019 में भी गोल्ड मैडलिस्ट था जिसकी इनाम की राशि 9–10 लाख रुपये बनते हैं लेकिन उस खिलाड़ी को अब तक केवल 50 हजार रुपये मिले हैं । जो खिलाड़ी इतनी छोटी उम्र में चार बार गोल्ड मैडल ले चुका है उसको अब तक केवल 50 हजार रुपये मिले हैं जब कि उसकी इनाम की राशि 9–10 लाख रुपये बनते हैं । आप कहते हैं कि हमें पता नहीं है । इसी तरह से पहलवान बजरंग पूनिया को भी 70 लाख रुपये कम मिले हैं । यह खबर तो अखबार में आई है । विनेश फोगाट को भी कम राशि मिली है। ये लोग रिजेंटमेंट करते हैं और मंत्री जी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है । मैं मंत्री

जी से पूछना चाहता हूं कि सब–जूनियर गेम्स में इनाम की राशि कम हुई या नहीं ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमने 3000 खिलाड़ियों को यह इनाम की राशि दी है । हम मानते हैं कि हमारे से भी गलती हो सकती है । मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि अगर किसी खिलाड़ी को उसके स्टेटस के अनुसार इनाम की राशि नहीं मिली है तो वह हमें पत्र लिख सकता है और हम उस गलती को ठीक करेंगे । जिस खिलाड़ी की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं उसका हमें तो कोई पत्र नहीं आया । सर, अगर हमें किसी खिलाड़ी का पत्र आएगा तो हम उसके प्रति पोजीटिव हैं क्योंकि हम उसको ठीक करना चाहते हैं और हम ठीक करेंगे ।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, अब आप ही बताओ कि खिलाड़ी खेल खेलेंगे या फिर पत्र लिखेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, पैरा स्पोर्टस का मामला चल रहा है अतः इस विषय पर मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। मेरे एरिया के कुछ पैरा एथलीट्स हैं जिनमें एक का नाम संदीप मोर है जोकि गांव रेढुवास का है और दूसरा रविन्द्र सिंह है जोकि सहलंगा गांव से संबंध रखता है तथा एक बैस्ट एम्पलाई भी रहा है, इनको सरकार द्वारा कैश अवार्ड दिया जाना था जोकि आज तक भी इनको नहीं दिया गया है। इन पैरा एथलीट्स ने मुझे एक रिप्रेजेंटेशन दी है जिसको मैं माननीय स्पोर्टस मंत्री जी के पास भी जरूर पहुचाउंगी। इन पैरा एथलीट्स ने कैश अवार्ड न मिलने वाला मामला विभाग के माध्यम से सरकार के पास भिजवाया है लेकिन आज तक भी यह कैश अवार्ड इनको नहीं मिल पाया है। इसी प्रकार हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और भी हैं जोकि केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने का काम करते हैं, वे भी अपनी इसी प्रकार की तकलीफों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। सरकार द्वारा ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित करने की बजाय, बार बार अपमान करने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार इवेंट्स मैनेजमैंट जैसे विषयों पर इतना समय लगा सकती है तो देश के तिरंगे को उपर उठाने का काम करने वाले खिलाड़ियों के लिए भी सम्मान समारोह आयोजित करके इनको सम्मानित करने का काम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने बहुत ही अहम सवाल किया है लेकिन मंत्री जी गोल–मोल करके उसका जवाब दे रहे हैं। खिलाड़ियों को जो सम्मान राशि देनी चाहिए थी उसको कम करने का काम यह सरकार कर रही है। अगर सरकार ने सम्मान राशि कम नहीं की है तो मंत्री जी इस बारे में बतायें, सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पहलवान जिसका नाम विरेन्द्र सिंह है और जिसको गूंगा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है, को अपने सम्मान की राशि को कोर्ट के माध्यम से लेना पड़ा था। (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कांग्रेस की सरकार के समय में हर गेम की जो प्राइज अमाउंट होती थी, उन सबको बढ़ाने का काम किया है। मैं इसको पढ़कर सुना देता हूँ तो सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय.... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, अब मंत्री जी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके आप खड़ी होकर बोलने लग गई हैं। जब आप लोगों ने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर भी तो सुन लो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, ओलम्पिक गेम्ज में जहां पहले गोल्ड मैडल के लिए 5 करोड़ रूपये मिलते थे हमने उसको 6 करोड़ रूपये कर दिया, सिल्वर मैडल के लिए 3 करोड़ की बजाय 4 करोड़ कर दिया, ब्रॉंज मैडल के लिए 2 करोड़ की बजाय 2.50 करोड़ रूपये कर दिए। पार्टिसिपेशन के लिए जहां पहले 11 लाख रूपये मिलते थे हमारी सरकार ने वह राशि 15 लाख रूपये कर दी। एशियन और पैरा एशियन में जहां पहले गोल्ड के लिए 2 करोड़ रूपये दिए जाते थे हमने उसको 3 करोड़ रूपये करने का काम किया और इसी प्रकार सिल्वर मैडल के लिए जहां पहले 1 करोड़ रूपया मिलता था हमने उसको 2 करोड़ रूपये देने का काम किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी फिर गोल मोल जवाब देने लग गए। सरकार ने सम्मान राशि कम करने का काम किया है इसके बारे में मंत्री जी क्यों नहीं बता रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कांग्रेस के राज में और भारतीय जनता पार्टी के राज में खिलाड़ियों को विभिन्न मैडल्ज के लिए दी जाने वाली राशि का तुलनात्मक विवरण दे रहे हैं। अतः हमारे विपक्ष के साथियों को चुप रहकर उनकी बात सुननी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया है केवल उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, स्वास्थ्य मंत्री जी पिछली सरकार और इस सरकार के दौरान खिलाड़ियों को दी जाने वाली सम्मान राशि की तुलना करके बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को शांत रहकर उनकी बात सुननी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी जो आंकड़े पढ़कर सुना रहे हैं यह सरकार के आंकड़े हैं। इनसे पता चल जायेगा कि इस सरकार ने सम्मान राशि कम करने का काम किया है या ज्यादा करने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो पढ़कर सुना रहे हैं वह बस रिकॉर्ड ही है इससे ज्यादा कुछ नहीं है। असलियत यह है कि खिलाड़ियों को कुछ नहीं दिया जा रहा है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को स्पेसिफिक यह बताना चाहिए कि सम्मान राशि कम की गई या नहीं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, मंत्री जी वही तो बता रहे हैं। आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को स्पेसिफिक सवाल का ही जवाब देना चहिए। (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं सारे उत्तर दूंगा बस इन लोगों को हाजमे की गोली खाने की जरूरत है। मैं इनको सलाह देता हूँ कि इन लोगों को सदन में हाजमे की गोली खाकर आना चाहिए ताकि इनको बात हजम हो जाये।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सवाल का जवाब तो देते नहीं फालतू बातें करने लग जाते हैं। गोली खा के आया करो, यह कहने का क्या मतलब है। हम कोई नशाखोर नहीं है? कैसी बात करते है? क्या मतलब है इनका।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, गोली खाकर आने से मेरा मतलब है कि यदि ये हाजमे की गोली खाकर आयेंगे तो इन लोगों को बात हजम हो जायेगी लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि किरण जी मुझसे इस प्रकार कैसे बोल रही हैं? क्या इनको बोलना नहीं आता? इनको आराम से बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, गोली खाने की बात इतनी बुरी तो नहीं है कि आप नाराज हो जाएं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी महिला सदस्या के साथ मुखातिब हो रहे हैं तो इनको थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। इनका ब्याह नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी महिला सदस्यों के साथ रूखा बोलने लग जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जवाब देना चाहिए बात को घुमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, पैरा कॉमन वैल्थ गेम्ज में जहां पहले गोल्ड के लिए 1 करोड़ रूपया दिया जाता था उसको हमारी सरकार ने 1.50 करोड़ रूपये करने का काम किया। इसी प्रकार सिल्वर मैडल के लिए जहां पहले 50 लाख रूपये दिए जाते थे, हमारी सरकार ने उसे 75 लाख रूपये करने का काम किया। ब्रांज मैडल के लिए जहां पहले 25 लाख रूपये दिए जाते थे अब हमारी सरकार ने 50 लाख रूपये देने का काम किया है। इसी प्रकार पार्टिसिपेशन में जहां पहले 5 लाख रूपये दिए जाते थे, उसे हमारी सरकार ने 7.50 लाख रूपये करने का काम किया। वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जोकि चार साल में एक बार आयोजित की जाती है में जहां पहले गोल्ड मैडल के लिए 10 लाख रूपये दिए जाते थे उसको हमारी सरकार ने 25 लाख रूपये करने का काम किया है। इसी तरह सिल्वर मैडल के लिए जहां पहले 8 लाख रूपये दिए जाते थे, हमारी सरकार ने उसको 20 लाख रूपये करने का काम किया है तथा ब्रांज मैडल के लिए जहां पहले 6 लाख रूपये दिए जाते थे उसे हमारी सरकार ने 15 लाख रूपये देने का काम किया। इसी प्रकार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्ज में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय एक नया पैसा भी देने का काम नहीं किया जाता था, हमने इसके लिए 7 लाख रूपये देने का प्रावधान किया। सिल्वर मैडल में भी पहले एक नया पैसा नहीं दिया जाता था लेकिन हमारी सरकार ने 5 लाख रूपये देने का प्रावधान कर दिया है। ठीक इसी

प्रकार ब्रांज मैडल में इनकी सरकार के समय कुछ नहीं दिया जाता था लेकिन हमारी सरकार ने 3 लाख रूपये देने का प्रावधान कर दिया है। स्पीकर सर, हमने गेम्ज के हर क्षेत्र में पैसा बढ़ाकर देने का काम किया है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताएं कि कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और सदन को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में एशियन गेम्स हुई थी लेकिन कांग्रेस पार्टी पदक धारकों को बिना इनाम दिए ही चली गई। उन पदक धारकों को इनाम भी हमारी सरकार ने ही आकर दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी प्रश्न का असली जवाब नहीं दे रहे हैं और सदन में यह भी नहीं बता रहे हैं कि खेलों का नौकरी में कितना कोटा है? सरकार यह भी बताएं कि खेल कोटे के हिसाब से अब तक कितनी भर्तियां की हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आपका खेलों में नौकरियां देने के नाम पर कोई प्रश्न नहीं था।

.....

To Check the Problem of Rainy Water

***3084. Shri Lalit Nagar:** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the rainy water accumulates in the roads and houses of Spring Field Colony, Inderprasth Colony, Ashoka Enclave, Sector-29 of Tigaon Assembly Constituency; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to check the abovesaid problem togetherwith the details thereof ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : (क) व (ख) नहीं, श्रीमान जी ।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब बड़ा आश्चर्यजनक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के सैक्टर्ज और कॉलोनियों में बारिश के समय 2–2, 3–3 फीट पानी भर जाता है। माननीय मंत्री जी ने एक मिनट में ही प्रश्न का जवाब दे दिया है कि कोई प्रपोजल नहीं है। यदि माननीय मंत्री जी अपने महकमे को नहीं

संभाल सकती तो माननीय मंत्री जी अपने पद से *** दे दें। इस प्रकार का जवाब माननीय मंत्री को नहीं देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य की बात पर ऑब्जैक्शन है। माननीय सदस्य को विषय से बाहर जाकर इस तरह का कॉमेंट माननीय मंत्री पर नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्य ने यह कैसे अंदाजा लगा लिया है कि वह अपना विभाग नहीं संभाल सकती हैं। यदि भाई ललित नागर साहब के विधान सभा क्षेत्र की कोई समस्या है तो वह सदन को बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ललित नागर साहब ने जो शब्द कहा है उसे रिकॉर्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रश्न के दौरान बीच में नहीं बोल सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री बोल सकते हैं। बहन किरण चौधरी पता नहीं इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं ? (शोर एवं व्यवधान) आप लोग बिना बात के बीच–बीच में खड़े हो जाते हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : श्री ललित नागर जी, आप बहुत अच्छे विधायक हैं। विधायक होने के नाते सदन की मर्यादा के अनुसार अपनी विधान सभा क्षेत्र की हर समस्या का हल संबंधित माननीय मंत्री से पूछना आपका हक भी है लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देता है।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मुझे यह भी बता दें कि हमारा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के तौर पर चुना गया था और मुझे यह भी बता दें कि आज तक स्मार्ट सिटी के तौर पर फरीदाबाद में कितना पैसा विकास पर लगा है? आज भी फरीदाबाद के सैक्टर 7,8,16 और 18 आदि में और ओल्ड फरीदाबाद में बारिश के समय 4–4, 5–5 फीट पानी भर जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो 2300 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी के नाम पर आया था वह पैसा कहां पर लगया गया है? माननीय मंत्री जी इस बात का भी सदन को जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : नागर साहब, आप सवाल तो कम पूछ रहे हैं और भाषण ज्यादा दे रहे

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

हैं। यदि आप टू दि प्वायंट सवाल पूछेंगे तो माननीय मंत्री जी भी टू दि प्वायंट जवाब देंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, असली बात तो यह है कि विपक्ष की तरफ से सुझाव ही मिलते हैं और सवाल कम पूछे जाते हैं। मैंने इस प्रश्न का जवाब 'नहीं, श्रीमान जी' में दिया है और मैं चाहती थी कि माननीय सदस्य की तरफ से कोई दूसरा सप्लीमैंट्री प्रश्न मिल जाये ताकि मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दे सकूं। दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य मुझसे मेरा *** मांग रहे हैं और मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय सदस्य की काबिलियत सदन को बताना चाहती हूँ कि इनको अपने हल्के में यह नहीं पता कि वाटर सप्लाई कौन सा विभाग देखता है। माननीय सदस्य ने अपने तारांकित प्रश्न में पूछा है कि– क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि– .....। इस प्रकार से जिस हल्के के विधायक को यह नहीं पता कि हल्के में ड्रेनेज का काम कौन सा विभाग देखता है, तो सबसे पहले उसे ही विधान सभा की सदस्यता से *** देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस नाते से तो मुझे इस प्रश्न का जवाब ही नहीं देना चाहिए था लेकिन यह सवाल जन समस्यओं से संबंधित है और जनता ने हमें इन समस्याओं को सुलझाने का दायित्व दिया है, इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ललित नागर : (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके प्रश्न का जवाब दे रही हूं, इसलिए इनको जवाब सुनने का माद्दा भी रखना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : कविता जी, माननीय सदस्य ने आपसे जो प्रश्न पूछा है आप इधर–उधर की बातें करने की बजाय उसका उत्तर दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ललित नागर : (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप आदरणीय सी.एल.पी. लीडर से कहिये कि वे विधान सभा के अध्यक्ष का काम स्वयं करने की कोशिश न करें और किसी माननीय मंत्री को यह न बतायें कि उन्हें कैसे जवाब

देना है । अगर उन्हें इस तरह की कोई बात कहनी है तो वे आपसे कहें न कि

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

सीधे–सीधे किसी माननीय मंत्री को कहें । वे हर माननीय मंत्री जी को सीधे–सीधे आदेश देने की कोशिश करती हैं । उन्हें इस तरह के आदेश अपने विधायकों को देने की कोशिश करनी चाहिए जो उनके आदेशों को न सुनते हैं और न मानते हैं । अतः माननीय सदस्या आपकी चेयर की पॉवर की स्वयं एक्सरसाइज करने की कोशिश न करें क्योंकि इस तरह से सदन नहीं चलता है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि माननीय सदस्या सदन की कार्यवाही के विषय में अवश्य जानती होंगी लेकिन इनको इस अनुभव का लाभ उठाना चाहिए और हमें भी यह लाभ देना चाहिए ।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि तिगांव विधान सभा क्षेत्र की स्प्रिंग फील्ड कॉलोनी तथा इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी में से एक बरसाती पानी का नाला गुजरता है । इस नाले को डी.एल.एफ. नाले के नाम से जाना जाता है और यह नाला इन कॉलोनियों के बरसाती पानी की निकासी करता है । इस नाले का उदगम स्थल इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी के सामने डी.एल.एफ. औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1 में है । यह नाला ढ़लान के अनुसार पुराने शेरशाह सूरी मार्ग के साथ–साथ बूड़ियां नाले में गिरता है । इस नाले की चौड़ाई 3.6 फीट तथा गहराई 3.0 से 4.5 फीट की है । नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा जून, 2019 के दूसरे सप्ताह में इस बरसाती पानी के नाले/डी.एल.एफ. नाले से गाद निकालने का कार्य आरम्भ किया गया था । इस उद्देश्य के लिए अनुबन्ध एजेंसी द्वारा नाले के बहाव को रोकने के लिए एक अस्थाई बांध बनाया गया जिससे कि गाद निकालने का कार्य सही ढंग से किया जा सके । माननीय सदस्य ने हमसे यह प्रश्न तो पूछ लिया लेकिन उन्होंने इस नाले की प्रैजेंट सिचुएशन नहीं बताई । इन्होंने इस नाले की जिस हालत की बात की वह स्थिति 2 जून की है । मेरा कहना है कि माननीय सदस्य को उस नाले की प्रैजेंट सिचुएशन भी पता होनी चाहिए । आज के दिन उस नाले से गाद निकालने का कार्य पूरा हो चुका है और वहां से अस्थाई बांध भी हटा दिए गए हैं । अब वहां पर तेज बारिश में भी इन क्षेत्रों में बरसाती पानी इकट्ठा नहीं होता और बरसाती पानी की तुरंत निकासी हो जाती है । अतः वहां पर सरकार का किसी

नाले आदि के विषय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो अमरूत योजना के तहत हुए कार्यों के बारे में जानना चाहा था उसके विषय में मैं इनको बताना चाहूंगी कि अमरूत योजना के तहत होने वाले कामों में सबसे ज्यादा काम फरीदाबाद में हुए हैं । यहां पर लगभग 80 परसैंट काम अमरूत योजना के तहत हुए हैं । तिगांव विधान सभा क्षेत्र में अमरूत योजना के तहत 8.23 करोड़ रूपये के काम वाटर सप्लाई के, 2.22 करोड़ रूपये के काम सीवर के हुए हैं । इस तरह से इन दोनों प्रोजैक्ट्स में सरकार ने लगभग साढ़े दस करोड़ रूपये का एक्सपैंडीचर किया है । हम 'सबका साथ, सबका विकास' नारे को अपने काम में भी चरितार्थ करते हैं । इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि तिगांव विधान सभा क्षेत्र की कुल 33 सी.एम. अनाउंसमैंट्स तो अकेले मेरे विभाग की हैं और उनमें से 20 सी.एम. अनाउंसमैंट्स का काम कम्पलीट हो चुका है। अब तक 60 करोड़ रुपये सी.एम. अनांउसमैंट्स के माध्यम से खर्च किये जा चुके हैं। इसी तरह से development of Barkhal road from two lane to four lane smart road का पोर्शन भी स्मार्ट सिटी के तहत लिया गया है जिस पर 42 करोड़ रुपये ऐस्टिमेटिड कॉस्ट है। इनमें से 2 करोड़ रुपये का काम कम्पलीट हो चुका है और बाकी वर्क इन प्रोग्रैस है। इसी तरह से माननीय सदस्य के क्षेत्र में डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेनेज की बात करें तो वहां पर जितने भी नाले हैं उनमें से 3 नाले हमारे विभाग के अन्तर्गत आते हैं– इसमें नम्बर 1 पर ओपन नाला नजदीक प्लॉट नम्बर 132 टू बूढ़ियां नाला, जिसको डी.एल.एफ. नाला भी कहते हैं और इसकी लम्बाई 3.7 किलोमीटर है। इसी तरह से नाला नम्बर 2 है along byepass road sector 37; and along byepass road from sector 29 new pull to spinner village ward No. 22, 26 and 27, जिसकी लम्बाई 2 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त नाला नम्बर 3 है जो कि Sapna Market Chowk sector No. 37 ward No. 22, जिसकी लम्बाई 1.5 किलोमीटर है। इन तीनों नालों की कुल लम्बाई 7.2 किलोमीटर है और इन नालों की डिवलैपमेंट का वर्क्स यू.एल.बी. विभाग कर रहा है। विभाग डीसिल्टिंग और पानी निकालने का कार्य लगातार कर रहा है।

श्री ललित नागरः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीया मंत्री जी बता रही थी कि 2 जून को संबंधित नालों की सफाई करवायी है जबकि 2 जून को संबंधित एरिया में बारिश नहीं हुई बल्कि 28–29 जुलाई को हुई थी जिसके कारण संबंधित एरिया में

पानी भर गया। अगर विभाग द्वारा 2 जून को सफाई करवा दी थी तो जुलाई में वहां पर पानी कैसे भर गया ?

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा जवाब ध्यान से नहीं सुना क्योंकि मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि 2 जून को नाले की सफाई का काम शुरू हुआ था और उसके बाद कान्ट्रैक्टर ने बांध बनवाया था। संबंधित एरिया में बांध बनने के बाद जब बारिश हुई तो बरसात का पानी रूक गया।

श्री अध्यक्षः ललित जी, माननीया मंत्री जी ने प्वॉयंट वाईज जवाब दे दिया है। अब कोई बात पूछने की नहीं रह गयी है।

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा संबंधित एरिया के पार्कस में ओपन जिम खोले गये हैं और सी.सी.टी.वी. कैमराज भी लगवाये गये हैं। ऐसी कोई मार्केट नहीं है, जहां पर विभाग द्वारा सफाई न करवायी गयी हो।

श्री ललित नागरः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ललित जी, माननीया मंत्री जी ने एक–एक प्वायंट का जवाब दे दिया है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब गीता भुक्कल जी अपना सवाल पूछेंगी।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवासः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ललित नागर जी को इसके लिए माननीया मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहिए।

श्री ललित नागरः अध्यक्ष महोदय, अभी संबंधित काम पूरा नहीं हुआ इसलिए माननीया मंत्री जी का धन्यवाद कैसे कर सकता हूं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ललित जी, माननीया मंत्री जी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है।

श्री ललित नागरः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के एरियाज की सीवर लाइन में 6–6 इंच के पाइप डाले जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ललित जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीया मंत्री जी जवाब देने में सक्षम हैं।

श्री ललित नागरः अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा सीवर लाईन में 6–6 इंच के पाइप डाले जा रहे हैं परन्तु 6 इंच के पाइप में से मल–मूत्र का निकास नहीं हो सकता। विभागीय अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं इनसे भी इस बात की जानकारी ली जा सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, अगर 6 इंच की पाइपलाइन डाली गयी होगी तो उसकी जांच करवायी जाएगी। हमने 6 इंच की पाइपलाइन डालने की सैंक्शन

नहीं दी। वर्तमान में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से 6 इंच की पाइपलाइन फिजिबल भी नहीं हैं। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह ठीक नहीं है। अगर यह बात सही हुई तो उसकी जांच करवाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ललित जी, माननीया मंत्री जी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है।

श्री ललित नागरः अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ा–लिखा विधायक हूं और कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। मेरे हल्के के एरियाज में 6–6 इंच के पाइप सीवर लाइन में डाले गये हैं। वहां पर एक–एक गली में 100–100 घर हैं। मैं ये बाते ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। विभागीय अधिकारी भी यहां पर बैठे हैं उनसे भी इस बारे में जानकारी ली जा सकती है।

श्री अध्यक्षः ललित जी, माननीया मंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है और न ही ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

श्री ललित नागरः अध्यक्ष महोदय, मैं किसी आधार पर ही ये बातें कह रहा हूं।

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह ठीक है क्योंकि माननीया मंत्री जी को सीवर लाइन में 6 इंच के पाइप डालने की जानकारी नहीं है। माननीया मंत्री जी को अपने विभाग द्वारा किये गये कार्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

श्री ललित नागरः अध्यक्ष महोदय, मैं सही कह रहा हूं कि मेरे हल्के के एरियाज में सीवर लाइन में 6–6 इंच के पाइप डाले जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवाान)

श्री अध्यक्षः ललित जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री ललित नागरः अध्यक्ष महोदय, पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। ऑफिसर और नेता मिलकर पैसे खा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ललित जी, माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि सीवर लाइन में 6 इंच के पाइप नहीं डाले गये हैं।

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात को करैक्ट करना चाहूंगी कि जैसे–जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, उसमें मेन रोड्ज पर जितनी भी सीवर लाइन बिछायी जा रही हैं। इसके लिए जो वर्क्स अलॉट होते हैं, उसमें यह प्रावधान किया जाता है कि सीवर लाइन में पाइप का साइज क्या होगा और किस तरह का मैटीरियल यूज किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हमने हरियाणा प्रदेश में कहीं भी मेन सीवर

लाइन में 6 इंच की पाइप लाइन डालने के आदेश नहीं दिये हैं, केवल इंडीविजुअल हाउस की सीवर लाइन ही 6 इंच की है। मान लीजिए कि मेरा घर है और मुझे अपने घर को मेन सीवर लाइन से कनैक्ट करना है तो केवल वही पर 6 इंच का पाइप लाइन डाला गया है। इसके अलावा हमने कहीं पर भी 6 इंच की पाइप लाइन लगाने के आदेश नहीं दिये हैं और अभी जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेन सीवर लाइन के अंदर 6 इंच का पाइप डाला गया है तो मैं इन्हें कहना चाहूंगी कि अगर ये मुझे इसके बारे में जानकारी देंगे कि किस मेन सीवर लाइन में 6 इंच की पाइप लाइन डाली गयी है तो मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस यह कहती हूं कि हम उसकी जांच करवायेंगे और जिस भी अधिकारी/कर्मचारी या कांट्रेक्टर ने ऐसा किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य ललित नागर जी ने तो बता दिया है कि मेन सीवर लाइन में 6 इंच की पाइप डाली गयी है तो माननीय मंत्री जी को इसकी जांच करवानी चाहिए।

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य श्री ललित नागर जी ने इंडीविजुअल सीवर लाइन के बारे में नहीं बताया है कि कौन सी सीवर लाइन में 6 इंच की पाइप डाली गयी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि वे उसकी जांच करवायेंगे।

श्री ललित नागरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इससे ज्यादा क्या बता सकता हूं। (शोर एवं व्यवधान) मैंने भी ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ललित नागर जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जायें। गीता भुक्कल जी, आप अपना प्रश्न पूछें।

.....

To Start Dialysis Centre in General Hospital

***3094. Smt. Geeta Bhukkal**: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) the time by which the dialysis Centre in General Hospital, Jhajjar is likely to be started; and

(b) the time by which 50 beded hospital in village Matanhail is likely to be fully operational ?

Health Minister (Shri Anil Vij): Sir,

(a) The Dialysis Centre in General Hospital Jhajjar is likely to be started by the end of this month.

(b) The proposal of operationalisation of 50 bedded hospital in village Matanhail is under process.

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि मातनहेल मेरा खुद का गांव और तहसील हेडक्वार्टर है और अभी जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि झज्जर में नागरिक अस्पताल में डायलिसिस केन्द्र इस महीने के अंत में शुरू कर दिया जायेगा। मैं बताना चाहूंगी कि पिछले साल और उससे भी पिछले साल माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि झज्जर के नागरिक अस्पताल में डायलिसिस केन्द्र शुरू कर दिया जायेगा। उसके बाद हम उस हॉस्पिटल को विजिट करने गये थे और उस हॉस्पिटल की थर्ड फ्लोर को भी पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था। पिछले सत्र में मुझे केवल यह आश्वासन दिया गया था कि उस अस्पताल में डायलिसिस केन्द्र शुरू कर दिया जायेगा, चूंकि जब मेरा यह प्रश्न दोबारा से इस सत्र में लिस्टेड हुआ तो विभाग ने कल ही कुछ मशीनें उस हॉस्पिटल में भिजवाई हैं। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री जी शीघ्रातिशीघ्र उस डायलिसिस केन्द्र को शुरू करवा देंगे ताकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर झज्जर है, वहां के लोगों को डायलिसिस की सुविधा जल्द से जल्द मिल सके। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी ने पिछली बार जब डायलिसिस केन्द्र शुरू करने का आश्वासन दिया था तो उस समय केवल बहादुरगढ़ में ही डायलिसिस केन्द्र शुरू हो पाया था और झज्जर में शुरू नहीं हो पाया था। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि झज्जर में जो 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है, उसकी जो पुरानी बिल्डिंग थी, वह पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। उस समय उस बिल्डिंग में कुछ सर्विसेज चल रही थीं, लेकिन आज की स्थिति यह है कि वह बिल्डिंग पूरी तरह से गिर चुकी है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि उसकी भी जांच करवाई जाये और यह भी विचार किया जाए कि इस बिल्डिंग का क्या किया जाये। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मातनहेल गांव में 50 बेड

हॉस्पिटल बनाने का प्रोसेस अभी चल रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जो मातनहेल गांव है, वह एक तहसील हेडक्वार्टर भी है। सी.एल.पी. प्लांट जोकि बिजली का कारखाना है वह खानपुर गांव में स्थित है और इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए सारा का सारा पैसा सी.एल.पी. प्लांट के द्वारा ही दिया गया था। इस हॉस्पिटल को बनाने की प्रक्रिया हमारी सरकार के कार्यकाल में ही शुरू की गई थी। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को पूरा बनवाने का काम किया, लेकिन इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग कम्प्लीट होने के बाद भी हैल्थ डिपार्टमैंट ने पी.डब्ल्यू.डी. से उसको टेक–ओवर नहीं किया और लम्बे समय तक वह बिल्डिंग खाली पड़ी रही और पी. एच.सी. मातनहेल एक टूटी–फूटी बिल्डिंग में चलती रही। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगी कि उसकी बिल्डिंग बनने के बाद खाली क्यों पड़ी रही? मैं लगातार डेढ़ साल से इस मामले को विधान सभा की पैटीशन कमेटी में उठाती रही हूं। वहां पर जो भी मशीनें हैं, चाहे एक्स–रे की मशीन हो, चाहे अल्ट्रासाउण्ड की मशीन हो या दूसरी मशीनें हों, वे सारी की सारी सी.एल.पी. प्लांट के द्वारा कारपोरेट रिस्पोंसिबिलिटी के तहत वहां पर भेजी गई हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि एक तहसील लेवल हेडक्वार्टर पर जो 50 बैड हॉस्पिटल है, उसको बने हुये बहुत ज्यादा समय हो गया है और वह आज तक क्रियाशील नहीं है। वहां पर केवल एक डॉक्टर, चार नर्सें और दो ए.एन.एम्ज. हैं और इसके अलावा वहां पर कोई भी फोर्थ क्लास कर्मचारी नहीं है। वहां पर बड़ी–बड़ी घास उग गई है, जिसके कारण उस हॉस्पिटल का गेट भी खुल नहीं सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि तकरीबन 4 से 5 साल बीत चुके हैं और लगभग 2 साल से ज्यादा उसकी बिल्डिंग को बने हुये हो गये हैं तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह एक स्पेसिफिक टाइम बता दें कि कब तक उस 50 बैड हॉस्पिटल को शुरू कर दिया जायेगा ?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, जहां तक झज्जर में डायलिसिस केन्द्र शुरू करने की बात है तो मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि थोड़े ही समय बाद वहां पर डायलिसिस केन्द्र चालू कर दिया जायेगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के सभी 22 के 22 जिलों में डायलिसिस केन्द्र शुरू करने जा रही है। 14 जिलों में डायलिसिस केन्द्रों में डायलिसिस मशीनें लग चुकी हैं और 15वें जिले में अभी लगनी बाकी है। हमारी

सरकार 22 के 22 जिलों में डायलिसिस केन्द्रों में डायलिसिस मशीनें लगाना चाहती है। इन सैंटरों में 830592 डायलिसिस मरीजों का सस्ती दरों पर इलाज किया गया है और 60 हजार ऐसे डायलिसिस मरीज थे, जिनका सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया है। इनमें B.P.L., Urban Slum Patients, Patients receiving handicapped allowance, poor patients who do not belong to any free category, poor patients belonging to S.C. category, patients belonging to economically weaker sections of Haryana and unattended victims of road-side accidents, भी शामिल हैं जिनका उस वक्त कोई वली–वारिस नहीं होता है। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमैंट इम्पलॉईज पेंशनर्ज एंड डिपैंडेंट्स का भी सरकार फ्री में इलाज करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि सरकार ने फ्री में बहुत बड़ी संख्या में इलाज किया है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार हरियाणा प्रदेश के 22 के 22 जिलों में डायलिसिस सैंटर खोलना चाहती है। हम इस बात को भी मानते हैं कि कहीं–कहीं पर थोड़ी बहुत देर भी हो जाती है। आदरणीय बहन जी ने झज्जर जिले में डायलिसिस सैंटर के बारे में जिक्र किया है तो हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पर डायलसिस सैंटर जल्दी से जल्दी चालू करवा दिया जाये। जहां तक मातनहेल की बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी मातनहेल में 50 बेडिड अस्पताल बना हुआ है। माननीय सदस्या की यह बात ठीक है कि इस अस्पताल को झज्जर पॉवर लिमिटेड ने बनाकर दिया था लेकिन हमारी सरकार ने इसकी जमीन का पोजैशन पास किया है। हमने इस अस्पताल में स्टाफ बढ़ाने के लिए और इक्विपमैंट्स की अप्रूवल के लिए एफ.डी. डिपार्टमैंट को लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमें जैसे ही स्टाफ बढ़ाने के लिए और इक्विपमैंट्स की अप्रूवल मिल जायेगी हम तुरन्त ही 50 बैडिड अस्पताल को चालू करवा देंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। (विघ्न)

Education Minister (Shri Ram Bilas Sharma): Speaker Sir, this is the first time when Hon'ble Sister Smt. Geeta Bhukkal thanked the Government. This Government is a performing Government. अध्यक्ष

महोदय, मैं बहन गीता भुक्कल जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस महीने के अंत तक मातनहेल का डायलिसिस सैंटर चालू करवा दिया जायेगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक और रिक्वैस्ट करना चाहूंगी कि झज्जर जिले में 100 बैड का अस्पताल कब तक शुरू हो जायेगा जबकि पुराने अस्पताल की बिल्डिंग डेमोलिश हालात में पड़ी हुई हैं तथा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए काफी लम्बा समय भी बीत चुका है। मैं इसके बारे में यह भी बताना चाहूंगी कि वहां की जमीन काफी किफायती है और यह जमीन हैल्थ डिपार्टमैंट के अंडर आती है और स्वास्थ्य विभाग ने झज्जर जिले में 100 बैडिड अस्पताल बनाने के लिए जो प्रपोजल सरकार को भेजा हुआ है तो मैं पूछना चाहती हूं कि यह अस्पताल कब तक बनकर तैयार हो जायेगा?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की योजना है कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज बनाया जाये। जैसा कि माननीय सदस्या जी कह रही है कि जहां–जहां पर अन्यूज्ड और खाली बिल्डिंग्ज पड़ी हुई हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसी बिल्डिंग्ज को यूटिलाईज करेगी। (विघ्न) हमने 6 नर्सिंग कॉलेजिज बनाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को कांट्रेक्ट दे रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार 22 के 22 जिलों में नर्सिंग कॉलेजिज और डायलिसिस सैंटर बनाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह भी मानना है कि सरकारी अस्पतालों को नर्सिंग कॉलेजिज के साथ अटैच किया जाये ताकि नर्सों को अच्छे तरीके की ट्रेनिंग मिल सकें। हमारे हरियाणा प्रदेश में जो प्राईवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वे नर्सिंग का कोर्स करवाते हैं लेकिन उनके पास अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसके कारण वहां पर अच्छी नर्सिंग भी तैयार नहीं हो पाती हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्या ने प्रश्न किया था कि हरियाणा प्रदेश के जिलों में जहां–जहां पर कंडम बिल्डिंग्ज़ पड़ी हुई हैं उनमें नर्सिंग कॉलेज चलाये जायें तो इनके परिपेक्ष्य में मैं यह कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम मैं खुद जाकर इन कंडम बिल्डिंग्ज़ को एग्जामिन करवाऊंगा। मुझे लगेगा कि यहां पर नर्सिंग कॉलेज चलाने का स्कोप है तो फिर इन बिल्डिंग्ज़ में नर्सिंग कॉलेज बनाने में हमें कोई परहेज नहीं होगा।

श्री विक्रम सिंह ठेकेदार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने मेरे जिले में नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए टैंडर जारी कर दिया है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि 5 साल से सरकार ने योजनाएं बनाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण चौधरी जी, कृप्या करके बैठ जाईये। (विघ्न)

11:00 बजे

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम आदरणीय बहन जी को यह बताना चाहता हूं कि नीति आयोग ने हरियाणा सरकार को सारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने में प्रथम स्थान पर माना है। इसके लिए हमारी सरकार को 6.55 परसैंट अंक दिये हैं। हमने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार किया है। हरियाणा प्रदेश की शिशु मृत्यु दर में सुधार आया है जब हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई थी उस समय शिशु मृत्यु दर 41 परसैंट थी जो कि अब 30 परसैंट है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। जब हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई थी उस समय मातृ मृत्यु दर 127 परसैंट थी जो कि अब वह घटकर 101 परसैंट रह गई है। इसी प्रकार से हमारी ओ.पी.डी. और आई.पी.डी. भी इनक्रीज हुई है। हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान ओ.पी.डी. और आई.पी.डी. में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जो कि इस बात का संकेत है कि सरकारी अस्पतालों में लोगों का विश्वास बढ़ा है। जहां तक मेडीकल कालेजिज की बात है हमने चार मेडीकल कालेजिज को बनाने का कांट्रैक्ट दे दिया है। इनको बनाने के लिए हमने वर्क अलॉट कर दिया है। (विघ्न) स्पीकर सर, आंकड़े बोलते हैं। किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता। इनको तो सभी तरफ अपनी बर्बादी ही बर्बादी नज़र आती है।

.....

Repair of Roads

***3097. Shri Anoop Dhanak :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the damaged road in village Daulatpur on Barwala road and road

from Village Agroha to village Siwani Bolan; if so, the time by which the abovesaid roads are likely to be repaired?

(b) whether it is a fact that water stagnate on the road between bus stand and railway fatak in Uklana; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to uplift the level of the road togetherwith the time by which the said work is likely to be completed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : (क) हाँ, श्रीमान् जी। जबकि बरवाला सड़क पर गांव दौलतपुर में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का काम फरवरी, 2020 तक पूरा होने की संभावना है, गांव अग्रोहा से गांव सिवानी बोलन तक सड़क अच्छी स्थिति में है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

श्री अनूप धानक : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर जी को यह बताना चाहूंगा कि जो सड़क कुलैरी से सिवानी बोलान तक है वह सड़क अभी नई बनी थी। इस सड़क में घटिया सामग्री लगी होने के कारण यह बहुत जल्दी ही टूट गई है। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिकवैस्ट है कि इस मामले की इंक्वॉयरी करवाकर दोषियों को सजा दी जाये और इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाया जाये।

श्री नरबीर सिंह : स्पीकर सर, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि मैं 2–3 दिन में ही इस मामले की इंक्वॉयरी करवा लूंगा, जो भी व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे उनको सजा दिलवायेंगे और इस सड़क का पुनर्निर्माण जल्दी से जल्दी करवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Place Ceiling on Purchase of Crops

***3102. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Food Minister be pleased to State-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to place ceiling on purchase of wheat, sugarcane, mustard and bajra crops; and

(b) If so, the details thereof?

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्ण देव कम्बोज): श्रीमान जी।

(क) नही, श्रीमान जी

(ख) इसलिए यह भाग लागू नही।

अतारंकित प्रश्न एवं उत्तर

The Number of Pensioners in State

801. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Social Justice and Empowerment be pleased to state-

(a) the district wise number of pensioners in respect of old age /handicapped/widow/eunuchs pensions registered in the State from March 2005 to October 2014; and

(b) the district wise number of pensioners in respect of the old age /handicapped/widow/eunuchs pensions registered in the State from November, 2014 till to date?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) :

(क) मार्च, 2005 से अक्तूबर, 2014 तक राज्य में वृद्धावस्था/दिव्यांग/विधवा/किन्नर की पंजीकृत पैंशनों से संबधित पैंशनधारकों की जिला वार संख्या अनुलग्नक ''ए'' पर संलग्न है।

(ख) नवम्बर, 2014 से अब तक राज्य में वृद्धावस्था/दिव्यांग/विधवा/किन्नर की पंजीकृत पैंशनों से संबधित पैंशनधारकों की जिला वार संख्या अनुलग्नक ''ए'' पर संलग्न है।

अनुलग्नक ''ए''

राज्य में जिलावार पैशनरों की संख्या

क0 स0	जिला का नाम	मार्च 2005 से अक्तूबर 2014 तक पंजीकृत वृद्ध / विकलांग / विधवा/महिला/किन्नरों पेंशनरों की जिलेवार संख्या	नवंबर, 2014 से अब तक राज्य में पंजीकृत वृद्ध/विकलांग/ विधवा /महिला/ किन्नरों पेंशनरों की जिलेवार संख्या
1	अम्बाला	23637	41045
2	भिवानी	61583	33577
3	चरखीदादरी	---	57119

4	फरीदाबाद	22298	54429
5	फतेहाबाद	31328	12758
6	गुरूग्राम	24438	23098
7	हिसार	51258	33560
8	झज्जर	57816	39665
9	जीन्द	37351	57357
10	कैथल	50187	5980
11	करनाल	34438	24309
12	कुरुक्षेत्र	66955	39248
13	मेवात	46337	32490
14	नारनौल	17463	35143
15	पलवल	52801	47974
16	पंचकुला	28638	14346
17	पानीपत	61604	38963
18	रेवाड़ी	34142	19883
19	रोहतक	62602	44507
20	सिरसा	63499	41853
21	सोनीपत	81077	63589
22	यमुनानगर	31947	20771
	कुल	**941399**	**781664**

नोटः– जिला समाज कल्याण अधिकारी, चरखीदादरी का कार्यालय चरखीदादरी में दिनांक 26.04.2018 से संचालित किया गया है।

Working of Water Supply and Sewerage System

809. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state-

(a) whether it is a fact that drinking water supply is not proper in Gohana town; and

(b) whether it is also a fact that the sewerage system is not working properly in new colonies of Gohana Town; and

(c) the details of machines available in Gohana town for cleaning of sewerage line?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी

(ख) नहीं, श्रीमान् जी

(ग) गोहाना शहर में सीवर लाईन की सफाई के लिए 1 न0 जेटिंग मशीन तथा 2 न0 बाल्टी आधारित सीवर सफाई मशीनें उपलब्ध हैं ।

Number of Overloading Vehicle Challans

802. Shri Karan Singh Dalal : Will the Transport Minister be pleased to state-

(a) the district wise and regional transport authority wise number of vehicle challans for the offence of overloading in the State during the year 2014-15 to 2018-19; and

(b) the district wise and regional transport authority wise details of total amount of compounding fee for overloading regarding the challan in 'a' above during the year 2014-15 to 2018-19 ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : महोदय, विवरण (अनुलग्नक ए) सदन की पटल पर रखा जाता है।

DISTRICT/REGIONAL TRANSPORT AUTHORITY-WISE TOTAL NUMBER OF CHALLANS FOR THE OFFENCE OF OVERLOADING AND COMPOUNDING FEES COLLECTED DURING THE YEAR 2014-2015 TO 2018-2019

Sr. No.	District/ Regional Transport Authority	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		TOTAL	
		Challan	Compounding fees	Challan	Compounding fees	Challan	Compounding fees	Challan	Compounding fees	Challan	Compounding fees	Challan	Compounding fees
1	Ambala	802	13,920,200.00	1,053	16,817,400.00	1,155	22,527,400.00	1,255	26,651,660.00	875	31,013,870.00	**5,140**	**110,930,530.00**
2	Bhiwani	1,110	30,405,300.00	1,839	44,619,300.00	2,737	67,035,600.00	1,857	49,403,270.00	1,589	57,051,350.00	**9,132**	**248,514,820.00**
3	Charkhi Dadri	0	0	0	0.00	0	0.00	3,248	109,715,800.00	3,340	120,626,400.00	**6,588**	**230,342,200.00**
4	Faridabad	2,732	41,648,100.00	3,184	57,972,500.00	2,676	58,820,600.00	1,235	55,161,800.00	1,938	86,800,400.00	**11,765**	**300,403,400.00**
5	Fatehabad	722	11,343,500.00	741	13,541,800.00	1,051	17,732,300.00	230	6,592,570.00	377	11,262,800.00	**3,121**	**60,472,970.00**
6	Gurugram	3,687	49,341,710.00	3,322	66,252,545.00	4,700	78,609,950.00	1,294	33,667,500.00	2,477	8,452,600.00	**15,480**	**236,324,305.00**
7	Hissar	1,029	17,338,900.00	741	12,121,250.00	1,898	30,462,400.00	897	22,617,750.00	1,680	31,263,200.00	**6,245**	**113,803,500.00**
8	Jind	1,106	14,783,100.00	1,220	19,511,300.00	2,835	42,822,600.00	776	19,813,535.00	697	19,923,607.00	**6,634**	**116,854,142.00**
9	Jhajjar	1,300	22,435,300.00	2,173	43,551,800.00	2,808	54,869,545.00	1,016	32,438,445.00	1,276	47,432,700.00	**8,573**	**200,727,790.00**
10	Kaithal	1,060	12,625,000.00	1,387	18,234,500.00	1,910	30,555,800.00	877	22,752,280.00	1,050	31,017,080.00	**6,284**	**115,184,660.00**
11	Karnal	3,267	42,466,275.00	3,049	52,438,250.00	3,296	54,920,400.00	3,246	93,580,260.00	4,899	205,322,350.00	**17,757**	**448,727,535.00**
12	Kurukshetra	1,625	31,352,250.00	1,473	27,938,500.00	1,565	3,492,900.00	929	25,641,350.00	1,680	79,134,400.00	**7,272**	**167,559,400.00**
13	Nuh	2,217	49,217,250.00	2,302	45,031,075.00	3,698	67,019,010.00	579	28,515,800.00	719	26,725,400.00	**9,515**	**216,508,535.00**
14	Narnaul	1,688	35,697,525.00	1,824	42,716,800.00	2,248	39,960,150.00	2,206	64,153,780.00	1,716	69,905,580.00	**9,682**	**252,433,835.00**
15	Panchkula	603	7,393,900.00	585	7,367,800.00	688	10,374,360.00	49	1,035,500.00	158	6,276,500.00	**2,083**	**32,448,060.00**

16	Panipat	1,143	21,500,970.00	1,040	23,809,800.00	1,606	37,110,300.00	841	32,649,560.00	873	48,765,750.00	**5,503**	**163,836,380.00**
17	Palwal	1,547	24,883,600.00	1,502	27,975,500.00	2,328	35,494,300.00	2,537	29,613,100.00	1,877	48,853,900.00	**9,791**	**166,820,400.00**
18	Rohtak	1,576	27,568,250.00	2,242	39,148,800.00	2,637	56,225,550.00	1,304	44,446,975.00	1,799	76,149,090.00	**9,558**	**243,538,665.00**
19	Rewari	1,824	38,719,800.00	2,424	57,865,300.00	3,355	62,926,700.00	3,878	108,753,600.00	3,398	129,521,900.00	**14,879**	**397,787,300.00**
20	Sonepat	821	17,421,050.00	1,405	26,989,400.00	2,470	54,479,900.00	1,876	32,901,940.00	2,302	69,921,900.00	**8,874**	**201,714,190.00**
21	Sirsa	450	9,684,800.00	537	13,659,400.00	587	20,936,550.00	150	7,248,000.00	272	11,021,700.00	**1,996**	**62,550,450.00**
22	Y. Nagar	1,394	21,290,700.00	2,164	32,661,700.00	2,825	44,970,700.00	2,737	81,434,400.00	2,938	131,640,400.00	**12,058**	**311,997,900.00**
	TOTAL	**31,703**	**541,037,480.00**	**36,207**	**690,224,720.00**	**49,073**	**891,347,015.00**	**33,017**	**928,788,875.00**	**37,930**	**1,348,082,877.00**	**187,930**	**4,399,480,967.00**

Compensation to the Farmers under PMFBY

808. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state-

(a) the total amount of claims filed under PMFBY from Kharif 2017 season to Rabi, 2019 season togetherwith total number of claims settled, pending and rejected alongwith the reasons of rejection of such cases; and

(b) the year wise number of compulsory and voluntary insurance cases togetherwith the district wise amount realized from such cases in the State since the inception of PMFBY alongwith the district wise details of compensation given in above said period ?

कृषि एव किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी,

(क) खरीफ 2017 से खरीफ 2018 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थानीय आपदाओं के अधीन 89171 किसानों ने अपने दावे दायर किए। जिनमें से 58463 किसानों को दावो के निपटान हेतु 133.36 करोड़ रूपए की राशि वितरित की गई। बाकी के आवेदन स्थानीय श्रेणी में न आने के कारण अस्वीकृत कर दिए गए थे जिनके लिए वे अपना दावा (अर्थात, जलभराव, भूस्खलन तथा ओलावृष्टि) कर रहे थे। रबी 2018–19 के लिए स्थानीय दावों का निपटान तथा विस्तृत आपदा दावे जो कि फसल कटाई प्रयोग होने के उपरान्त उपज में आई कमी के आधार पर संगणित किए हुए है जिनका निपटान उचित समय पर कर दिया जाएगा।

(ख) खरीफ 2016 से खरीफ 2018 के लिए जिन किसानों द्वारा मुआवजे सहित अनिवार्य तथा स्वैच्छिक आधार पर प्रीमियम का भुगतान किया है। उनकी सूची अनुबन्ध "क" पर रखी गई है।

अनुबन्ध "क"

खरीफ 2016 से खरीफ 2018 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधीन किसानों को दिया गया जिलावार अनिवार्य तथा स्वैच्छिक किसानों की संख्या तथा मुआवजा राशि।

कुल संख्या	जिला	खरीफ 2016			रबी 2016–17		
		अनिवार्य किसानों की संख्या	स्वैच्छिक किसानों की संख्या	मुआवजा राशि (लाख रूपए में)	अनिवार्य किसानों की संख्या	स्वैच्छिक किसानों की संख्या	मुआवजा राशि (लाख रूपए में)
1	सिरसा	72582	52	2083.68	40384	6	516.01
2	भिवानी	72081	29	2033.16	55834	105	690.08
3	फरीदाबाद	4303	4	137.75	4223	1	7.10
4	कुरूक्षेत्र	40318	12	482.79	29728	0	597.23

5	कैथल	46535	19	1389.61	38352	0	267.54
6	पंचकूला	6803	5	42.51	2783	82	37.96
7	रेवाड़ी	27231	44	366.46	38179	7	29.72
8	हिसार	69811	412	3432.14	61046	98	784.65
9	सोनीपत	43053	14	1705.66	30057	565	174.75
10	गुड़गांव	7034	7	407.80	8874	5	61.92
12	करनाल	54349	1	1572.12	41520	2	225.30
12	अम्बाला	26592	0	938.12	19853	24	95.97
13	जीन्द	47708	557	3329.81	40369	2	248.80
14	महेन्द्रगढ़	27767	12	119.84	40174	70	238.94
15	फतेहाबाद	54723	56	1012.92	46291	0	423.45
16	रोहतक	30209	112	1698.14	14829	13	351.28
17	झज्जर	23403	150	1085.14	19488	1	61.47
18	मेवात	9261	10	511.29	8456	16	62.66
19	पलवल	20147	329	414.75	17867	144	243.67
20	पानीपत	19164	18	359.24	15588	0	79.13
21	यमुनानगर	33779	99	300.11	22220	42	505.01
कुल		**736853**	**1942**	**23423.04**	**596115**	**1183**	**5702.64**

अनुबन्ध "क"

कुल संख्या	जिला	खरीफ 2017			रबी 2017–18			खरीफ 2018		
		अनिवार्य किसानों की संख्या	स्वैच्छिक किसानों की संख्या	मुआवजा राशि (लाख रूपए में)	अनिवार्य किसानों की संख्या	स्वैच्छिक किसानों की संख्या	मुआवजा राशि (लाख रूपए में)	अनिवार्य किसानों की संख्या	स्वैच्छिक किसानों की संख्या	मुआवजा राशि (लाख रूपए में)
1	सिरसा	69200	39	33909.06	88678	46	1572.46	79389	245	14829.83
2	भिवानी	49784	23	11495.84	59758	411	1373.49	43865	1431	13490.53
3	फरीदाबाद	4157	11	34.83	4253	8	4.93	4242	59	21.67
4	कुरूक्षेत्र	30996	9	734.47	27043	7	799.14	31634	156	3980.65
5	कैथल	47356	197	606.98	48685	14	1073.33	47747	125	3090.10
6	पंचकूला	5503	5	24.67	5071	92	50.76	4507	27	148.97
7	रेवाड़ी	28141	4	828.25	37266	6	32.42	38750	145	3004.73
8	हिसार	72720	172	12059.53	82694	112	564.92	84386	261	10473.53
9	सोनीपत	33522	66	1688.47	37795	17	106.03	38862	449	2749.86
10	गुड़गांव	8087	14	260.45	11260	15	50.16	9902	196	252.96
12	करनाल	43008	26	577.24	38533	212	1541.32	37063	84	1865.06
12	अम्बाला	24283	10	527.34	22050	7	254.70	23068	33	3297.89
13	जीन्द	45719	227	4071.18	49166	28	133.32	58370	956	5988.54
14	महेन्द्रगढ़	31554	64	1531.99	38124	87	487.22	37753	271	727.88
15	फतेहाबाद	47076	71	8644.35	47059	14	30.66	57555	423	5220.10
16	रोहतक	17219	12	483.35	24371	18	155.63	23248	245	738.24
17	झज्जर	19132	17	898.67	16886	154	232.62	20388	245	863.61
18	मेवात	6375	8	202.50	8462	13	26.87	6267	95	258.65
19	पलवल	16701	19	981.55	16998	4	8.53	17854	417	771.96
20	पानीपत	15639	6	38.72	15676	9	7.00	18812	155	535.89

21	यमुनानगर	24337	53	105.39	16864	11	25.35	17676	64	805.76
22	चरखीदादरी	-	-	-	-	-	-	15243	290	2831.69
कुल		**640509**	**1053**	**79704.83**	**696692**	**1285**	**8530.86**	**716581**	**6372**	**75948.1**

Total Amount Collected by Stamp Duty

803. Shri Karan Singh Dalal: Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state-

(a) the year wise details of total amount of stamp duty levied on registration of conveyance of properties in the State from the year 2014-15 to 2018-19 ; and

(b) year wise details of total value of properties of which conveyance deeds were executed on which stamp duty in 'a' above was collected from the year 2014-15 to 2018-19?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान् जी।

(क) स्टाम्प शुल्क की कुल राशि का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है–

वर्ष	स्टाम्प शुल्क की कुल राशि का वर्षवार ब्यौरा (रूपये करोड़ में)
2014–15	2287
2015–16	2670
2016–17	2648
2017–18	3292
2018–19	4254

(ख) स्टाम्प शुल्क एकत्रित हुआ की कुल कीमत का वर्ष–वार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	स्टाम्प शुल्क एकत्रित हुआ की कुल कीमत का वर्ष–वार ब्यौरा (रूपये करोड़ में)
2014–15	39130
2015–16	45681
2016–17	46621
2017–18	78832
2018–19	77060

To Construct New Water Tank

813. Shri Ved Narang : Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new water tank in village Bandaheri in Hansi Assembly Constituency, if so, the details thereof together with the time by which it is likely to be constructed ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल) : हां, श्री मान जी,एक अनुमान जिसकी लागत 250.00 लाख रूपये है, हांसी विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव बनदाहेड़ी (बांड़ाहेड़ी) में स्वतंत्र जलघर बनाने हेतु अनुमोदित हो चुका है तथा धनराशि भी उपलब्ध करवा दी गई है। यह कार्य हाल ही में आबंटित किया गया है और इस कार्य के पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.08.2020 है।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———————

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर निम्नलिखित कागज पत्र रखता हूँ :–

बिजली अधिनियम 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या 43/2019/एच.ई.आर.सी., दिनांकित 29 अप्रैल, 2019।

बिजली अधिनियम 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./44/2019, दिनांकित 29 अप्रैल, 2019।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, राज्य वित्त पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

———

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैंने आपकी सेवा में एक कालिंग अटैंशन मोशन "regarding reduction of market fee on cotton by Rajasthan Government the business of cotton ginning factories in Haryana under threat" दिया है मुझे उसका फेट बताया जाये। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अंदर कपास की मार्किट फीस 80 पैसे प्रति क्विंटल कर दी गई है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश में भी कॉटन पर मार्किट फीस को कम किया जाये। स्पीकर सर, मैंने दूसरा कालिंग अटैंशन मोशन आपको राज्य में युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के विषय पर दिया है। घरेलू बचत का जी.डी.पी. में पहले सहयोग 37 परसैंट होता था जोकि अब घटकर 30 परसैंट रह गया है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी बात है कि आज देश में मंदी बहुत ज्यादा हावी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार कहीं आर्टिकल 370 में तथा कहीं तीन तलाक बिल पास करवाने में उलझी हुई है। असली मुद्दा देश में बेरोजगारी का है। आज देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज नौजवान बेरोजगार बैठे हुये हैं। इसी प्रकार से आज आप शहरों में जा कर देखिये बाजार सूने पड़े हुये हैं तथा घरेलू बचत घट रही है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आज देश और प्रदेश की हालत भारतीय जनता पार्टी के राज में बिगड़ती जा रही है। लोगों का ध्यान सरकार की विफलताओं से हटाने के लिए हर सोमवार को सरकार कोई न कोई अलग काम करती रहती है। सरकार का असली काम बेरोजगारी को रोकना है तथा घरेलू बचत जो आज लगातार घट रही है इस पर भी सरकार को जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में कपास की खरीद पर लगने वाली मार्केट फीस 80 पैसे प्रति क्विंटल लगती है जबकि हरियाणा में यह मार्केट फीस 2.80 रुपये प्रति क्विंटल लगती है। इससे यह नुकसान होगा कि हमारी सारी कपास हरियाणा की मंडियों में न आ कर राजस्थान की मंडियों में चली जायेगी। इस बारे में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था उसका भी फेट बताया जाये। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जब मुख्यमंत्री जी जवाब दें तो इस बात का भी जवाब दिया जाये।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आपका कपास की मार्केट फीस से संबंधित जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था वह मैंने सरकार के पास कमेंट्स के लिए भेज दिया है।

इसके अलावा आपका जो दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी से सबंधित है वह मुझे आज प्रातः ही 10.40 पर मिला है इसलिए उसको डिसलाऊ कर दिया है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों की जमीनों के मुआवजे को लेकर किसानों द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें ढाणी फौगाट गांव के एक किसान रामअवतार की मौत भी हो गई है, उसके बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपको दिया था लेकिन आपने उसको रिजैक्ट कर दिया। उसमें आपने लिखा है कि the matter lacks urgency because it is not recent occurrence. जिस समय मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपको दिया था उस समय उस किसान का दाहसंस्कार बाकी था और आप कह रहे हैं कि दा मैटर लैक्स अर्जेन्सी तो इससे ज्यादा क्या अर्जेन्सी हो सकती है कि एक किसान का परिवार बर्बाद हो गया है। उस किसान के पास दो एकड़ जमीन थी और दो की दो एकड़ जमीन ग्रीन कोरीडोर जो कि नैशनल हाईवे नं. 152–डी है, उसमें आ गई है। वहां पर किसान जमीनों के मुआवजे बढ़वाने के लिए धरने पर बैठे हुये हैं और उसी दौरान उस किसान की मौत हो गई जिससे उसका परिवार उजड़ गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने इससे संबंधित जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था उसमें ऐसी कौन सी कमी रह गई कि इसमें अर्जेन्सी नहीं थी या इसमें कोई रिसैंट अकरेंस नहीं था।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, इस बारे में मुख्यमंत्री जी जवाब दे देंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आपको कैसे पता चला कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में जवाब देंगे?

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, मेरी इस बारे में मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और आज ही मुख्यमंत्री जी इस बारे में जवाब देंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैंने और डॉक्टर कादियान ने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। वहां पर एक किसान की मौत हो गई है और आप कह रहे हैं कि इसमें कोई अर्जेन्सी नहीं है तो फिर कहने को क्या रह गया है? हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। आज हमारा किसान मर रहा है और उसके लिए हम चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि हम उनकी जमीनों का मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप लोगों ने जो भी मुद्दे उठाये हैं मुख्यमंत्री जी उन सभी का जवाब देंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हम जितने भी मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते हैं आप उन सभी को रिजैक्ट करके भेज देते हैं। हम किसी मुद्दे को ऐसे ही नहीं उठाते, हम नियमानुसार ही मुद्दे उठाते हैं। यह तो किसान का मामला है। उस बेचारे ने अपना मुआवजा बढ़वाने के लिए अपनी जान दे दी है। वह इलाका भी एन.सी.आर. में आता है। हमारी सरकार के दौरान भिवानी तथा महेन्द्रगढ़ को एन.सी.आर. में शामिल किया गया था।

श्री अध्यक्षः किरण जी, इस बारे में मुख्यमंत्री जी आज जवाब देंगे।

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, नैशनल हाईवे नं. 152–डी में करनाल जिले के 9 गांवों की जमीन एक्वायर की गई है। किसान अपनी जमीनों का मुआवजा बढ़वाने के लिए करनाल जिले के गंगटेहड़ी पोपड़ा गांव में पिछले 28 दिनों से धरने पर बैठे हुये हैं। इसी प्रकार से इनऐडिक्वेट और अनइक्वल लैंड कम्पनसेशन जो सोनीपत के बाई पास के लिए जाहरी गांव में दिया गया है जो कि गन्नौर विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरता है। वहां पर भी किसान मुआवजा बढ़वाने के लिए धरने पर बैठे हुये हैं। मैंने दोनों के बारे में आपको कालिंग अटैंशन मोशन दिया था । आपने कल कहा था कि इस बारे में गवर्नमैंट ब्यान देगी या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में कोई रिप्लाई देंगे । आपसे मेरा यह निवेदन है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि सरकार इस बारे में अपना कथन या जो भी प्रस्ताव है उसको सदन में अवश्य प्रस्तुत करे। आज किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन आज तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने तक नहीं गया है । इतने संवेदनशील विषयों के प्रति सरकार जो इतनी उदासीनता दिखा रही है मैं समझता हूं कि यह सरकार का ठीक एटीट्यूड नहीं है। सरकार को वहां जाकर उन किसानों से बात करनी चाहिए क्योंकि वे किसान अपना काम छोड़कर धरने पर बैठे हुए हैं । आपसे मेरा यही निवेदन था । स्पीकर सर, वैसे आपको मेरे इस कालिंग अटैंशन को अलाऊ करना चाहिए था ।

.....

सदस्यों द्वारा विभिन्न मांगों को उठाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदस्यगण अपने हल्कों संबंधित मागों पर बोल सकते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर सदन का ध्यान पटल पर दिलवाना चाहती हूं । वर्ष 2016 में दो हजार एस.पी.ओज.

भर्ती किए गए थे । उन्होंने मुझे बताया था और मैं इस बारे में वित्त मंत्री जी से कहना चाहती थी लेकिन अब वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने इन एस.पी.ओज. को कहा था कि आप एक बार वर्दी पहन लो बाद में हम तुम्हें पक्का कर देंगे, लेकिन वर्ष 2016 से लेकर आज वर्ष 2019 हो गया है तीन साल का समय बीत जाने के बाद भी वे दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन उनको अभी तक पक्का नहीं किया गया है । जबकि वह आठ महीने की ट्रैनिंग भी पूरी कर चुके हैं । ये लगभग दो हजार लोग हैं इनमें कुछ एक्स–सर्विसमैन भी शामिल हैं । इस तरह से ये लगभग दस हजार लोग हैं । मंत्री जी अब सदन में नहीं बैठे हैं इसलिए मैं शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस की ओर थोड़ा ध्यान दें क्योंकि आपने ही मुझे कहा था कि आप इस बात को सदन में उठाएं तो अब मैं इस बात को उठा रही हूं कि जो ये इतने लोग इतने सालों से दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा है ।

.....

हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य संसदीय सचिव व हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, इस समय आदरणीय राम पाल माजरा, पूर्व सी.पी.एस. और पूर्व विधायक, डॉ. सीता राम सदन की अति विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित हैं । यह सदन उनका अभिनन्दन करता है ।

.....

सदस्यों द्वारा विभिन्न मांगों को उठाना (पुनरारम्भ)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार इन लोगों को पक्का करे, जैसा कि मंत्री जी का वायदा भी था । जो वायदे किए जाते हैं अगर वे आराम से पूरे हो जाएं तो उसका फायदा होता है । इस तरह से दर–दर की ठोकरें खिला–खिलाकर कोई वायदा पूरा किया तो क्या किया ? ये लगभग 10 हजार लोग हैं जिनमें दो हजार एस.पी.ओज. हैं जिनका मासिक वेतन 18000 रुपये निर्धारित किया गया था और उनको उस समय कहा गया था कि आप एक बार वर्दी पहन लो, पक्का तो हम अपने आप कर देंगे । अब वे वर्दी में हैं इसलिए वे अब बोल भी नहीं सकते । इसकी तरह से बेचारे ये पुलिस वाले भी नहीं बोल सकते कि हमें भी पंजाब के समान वेतन दिया जाए । उनको भी सरकार ने मना

कर दिया है । कम से कम ये जो 10 हजार कर्मचारी हैं जिनके मामले को मैं अच्छी तरह से आपकी संज्ञान में लेकर आई हूं । कृपा करके इन सभी लोगों को पक्का कीजिए और जो इनका हक है, वह इनको दिलवाइए ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, अभी बहन गीता भुक्कल जी ने मातनहेल में डायलिसिस का इलाज शुरू करवाने के ऐवज में स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद किया है । मैं बहन किरण चौधरी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह सरकार परफौर्म करने वाली सरकार है । आदरणीय सी.एल.पी लीडर ने जिन एस.पी.ओज. की बात की है उसके लिए मैंने इनको धक्के से उनके बारे में इस हाऊस में बुलवाया है । यह बात अलग है कि अब उनकी रुचि काम करवाने में कम है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी रुचि नहीं होती तो मैं यह बात उठाती ही नहीं । आप ये देखिए कि वर्ष 2016 से वह 10 हजार आदमी दर–दर की ठोकरें खाते धूम रहे हैं । उनको आज तक पक्का नहीं किया गया ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग कह कर पल्ला झाड़ लेते हैं लेकिन हम वो हैं जो करके दिखाते हैं । हमारी बीजेपी की सरकार ने धारा 370 को हटाने का वायदा किया था । कल से पूरी दुनिया में बवंडर मच रहा है, जलेबियां बंट रही हैं । अतः हम इतिहास भी बदलते हैं, हम विश्वास भी बदलते हैं, हम भूगोल भी बदलते हैं । कल हमारी सरकार ने डॉ. मुखर्जी की कुर्बानी को श्रृद्धांजलि दी है ।

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को विषय पर बात करनी चाहिए लेकिन यह तो इस हाउस में स्पीच देने लग गए हैं। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब तो विषय यही है कि बहन शकुंतला जी अपनी सीट पर विराजमान हो जायें। रखड़ी का त्यौहार आ रहा है मैं इनको 1100 रूपये दूंगा और रखड़ी बंधवाउंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी रखड़ी बंधवा भी रहे हैं या फिर यूं ही बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरी बहन किरण को ऐसा नहीं कहना चाहिए। सदन की जितनी भी हमारी बहनें हैं मैं सबको 1100–1100 रूपये दूंगा।(हंसी) अध्यक्ष महोदय, जैसाकि बहन किरण जी ने आज एस.पी.ओज. का मुद्दा उठाया ठीक इसी प्रकार कल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी खाना खाते समय यह मुद्दा मेरे सामने उठाया था। शुरूआत में एक सरकार ने हरियाणा

औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से पुलिस के सहयोग से इन नौजवानों की भर्ती की थी। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा। इसके बाद वह सरकार बदल जाती है और दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। इस सरकार ने ट्रेनिंग प्राप्त इन युवाओं को नौकरी से बाहर करने का काम किया। इसके बाद इन युवाओं ने नौकरी के लिए प्रदर्शन किए और कड़ाके की ठंड में अपने कपड़े फाड़कर नंगे बदन प्रदर्शन करके नौकरी की गुहार लगाई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन युवाओं को एस.पी.ओज के नाम से भर्ती करके नौकरी में रखने का काम किया। शुरू में इनको 15000 रूपये तनख्वाह दी जाती थी इसके बाद 18000 रूपये तनख्वाह दी जाने लगी और अब इनको 24000 रूपये तनख्वाह दी जा रही है। हमारी सरकार ने इनकी सेवाओ में साल दर साल बढ़ोतरी करने का काम किया है और नौकरी से नहीं हटाया है। ठीक इसी प्रकार हमने अपने नौजवान गैस्ट टीचर्ज को नौकरी से न हटाने के आश्वासन को भी पूरा करने का काम किया है। हमारी सरकार ने 40 हजार गैस्ट टीचर्ज तथा एक्सटैंशन लैक्चरर्ज को नौकरी से न हटाने का निर्णय लिया है। पहले इनको मात्र 16000 रूपये तनख्वाह के तौर पर मिलते थे जिसको बाद में 25000 रूपये करने का काम किया गया और पिछले सत्र में हमारी सरकार ने इनके लिए 57655 रूपये तनख्वाह देने का का काम करके अपना फर्ज निभाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, चार साल हो गए है लेकिन एस.पी.ओज. के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। सरकार को इनको रेगुलर कांस्टेबल के तौर पर भर्ती करना चाहिए। इतना लंबा समय हो गया है लेकिन इन एस.पी.ओज. के लिए कोई राहत देने वाला कदम नहीं उठाया गया है। सरकार ही बता दे इनकी लाईफ में कोई फर्क पड़ा है या नहीं? सरकार के मंत्री आरामदायक कमरों में आराम से बैठते हैं और यह लोग दर–दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, किरण जी को यह बात याद रखनी चाहिए कि इन लोगों को नौकरी से हटाने का काम इन्हीं की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): स्पीकर सर, जिस विषय पर मंत्री जी बात कर रहे हैं इस संबंध में सदन में बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के समय प्राइवेट सैक्टर की तरफ से यह डिमांड आई थी कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुरक्षा बल कंपनी तैयार की जाये जिसको हरियाणा की औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के

लिए तैनात किया जाये। यह भी प्रावधान किया गया था कि इस सुरक्षा बल कंपनी की तनख्वाहें प्राईवेट सैक्टर इंडस्ट्रीज वाले लोग देने का काम करेंगे और सरकार द्वारा इस सुरक्षा बल के जवानों को हथियार देने का काम किया जायेगा और यह जवान 8 घंटे के हिसाब से अपनी डयूटी देने का काम करेंगे। इसके बाद हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल की भर्ती की गई। स्पीकर सर, गुड़गांव में बढ़ते अपराध के हालात को देखते हुए यह भर्ती की गई थी। हमारी सरकार जाने के बाद जब वर्ष 2005 में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो इस सरकार ने इन युवाओं को नौकरी से हटाने का काम किया। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में रही लेकिन हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के इन जवानों की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई और वर्ष 2016 में इस सरकार ने हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के इन जवानों को एस.पी.ओज. के तौर पर नौकरी में रखने का फैसला लिया। स्पीकर सर, किरण जी ने आज यह सवाल उठाया कि सरकार द्वारा हरियाणा औद्योगिक बल के इन जवानों को आश्वासन दिया गया था कि इनको कांस्टेबल के रूप में भर्ती कर लिया जायेगा लेकिन आज तक इनको भर्ती नहीं किया गया हैं। मुझे किरण जी की तरफ से यह सवाल सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। स्पीकर सर, कांग्रेस की सरकार लगातार 10 वर्ष तक सत्ता में रही लेकिन इतने लंबे समय तक इनको इन युवाओं की कोई चिंता नहीं हुई कि इनको नौकरी में रखना चाहिए या नहीं? आज किरण जी की चिंता देखकर यह जरूर लगा कि कम से कम कांग्रेस पार्टी को अपनी गलती का अहसास तो हुआ है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने इन एस.पी.ओज. की तनख्वाह में बढ़ौत्तरी की है। लेकिन इनकी तनख्वाह बढ़ाकर भी इनको पद के मुताबिक कोई पद न देकर इनका अपमान किया जा रहा है। इन एस.पी.ओ. ने 9–10 महीने की बकायदा मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सैन्टर में पुलिस कांस्टेबल के रूप में ट्रेनिंग ली हुई है। इन बच्चों को मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सैन्टर से पास आउट किया गया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन पर कोई संज्ञान नहीं लिया क्योंकि यह भर्ती हमारी सरकार के समय हुई थी। इन बच्चों के साथ भेदभाव हुआ है और वही भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यों का त्यों कर रही है। अध्यक्ष महोदय, एस.पी.ओ. और पुलिस कांस्टेबल में बड़ा अंतर है। सरकार अगर सही मायने में यह कहती है कि हम किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करते हैं तो फिर इन बच्चों की जो संख्या 819 के करीब हैं इन सबको पुलिस के

कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2004 से जब से इन्होंने पुलिस की ट्रेनिंग ली हुई है तब से इनकी सेवाओं को नियमित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से उम्मीद करूँगा कि इस बात पर ध्यान देगी और न केवल इनको एस.पी.ओ. रखेगी बल्कि इनको कांस्टेबल का दर्जा देकर इन नौजवानों का हौंसला बढ़ाने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ एक और दूसरा इशू नारायणगढ़ के नबीपुर गांव का है। (विघ्न) श्री राम बिलास शर्मा जी सदन में यदि जीरो ओवर में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठ रहा हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस मुद्दे की तरफ ध्यान ही न दे।

श्री राम बिलास शर्मा : अभय जी, मैं आपकी हर बात को बड़ी गम्भीरता से लेता हूँ। स्पीकर साहब के रात्रि भोज के समय आपके द्वारा कही बात को मैंने नोट कर ली थी और सदन में भी कही थी।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री सदन में यह आश्वासन दें कि हम इन एस.पी.ओज. को पुलिस कांस्टेबल का दर्जा देने का काम करेंगे। जब मेरी रात्रि भोज वाली बात भी शर्मा जी ने स्वीकार कर ली तो यह बात भी जरूर स्वीकार कर लें।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 819 आई.आर.बी. की भर्ती थी और 2000 के करीब एच.आई.एस.एफ. की भर्ती थी दोनों को ही एस.पी.ओ. लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला को सही तथ्य सदन में देने चाहिए। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन एस.पी.ओज. को वर्ष 2016 के अंदर रेगुलर करने का वायदा किया गया था और बकायदा इन्होंने पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग भी ली हुई है। (विघ्न)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष महोदय, इनैलो तो इनकी भर्ती करके चली गई लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इनके लिए क्या काम किया है? यह भी बहन किरण चौधरी जी सदन में बता दें। (विघ्न) उन बच्चों का क्या कसूर था? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : बहन किरण जी, प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बहन किरण चौधरी जी और श्री कृष्ण कुमार बेदी जी दोनों ही अपनी–अपनी बातों में उलझे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, न तो 10 साल कांग्रेस पार्टी ने इनके बारे में कुछ किया था और न ही मौजूदा सरकार इनको पक्का करने का काम कर रही है। (शोर एवं व्यवधान) दोनों पार्टी के सदस्य इन एस.पी.ओज. के प्रति दिखावा कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि दिखावा तो पता नहीं कौन सी पार्टी के सदस्य कर रहे हैं लेकिन हमारी सरकार ने उनको रोजगार देने का काम किया है। यह काम हमने दिखावे के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी के साथ किया है। हमारी सरकार ने उन लोगों को विश्वास भी दे रखा है कि उनकी रोजी रोटी नहीं छीनेंगे और उनके साथ किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, जितना बेईमाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है उतना बेईमाना किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, यदि हमारी सरकार में बेईमाना होता तो हम 10 की 10 लोकसभा सीटें नहीं जीतते। बहन खटक को भी आगे विधान सभा के चुनाव में पता चल जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं नारायणगढ़ के नबीपुर गांव का जिक्र कर रहा था। नबीपुर गांव में पंचायत की 20 एकड़ जमीन है। उस जमीन पर रातो रात तारबंदी की गई और अवैध माइनिंग शुरू की गई है। यह मामला डी.सी. के संज्ञान में लाया गया था। पूरी गांव की पंचायत जब डी.सी. से मिली तो डी.सी. साहब ने अवैध माइनिंग के ऊपर रोक लगा दी थी। लेकिन अब दोबारा फिर से उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। गांव की पंचायत की तरफ से एक रिजौल्यूशन दिया गया और डी.सी./एस.पी. साहब से मांग की गई कि जब यह मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है तो अवैध माइनिंग पर रोक लगाई जाए। अध्यक्ष महोदय, यह अवैध माइनिंग कोई और नहीं करवा रहा है बल्कि गांव की पंचायत की तरफ से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि यहां के प्रतिनिधि जो अब लोकसभा के सदस्य बन गए हैं उनके आदमियों ने ही जमीन पर कब्जा कर रखा है और अवैध माइनिंग शुरू करवा रखी है। आज फिर पंचायत की तरफ से दोबारा

से लिखकर दिया हुआ है कि इस तुरंत प्रभाव से अवैध माइनिंग के कार्य को रोका जाए। यह शामलात की जमीन है और इसके हिस्सेदार बहुत सारे लोग हैं। कहीं से केवल अपने दो आदमियों से लिखवाकर सारी जमीन पर तारबंदी नहीं की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हाउस को आश्वस्त करें कि वे आज ही डी.सी. साहब को आदेश करेंगे ताकि जो अवैध माइनिंग हो रही है उस पर रोक लगे और प्रशासन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करे। अध्यक्ष महोदय, पंचायत के द्वारा दिया गया रिजौल्यूशन आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी को देता हूँ। (इस समय पंचायत की रिजौल्यूशन की कॉपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को दी गई।) अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से माननीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा हाउस को आश्वस्त करें कि इन एस.पी.ओज. को पुलिस कांस्टेबल का दर्जा देकर नियमित करेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (एस.सी.) : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की एक–दो समस्या यहां उठाऊं उससे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि हरियाणा सिविल डैंटल सर्जन एसोसिएशन ने एक ज्ञापन आपके नाम से दिया हुआ है। उस ज्ञापन में चेंज ऑफ नौमिनक्लेचर की रिक्वैस्ट है जिसमें डैंटल सर्जन को मैडिकल ऑफिसर, पे–स्केल, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट फॉर डिप्टी सिविल डेंटल सर्जन से डेंटल सर्जन का जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस एसोसिएशन की डिमाण्ड के संबंध में यह कहना चाहती हूँ कि जो मेवात में हमारे डॉक्टर्ज पोस्टिड हैं उनको सरकार द्वारा स्पेशल अलाउन्सिज दिए जाते हैं। इस एसोसिएशन की भी यही डिमाण्ड है कि जो डेंटल सर्जन मेवात में पोस्टिड होते हैं उनको भी स्पेशल अलाउन्सिज उसी हिसाब से मिलना चाहिए क्योंकि वे भी दूसरे डॉक्टर्ज की तरह उन्हीं वर्किंग कंडीशंज में काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने भी एक ज्ञापन जोकि कैशलैस मैडिकल फैसिलिटी प्रदान किए जाने बारे है, पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जगह दिया हुआ है और इस हिसाब से आपके पास भी आया होगा। यह ज्ञापन पहले भी आया था और हमने इसे विधान सभा के पटल पर रखने का काम भी किया था। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की कैशलेस मैडिकल सुविधा की मांग है जोकि वे बार–बार उठाते हैं, उस मांग को पूरा किया जाये। इसके अतिरिक्त उनकी पैंशन को भी संशोधित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि उम्र बढ़ने पर पैंशन बढ़ाने की बात सरकार

ने मानी है उसको इम्पलीमैंट करने का काम करना चाहिए तथा रिटायर्ड कर्मचारियों की जो मुख्य मांग मैडिकल कैशलेस सुविधा की है वह भी बहाल करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा इशू यह है कि जो रोडवेज कर्मचारी हटाए गए थे, उसके कारण रोडवेज कर्मचारी आंदोलनरत है। उन आंदोलनरत कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया जिसके कारण उन कर्मचारियों को काफी चोटें वगैरह लगी हैं और उनके खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, उन आंदोलनरत कर्मचारियों ने भी एक ज्ञापन दिया है कि हमारी सही ढंग से सुनवाई हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहूँगी कि हमारे झज्जर शहर में एक अग्रसैन चौक है और उस अग्रसैन चौक पर भगवान अग्रसैन की प्रतिमा लगी हुई थी जो शरारती तत्वों द्वारा खण्डित कर दी गई है। इसके पहले भी हमारे महान महापुरूषों की प्रतिमाएं खण्डित हो चुकी हैं। यह हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं तो यह कहती हूँ कि जो भी महापुरूष होते हैं वे किसी एक विशेष बिरादरी के न होकर बल्कि पूरे समाज के होते हैं, इस नाते से उनका मान–सम्मान रखना पूरे समाज की जिम्मेवारी बनती है। जब भगवान अग्रसैन महाराज की प्रतिमा को खण्डित किया गया तो बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने इसके विरोध में प्रशासन को ज्ञापन भी दिया था और सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ सदस्य झज्जर भी गए थे और उन्होंने भी प्रशासन को ज्ञापन देने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, इस घटना के संबंध में हमारे साथियों द्वारा कई बार आवाज उठाने के बाद भी प्रशासन आज तक भी उन शरारती तत्वों का पता नहीं कर पाया है कि यह घिनौना काम किसने किया है? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो प्रतिमा वहां पर खण्डित हो गई है उसे प्रशासन जल्दी से जल्दी नई बनवाकर लगवाने का काम करे। क्योंकि इस घटना से हमारे क्षेत्र के लोगों में रोष है। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में मर्डर्ज के मामले भी बढ़ रहे हैं और लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति खराब है। सरकार द्वारा कहा गया था कि पूरे हरियाणा प्रदेश में सी.सी.टी.वी. कैमराज लगवाये जाएंगे। झज्जर जिले में भी सी.सी.टी.वी. कैमराज लगाये गये हैं परन्तु वे फंग्शनल नहीं हैं। इस बारे में होम डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस से सम्पर्क करके पूछा तो उन्होंने बताया कि सी.सी.टी.वी. कैमराज को मॉनीटर करने का काम संबंधित नगरपालिकाओं का है परन्तु नगरपालिकाओं की तो सिर्फ इनके इंस्टालेशन की ही जिम्मेवारी है। सी.सी.टी.वी. कैमराज को मॉनीटर करने की जिम्मेवारी पुलिस विभाग की है। जब कभी सी.वी.टी.वी फुटेज की

आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित कैमराज फंग्शनल नहीं मिलते क्योंकि लगभग 40 प्रतिशत कैमराज फंग्शनल नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि संबंधित कैमराज को वर्किंग कंडीशन में रखा जाए। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। अगर सरकार संबंधित कार्य करवा देगी तो हम धन्यवाद जरूर करेंगे। सरकार द्वारा सैनिक स्कूल, मातनहेल के बारे में बड़ी–बड़ी बातें की जा रही हैं। मैं सैनिकों को सलाम करती हूं। मेरा क्षेत्र वीर सैनिकों का है। चुनाव के दौरान यह प्रचार किया गया कि मातनहेल का सैनिक स्कूल बनाने का कार्य शुरू किया जा चुका है जबकि वहां पर एक भी ईंट नहीं लगायी गयी है। इसके अतिरिक्त हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में एक सैंट्रल स्कूल बनवाना मंजूर किया गया था। वर्तमान सरकार ने उसको मातनहेल के प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग में शुरू करवा दिया है। मातनहेल प्राईमरी स्कूल नेशनल लेवल पर फर्स्ट आया था परन्तु सरकार ने उसकी बिल्डिंग को खाली करवाकर उस स्कूल के बच्चों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दिया। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने निवेदन है कि सैंट्रल स्कूल के लिए नयी बिल्डिंग बनवाने का काम शुरू करवा दिया जाए।

श्री अध्यक्षः गीता जी, आपकी बात समाप्त हो गयी है। प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री आनंद सिंह दांगी जी अपनी बात रखेंगे।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, इस जाने वाली सरकार के सामने क्या बात कहें ?

श्री आनंद सिंह दांगी (मेहम): अध्यक्ष महोदय, कई बार विपक्ष के माननीय सदस्यों को अपने हल्के की बात रखने के लिए समय नहीं दिया जाता।

श्री अध्यक्षः दांगी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी माननीय सदस्यों को अपने हल्के की बात रखने के लिए 2–2 मिनट का समय दिया जाएगा।

श्री आनंद सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अध्यक्ष के पद पर 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई देना चाहूंगा कि आपने सदन को ठीक ढंग से चलाया है। आपने कई बार रूलिंग पार्टी का फेवर भी किया है और कई बार निष्पक्षता भी की है। लेकिन आपका टोटल परसंटेज ठीक रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री आनंद सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, आपका स्वभाव सही है और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कराहट ही रहती है। दूसरी बात यह है कि विधान सभा के सैशंज के दौरान हर माननीय सदस्य का फर्ज होता है कि वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए डिमांड्स रखे और सरकार का काम यही काम होता है कि उनको पूरा करके लोगों की सुविधा दें। इन 5 सालों में सरकार की तरफ से डिमांड्स को पूरा करने के आश्वासन तो मिले लेकिन उनको जमीन पर क्रियान्वित नहीं किया गया। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि निंदान गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म हुआ था और वह गांव मेरे हल्के में पड़ता है। सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी भारत सरकार के रेलवे मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी को साथ लेकर उस गांव में गये थे और वहां जाकर संबंधित गांव को गोद लिया था। सरकार द्वारा संबंधित गांव का ओवर ऑल डिवैलपमैंट करने की बात कही गयी थी लेकिन बड़े दुःख की बात है कि वर्तमान सरकार का आखिरी टाईम चल रहा है परन्तु वह गांव ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। हमारी सरकार ने संबंधित गांव को मॉडल गांव बनाया था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी संबंधित गांव में जो आश्वासन देकर आये थे, उनको पूरा नहीं किया। इस बारे में पिछले सैशन के दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट की थी कि संबंधित गांव में विकास कार्य करवाये जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बहुत गलत रिपोर्ट है क्योंकि उस रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंधित गांव में 93–94 प्रतिशत विकास कार्य करवाये जा चुके हैं और सिर्फ 6–7 प्रतिशत विकास कार्य ही बाकी है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उस गांव में केवल 5 से 6 परसेंट ही विकास के कार्य हुए हैं और लगभग 94 से 95 परसेंट विकास के कार्य अभी भी बाकी हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से सदन में जो भी आश्वासन दिये जाते हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। सरकार का यह दायित्व होता है कि उसके द्वारा सदन में जो भी आश्वासन दिया जाता है, उसे पूरा किया जाये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस सदन में हम सभी माननीय सदस्यों का बहुत ही खट्टा–मीठा अनुभव रहा है। हमने इस सदन में माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी के सारे चमौले भी सुने हैं और मैं तो यहां तक कहता हूं कि पंडित लख्मी चंद जी के बाद राम बिलास शर्मा जी ही एक ऐसे व्यक्ति पैदा हुये हैं जो इस सदन में बातों को जलेबी की तरह घुमा–फिराकर कर करते हैं और वे इस विधान सभा में 250 मीटर को 250 किलोमीटर बताकर के बात करने लगते हैं। इस तरह की बातों से इस सदन में एक मनोरंजन सा माहौल भी

बन जाया करता था, जिससे कभी–कभी निराशा की बात या उदासी की बात आती थी तो इस तरह की बात से सभी माननीय सदस्यों के मन भी आपस में मिल जाया करते थे। मेरा कहना यही है कि इस सदन के हम सभी माननीय सदस्यगण भाई और बहन हैं और हम सभी को आपस में प्यार और प्रेम के साथ रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार यदि लोगों के प्रति समर्पित होती या फिर अपना दायित्व और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती तो शायद मुझे आज यह बात न कहनी पड़ती। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा यह जो 5 साल का समय बीता है, उस दौरान हमारे आपस में भाइचारे, प्यार–प्रेम और खट्टे–मीठे सारे अनुभव हमारे बीच में हुये हैं। मैं इन सब बातों के साथ सभी माननीय सदस्यों के लिए कामना करता हूं कि सभी माननीय सदस्यों के घरों में सुख–शांति बनी रहे और हरियाणा प्रदेश में भी सुख–शांति और अमन–चैन बनी रहे और हमारा हरियाणा प्रदेश हमेशा तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहे। हरियाणा प्रदेश में सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, उसे अपनी जिम्मेदारी के साथ इस प्रदेश में काम करने की आवश्यकता है। आज हमारे माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी सत्ता पक्ष वाली सीट पर बैठे हुये हैं और अभी जिस तरह का चक्कर चल रहा है तो मुझे लगता है कि उस चक्कर में हमारी भी सत्ता पक्ष वाली सीट पर बैठने की बारी आयेगी। (हंसी) इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक एजूकेशन, हैल्थ, नहर का पानी, पीने का पानी, डिवैल्पमैंट और जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए होती हैं, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा दुर्गति हुई है। हमने आज तक किसी भी सरकार के प्रति जनता की ऐसी निराशा नहीं देखी, जिसे हमने वर्तमान सरकार के पिछले पांच सालों के कार्यकाल में देखा है। अध्यक्ष महोदय, इस बात पर भी माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, इन्हें अब गंभीर हो जाना चाहिए और मैं जो भी बातें बोल रहा हूं, वे सारी की सारी सच हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपको तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब ओम प्रकाश बड़वा जी अपनी बात करें।

श्री ओम प्रकाश बरवा (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, मैं आज इस सदन में ज्यादातर उन्हीं बातों को रखूंगा, जो मेरे हल्के से संबंधित होगा और जिनके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जनसभा में घोषणा की है और वे सारे के सारे कार्य अभी तक पूरे नहीं हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले इस सदन में ढिगावा बाईपास बनाने के

बारे में चर्चा चल रही थी। परिवहन मंत्री जी कह रहे हैं कि इनकी जानकारी में यह बात नहीं है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ढिगावा में एक जनसभा में बाकायदा घोषणा करके आये थे कि ढिगावा में बाइपास बनाया जायेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोहारू कस्बे में वर्ष 2014 में 12 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि महिला कॉलेज के भवन निर्माण के लिए आई थी। ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' सरकार का यह नारा है और सरकार का 5 साल का कार्यकाल निकल चुका है, लेकिन राशि आने के बावजूद अभी तक उस महिला कॉलेज के भवन का निर्माण नहीं हुआ है और वह महिला कॉलेज आज भी एक टूटी–फूटी धर्मशाला में ही चल रहा है, इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है ? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब इनकी सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए ये कम से कम जाते–जाते इस बात का फैसला कर दें कि उस महिला कॉलेज की बिल्डिंग कहां पर बनेगी ? इसके अलावा जहां तक बहल ब्लॉक की बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहल ब्लॉक को उपमंडल बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बहल से लेकर ईशरवाल तक का जो रोड है, वह बहुत ही जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये उस रोड की मरम्मत का काम भी जरूर से जरूर करवायें। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सिवानी ब्लॉक के अंदर वन महोत्सव मनाया गया था और उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर यह घोषणा करके आये थे कि वे सिवानी ब्लॉक को हिसार में शामिल कर देंगे, लेकिन उनकी की तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि इस ब्लॉक की डिमांड हमेशा से ही रही है क्योंकि सिवानी ब्लॉक भिवानी जिले से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हिसार जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बावजूद भी इस ब्लॉक को नजरअंदाज कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें ऐसी कौन सी तकनीकी कमी रह गई और ऐसी क्या वजह है? हमें इस बारे में कम से कम बताया जाये कि इस वजह से इस ब्लॉक को हिसार जिले में शामिल नहीं किया गया है जबकि इस बात को लेकर वहां के किसान लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं? हमें इस बारे में कम से कम बताया तो जा ही सकता है कि इस वजह से सिवानी ब्लॉक को हिसार जिले में शामिल नहीं किया जा सकता? इसके अलावा मैं इस महान सदन में सिवानी ब्लॉक के किसानों से संबंधित बात करना चाहूंगा। सिवानी शहर में बरसात के दिनों में जल भराव की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। अभी हमारे माननीय

सदस्य श्री ललित नागर जी ने सदन में सीवरेज से संबंधित बातें कही थी। अध्यक्ष महोदय, सिवानी ब्लॉक एक बहुत बड़ा कस्बा है। इसमें सीवरेज के लिए छोटे साईज की पाइप डाल दी गई जिसकी वजह से पूरे सिवानी कस्बे में जल भराव हो गया और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसके साथ–साथ और भी शहर जुड़े हुए हैं? सरकार को इस बारे में भी विचार करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री ललित नागर जी ने बताया कि लोगों को जल भराव के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, सिवानी ब्लॉक में रोडवेज सब–डिपो नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि वहां पर एक सब–डिपो बनाया जाना चाहिए। मैं इसके अलावा बताना चाहता हूं कि वहां पर देवसर फीडर नहर है, वहां पर नहर के होने के बावजूद भी सिवानी ब्लॉक हमेशा से ही सूखे से प्रभावित रहा है और हमारी बदकिस्मती भी यही रही है कि हम पर राम भी राजी नहीं है और राज भी राजी नहीं है। वहां पर बारिश न होने के कारण आधे ब्लॉक से भी अधिक गांव आज भी सूखे से प्रभावित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में आपके माध्यम से इस महान सदन में पहले भी निवेदन किया था और आज मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि हमारी जो देवसर फीडर नहर है। हमारे ब्लॉक के लोगों की मांग भी यही है कि उस नहर में महीने में दो हफ्ते तक पानी छोड़ा जाना चाहिए। अगर सरकार इस नहर में महीने में दो हफ्ते तक पानी नहीं छोड़ना चाहती है तो कम से कम बारिश के मौसम में तो इस नहर में अधिक पानी छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस ब्लॉक के किसान बहुत गरीब हैं। पानी के बिना यहां के किसानों का जीवन जीना भी दूभर हो गया है और उनको अपना जीवन निर्वाह करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इस संबंध में इतना ही कहना है कि देवसर फीडर नहर में बरसात के समय में अधिक पानी छोड़ा जाये। ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं यदि आप चाहते हैं तो इस बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से पूछ भी सकते हैं कि इस नहर में बरसात के समय में पीछे जब एक हफ्ते पानी छोड़ा गया था तो उस समय नहर में कितना पानी था? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण है कि बरसात के समय में भी इस नहर में पानी पूरा नहीं छोड़ा जाता है? यहां का किसान दुखी और परेशान है। सरकार को इस बारे में भी विचार करने की जरूरत है। अभी तक हमें सरकार की तरफ से आश्वासन ही दिए जाते

रहे हैं लेकिन इसकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी कह रहे थे आप आज सरकार को धन्यवाद कर दें। अध्यक्ष महोदय, हम सरकार का कैसे धन्यवाद कर दें जबकि हमारे इलाके के किसान बहुत दुखी और पीड़ित हैं। हम यह भी जानते हैं कि हरेक माननीय सदस्य को इस लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कई बार इस महान सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया है, मैं उसके लिए तो आपका और सरकार का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम सरकार का धन्यवाद तो तब करें जब सरकार ने सिवानी ब्लॉक के किसानों से संबंधित मामले हल कर दिये हों लेकिन वहां का किसान तो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को फव्वारा व ड्रिप सिंचाई सिस्टम लगाने के लिए कहा है, उसके तहत लोहारू ब्लॉक और बहल ब्लॉक के किसानों को 85 प्रतिशत की सब्सिडी दी गई है जबकि सिवानी ब्लॉक के किसानों को 65 प्रतिशत की सब्सिडी दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने पिछड़े हुए इलाके (सिवानी ब्लॉक) के साथ इतना भेदभाव क्यों किया? मैं इसके साथ यह भी कहना चाहूंगा कि कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को फव्वारा व ड्रिप सिंचाई सिस्टम लगाने से जो थोड़ा बहुत पानी मिल भी रहा है तो सरकार ने सिवानी ब्लॉक के किसानों की सब्सिडी को घटा दिया गया इसलिए यहां के किसानों को भी अधिक से अधिक सब्सिडी प्रदान की जाये। सरकार ने हरेक टेल तक पानी पहुंचाने का दावा तो बहुत किया था। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा घूमाया गया और ऊँटों की सवारी भी करवाई गई लेकिन सरकार का यह दावा भी खोखला साबित हुआ। अध्यक्ष महोदय, आप चाहे देवसर फीडर नहर की बात ले लो, चाहे दमकौड़ा माइनर की बात ले लो और चाहे आप हरियाणा प्रदेश में जितनी भी टेलें हैं, उनकी बात कर लो। इसके लिए सरकार ने हरेक टेल तक पानी पहुंचाने के लिए कहा था लेकिन किसी भी टेल तक पानी नहीं पहुंचा है और मैं समझता हूं कि सरकार ने केवल दिखावे के सिवाय और कुछ नहीं किया?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण बैठे हैं, वहां वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक श्री ओम प्रकाश बड़वा जी बैठा करते थे। हमारे यहां मिट्ठी मतानी माइनर है जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने

कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस माइनर की टेल पर ऊँटों पर चढ़कर गये थे। यह बात सच भी है क्योंकि उस इलाके में ऊँटों के द्वारा खेती की जाती है। अब मैं इस परिपेक्ष्य में बड़वा जी से पूछना चाहूंगा कि वह ईमानदारी के साथ सदन में बतायें कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस माइनर की टेल पर गये थे क्या इस दिन टेल पर पानी नहीं था?

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, वहां पर एक जगह का पानी रोक कर दूसरी जगह पर भेजा गया था। इस प्रकार के अस्थायी प्रयासों से टेल तक पानी नहीं पहुंचता। वह हमारा इलाका है और हम उसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, बहन किरण चौधरी कह रही हैं कि एक जगह का पानी रोक कर वहां भेजा गया। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि ये यह बतायें कि पिछले 20 साल के दौरान क्या वहां पर कभी पानी पहुंचा था? यह जानकारी श्री ओम प्रकाश बड़वा जी ने खुद दी थी और उन्होंने यह स्वयं स्वीकार किया है कि पिछले 20 साल के दौरान वहां पर कभी पानी नहीं पहुंचा था।

श्री अध्यक्ष : बड़वा जी, आप कृपया कंटिन्यू करें।

श्री ओम प्रकाश बड़वा : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि 2018 की खरीफ की फसल के लिए मेरे क्षेत्र का 14 करोड़ रूपये का मुआवज़ा घोषित हुआ था। डी.सी. साहब ने इस सम्बन्ध में ब्यान भी दिया था। इसके लिए सम्बंधित किसानों के बैंक अकाउंट्स के नम्बर भी लिये थे लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमें अभी तक उसकी कोई भी जानकारी नहीं है। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के किसानों की वर्ष 2015 की रबी की फसल का मुआवज़ा भी अभी तक पैंडिंग है। मेरे क्षेत्र में जुई कैनाल से जो रजबाहे निकलते हैं उनकी अभी रिमॉडलिंग हो रही है। रिमॉडलिंग करते समय उनमें पॉलीथीन कवर लगाया जा रहा है। अगर वहां पर इस प्रकार से पॉलीथीन कवर लगाया जायेगा तो वहां पर अण्डरग्राउंड वॉटर की रिचार्जिंग कैसे होगी? लोहारू में जहां पर अण्डरग्राउंड वॉटर का स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है वहां पर इन रजबाहों में पॉलीथीन कवर न लगाये जायें ताकि अण्डरग्राउंड वॉटर लैवल ऊपर आ सके। एक बात मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहल में बुधशैली और गंगाला के विद्यालयों को अपग्रेड करने की घोषणा की थी लेकिन इस घोषणा पर भी अभी तक सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी प्रकार से मैंने बड़वा गांव में स्थित लड़कियों के हाई स्कूल को 10+2

स्तर तक अपग्रेड करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से रिक्वैस्ट की थी लेकिन उस दिशा में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पुनः रिक्वैस्ट करता हूं कि इस काम को भी जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें। स्पीकर सर, बहल और लोहारू में सरसों की खरीद में टोकन घोटाला हुआ है जिसके लिए किसान लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए भी मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। इसी प्रकार से जैसे माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने भी मार्किट फीस को कम करने का मुद्दा उठाया है मेरी भी सरकार से रिकवैस्ट है कि कॉटन पर मार्किट फीस कम की जाये ताकि किसान अपनी कपास की फसल को बेचने के लिए राजस्थान में न जायें और प्रदेश के रेवेन्यू का किसी भी प्रकार से नुक्सान न हो। राजस्थान में कपास पर मार्किट फीस 80 पैसे प्रति क्विंटल है और हरियाणा में 2.80 रूपये प्रति क्विंटल है। सिवानी ब्लॉक के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि –

"जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है,
सूखे कुए तुम्हारा इम्तिहान बाकी है।
बरस जाना ए मेघ समय पर, किसी का मकान गिरवी है,
तो किसी का लगान बाकी है।।"

स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे द्वारा उठाये गए मुद्दों पर जल्द से जल्द गौर फरमाये। इस सरकार के कार्यकाल के दौरान मीटर खरीद घोटाला, आर.टी.ए. घोटाला, फर्जी टिकट घोटाला, किलोमीटर स्कीम घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, जी.एस.टी. फर्जीवाड़े सहित जो बड़े–बड़े घोटाले हुए हैं उनकी निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाये। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई।)**

श्री पिरथी सिंह (नरवाना) (एस.सी.): माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी व मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नरवाना विधान सभा क्षेत्र के गांव उझाना में सी.एच.सी. की बिल्डिंग वर्ष 1989 में सैंक्शन हुई थी मगर आज तक यहां पर बिल्डिंग नहीं बनी है। दूसरी बात यह है कि सी.एच.सी. अभी तक पी. एच.सी. की बिल्डिंग में चल रही है इसलिए इसको जल्दी बनवाया जाये। इसी प्रकार से नरवाना सामान्य अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि नरवाना सामान्य नागरिक अस्पताल में सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, तथा बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाये।

इसी प्रकार से इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन काफी समय से आई हुई है लेकिन डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण यह चल नहीं पा रही है। इस मशीन को चलाने के लिए वहां पर यथाशीघ्र डॉक्टर की नियुक्ति की जाये। इसके अतिरिक्त नरवाना में आई.टी.आई. का निर्माण वर्ष 1960–63 में हुआ था जो कि 9 एकड़ में फैला हुआ है। उस समय यहां पर ट्रेडों में आए हुए सामान को लेकर बड़ी वर्कशॉप बनाई गई थी लेकिन अब वहां पुरानी बड़ी वर्कशॉप को तोड़कर छोटी वर्कशॉप बना दी गई है। मगर आज यहां पर 53 यूनिट व 21 ट्रेड हैं। आज बच्चों की संख्या भी काफी बढ़ गई है जिससे वर्कशॉप में मशीनों को रखने के लिए जगह व बच्चों को भी काम करने के लिए जगह काफी कम पड़ गई है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इन ट्रेडों में आए हुए सामानों के सही तरीके से रख–रखाव के लिए व बच्चों को सही स्पेस के साथ काम करने के लिए आई.टी.आई. कैम्पस नरवाना को वर्कशॉप की नई बड़ी बिल्डिंग प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार से मांग है कि नरवाना आई.टी.आई. कैम्पस में बच्चों की परीक्षाओं, सेमीनार व अन्य कार्यों के लिए एक मल्टी परपज हॉल विद कैंटीन का निर्माण किया जाए क्योंकि जब किसी ट्रेड के बच्चों की परीक्षा होती है तो दूसरी ट्रेड के बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, नरवाना शहर की बाहरी कालोनियां नई बस्ती, आजाद नगर व गांधी नगर आदि में काफी संख्या में लोग बसे हुए हैं। इन लोगों को पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन कालोनियों के लिए नया बूस्टिंग स्टेशन बनाया जाये और उसे माईनर से या नरवाना नेहरू पार्क वाटर वर्क्स से जोड़ा जाये। उपाध्यक्ष महोदया, इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से आज इस सदन को बताना चाहता हूं कि पी.एम.एस.(पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप) में वजीफे की दरें 1 जुलाई, 2010 को रिवाइज हुई थी जबकि स्कीम में प्रावधान यह है कि हर दो साल के बाद वजीफे की दरों में महंगाई को ध्यान में रखते हुए इसे रिवाइज किया जायेगा। आज तक इसमें कोई रिवीजन नहीं किया गया है इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस पॉलिसी को देख कर इसमें उचित व संतोषजनक वृद्धि की जाये। इसके अतिरिक्त नरवाना एच.एस.आई.आई.डी.सी. की 108 एकड़ जमीन है यहां पर सीवरेज व सड़कों का बजट तो मंजूर हो चुका है मगर अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। क्या सरकार बतायेगी कि यहां कब तक कार्य शुरू हो जाएगा? उपध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी की घोषणा के उपरांत राजकीय प्राईमरी स्कूल ढ़ाणी

नरवाना व राजकीय प्राइमरी स्कूल बिधराना को अपग्रेड करके माध्यमिक स्कूल का दर्जा तो दे दिया गया मगर दो साल बीत जाने पर भी यहां पर माध्यमिक स्कूल के लिए न कोई नई बिल्डिंग दी गई और न ही अन्य जरूरी सुविधाएं दी गई हैं। राजकीय प्राइमरी स्कूल ढाणी नरवाना में तो अब हालत ये है कि इस स्कूल की बाउंड्री वॉल भी गिर गई है व सीवरेज का पानी भी ओवरफ्लो होकर स्कूल में भर गया है। मुख्यमंत्री जी बताएं कि कब तक इन माध्यमिक स्कूलों को सभी सुविधाएं व बिल्डिंग मुहैया करवा दी जाएगी ताकि इसमें बच्चों को पढ़ने में असुविधा न हो । उपाध्यक्ष महोदया, नरवाना विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय की हम काफी लम्बे समय से मांग उठाते आ रहे हैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि नरवाना में राजकीय कन्या महाविद्यालय की सौगात देने का काम करें क्योंकि पिछले साल यहां बच्चों की संख्या लगभग तीन हजार थी जिसमें से लड़कियों की संख्या 1600–1700 के करीब है । लड़कियों की इतनी अधिक संख्या होने के कारण यहां कन्या महाविद्यालय बनाना बहुत जरूरी है और यह सरकार की पोलिसी भी है । उपाध्यक्ष महोदया, नरवाना–हिसार रोड रेलवे फाटक के नीचे सटी बस्ती में अवैध कारोबार पूरे जोर–शोर से चलता है । यहां समैक, गांजे का अवैध कारोबार किया जाता है जिसकी चपेट में आज हजारों बेराजगार युवा हैं । हमारी सरकार से मांग है कि इस अवैध कारोबार को नरवाना से जड़मूल से खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं । उपाध्यक्ष महोदया, यह ठीक है कि मंत्री जी ने मेरे हल्के में बड़ा अच्छा काम किया है लेकिन मैं धरौदी माईनर को भाखड़ा नहर से जोड़ने की मांग पांच साल से उठाता आ रहा हूं जिस पर मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय साथी को तो सरकार का धन्यवाद करना चाहिए । उनके क्षेत्र में सरकार ने 11 गांवों के अलावा और 6 गांवों को भिठमड़ा माईनर से पानी देने का काम भी किया है। आपको तो सरकार का धन्यवाद करना चाहिए ।

श्री पिरथी सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, यह तो सरकार का काम है फिर भी इसमें इतना लम्बा समय लग गया है ।

श्री कृष्ण कुमार बेदी : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय साथी के क्षेत्र में जो काम हो गया है उसको भी ये दोबारा से कह रहे हैं । मुख्यमंत्री जी ने इनके क्षेत्र को इतनी फ्राखदिली से 11 गांवों को धरौदी माईनर का पानी दे दिया है और 6 गांवों को

भिठमड़ा माईनर से पहले ही जोड़ दिया है तो इनके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी । जहां पर पहले मुख्यमंत्री व कई–कई विभागों के मंत्री रह कर चले गए हैं क्या उन्होंने कभी वहां जाकर भी देखा था ? और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो आपको इतनी बड़ी सौगात दे दी है ।

श्री पिरथी सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वह उस माईनर के कागजात तैयार करवाकर उसमें जल्दी से जल्दी पानी चालू करवा दें ताकि वहां के लोगों को उस माईनर के पानी से फायदा हो सके । उपाध्यक्ष महोदया, आठ–नौ साल से नरवाना के गांव धमतान साहिब से कालवन टोहाना रोड की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है । उसको नया बनाना था जिसका एस्टीमेट तो बन गया है लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इसके बारे में क्या मंत्री जी बताएंगे कि उस रोड को बनाने में देरी क्यों हो रही है ? और इसको कितना जल्दी बनाया जाएगा । उपाध्यक्ष महोदया, नरवाना शहर में वाल्मिकी धर्मशाला के लिए कमेटी से जमीन ली गई थी । जिसकी चार दीवारी को तो बाल्मिकी समाज ने पैसे कलैक्शन करके बना दिया है लेकिन उनकी आर्थिक तंगी होने के कारण वह काम आज तक अधूरा पड़ा हुआ है । इसको बनाने के लिए मंत्री जी दिनांक 8.10.2016 को 15 लाख रुपये देने का वायदा करके आए थे । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वह पैसा कब आएगा ? दूसरा 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी जब जीन्द में गए थे तो वह भी इस धर्मशाला को बनाने के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा करके आए थे । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी व मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वाल्मिकी धर्मशाला को बनाने के लिए वह पैसा जल्दी भेजें ताकि उसका काम आगे बढ़ सके ।

12:00 बजे

श्री कृष्ण कुमार बेदी : उपाध्यक्ष महोदया, जैसाकि पिरथी जी ने प्रश्न उठाया है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जिला जींद में भगवान वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि धर्मशाला के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, चौधरी विरेन्द्र सिंह जी तथा मैंने भी पैसे देने की एक घोषणा की थी। हमारी तरफ से पैसे केवल इसीलिए नहीं दिए जा सके हैं क्योंकि अभी तक इस पैसे के लिए वहां की नगरपालिका का रिजोल्यूशन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य पिरथी जी को आश्वस्त करता हूँ कि जिस दिन यह रिजोल्यूशन आ जायेगा उसी दिन पैसा रिलीज कर दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदया, जींद में

वाल्मीकि समाज के तीन पार्षद हैं मैंने उनसे भी कहा था और इस सदन के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि जिस दिन यह रिजोल्यूशन आ जायेगा उसी दिन घोषणा की राशि की एक–एक पाई देने का काम किया जायेगा।

श्री पिरथी सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, रिजोल्यूशन मंगवाना तो सरकार का काम है। जब चौधरी बिरेन्द्र सिंह ने भी अपने द्वारा की गई घोषणा के पैसे दे दिए है तो सरकार के मंत्री द्वारा उनके द्वारा की गई घोषणा के पैसे भी दिए जाने चाहिए। जैसे रविदास धर्मशाला, डॉ. भीम राव अम्बेडकर भवन तथा अन्य धर्मशालाओं के लिए पैसा आया है तो वाल्मीकि धर्मशाला के लिए भी घोषणा की गई राशि को दे देना चाहिए।

श्री कृष्ण कुमार बेदीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं फिर से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि आज–कल या परसो या जिस दिन भी नगरपालिका का रिजोल्यूशन हमें प्राप्त हो जायेगा उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मेरे द्वारा की गई घोषणा की राशि रिलीज कर दी जायेगी।

श्री बलकौर सिंह (कालांवाली) (एस.सी): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैंने पूर्व में इस सदन में जो मांगे उठाई थी, उन मांगों को इस सरकार ने काफी हद तक पूरा करने का काम किया है। मेरे हल्के में कॉलेज की एक काफी पुरानी डिमांड थी। जब मैंने सदन में कॉलेज की मांग की तो यह मांग पूरी कर दी गई। आज मेरे हल्के कालांवाली में लडकियों का कॉलेज बढ़े अच्छे ढंग से चल रहा है। चाहे सड़कों की मरम्मत की बात हो, पुल बनाने की बात हो, बस स्टैंड बनाने की बात हो सरकार ने मेरी इन सभी मांगों को पूरा करने का काम किया है लेकिन बावजूद इसके अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने पिछले सैशन में भी यह मसला उठाया था और आज फिर उठा रहा हूँ कि मेरे सिरसा जिले में घग्गर नदी है जोकि बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा उफान पर होती है। घग्गर नदी पंजाब के एरिया से निकलकर रंगा और लहंगेवाला गांव से होती हुई कालांवाली हल्के को टच करती है। सरकार ने घग्गर नदी से अलग–अलग विधान सभा क्षेत्रों के लिए बहुत वाटर चैनल्ज देने का काम किया है लकिन आज तक मेरे हल्के कालांवाली के लिए वाटर चैनल देने का काम नहीं किया गया है। अतः आज इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे हल्के कालांवाली के लिए घग्गर नदी

से एक बढ़िया चैनल देने का काम किया जाये। घग्गर नदी चूंकि बरसात के दिनों में उफान पर होती है और इसका अतिरिक्त पानी एक तरह से आगे जाकर नुकसान करने का ही काम करता है लेकिन यदि घग्गर नदी से मेरे हल्के के लिए बढ़िया वाटर चैनल निकाल दिया जाये तो यह अतिरिक्त पानी जो आगे जाकर नुकसान का कारण बनता है, इस पानी को खेती में प्रयोग करके फायदा उठाया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदया, पिछले दिनों घग्गर नदी में पानी के उफान के कारण सारणी गांव में 200–300 एकड़ फसल नष्ट हो गई थी। उपाध्यक्ष महोदया, अगर मेरे कालांवाली हल्के के गांव रंगा व लहंगेवाला में घग्गर नदी से वाटर चैनल बनाकर निकाल दिया जाता है तो इससे घग्गर नदी का यह पानी गांव रंगा और लहंगेवाला से निकलकर गांव फग्गू और रोड़ी से होता हुआ झोरड़रोही, कालांवाली और डबवाली क्षेत्र तक के बहुत सारे गांवों को फायदा पहुंचाने का काम करेगा और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। यही नहीं इससे इन क्षेत्रों का वाटर लैवल भी उपर आ जायेगा। उपाध्यक्ष महोदया, मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि घग्गर नदी से मेरे हल्के कालांवाली के लिए वाटर चैनल निकलवाकर किसानों तथा आमजन को राहत पहुंचाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे हल्के के जिन गांवों में ट्यूबवैल्ज के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है, उन गावों में यह पानी बहुत सी बीमारियों का कारण बनता जा रहा है क्योंकि धरती का पानी बहुत खराब हो चुका है। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसे गांव जिनको ट्यूबवैल्ज के माध्यम से पानी दिया जाता है, वहां पर नहर या किसी अन्य तरीके से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे हल्के के हांडीखेड़ा व रसूलपूर गांवों में तो ट्यूबवैल्ज के पानी से बहुत ज्यादा बीमारिया फैल रही हैं। अतः इन गांवों के साथ–साथ अन्य दूसरे गांवों में तुरंत प्रभाव से पीने के पानी को अन्य दूसरे तरीको से उपलब्ध करवाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं नशे की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने नशे जैसे बहुत ही गम्भीर मसले पर सदन का ध्यान दिलाया था। यह बहुत जरूरी मसला है। मेरा हल्का कालांवाली, पंजाब के बार्डर के साथ लगता एरिया है। पंजाब में नशा अपनी चरम सीमा पर है जिसका प्रभाव मेरे हल्के के नौजवानों पर भी पड़ता जा रहा है। मेरे हल्के के 10–10 साल तक के बच्च नशे की लत के शिकार होने के साथ–साथ नशे के लिए प्रयोग की जाने वाल सुइयों की वजह से एडस जैसी भयानक बीमारियों का शिकार तक हो गए हैं। अतः

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि वहां डी.जी.पी. या सी.एम. लैवल की कोई स्पैशल टीम बनाकर भेजी जाए क्योंकि वहां की पुलिस नशों को रोकने के लिए नाकाम और नाकाफी है । डबवाली और कालांवाली हल्कों में नशों के कारण लोगों को बहुत गम्भीर बीमारियां हो जाती हैं । वहां पर नशेड़ियों के इलाज के लिए कोई स्पैशल नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए । मेरे हल्के कालावांली में डॉक्टर्स की बहुत कमी है । वहां की एक पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में अवश्य अपग्रेड किया गया है लेकिन उसमें डॉक्टर्स नहीं भेजे गए । विधान सभा के सत्र में जब मैं इस संबंध में प्रश्न लगाता हूं तो उस समय वहां पर 1–2 महीने के लिए डॉक्टर नियुक्त कर दिया जाता है लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर स्थिति ज्यों की त्यों होती है और उस डॉक्टर को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है । अगर वहां पर कोई एक्सीडैंट हो जाता है या फिर कोई डिलीवरी केस होता है तो उनको इलाज के लिए वहां से 40–45 किलोमीटर दूर सिरसा जाना पड़ता है । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने कालावांली के जिस पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में अपग्रेड किया है उसमें डॉक्टर्स की उपल्बधता और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं । इस समय सदन में माननीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा बैठे हैं । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहूंगा कि इन्होंने प्रदेश के बहुत–से स्कूल्ज को अपग्रेड किया है लेकिन अभी तक मेरे हल्के के सिर्फ 2 स्कूल्ज को ही अपग्रेड किया गया है । मेरे हल्के के एक गांव कोटली के लगभग 800 बच्चे पढ़ने के लिए 8–10 किलोमीटर दूर जाते हैं । अतः मैं आपसे विनती करूंगा कि उस स्कूल को आठवीं कक्षा से अपग्रेड करके बारहवीं कक्षा तक कर दिया जाए ।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे बड़े वीर सरदार बलकौर सिंह जी बड़ा चंगा बोल रहे हैं । इन्होंने हमारी सरकार का इनके हल्के में कुड़ियों के लिए महिला महाविद्यालय बनाने के लिए धन्यवाद किया है । वह महाविद्यालय बहुत चंगा चल रहा है । मैं माननीय सदस्य सरदार बलकौर सिंह के विषय में कहना चाहूंगा

अव्वल अल्ला नूर उपायो,
कुदरत दे सब बन्दे,
एक नूर ते सब जग ज्या,
कौन भले कौन मन्दे ।

माननीय सदस्य जिन स्कूल्ज को अपग्रेड करवाना चाहते हैं उनके नाम मुझे लिखकर दे दें । मैं एक कलम से उन्हें अपग्रेड करने की मंजूरी दे दूंगा ।

सरदार बलकौर सिंह कालांवाली : उपाध्यक्ष महोदया, मैं दो गांवों के इन स्कूल्ज के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को एक नहीं बल्कि दो–दो बार लिखकर दे चुका हूं । इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी लिखकर दे चुका हूं लेकिन अभी तक इन स्कूल्ज को अपग्रेड नहीं किया गया है । अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो 'अव्वल अल्ला नूर उपाय कुदरत दे सब बन्दे' वाली बात कही है इस पर मेरा कहना है कि यह तो ठीक है लेकिन मेरा अनुरोध है कि मेरे हल्के के दो गांवों के उन स्कूल्ज को अपग्रेड कर दें तो इनकी बहुत मेहरबानी होगी । मेरे अपने गांव जोहड़रेही में केवल एक पी.टी. मास्टर ही सारे स्कूल को चला रहा है । अतः मेरा निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए । वहां के स्कूल्ज में स्टाफ की बहुत कमी है । अतः मेरा निवेदन है कि स्कूल्ज में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए । उपाध्यक्ष महोदया, इस सरकार को बने हुए 5 साल होने वाले हैं । आपने और अध्यक्ष महोदय ने इस दौरान सदन को बहुत अच्छे तरीके से चलाया है, इसलिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं ।

श्रीमती सीमा त्रिखा (बड़खल) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं । वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनी थी और अब वर्ष 2019 चल रहा है । आज मेरे विचार से इस सरकार के अंतिम सत्र का अंतिम दिन है । आज इस समय मुझे वह दिन याद आ रहा है जब मैंने विधान सभा के सत्र में पहली बार बोलते हुए मुख्यतः चार विषय उठाये थे और साथ ही मुझे वह समय भी याद आ रहा है जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे विधान सभा क्षेत्र बड़खल में एक रैली की थी । मैंने उस दिन हाउस में पहला विषय फरीदाबाद को एक यूनिवर्सिटी देने, दूसरा विषय मैंने बड़खल झील पर काम करने संबंधी, तीसरा विषय मैंने गरीब तबके के लिए रहने की व्यवस्था करने का उठाया था क्योंकि मेरे क्षेत्र में एक तबका ऐसा है जिसके पास आय के साधन भी बहुत कम है और रहने के लिए न घर है और वे जहां जगह मिले उसे घेरकर रहने लग जाते हैं, चौथा विषय मैंने फरीदाबाद के पुराने गौरव को लौटाने के लिए एक मदर यूनिट देने का उठाया था क्योंकि फरीदाबाद शहर की पहचान एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मेरे क्षेत्र का विकास करने के लिए दिल से धन्यवाद देती हूं । मैं बड़खल हल्के का प्रतिनिधित्व करती हूं लेकिन मैं पूरे फरीदाबाद जिले की जनता की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं । मेरा इलाका एक ऐसा इलाका है

जो वर्षों तक हरियाणा प्रदेश को कैटर करता रहा है । मुझे यह बताते हुए बड़ा गौरव महसूस होता है कि इस सरकार ने हमारे क्षेत्र की बरसों पुरानी मांग को पूरा करते हुए बड़खल को उप–मण्डल/सब–डिवीजन और तहसील बनाने का काम किया है । यह काम जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किया है वह पिछले 48 सालों में कोई भी सरकार नहीं कर सकी थी । हमारा फरीदाबाद शहर दिल्ली के साथ बिल्कुल सटा हुआ है । मैं एक शिक्षिका रही हूं । इस नाते से मुझे यह देखकर बहुत खराब महसूस होता था कि देश की राजधानी के इतने नजदीक होते हुए भी फरीदाबाद शहर 50 सालों से एक यूनिवर्सिटी का हकदार नहीं बन सका था । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बड़खल में विकास रैली की तो उसी रैली में जब हमने फरीदाबाद के लिए यूनिवर्सिटी की मांग की तो उन्होंने फरीदाबाद में एक की बजाय दो–दो यूनिवर्सिटीज मंजूर कर दी । एक यूनिवर्सिटी पृथला हल्के के गांव दुधौला में बन रही है और यह यूनिवर्सिटी प्रदेश में अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी है । इस यूनिवर्सिटी का नाम 'विश्वकर्मा स्किल डिवैल्पमैंट यूनिवर्सिटी' है । इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री महोदय फरीदाबाद की दूसरी यूनिवर्सिटी 'वाई.एम.सी.ए. यूनिवर्सिटी' का अब किसी भी दिन उद्घाटन कर सकते हैं । इस यूनिवर्सिटी के लिए बड़खल हल्के के गांव 'भाकड़ी' में जगह को सुनिश्चित किया गया है । बड़खल, फरीदाबाद और गुरूग्राम ये तीनों शहर ट्विन सिटीज के रूप में इकट्ठे चलते हैं । इन शहरों के लिए हमने माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैट्रो कनैक्टिविटी देने की मांग की थी । मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इनमें मैट्रो चलाने के लिए मंजूरी दे गई है । अब केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर इस प्रोजैक्ट को पूरा करेंगी । इसके अलावा फरीदाबाद शहर में दुनियाभर के उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आते थे लेकिन यहां के लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली और गुरूग्राम के चक्कर लगाते थे । हमारी सरकार आने के बाद फरीदाबाद में पासपोर्ट ऑफिस बन गया है । यह एक ऐसा काम था जो पिछले 48 सालों से नहीं हुआ था । इस कार्य के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, केन्द्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुष्मा स्वराज का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं । हमारे क्षेत्र में इस सरकार में ऐसे बहुत–से कार्य करवाये गए हैं जिनकी पिछले अनेकों सालों से मांग की जा रही थी । इसी तरह हमारे इलाके में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण हुआ है । बड़खल झील को सूखे हुए 25 साल हो चुके थे लेकिन इसकी किसी भी सरकार ने सुध नहीं ली थी । हमने इस झील के

पुनर्उद्धार के लिए बहुत मेहनत की और यह एक ऐसा काम था जिसके लिए हर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। अब इस झील के काम ने अपनी रफ्तार पकड़ रखी है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सावन में इस झील में बोटिंग की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। मेरी कल माननीय मुख्य मंत्री महोदय से घोषणा पत्र के संबंध में बात हुई थी। हमारी सरकार ने ऐसा काम किया है कि आज चाहे किसी भी घर का दरवाजा खटखटाते और बुजुर्गों से पूछते हैं कि क्या आपको 2,000 रुपये पैंशन मिल रही है ? इसके बारे में हर बुजुर्ग के घर से आवाज आती है कि उन्हें 2,000 रुपये पैंशन के रूप में मिल रहे हैं। यह ऐसी सरकार है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने गीता को कुरूक्षेत्र की धरती से उठाकर दुनिया में बहुत ऊपर तक इसकी ख्याति को बरकरार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम मनोहर है परन्तु उन्होंने गीत श्री कृष्ण का गाया है और उसको अपने जीवन में भी चरितार्थ किया है। गीता का यही उपदेश है कि आप कर्म करते जाएं और फल की चिन्ता ना करें। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि पिछली सरकारों ने फल की चिन्ता करते हुए कर्म किये। लेकिन श्री मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने कर्म किया है परन्तु फल की चिन्ता नहीं की। इनके कर्म का ही नतीजा है कि नौकरियों में पारदर्शिता बढ़ने से जुगाड़ खत्म हो गया है जिससे पर्ची और खर्ची का खेल भी खत्म हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फरीदाबाद की जनता की तरफ से और मेरे हल्के की जनता की तरफ से भी धन्यवाद करती हूं और आगे आने वाले भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी देती हूं।

श्री वेद नारंग (बरवाला): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब मुझे 5 साल पहले इस महान् सदन में पहली बार आने का मौका मिला तो सदन में एक अच्छा माहौल देखने को मिला और यहां पर कुछ खट्टे–मीठे अनुभव मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा दिया था। मैं खासकर बरवाला हल्के के संदर्भ में बात करूं तो पहली बार विधायक बनने के बाद मन में यह बात रहती थी कि हम सरकार के सामने हल्के के लिए जो भी डिमांड्स रखेंगे, उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मेरे हल्के की डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया, इसलिए विपक्ष की पार्टी का माननीय सदस्य होने की मन में एक टीस लगी रहती है। मैंने बरवाला हल्के के जो भी मुद्दे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को

लेकर उठाये, उनमें लगभग हर बात का जवाब नहीं में मिला। सबसे पहले बरवाला हल्के की सीवरेज की समस्या को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 3 मंत्रियों के सामने रखा परन्तु कोई समाधान नहीं करवाया गया। इससे मेरे हल्के की सीवरेज की समस्या गम्भीर रूप धारण करती गयी। इसके अतिरिक्त पेयजल की समस्या का मामला उठाया तो माननीय मंत्री जी का जवाब आता था कि संबंधित क्षेत्र में पेयजल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है परन्तु यह समस्या हर साल गम्भीर रूप धारण करती गयी। जहां तक सीवरेज सिस्टम का सवाल है उसमें चाहे बरवाला शहर हो या मिलगेट का क्षेत्र हो, सभी जगहों पर सीवरेज सिस्टम ठप पड़ा है परन्तु सरकार की तरफ से जवाब मिलता था कि बरवाला हल्के में सीवरेज की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाएं तो वहां पर नहरों में पानी की समस्या है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। किसानों की समस्याओं को हल करवाने के लिए सभी चुने हुए प्रतिनिधि ही उनकी आवाज उठाते हैं। मेरे हल्के की नहरों में पर्याप्त पानी मिल रहा है। जहां तक सरकार द्वारा फसल खरीदने की बात है उसमें भी किसानों को दिन–रात बहुत सी उलझनों में से निकलना पड़ा। प्रधान मंत्री जी के नाम से फसल बीमा योजना चलायी गयी परन्तु इसमें किसानों को राहत देने की बजाय उनकी जेब काटने का काम किया गया है। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालकर उनकी जेबें काटी गयी हैं। किसानों को पैसे देने की बजाय उनके अकाउंट्स में से पैसे काटे गये। इस स्कीम से ऐसा लग रहा था कि सरकार किसानों को राहत देगी परन्तु कोई राहत नहीं दी गयी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन किसानों को कुछ राहत देने के बजाय उनकी जेब काटने का काम किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से मांग की गई है कि उनकी उम्र बढ़ने पर उनकी पैंशन बढ़ाई जाये और उनको कैशलैस मेडिकल सुविधा भी दी जाये, मैं चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ भी तुरन्त विचार करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन कम्प्यूटर टीचर्ज को बार–बार परीक्षा देनी पड़ती है, सरकार उनको भी राहत देने का काम करे। इन पांच सालों में जब भी हम में से किसी भी माननीय सदस्य ने इस सदन में अपनी बात रखनी चाही तो स्पीकर सर ने हम सभी माननीय सदस्यों को बहुत ज्यादा बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं स्पीकर सर का धन्यवाद

करता हूं और इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदया और चेयर पर हमारे जो भी माननीय सदस्य आयें, मैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य श्री वेद नारंग जी को भी बहुत–बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।

श्री कृष्ण कुमार बेदी: उपाध्यक्ष महोदया, मैं भी माननीय सदस्य श्री वेद नारंग जी को बहुत–बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदया: जय प्रकाश जी, आप भी अपनी बात इस सदन में रखें।

श्री जय प्रकाश (कलायत): उपाध्यक्ष महोदया, वर्तमान की जो सरकार है, वह 5 साल पहले बनी थी। हमारी प्रजातंत्र प्रणाली में सत्तापक्ष और विपक्ष दो पक्ष होते हैं। यह ठीक है कि सत्तापक्ष हमेशा ही यह कोशिश करती है कि उसे बहुत अच्छा काम करना है और विपक्ष की यह जिम्मेवारी होती है कि वह सरकार की खामियों को उजागर करे। इस प्रजातंत्र प्रणाली में विपक्ष की भी उतनी भूमिका होती है, जितनी की सत्तापक्ष की होती है। इस सदन में पिछले पांच सालों में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी–अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है। कई बार इस सदन में माननीय सदस्यों की हाजरी या संख्या का प्रश्न खड़ा हो जाता था और उस संख्या के बल के आधार पर सत्ताधारी दल निरंकुशता की तरफ चले जाते थे। मेरा काफी लम्बे अर्से का लोक सभा और विधान सभा का अपना तजुर्बा रहा है और उस तजुर्बे के आधार पर मैंने यह महसूस किया है कि पिछले 5 सालों में माननीय स्पीकर साहब का व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा है। इन पांच सालों में केवल एक बार ही कहीं न कहीं खामी रही थी, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के माननीय साथियों को सस्पेंड किया गया, वरना उसके बाद चेयर की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जिसके लिए हम यह कहें कि इस सदन में कहीं–न–कहीं व्यवस्था के खिलाफ कोई कार्य किया गया है, इसके लिए मैं उपाध्यक्ष महोदया और स्पीकर साहब का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और श्री अभय सिंह चौटाला जी कुछ दिनों पहले धरौदी गांव में धरने पर गये थे, क्योंकि उस गांव में लगभग 45 दिनों से किसान धरने पर बैठे हुये थे, क्योंकि वहां पर पीने का पानी तक नहीं था। माननीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी वहां पर किसानों से यह वायदा करके आये थे कि वे वहां के किसानों को पानी देंगे, लेकिन इन्होंने अपने आश्वासन में थोड़ी सी चूक कर दी, इन्होंने कहा था कि ये वहां के किसानों को

अप्रैल में पानी देंगे, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया ये उस गांव में पानी के लिए टैम्परेरी इन्तजाम जल्दी से जल्दी करवा दें। हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा–अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस सदन के मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया है और मैं इनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कई बार सत्ताधारी दल के मंत्री अपने आप को यह समझ लेते हैं कि ये प्रदेश के मालिक हैं, लेकिन मैं इन को कहना चाहूंगा कि मालिक ये नहीं, बल्कि इस प्रदेश की जनता है, जिसने हमें चुनकर इस सदन में भेजा है। इस सदन में हम सभी माननीय सदस्यों की अलग–अलग जिम्मेदारी है और हम सबने अपनी–अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई भी है। मैं सत्ताधारी दल के माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि इनसे जहां पर भी गल्तियां हुई हैं, ये उसके लिए खुद में ही पश्चाताप महसूस कर लें ताकि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि यह इस सत्र का आखिरी दिन है, इसलिए चाहे मुझ से कोई गलती हुई हो, क्योंकि मैं थोड़ा नोक–झोंक ज्यादा कर लेता हूं तो मुझे माफ कर दें। मैं सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि हम सभी माननीय सदस्य एक साथी के रूप में हमेशा रहेंगे। हम सभी एक–दूसरे के लिए अच्छे भविष्य की कामना करेंगे ताकि हम सभी माननीय सदस्य दोबारा से चुनाव जीतकर इस सदन में आयें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : उपाध्यक्ष महोदया, श्री रामविलास पासवान जी ने लोकसभा में कहा था कि मेरे से बड़ा कोई मौसम वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि मैं हमेशा से ही एन.डी.ए. के साथ रहा हूं इसलिए मैंने आज तक कोई पार्टी भी नहीं बदली है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से श्री जय प्रकाश जी को बताना चाहूंगा कि आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, आपको लोकसभा और विधान सभा दोनों का ही काफी अनुभव हैं और आज आपने इस महान सदन में अपने वक्तव्य का काफी अच्छा प्रदर्शन किया है इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

डॉ. कृष्ण लाल मिडढा (जींद) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। श्री मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ''समान काम–समान विकास'' की नीति बनाई बल्कि उसको अमलीजामा भी पहनाने का काम किया। उन्होंने अभी

हाल ही में हांसी–जींद रेलवे के लिए लगभग 923 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, जैसे कि पूर्व की सरकारों ने जींद जिले की निरन्तर उपेक्षा करने का काम किया है। जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में सत्ता की कमान संभाली है तब से हरियाणा प्रदेश में विकास कार्यों ने नई बुलंदियों को छूने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगों को इस महान सदन में रखना चाहता हूं। आज मुझे दूसरी बार इस विधान सभा सत्र में आने का मौका मिला है। मैं बताना चाहूंगा कि जब से जींद जिला एन. सी.आर. में आया है तब से एन.सी.आर. के मुताबिक सरकार ने कोई ग्रांट प्रदान नहीं की है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं मिली है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बजट मुहैया करवाने के लिए केन्द्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी जाए। जिससे जींद जिले में एन.सी.आर. के मुताबिक विकास कार्य किए जा सकें क्योंकि वहां पर सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल ठप्प पड़ी हुई है। इस बारे मे मैं इस महान सदन में पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि अभी तक सीवरेज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया है। मैं चाहता हूं कि सीवरेज की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ मशीनों की व्यवस्था की जाये ताकि सीवरेज की अव्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदया, जैसे कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी ने स्कूलों को अपग्रेड करने की बात कही थी तो उस वक्त उन्होंने एक बात यह भी कही थी कि ''राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट''। इस बारे में मैं भी यही कहना चाहता हूं कि जींद अमरेहड़ी गांव में स्कूल को भी अपग्रेड करने का काम किया जाये। रायचन्द वाला, खूंगा कोठी, दालमवाला, बोहतवाला को अलेवा उपमंडल से जोड़ा गया है जोकि ये गांव पहले जींद उपमंडल का हिस्सा थे और ये सभी गांव जींद विधान सभा क्षेत्र में भी आते हैं। इन गांवों को वापिस जींद जिले के अंडर किए जाने का प्रावधान करें। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र के गांव अहीरका, निर्जन और लोहचब आते हैं इनमें पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि सरकार ने पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण यहां के लोगों को आये दिन बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक रेलवे ओवर ब्रिज

का मामला है तो उसमें एक गांव पाण्डु पिण्डारा है, उस गांव में एक बहुत बड़ा सोम तीर्थ स्थल बना हुआ है। पानीपत–जींद व जींद–सोनीपत रेलवे लाईन पर पुल को पिलरों पर बनाने का काम किया जाये ताकि सोम तीर्थ स्थल पर पहुंचने के लिए आने जाने का रास्ता बनाया जा सके क्योंकि यात्रियों को सोम तीर्थ स्थल पर आने जाने के लिए बहुत लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदया, एक बार पुनः मैं आपका और अध्यक्ष महोदय का दिल की गहराईयों से धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं पुनः आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री बलवंत सिंह (सढ़ौरा) (एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वर्तमान सरकार चल रही है। मैं हरियाणा सरकार की कैबिनेट का भी आभार व्यक्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में ''हरियाणा एक हरियाणवी एक'' के नाम से जो नारा दिया था, उसको साकार करने का भी काम किया है। मैं समझता हूं कि आज सभी 90 के 90 हल्कों में विकास कार्य बढ़ चढ़कर हुए हैं। मैं अपने हल्के के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में पहले न तो कोई कॉलेज था, न ही कोई स्कूल था और न ही कोई पॉलिटैक्निक कॉलेज था क्योंकि मेरे हल्के के गांव पहाड़ों से सटे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदया, वहां 10वीं के बाद पढ़ने वाले बच्चों को लगभग 20–30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी ने मेरे क्षेत्र के 6 स्कूलों को अपग्रेड करके 12वीं तक करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीन कॉलेज पॉलिटैक्निक कॉलेज सढ़ौरा, गवर्नमैंट कॉलेज बिलासपुर और गवर्नमैंट कॉलेज मुस्तफाबाद को भी बनाने का काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मेरा हल्का हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। मेरे इलाके के बहुत से बच्चे और बच्चियां रोजगार के लिए हिमाचल प्रदेश में जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदया जी, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक विशेष अनुरोध अवश्य करना चाहूंगा कि मेरे हल्के में जल्दी से जल्दी एक इंडस्ट्रियल ज़ोन स्थापित किया जाये ताकि मेरे हल्के के बच्चे और बच्चियों को रोजगार के लिए हिमाचल प्रदेश में न जाना पड़े। उपाध्यक्ष महोदया, आपने और स्पीकर साहब ने हाउस में पुराने सदस्यों के मुकाबले नये सदस्यों को बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दिया इसके लिए स्पीकर साहब और आप दोनों ही बधाई व धन्यवाद के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे हाउस में

बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भगवान दास कबीरपंथी (नीलोखेड़ी) (एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदया, 14वीं विधान सभा का यह अंतिम सत्र है। इस विधान सभा में कुछ विधायक पहली बार और कुछ विधायक पुनः चुनकर पहुंचे हैं। यहां पर सभी ने अपने–अपने क्षेत्रों की समस्यायें रखी। सभी माननीय सदस्यों ने अपने–अपने क्षेत्र से सम्बंधित जनहित के मुद्दों को उठाया। यह पांच साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। यहां पर सभी माननीय सदस्यों को बोलने का समान अवसर दिया गया। इसके लिए मैं स्पीकर साहब और उपाध्यक्ष महोदया को बहुत–बहुत धन्यवाद एवं बधाई देता हूं। मैं भी पहली बार विधायक बनकर इस महान सदन में पहुंचा हूं। यहां पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत से काम करवाने का प्रयास किया। इन पांच वर्षों में हमारी सरकार ने बहुत से जनहितकारी फैसले लेकर उनको कार्यान्वित करवाया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता सम्भाली थी उस समय उन्होंने यह बात कही थी कि हम राज करने के लिए नहीं अपितु प्रदेश के सभी वर्गों की सेवा करने के लिए आये हैं। इन पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रदेश के सभी वर्गों की भलाई के लिए बहुत से काम किये गये। हमारी सरकार द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खुलवाने का काम किया गया। इसी प्रकार से हमारी सरकार द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में नई सड़कों का निर्माण करवाया गया व पुरानी सड़कों को मुरम्मत करके बेहतर बनाया गया। मेरा विधान सभा क्षेत्र प्रत्येक मामले में पिछड़ा हुआ था। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। न तो वहां पर बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कोई कॉलेज था, न ही अस्पताल था और न ही कोई स्टेडियम था। मेरे हल्के की तमाम सड़कों की हालत बहुत ही खराब थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को और माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारे क्षेत्र में चहुंमुखी विकास की गंगा बहाई। हमारी सरकार द्वारा ही मेरे क्षेत्र के लोगों को मेरे क्षेत्र में बागवानी विश्वविद्यालय खोलकर सबसे बड़ी सौगात दी गई। निकट भविष्य में इससे मेरे हल्के के किसानों को निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा यह होगा कि मेरे क्षेत्र के किसान गेहूं व धान के फसल चक्र से निकलकर बागवानी की तरफ रुख करेंगे। मेरे हल्के में लड़कियों के लिए भी कोई कॉलेज नहीं था।

हमारी सरकार द्वारा मेरे हल्के में लड़कियों के दो कॉलेज क्रमशः तरावड़ी और निसिंग में खोलने का काम किया गया है। मेरे क्षेत्र में जो पॉलिटैक्निक कॉलेज था उसको हमारी सरकार द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्ज़ा दिया गया है जिससे वहां पर बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से मेरे हल्के में कोई बड़ा हॉस्पिटल नही था इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा नीलोखेड़ी में 100 बैड का हॉस्पिटल बनाया गया और तरावड़ी में 50 बैड का हॉस्पिटल बनाया गया है। इसी प्रकार से समाना बाहू गांव के सब–सैंटर को पी.एच.सी. में अपग्रेड किया गया है और पधाना, गोंदर व गुल्लरपुर इत्यादि गांवों में नई पी.एच.सीज़. की स्थापना की गई है। इस प्रकार से हमारी सरकार द्वारा इस प्रकार के काम करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर नये आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। पिछली सरकार के समय में हमारे क्षेत्र में खेलों के लिए एक भी खेल स्टेडियम नहीं बनवाया गया था लेकिन हमारी सरकार ने हमारे क्षेत्र के बस्थली, जाम्बा, माजरा, सीकरी तथा समानाबाहू गांवों में खेल स्टेडियमों का निर्माण करवाया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र का एक बच्चा नवदीप सैनी जिसका पिछले दिनों में वैस्टइंडीज के दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। उसने पहले ही मैच में तीन विकेट लेकर एक रिकॉर्ड बनाया उसके लिए मैं उसको बधाई देता हूं। यह सबकुछ इस पारदर्शी सरकार की वजह से हुआ है कि एक छोटे से कस्बे तरावड़ी का एक मेहनती बच्चा अपनी मेहनत के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम में चुना गया। इस सरकार में ईमानदारी से सभी को बराबर का मौका मिलता है। सरकार की नीतियों के कारण ही यह मौका मिला है। आज सरकार ने हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया है उसी के तहत हमारे क्षेत्र में बहुत से 65–65 फुट के ऐसे कच्चे रास्ते थे जो दबे हुये थे ऐसे लगभग 20 रास्तों को कब्जों से निकाल कर उनको पक्के करने का काम सरकार ने किया है उसके लिए मैं माननीय बी.एण्ड आर. मंत्री जी को बधाई देता हूं। इन रास्तों से आज आम आदमी को बहुत सुविधा हुई है। इसी प्रकार से बहुत सी सड़कें ऐसी थी जो 12 फुट चौड़ी थी जिनको सरकार द्वारा 18 फुट चौड़ा किया गया है जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त हमारे निगधू क्षेत्र में तहसील की एक मांग थी जिसके लिए सरकार द्वारा 4.5 करोड़ रुपये जारी करके तहसील की बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है। वहां पर पानी निकासी की भी बहुत बड़ी समस्या थी जिसको सरकार ने नाला बनाकर दूर किया है। इसी प्रकार से हमारे शहर में अंडरब्रिज की

बहुत पुरानी मांग थी जिसको 8 करोड़ की लागत से सरकार ने बनाया है इससे लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। इसी तरह से शहर के बीच से गुजरने वाले गंदे नाले को कवर करके सरकार ने लोगों को उस नाले से आने वाली बदबू से निजात दिलाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे काम हुये हैं जिससे हमारे क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हुआ है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंत्रीगण का आभार प्रकट करता हूं। हमारे क्षेत्र में बहुत से काम शुरू हो चुके हैं और उन पर काम चल रहा है उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, हमारा क्षेत्र धान का क्षेत्र है तथा ज्यादातर राईस मिलर्स चावल एक्सपोर्ट करते हैं। यहां पर कृषि मंत्री जी बैठे हुये हैं मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले महीने हमारे क्षेत्र के मिलर्स ने लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का चावल ईरान में एक्सपोर्ट किया था लेकिन किन्हीं कारणों से आज तक वह पेमेंट नहीं आई है। आने वाला समय पैडी का सीजन है और अगर उनकी वह पेमेंट नहीं मिली तो इन मिलर्स को बहुत आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर वे वित्तीय तौर पर तंगी का सामना करते रहेंगे तो जब किसान भाई अपनी धान मंडियों में लेकर आयेंगे तो उनको भी पेमेंट में दिक्कत आयेगी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि केन्द्र सरकार में बात करके उन मिलर्स की पेमेंट करवाने की कोशिश कीजिए ताकि किसानों को उनकी धान की पेमेंट में किसी तरह की दिक्कत न आए। इसी प्रकार से हमारे कुछ गांव अंजनथली, डबकथला, सोलो इत्यादि जो निगधू तहसील में लगते हैं जो कि लगभग 25–30 किलोमीटर दूर है लेकिन वे नीलोखेड़ी से 5 किलोमीटर के दायरे में पड़ते हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इन गांवों को निगधू तहसील से निकाल कर नीलोखेड़ी तहसील में जोड़ दिया जाये ताकि लोगों को जो आने–जाने में परेशानी होती है वह दूर हो सके। इससे लोगों का खर्च भी बचेगा और समय भी बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री ललित नागर (तिगांव) : उपाध्यक्ष महोदया, इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी बहुत अच्छी हैं और स्पीकर साहब भी बहुत अच्छे हैं । आप सच में ही बहुत शरीफ हैं और शराफत की मूर्ति हैं । आपने 5 वर्ष तक बहुत अच्छे ढंग से व बहुत

शराफत से सदन को चलाया है लेकिन आप अपनी पार्टी के सदस्यों को भी समझाईए क्योंकि ये इतने अच्छे नहीं हैं । (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, अब से पहले मैं अपने प्रश्न पर बोला था अब ये सदस्य मेरे बोलने पर विरोध क्यों कर रहे हैं ? उस समय मैं अपने प्रश्न पर बोला था । अब मेरा जीरो ओवर पर बोलने का समय है । (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मेरे तिगांव क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिनको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा । हमारे मंत्री कैप्टन साहब भी यहीं पर बैठे हुए हैं । मेरे तिगांव विधान सभा क्षेत्र में 16 गांव ऐसे हैं जो तिगांव गांव से एक–एक, दो–दो व पांच किलोमीटर की दूरी पर हैं जिनकी तहसील तिगांव की बजाय दयालपुर लगा रखी है जबकि दयालपुर उन गांवों से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है और तिगांव उन गांवों से एक किलोमीटर दूर है । जैसे भैंसरावली, बदरौला, बहादुर पुर, मंधावली बुक, अरवा, चांदपुर, कोराली, बदरौला, प्रह्लादपुर, घरोड़ा, खुड़ासन, बेला आदि ये ऐसे गांव हैं जो तिगांव से एक–एक, दो–दो किलोमीटर की दूरी पर हैं लेकिन ये गांव 15 किलोमीटर दूर दयालपुर तहसील में लगा रखे हैं । मैं कैप्टन साहब से कहना चाहूंगा कि इन गांवों को हमारी तिगांव की तहसील में लगा दें क्योंकि उन गांवों का बाजार भी तिगांव ही लगता है और तिगांव इन गांवों से एक किलोमीटर की दूरी पर है । उपाध्यक्ष महोदया, दूसरी जो बिजली की बात है उस संबंध में मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे घरों के ऊपर से 11 हजार वोल्टेज की व और दूसरी लाईनें जा रही हैं जिससे वहां आए दिन कहीं न कहीं दुर्घटना होती रहती है । वहां आए दिन करंट लगने से मृत्यु होती रहती है क्योंकि 11 हजार वोल्टेज पावर की लाईन घरों के ऊपर से जा रही हैं । कहीं–कहीं पर जब घरों की औरतें अपनी छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती हैं तो वह करंट लगने से मर गई, कहीं पर कोई बच्चा छत पर खेलता हुआ करंट लगने से मर गया । कहीं पर कोई मिस्त्री काम करता हुआ करंट लगने से मारा गया ।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : उपाध्यक्ष महोदया, बिजली विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है । इस संबंध में पूरे प्रदेश में निगम ने फैसला लिया है कि लाल डोरा के अन्दर आने वाली एच.टी. या एल.टी. लाइन को शिफ्ट करने के लिए सारा पैसा निगम खर्च करेगा और जो लाइन लाल डोरा से बाहर है उसको शिफ्ट करने के लिए सारा पैसा मालिक या पंचायत खर्च करेगी। यदि माननीय

साथी की एच.टी. या एल.टी. लाइन लाला डोरा के अन्दर आती हैं तो आप उनके बारे में लिख कर दे देना निगम उनको बिना खर्चे के शिफ्ट कर देगी ।

श्री ललित नागर : उपाध्यक्ष महोदया, मैं इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । मंत्री जी, वैसे वहां ज्यादातर लाईन लाल डोरे के अन्दर ही आती हैं । वहां के लोग आपको लिख कर दे देंगे या आप वहां ऑर्डर कर दीजिए । हम एस.डी.ओ. को लिख कर दे देंगे । दूसरा ढाणियों में बहुत सारे ऐसे घर हैं उनको घरेलू बिजली नहीं मिल पा रही है जिसके लिए लोग मारे–मारे फिर रहे हैं ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे साथी ने जो प्रश्न उठाया है उसके जवाब में मैं उनको बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में 59 हजार ढाणियां थी और 11 हजार के करीब बस्तियां थी । उनमें जो पिछली सरकारें थी उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था कि जहां 11 घर होंगे उसको एक ढाणी माना जाएगा लेकिन जब यह बात हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने रखी कि एक किसान के दो बेटे हैं तो वह अपने दो ही घर बनाएगा । वह 11 घर क्यों बनाएगा ? अब हमने यह तय कर दिया कि किसी भी ढाणी में 10 से ज्यादा सदस्य हैं तो हमने उसको ढाणी मान लिया है जिसकी चिट्ठी हमने पूरे प्रदेश में सर्कूलेट कर दी है । अगर किसी ढाणी में 10 व्यक्ति या 10 से ज्यादा हैं तो उसको हम बिजली का कनैक्शन देंगे लेकिन उसके लिए हमने क्राइटेरिया निश्चित किया है कि कोई भी ढाणी गांव के लाल डोरे के एक किलोमीटर तक गांव के चारों तरफ एरिया में है तो वह ढाणी गांव से सप्लाई ले सकती है । इसका प्रावधान भी हमने कानून में तय कर दिया है ।

श्रीमती किरण चौधरी : मंत्री जी, क्या इस 10 की संख्या में बच्चे भी शामिल हैं ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, इस संख्या में बच्चे भी शामिल हैं । इसके लिए राशन कार्ड में सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए जिसमें बच्चे भी शामिल हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री श्याम सिंह राणा : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा भी एक सवाल इसी से संबंधित है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ललित नागरः उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए अलाउ किया है और मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए राणा जी को बिठाकर मुझे बोलने का मौका दिया जाये।(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः राणा जी, अभी आप बैठिए और ललित जी को अपनी बात रखने दे। उनके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं।

श्री श्याम सिंह राणाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके आश्वासन पर अपनी सीट पर बैठता हूँ लेकिन बाद में मुझे बोलने का मौका जरूर दिया जाये।

श्री ललित नागरः उपाध्यक्ष महोदया, हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में अभी तक भी रोड्ज की पूर्णतय कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। इसका कारण यह रहा है कि अनेक जगहों पर किसानों ने रोड्ज पर अनाधिकृत कब्जे कर रखे हैं। इस संबंध में संज्ञान लेते हए माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन रोड्ज पर जितने भी अनाधिकृत कब्जे हैं उन सबको हटाकर रोड्ज की कनेक्टिविटी बेहतर ढंग से की जाये। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद अभी भी कुछ प्रभावशाली लोगों ने रोड्ज पर अनाधिकृत कब्जे किए हुए हैं इसके लिए उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन अनाधिकृत कब्जों पर संज्ञान लेते हुए ग्रेटर फरीदबाद में रोड्ज की बेहतर कनेक्टिविटी की जाये। दूसरा हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर काफी बड़ी तादाद में लोग घर बनाकर रह रहे हैं लेकिन बावजूद इसके उनको बिजली की सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। इसका फायदा बिल्डर्ज उठा रहे है जोकि अपनी मनमर्जी से 27 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली सप्लाई के लिए चार्ज करते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे ग्रेटर फरीदाबाद में सरकार द्वारा बिजली की बेहतर व्यवस्था की जाये ताकि यहां के बाशिंदों को बिल्डर्ज से महंगे दामों पर बिजली न खरीदनी पड़े। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं सदन के माध्यम से उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे हल्के में बहुत से ऐसे स्कूल्ज हैं जहां पर टीचर्ज नहीं हैं। इन स्कूलों में कार्यरत एक–दो टीचर्ज को पांच–छह टीचर्ज का काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि यहां पर टीचर्ज का उचित प्रबंध किया जाये ताकि मेरे हल्के में बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त जैसाकि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हरियाणा के अनेक स्कूलों को अपग्रेड करने का काम किया है ठीक उसी प्रकार मेरे हल्के के भी एक–दो स्कूलों को अपग्रेड करने का काम किया गया है। यह संख्या बहुत कम है अतः मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे हल्के के कुछ और स्कूलों को भी अपग्रेड करने का काम किया जाये। जैसे मेरे हल्के में एक बड़ोली गांव है जिसमें कई हजार बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

बावजूद इसके इस स्कूल को अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है जबकि इसको जल्द से जल्द अपग्रेड करने की बहुत आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे यहां एक छायसा माइनर है जिसमें टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। किसानों द्वारा बार–बार शिकायतें की जाती हैं कि इस माइनर में ज्यादा पानी छोड़ा जाये ताकि इसकी टेल तक पानी पहुंच सके और किसानों की फसलों की सिंचाई हो सके। सरकार द्वारा बार–बार हर माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने की बात की जाती है लेकिन मेरे हल्के में यह बात खरी नहीं उतर रही है। इसलिए मेरा सरकार से अनरोध है कि छायसा माइनर में ज्यादा पानी छोड़कर टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं एक और गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे हल्के में इको ग्रीन नाम की एक कंपनी प्रत्येक घर से 50 रूपये के हिसाब से कूड़ा उठाने का काम करती है। यहां पर लाखों घर हैं यदि 50 रूपये के हिसाब से इन लाखों घरों से ली जाने वाली राशि को देखें तो कूड़ा उठाने की एवज में हर माह इस कंपनी के पास 50 लाख रूपये तक की राशि इकट्ठा हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदया, यह कंपनी मनमाने तरीके से काम करती है और महीने में महज 2–4 दिन ही इस कंपनी के लोग कूड़ा उठाने आते हैं या जिस दिन इनको पैसे लेने होते हैं केवल उसी दिन ही पैसा मांगने आते हैं और लोगों द्वारा कूड़ा न उठाने संबंधी जब विरोध किया जाता है और पैसे देने के लिए मना करते हैं तो यह लोग दादागिरी करने लग जाते है और घर में चाहे इन्हें औरत मिले या आदमी मिले यह जबरदस्ती पैसा मांगने लगते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बात को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह अब मैं राशन डिपो में हो रही घपलेबाजी की समस्या पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आज राशन डिपो के मामले में सबसे बड़ा घपला किया जा रहा है। हमारे यहां के राशन डिपो में 3–3 महीने राशन नहीं बंटता है। इन राशन डिपो में थंब इंप्रेशन कंप्यूटर पर लेकर हर महीने गेहूं और अन्य राशन दे दिया जाता है लेकिन राशन के डिपो होल्डर्ज ने कुछ इस तरह से उपभोक्ताओं के थंब इंप्रेशन कंप्यूटर पर ले रखे हैं कि वे अवैध तरीके से इन थंब इंप्रेशन की स्क्रीनिंग करके यह दिखा देते हैं कि इन्होंने डिपो पर से राशन या गेहूं बांट दिया है जबकि असलियत यह होती है कि 3–4 महीने तक इन डिपो पर राशन ही नहीं बंटता है। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में राशन डिपो के संबंध में एक अनियमितता यह भी देखने को

मिलती है कि यहां पर एक–दो आदमी ऐसे हैं जिन्होंने 20 से लेकर 50 राशन डिपो तक ले रखे हैं और अपनी मोनोपोली चला रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, कितनी अजीब बात है कि कांग्रेस के समय में भी यही आदमी हुआ करते थे और आज भी यही आदमी हैं। पता नहीं ये लोग मंत्रियों से मिले हुए हैं या आफीसर्ज से मिले हुए है। मैं समझता हूँ कि राशन के डिपोज में जो यह इतनी बड़ी गडबड़ हो रही है इसमें सरकार द्वारा सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगह–जगह गऊशालायें खोलकर बहुत अच्छा काम किया है। सरकार का यह विचार बहुत अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा गऊशालायें खोली जाये लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन गऊशालाओं में गायों के लिए पूरा राशन नहीं पहुंच पाता है। कभी हरा चारा नहीं पहुंचता है और कभी पहुंचता भी है तो कड़वा चारा भेज दिया जाता है जिसकी वजह से गाय भूखी रहकर बीमार हो जाती है और मर जाती हैं। उनके लिए न किसी प्रकार की दवाइयों का प्रबन्ध हो रहा है और जब ये मर जाती हैं तो इनको वहीं पर दबा भी दिया जाता है। जिससे वहां और भी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। उपाध्यक्ष महोदया, गउशाला खोलना अच्छी बात है लेकिन उनमें ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने और मेरे कई साथियों ने कई बार यह कहा है कि भले ही सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, चाहे पहले इनैलो की सरकार रही और अब आ जाए, चाहे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और अब आ जाए या फिर अब भाजपा की सरकार रही और अब फिर आ जाए इस बात का हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी विपक्ष के सदस्य होते हैं उन्हें अपने हल्के के विकास के लिए एक ग्रांट दी जानी चाहिए। इस संबंध में चाहे हम महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश या दिल्ली की बात करें उनमें हर सदस्य को ग्रांट के रूप में अपने क्षेत्र के विकास के लिए फंड दिया जाता है। जिस से वह अपने क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों की रिपेयर, बिजली, पानी आदि क्षेत्रों में विकास के काम करवा सके। उपाध्यक्ष महोदया, जो विधायक चुनकर आता है वह उस इलाके का अच्छा व्यक्ति होता है, तभी उस क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर सदन में भेजती है। लेकिन सदन में आने के बाद उसके साथ बर्ताव होता है कि यह विधायक विपक्ष में कांग्रेस पार्टी का है, इनैलो का है या फिर अन्य किसी पार्टी का है तो इनको ग्रांट नहीं दी जानी चाहिए। उनकी विकास के नाम की कोई फाइल भी पास नहीं होनी चाहिए। ऐसा बर्ताव सदन में नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, विधायक तो विधायक ही होता है चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, इसलिए

इस गंभीर बात पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि चाहे आगे किसी भी पार्टी की सरकार बने उसमें विपक्ष के सदस्यों को भी अपने क्षेत्र में विकास के नाम पर ग्रांट मिलनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि भविष्य में सरकार को हर साल 3 करोड़ रुपये से लेकर 6 करोड़ रुपये तक प्रत्येक सदस्य को अपने क्षेत्र के विकास के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, अंत में मैं एक बात और आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि फिजियोथैरेपिस्ट्स चाहते हैं कि हमारी अलग से परिषद् बनाई जाए और इसके लिए वे पिछले 2–3 दिन से आंदोलन भी कर रहे हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनकी भी एक परिषद् बनाई जाए। उपाध्यक्ष महोदया, आपने और अध्यक्ष महोदय ने 5 वर्षों तक सदन को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाय है, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिन्द।

श्री बिक्रम सिंह यादव (कोसली) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहकारिता दिवस पर कोसली हल्के में विकास की जो घोषणाएं की थी, उन सभी घोषणाओं पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ कि जो 2–3 घोषणाओं पर विकास का कार्य धीमी गति से चल रहा है उन घोषणाओं पर तेज गति से काम करवाने के लिए आदेश जारी करें। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, एक कोसली बाई पास के निर्माण का कार्य है, जिसके कारण वहां पर बड़े–बड़े व्हीकल्ज को गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें कुछ पार्ट रेवाड़ी के शहादत नगर का है और कुछ पार्ट झज्जर जिले के धनिया गांव का है। अध्यक्ष महोदय, धनिया गांव के 1–2 किसानों ने जमीन देने में कुछ अड़चनें पैदा कर रखी है। इसमें मेरा माननीय लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री से निवेदन है कि इस मैटर को सुलझा कर काम आरम्भ करवाना चाहिए क्योंकि इसके लिए बजट भी पास हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास भी कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसी कड़ी के साथ कोसली का रेलवे अंडर पास का मामला है। इस अंडर पास को रेलवे विभाग ने हमारे लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग को सौंप दिया है, इसके लिए भी लगभग 6 करोड़ रुपये का बजट पास हो चुका है और शिलान्यास भी हो चुका है

लेकिन काम शुरू होना बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि मेरी इन दोनों मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का मेरे हल्के कोसली के कृष्ण नगर में एक रीजनल सैंटर और जाटूसाना में एक गवर्नमैंट कॉलेज खोलने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा । जाटसाणा गवर्नमैंट कॉलेज में कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं । इसके अलावा मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि कृष्ण नगर में जो रीजनल सैंटर खोला गया है उसे शुरू हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसके भवन का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है जबकि इसके लिए विभाग पैसे भी दे चुका है । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उस भवन का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए । मैं जाटूसाना में गवर्नमैंट कॉलेज खोलने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं । मेरे हल्के कोसली में पहले कुल 4 सरकारी कॉलेज थे जो अब बढ़कर 6 हो गए हैं । जो नये कॉलेज खुले हैं उनमें कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जाटूसाना गवर्नमैंट कॉलेज में स्टाफ की बहुत कमी है । अतः वहां पर स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई समस्या न आए । मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कोसली हल्के के 50 सालों से पैंडिंग पड़े कामों को कम्पलीट करने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इन 5 सालों में मेरे हल्के के कामों को पूरा करके कोसलीवासियों को तोहफे दिए हैं । इसके अलावा मैं मेरे हल्के के गावों की रोड कनैक्टिविटी के विषय में बताना चाहूंगा । मेरे हल्के में 50–55 रोड्स ऐसे हैं जिनका फिलहाल पी.डब्ल्यू.डी. या मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा निर्माण कार्य चल रहा है । इस कार्य के लिए मैं माननीय कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ और माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री नरबीर सिंह का धन्यवाद करता हूं । मेरे हल्के की जिन सड़कों का पिछले दस सालों में रिपेयरिंग का भी काम नहीं हुआ था हमारी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में उन सभी सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया है इसके लिए मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री को पुनः धन्यवाद देता हूं । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे हल्के के भाकली गांव में एक लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। मेरा निवेदन है कि वह घोषणा अभी तक लंबित है । अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय उस कॉलेज

की फिजिबिलिटी चैक करवाकर उसके निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू करवायें । अब मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हरियाणा में 6 नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रोसैस शुरू करवाया है और इनमें से एक नर्सिंग कॉलेज मेरे हल्के के शहादतनगर में भी दिया है । इन कॉलेजिज के टैण्डर्ज कॉल कर लिए गए हैं और आने वाली 16 तारीख को टैण्डर्ज अलॉट करने का प्रोसैस शुरू कर दिया जाएगा । आदरणीय स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं ।

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष जी, श्री फूल सिंह खेड़ी, भूतपूर्व विधायक, हरियाणा विधान सभा की वी.आई.पीज. गैलरी में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं मैं सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों के इस्तीफे की घोषणा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 58 (2) के अंतर्गत सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री दिनेश कौशिक, एम.एल.ए. और श्री रहीश खान, एम.एल.ए. ने सदन से अपने पद से आज त्याग–पत्र दे दिया है जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है ।

सदस्यों द्वारा विभिन्न मांगों को उठाना (पुनरारम्भ)

डॉ. पवन सैनी (लाडवा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आपने पिछले 5 सालों में हरियाणा विधान सभा के सभी सत्रों को इतने बढ़िया ढंग से चलाया है कि पूरे प्रदेश में इस विषय पर आपकी प्रशंसा हो रही है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदन को हमेशा अच्छे ढंग से, अच्छे मन से और स्माइलिंग फेस के साथ चलाया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी की लम्बी आयु की कामना करता हूं। आप बार–बार इस महान् सदन के माननीय सदस्य बनकर इन पदों को सुशोभित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों से हम इस विधान सभा के माननीय सदस्य बने हैं। हमने पहले बहुत सी सरकारों का कार्य देखा है। हमारे हिन्दू धर्म में पित्रों को पिण्ड दान करने के लिए एक स्थान (जिसको 'भूरखी' कहते हैं) बनाया जाता है परन्तु पिछली सरकार ने 10 सालों में वहां पर एक भी ईंट नहीं लगायी। इसमें न तो नींव खोदी जाती है और न ही खिड़की दरवाजे लगते हैं और न ही लैंटर की शटरिंग की आवश्यकता होती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उम्मीदों

13:00 बजे

से बढ़कर काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो भी मांगें रखी गयी हैं फिर उसमें चाहे रैली के दौरान मांग रखी गयी हों, उन सभी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया है। मेरे हल्के के क्षेत्र में देश की तीसरी एन.आई.डी. (नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ डिजाइन) उमरी में बनायी गयी है। पिपली में बी.डी.पी.ओ. ब्लॉक और लाडवा हल्के को सब डिवीजन बनाया गया है। पहले मेरे हल्के में सब डिवीजन नहीं थी परन्तु मेरे हल्के साथ लगते थानेसर, पिहोवा और शाहबाद सब डिवीजन थीं। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में पॉलिटैक्निक कॉलेज बनाया गया है और मेरे जिले के मथाना गांव में 15 करोड़ रुपये की लागत से केन्द्रीय विद्यालय बनाया जा रहा है। मेरे हल्के के बबैन में किसान भाईयों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए माननीय कृषि मंत्री जी के आशीर्वाद से 1.3 करोड़ रुपये की लागत से किसान रेस्ट हाउस बनाया गया है। मेरे हल्के लाडवा में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से सब ट्रॉपिकल फ्रूट सैंटर (बागवानी केन्द्र) बनाया गया है जो हरियाणा राज्य का एक ऐक्सीलैंसी सैंटर बना है। मेरे हल्के लाडवा में एक आदर्श एस.टी.पी. (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगभग 10.50 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इसमें खास बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 154 एकड़ लैंड के लिए अंडर ग्राउंड वॉटर पाइपलाइन डाली गयी है। इस एस.टी.पी. के पानी का यूज फव्वारा विधि (माइक्रो इरीगेशन) सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें न तो बिजली की जरूरत पड़ेगी और न ही ट्यूबवैल चलाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये की लागत से एक ट्रैशरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। इससे सोलर सिस्टम द्वारा पम्प सैट के जरिए खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाये गये विकास कार्यों के लिए धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मेरे लाडवा हल्के के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया जिसको 2031 तक पूरा कर लिया जाएगा। मेरे हल्के लाडवा, पिपली और बबैन की सड़कों को 4 लेन किया गया है। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के के बोहली गांव में एक वेटरनरी पॉलीक्लिनिक कॉलेज बनवाया गया है। बैवन की पी.एच.सी. को अपग्रेड करके सी.एच.सी. बनाया गया है। पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड. आर.) विभाग ने सड़क बनाने में रिकार्ड तोड़ दिया है। किसी भी सड़क में गड्ढे नहीं हैं और बहुत सी नयी सड़के बनायी गयी हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किसी के जन्मदिन के

ऊपर भी महिला विश्वविद्यालय खोलने की घोषणाएं की थी और वे विश्वविद्यालय बन भी रहे हैं। मेरे हल्के में बेटियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है और इसके लिए मैं पिछले 5 सालों से हर सैशन में मांग उठाता रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बेटियों के लिए कॉलेज बनवाने की घोषणा की थी, इसलिए रामशरण माजरा में संबंधित कॉलेज बनवाया जाए। मेरे हल्के लाडवा का बाईपास बनवाने का सर्वे हो चुका है उसको भी जल्दी बनवाया जाए। मेरे हल्के लाडवा की सी.एच.सी. छोटी पड़ गयी है क्योंकि उसमें सिर्फ 30 बैड की ही कैपेसिटी है। इसकी 30 बैड की कैपेसिटी को बढ़ाकर 100 बैड किया जाए। मेरे हल्के लाडवा में आलू–टमाटर की खेती होती है इसलिए वहां पर फार्मा इन्डस्ट्री के नाते से कोई प्रोसैसिंग यूनिट बनायी जाए। मेरे हल्के के मथाना गांव में बिजली की सब डिवीजन बनायी जाए। भादसौं में एक शुगर मिल है और मेरे हल्के के लाडवा रोड और इन्द्री रोड के बीच में जो गांव आते हैं, उनकी शुगर मिल भादसौं में पड़ती हैं। मेरे बड़े भाई माननीय मंत्री श्री करण देव कम्बोज जी भी बैठे हैं और इनका हल्का भी इन्द्री है। हमारे हल्कों के किसान भाईयों की लगभग 50 करोड़ रुपये की पेमेंट बकाया है। संबंधित किसान पेमेंट के लिए इन्तजार कर रहे हैं परन्तु गन्ने की पेमेंट एक साल के बाद की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि संबंधित किसानों को उनके गन्ने की पेमेंट जल्दी दिलवायी जाए। इसके अतिरिक्त बिजली विभाग में 10–15 साल से जो कर्मचारी डी.सी. रेट पर लगे हुए हैं उनको पक्का करने के बारे में भी विचार किया जाए। कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत कर्मचारी अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए मुझसे कई बार मिल चुके हैं, उनकी मांगे भी पूरी की जाएं। पुलिस विभाग में गुरूग्राम रेंज के कर्मचारियों की प्रमोशन जल्दी हो जाती है परन्तु अंबाला रेंज के कर्मचारियों की प्रमोशन जल्दी नहीं होती। मान लीजिए कोई जवान कांस्टेबल भर्ती होता है और वह गुरूग्राम रेंज में ज्वॉईन करता है तो वह जल्दी–जल्दी प्रमोशन पाकर सब इन्सपेक्टर के पद पर पहुंच जाता है परन्तु उसी दिन अंबाला रेंज में ज्वॉईन करने वाला कर्मचारी हैड कांस्टेबल के पद पर ही रह जाता है। इसलिए सभी की प्रमोशन बराबर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के के गांवों के स्कूल्ज अपग्रेड किये जाएं जिसमें कोलापुर, संगोर, गनगोर, खेड़ी–दबदलान और शीतल गांवों के स्कूल्ज शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में भी कहना चाहूंगा। हमने गुजरात मॉडल के बारे में सुना है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में माननीय

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इस प्रकार की योजना चलाई है कि इस देश के सारे प्रदेश उस मॉडल को फॉलो–अप कर रहे हैं, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो या फिर चाहे किसी पद पर छात्रों की भर्ती की बात हो। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में जेल वार्डर को उस ट्रांसफर पॉलिसी से बाहर किया जाये, क्योंकि वे बेघर हो रहे है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ समय पहले हमारे प्रदेश में बी.पी. एल. का सर्वे हुआ था और हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत से परिवार हैं, जो इकनॉमिकली बैकवर्ड हैं, लेकिन वे बी.पी.एल. में नहीं आते हैं, उन परिवारों के किसी सदस्य की किडनी खराब हो जाती है या किसी के लिवर की ट्रांसप्लांटेशन करनी होती है, इसलिए ऐसे परिवारों को भी आर्थिक आधार पर आयुष्मान भारत योजना में जोड़ने का काम किया जाये। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री श्री राव नरबीर सिंह जी से कहना चाहूंगा कि हमारे बबैन गांव के अंदर एक पी.डब्ल्यू. डी. रेस्ट हाउस बनवाने का काम करें और इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लाडवा और बबैन के अंदर किसानों की बहुत संगोष्ठी होती हैं इसलिए वहां पर उनके लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्षः असीम गोयल जी, आप अपनी बात शुरू करें।

श्री असीम गोयल (अंबाला शहर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की मांगों के ऊपर नहीं बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और उपाध्यक्ष महोदया का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संयम और सूझ–बूझ के साथ इस सत्र को चलाया है। इस सदन में हमारे कई नये माननीय सदस्य चुनकर आये थे। अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी पार्टी के नये माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझा कि हम सभी माननीय सदस्य अपने हल्के में किस प्रकार से विकास के कार्य करवाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सभी विकास कार्यों को गति मिली है, जिसके कारण आज हरियाणा के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अंदर विकास की एक नई इबारत लिखी गई है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि कल का दिन देश के लिए एक पूर्ण आजादी का दिन था, क्योंकि कल के दिन जम्मू एवं कश्मीर से धारा

370 हटाई गई है। हमारे हरियाणा प्रदेश में भी एक धारा–370 लगी हुई थी, लेकिन वह क्षेत्रवाद और भाई–भतीजावाद की धारा–370 लगी हुई थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अपनी ''हरियाणा एक–हरियाणवी एक'' की नीति का अनुसरण करते हुये, उस उपरोक्त धारा–370 को जो हरियाणा प्रदेश के विकास में अवरोधक थी, उसको हटाने का काम किया। आज इस सदन के अंतिम सत्र का अंतिम दिन है, इसलिए मैं अपनी तथा अपने विधान सभा क्षेत्र के सभी लोगों की भावनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रिपरिषद के सभी सम्मानित मंत्रीगण के सामने रखना चाहूंगा, जिन्होंने बड़ी अनुकम्पा करके मेरे विधान सभा क्षेत्र में सभी जो विकास के कार्य हैं, चाहे अर्बन क्षेत्र की बात हो या चाहे रूरल क्षेत्र की बात हो, उनको गति देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बी.एस.पी. के बारे में कहना चाहूंगा, मेरा आशय बहुजन समाज पार्टी से नहीं, बल्कि बिजली, सड़क और पानी से है। हमारे प्रदेश में बी.एस.पी. एक ऐसा फैक्टर था, जिसके नाते प्रदेश में चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन तीन चीजों का ऐसा तोड़ निकाला कि कोई भी विधायक यह नहीं कह सकता है कि उनके विधान सभा क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लगभग आधे से ज्यादा हरियाणा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 के 24 घंटे बिजली देने का काम किया। जहां तक सड़कों की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में सड़कों का एक नया जाल बिछवाया है। हमारे माननीय मंत्री श्रीमती कविता जैन जी और श्री राव नरबीर सिंह जी की अनुकम्पा से हमारे अम्बाला जिले के शहरी विधान सभा क्षेत्र में मुझे नहीं लगता है कि हमारी कोई भी सड़क ऐसी बची होगी, जिसके ऊपर अच्छे तरीके से काम न किया गया हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बस स्टैंड का बहुत ही दिनों से एक लम्बित मामला था, हमारे पूर्व की सरकार के विधायक कहते थे कि मुख्यमंत्री जी मेरी जेब में हैं और जो 10 साल तक सुपर सी.एम. के नाते पूरे हरियाणा में प्रचलित रहे। वे इस बस स्टैंड की जमीन को हड़पना चाहते थे और कहीं दूर जाकर 84 कैनाल उन्होंने एक्वायर भी करा दी, लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और आदरणीय कृष्ण लाल पंवार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने न केवल उस जमीन को कायम रखा, बल्कि एक अभूतपूर्व बस स्टैंड बनाने का भी काम किया है, जहां से इसी 31 अगस्त, 2019 से बसें निकलनी शुरू हो जायेंगी। इसके साथ ही साथ अम्बाला शहर में सिविल हॉस्पिटल के लिए एक आधुनिक बिल्डिंग बन रही है

और इसके साथ ही साथ नन्यौला में पी.एच.सी. और चौड़मस्तपुर में सी.एच.सी. बन रही है, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय श्री अनिल विज जी का धन्यवाद करता हूं। अम्बाला शहर भगवान विष्णु के पांचवें अवतार (वामन अवतार) की अवतारस्थली है और आदरणीय अध्यक्ष महोदय आप खुद उस मेले में एक बार गये थे। वहां पर तीन दिन का मेला होता था और वहां पर एक तालाब बना हुआ था। केवल तीन दिन के मेले के लिए उस तालाब की सफाई की जाती थी और उस तालाब की सफाई में 3 दिन लगते थे। पहले उस तालाब में 365 में से 355 दिन लोग गंदगी गिराने का काम करते थे, उसके बाद जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी दी गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरन्त करोड़ों रुपये की लागत से उस तालाब का मॉडल पास कर दिया और आने वाले समय में उसको एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है, जो अगले साल तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके अलावा हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से दूसरा ''तारा मंडल'' बनाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों ने वर्ष 1969 में एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैं उसके बारे में इस महान सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि पंजाब प्रांत के जो माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह जी हैं, उनके दादा महाराजा भूपेन्द्र सिंह जी लखनौर साहब गये थे जोकि दसवें गुरू गोबिंद सिंह जी महाराज का ननिहाल स्थल है। उन्होंने वहां पर वर्ष 1969 में माता गुजरी कौर जी के नाम से एक कॉलेज बनाने के लिए पत्थर लगाया था और वहां पर पत्थर के अलावा कुछ भी काम नहीं हुआ था। मैं धन्यवादी हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में 37 करोड़ रुपये की लागत से दूसरा सरकारी बी.एड. कॉलेज माता गुजरी कौर जी के नाम से बनाने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष : असीम जी, आप जल्दी से जल्दी वाइंड–अप कीजिए।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज बहुत सी बातें इस महान सदन की जानकारी के लिए बतानी है परन्तु मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि कल इस देश के उच्च सदन में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए धारा 370 को हटाने का काम किया गया लेकिन विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण धारा 370 को हटने से एक मत नहीं दिखे। इन्होंने इस महान सदन के लगभग 45 मिनट इसी शोर शराबे में गुल कर दिए कि इस धारा 370 के संकल्प की एक कॉपी सदन की टेबल पर रखी जाये। अध्यक्ष

महोदय, कल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को तो ''भारत माता'' की जय बोलने में भी तकलीफ हो रही थी लेकिन मैं

इसी विषय के संबंध में एक बात और बताना चाहता हूं कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के सुपुत्र श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने एक बयान दिया कि 21वीं सदी में धारा 370 का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि क्या वे अपनी इस गलती को रियलाईज करेंगे? कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता श्री जनार्दन द्विवेदी जी ने कहा कि इतिहास में की गई बड़ी गलती आज सुधार ली गई है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर कालिता जी ने कहा कि सदन में धारा 370 हटाए जाने का विरोध नहीं कर सका इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से और चीफ व्हिप से इस्तीफा दे रहा हूं। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी आत्महत्या की ओर आगे बढ़ रही है और मुझे मेरी आत्मा ने कहा कि अब देश बदल रहा है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट के माननीय मंत्री जी और सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को सिर्फ इतनी ही कहना चाहूंगा कि हमें यहां पर परमपिता परमात्मा ने 5 साल प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका दिया था और हमने अपनी तरफ से प्रदेश की जनता की सेवा करने में भरसक प्रयत्न भी किए हैं। मैंने इस महान सदन में और भी कई बातें कहनी थी परन्तु कुछ बातें रह गई हैं इसलिए मैं यह कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि–

''जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है,
जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है।
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन,
अभी नापना पूरा आसमान बाकी है''।

धन्यवाद। जय हिन्द। जय हरियाणा।

पंजाब विधान सभा के सदस्यों का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब के दो माननीय विधायक श्री बुधराम, विधायक, बुढलाडा और गुरमीत सिंह मीत, विधायक, बरनाला हरियाणा विधान सभा की वी.आई.पीज. गैलरी में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं। मैं पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

सदस्यों द्वारा विभिन्न मांगों को उठाना (पुनरारंभ)

श्री मूल चन्द शर्मा (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधान सभा में वर्ष 2014 में चुनकर आया था और मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां भारत के लगभग सभी लोग रहते हैं। 5 वर्ष पहले बल्लभगढ़ विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था और इस विधान सभा क्षेत्र के अंडर 80 कालोनी, 8 सैक्टर, स्लम के 25 बूथ और 3 गांव आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में विकास का कहीं कोई अता पता नहीं था कि विकास भी किसी चिड़िया का नाम होता है क्योंकि वहां पर न तो सीवर थे, न ही कोई समुदायिक भवन थे, न ही पीने के लिए पानी की व्यवस्था थी और न ही वहां पर अच्छी सड़कें थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और बहन कविता जैन जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इसे निगम बनाने का काम किया। वर्तमान सरकार के समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 125 किलोमीटर आर.एम.सी. रोड भी बनाई है और 100 किलोमीटर की सीवर लाईन भी बिछाने का काम किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय नरबीर सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे क्षेत्र में 10 किलोमीटर आर.एम. सी. रोड बनाने का काम किया। श्रीमती कविता जैन जी ने 3 करोड़ रुपये की लागत से 11 सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण करवाया इसलिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं था वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 14 जनवरी, 2015 को 100 करोड़ रुपये की ग्रांट देकर बल्लभगढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की शुरूआत की इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ और पलवल दो तहसीलें ऐसी थी जो हरियाणा के मानचित्र पर विशेष स्थान रखती थी। स्पीकर सर, माननीय मंत्री राव नरबीर सिंह जी मुझे बार–बार यह बात कहते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में फरीदाबाद के लोगों द्वारा गुरूग्राम से विकास के नाम पर लिये गये 100 करोड़ रुपये अभी तक वापिस नहीं किये। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में फरीदाबाद के विकास के लिए गुरूग्राम से उधार मांगा जाता था या यह कह लीजिए कि भीख मांगी जाती थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय में ही सूरजकुण्ड की लाखों एकड़ जमीन जिसकी कीमत करोड़ों रूपये थी उसको विकास के नाम पर कोड़ियों के

भाव बेच दिया गया। अगर उस समय फरीदाबाद के विकास पर नज़्र डाली जाये तो यह पता चलता है कि फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। यहां पर भाई ललित नागर जी बड़े जोर–शोर से चिल्ला रहे थे कि हमारी सरकार द्वारा उनके हल्के में विकास के काम नहीं करवाये जा रहे हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री ललित नागर जी को यह बताना चाहता हूं कि काम करने वाली सरकारों के लिए न कभी काम खत्म हुआ है और न ही आने वाले समय में कभी काम खत्म होगा। हमारी सरकार के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तिगांव हल्के में मेरे हल्के बल्लभगढ़ के बराबर ही काम करवाये गये हैं। इतना ही नहीं हमारी सरकार द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के एक समान काम करवाये जा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण यह है कि भाई ललित नागर के विधान सभा क्षेत्र में गुड़गांव व आगरा कैनाल पर 30 फ्लाई ओवर्स का निर्माण हमारी सरकार द्वारा करवाया गया है। फरीदाबाद जिले में अमरूत योजना का 80 परसैंट पैसा तिगांव विधान सभा क्षेत्र में लग रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी चार फ्लाई ओवर्स का निर्माण हुआ है। प्रदेश के लोग विकास चाहते हैं। प्रदेश के लोगों की यह इच्छा है कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करवायें और अपने विधान सभा क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास करवायें। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र बल्लभगढ़ की समस्त जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, भाई नरबीर जी और बहन कविता जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक से बढ़कर एक रिकार्ड तोड़ विकास के कार्य करवाये हैं। मेरे विधान सभा हल्के में एक ही कॉलेज था। हमारी सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक और नये कॉलेज की स्थापना करके मेरे पूरे क्षेत्र की जनता को अनुगृहीत किया है। इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा दो विद्यालयों की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। हमारी सरकार के आने से पहले बल्लभगढ़ शहर में सफाई का भी बहुत ही बुरा हाल था लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमारा बल्लभगढ़ पूरी तरह से चमक रहा है। हमारी सरकार द्वारा बल्लभगढ़ में 20 हजार पेड़ों की रोपाई करके बल्लभगढ़ की ग्रीन बैल्ट को बढ़ाया गया है। सभी स्लम कालोनीज़ में सीवरेज की व्यवस्था की गई है जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रही है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहूंगा कि मेरे शहर में पानी

की सप्लाई की शुरूआत तो हुई है लेकिन अभी वह अपर्याप्त है क्योंकि हमारा शहर बहुत ही बड़ा है इसलिए मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि शहर में पानी की कमी को दूर करने के लिए यमुना नदी से प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा बढ़ाई जाये। मेरे हल्के के सारे के सारे बड़े रोड्ज के निर्माण के कार्य कम्पलीट हो चुके हैं। मेरा ऑनरेबल लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर बहन कविता जी से अनुरोध है कि उन्होंने बल्लभगढ़ के लिए सीवरेज की सफाई के लिए चार मशीनें बल्लभगढ़ को दी लेकिन बिना सीवरमैन के ये सभी मशीनें ऐसी ही खड़ी हैं इसलिए उनको चलाने के लिए सीवरमैन की जल्दी से जल्दी नियुक्ति की जाये। स्पीकर सर, जिस प्रकार से एक बड़े ही सुन्दर, सुव्यवस्थित और अनुशासित तरीके से पांच सालों के दौरान आपने विधान सभा की कार्यवाही का संचालन किया है उसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। पहले तो ऐसा होता था कि विपक्षी पार्टियों के सदस्यों को यहां पर बोलने ही नहीं दिया जाता था और जब कोई सदस्य बोलता था तो उसको मार्शल की मदद से बाहर निकाल दिया जाता था। इन पांच वर्षों के दौरान सभी 90 माननीय सदस्यों को बोलने का समान अवसर दिया गया। स्पीकर सर, विधान सभा अध्यक्ष के रूप में आपका कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है इसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाये वह कम होगी। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री और अपनी पूरी की पूरी केन्द्र सरकार को जम्मू–कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री महिपाल ढांडा (पानीपत ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, हम लोग एक ऐसी विचारधारा से निकले हुए लोग हैं जिन्होंने इस देश के हित में अपनी कुर्बानियां दी हैं। हमने लम्बी–लम्बी लड़ाइयां लड़ी हैं और लम्बी लड़ाइयां लड़ते–लड़ते आज वे धीरे–धीरे सकारात्मक रूप ले रही हैं तथा वे सार्थक भी हो रही हैं। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि धारा 370 हटनी चाहिए वह अब हटी है। उसके लिए वर्षों तक हमने संघर्ष किया और उस संघर्ष का नतीजा और संघर्ष करने वाले हमारे साथी हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे अग्रणी रहे यह उनकी जीत है। यह एक बहुत बड़ा काम हमारी विचाराधारा के ऐसे एक सिपाही ने करके दिखाया जिससे पूरे हिन्दुस्तान को उम्मीद थी। कोई भी देश हित का काम हो उन्होंने कभी अपने स्वार्थ की चिन्ता नहीं की। मैं अभी बैठे–बैठे सोच रहा था कि क्या बोलूं तो मुझे दो–तीन

व्यक्ति याद आये जिनमें एक श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे। आडवाणी जी एक बार हमारे पानीपत में आये थे। उन्होंने कहा कि अगर इस देश का भला चाहते हो तो हिन्दुस्तान में से जितने भी क्षेत्रीय दल हैं इन सबका सूपड़ा साफ कर दो। कब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बोला था कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए और आज जा कर हमें धारा 370 से मुक्ति मिली है। इसी प्रकार से कब आडवाणी जी ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों का सूपड़ा साफ कीजिए और आज जाकर हमें काफी हद तक क्षेत्रीय दलों से मुक्ति मिली है। इसी प्रकार से तीसरा नारा आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने दिया कि इस देश में सब समस्याओं की जड़ कांग्रेस है इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत बनाना हमारा काम है। उन्होंने कब बोला था और सिर्फ 5 साल में हमने भारत को कांग्रेस मुक्त कर दिया है जो कि हमारी पार्टी की विचारधारा की सबसे बड़ी जीत है। कुछ लोग हमारी पार्टी की विचारधारा पर बिना वजह ही अंगुली उठा देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इधर–उधर की बातें करने की बजाय अपने विधान सभा क्षेत्र की बात उठानी चाहिएं। उनकी कोई मांग हो तो वह भी उठा सकते हैं लेकिन इस प्रकार की बातें इस महान सदन में करने का कोई औचित्य नहीं है। इस तरह से तो और सदस्यों को बोलने के लिए समय ही नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आपकी पार्टी के भी सभी सदस्यों को बोलने के लिए समय मिलेगा।

श्री महिपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पिछली सरकार में हरियाणा में गदर मचा हुआ था। आज कांग्रेस का जो भी सदस्य बोलने के लिए खड़ा होता है तो जो काम हमारी सरकार ने किया हो उसी पर अंगुली रखने का काम का काम करते हैं कि यह काम हमारी सरकार के समय में हुआ था। कुछ लोग 10–10 साल सरकारों में रहे लेकिन वे अपने काम नहीं करवा पाए। पहले तो वे नारे लगाते थे कि नम्बर वन हरियाणा लेकिन आज वे जब हाउस में बोल रहे थे तो वे कह रहे थे कि मेरे हल्के की गलियां नहीं बनी, पशु हॉस्पिटल नहीं बना, चौपाल नहीं बनी तथा मेरे हल्के में पानी नहीं पहुंचा। इस प्रकार की सभी मांगें यहां हाउस में उठा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, अदभुत बात देखिये कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबका–साथ, सबका–विकास की अवधारणा पर चलते हुये हर काम को पूरा किया है। इसी का नतीजा है कि हरियाणा में पहली बार लोगों ने अपने आप कहा कि बिना किसी

विरोध के मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यह भी एक अदभुत सुगबुगाहट लोगों के अन्दर से आ रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जो क्रांतिकारी सोच है उसका नतीजा है कि लोग कह रहे हैं कि इस बार आप 85 पार सीटें जीत रहे हैं। अगर किसी को इस बात से कोई जलन होती है, किसी का नम्बर कटता है नहीं कटता है वह एक अलग बात है मगर लोगों की जो भावना है वह यह है कि पहली बार हरियाणा प्रदेश में भी और हिन्दुस्तान में भी एक ईमानदार सरकार बनी है। ईमानदारी से भी काम किया जा सकता है और मनोहर लाल जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। इसी बात को लेकर लोगों में जो संतोष है और उस संतोष का नतीजा अक्तूबर में फिर से हम सब लोगों के सामने आने वाला है। आपने 5 साल कितनी स्पष्टता से कितनी ईमानदारी से सबको समय देते हुये जो सदन चलाया उसके लिए हम आपके बहुत–बहुत आभारी हैं। आपने बिना पक्षपात के जो काम किया है वह वाकई काबिले तारीफ है। पहले जो लोग अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते थे उन्होंने किस तरह का काम किया था उसके बारे में तो लोग बोलते ही हैं लेकिन आपने जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत–बहुत आभारी हूं कि उन्होंने जो काम किये हैं उनके बारे में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसीलिए आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से अभिनन्दन करता हूं कि हमारे हरियाणा विधान सभा के हर सदस्य को नर्क से बाहर निकाल कर शानदार जिन्दगी के रास्ते पर बढ़ने का मौका दिया है। मैं उनका बार–बार आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डॉ. कमल गुप्ता (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, इस 14 वीं विधान सभा के अन्तिम सत्र के अन्तिम दिन में और अन्तिम घण्टे में आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । इस संसार में वेद भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं और संत मुनि भी कहते हैं । सभी लोग ये कहते हैं कि आवागमन सृष्टि का नियम है । जो प्राणी इस संसार में आया है उसका जाना निश्चित है । संत कबीर जी ने भी कहा है कि–

आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर।(विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं डॉ. साहब की बात पर कहना चाहता हूं कि कोई नहीं जाएगा । 14 वीं विधान सभा में सभी आएंगे । आप भगवान से प्रार्थना कीजिए क्योंकि ये विदाई के क्षण वैसे ही बहुत खराब होते हैं ।

मैं माननीय कमल गुप्ता जी से कह रहा हूं कि हम सभी साथी अक्टूबर में दोबारा फिर आ रहे हैं । इसलिए आप कबीर जी को कोट मत कीजिए । यह आवागमन विधान सभा का आवागमन है ।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, संत कबीरदास जी ने कहा है कि –

"आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिहांसन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर ।"

सवाल ये है कि ठीक उसी तरह विधान सभा में भी जो आएंगे विधान समाप्त होने पर सभी जाएंगे लेकिन इस जनता ने देखा है कि इस पांच साल में किसने क्या–क्या किया है । अबकी बार जनता ने 47 विधायक बनाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष दिया है। जनता ने ही विपक्ष को 19 सीटें देकर विपक्ष दिया और विपक्ष का नेता बनाया और एक दूसरा विपक्ष भी दिया । अब इन पांच सालों में सत्ता पक्ष ने क्या काम किए और उनका क्या रिजल्ट आया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है । जनता ने कामों के बदले पहले पांचों मेयर जिताए क्योंकि जनता ने सत्ता पक्ष के काम देखे । अब मैं वह काम गिनाउंगा तो बहुत समय लग जाएगा । वह काम अनेक थे, चाहे वह भर्तियां हों, चाहे वह ट्रांसफर हों, चाहे वह ई–टैंडरिंग हो, कोई भी काम हो फिर उसके बाद जीन्द विधान सभा का चुनाव आया जीन्द में भी जनता ने सत्ता पक्ष को जिता कर मोहर लगाई । उसके बाद लोक सभा के चुनाव आए उसमें भी जनता ने सारी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर भारतीय जनता पार्टी के कामों पर मोहर लगाई । अब दूसरी तरफ विपक्ष से तो अपनी विपक्ष की सीट भी नहीं संभली ।

श्रीमती शकुन्तला खटक : स्पीकर सर, क्या यह एजेंडा चल रहा है ? यह स्पीच हाऊस नहीं है ।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जब हम पहली बार चुनकर आए थे तो हमने विधान सभा में जो देखा उनमें कुछ चीजें बड़ी शर्मनाक थी । यहां विधान सभा में जूते चले । एक–दूसरे सदस्य को गाली दी गई । इन सभी चीजों को देखकर हमें आगे के लिए एक सीख लेनी चाहिए क्योंकि आगे भी विधान सभाएं आएंगी उनमें जो नये विधायक आएंगे उनके लिए सीनियर लोगों ने एक उदाहरण देना चाहिए । आज जब कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने का मौका मिला है तो उनका विपक्ष का नेता बनने के लिए झगड़ा हो रहा है । ये आपस में फैसला नहीं कर पा रहे हैं । जनता यह सभी चीजें देख रही है ।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी को अपनी पार्टी की उन हरकतों को भी याद कर लेना चाहिए जब भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों ने अपने इसी मुख्यमंत्री के खिलाफ षडयंत्र करके पद से हटाने की कोशिश की थी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, किरण जी सबसे ज्यादा बोलती हैं। नया विधायक बोलने के लिए दो मिनट क्या खड़ा हो गया इनके लिए यह चीज बर्दाश्त से बाहर हो गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी को कुछ कहने से पहले अपने पार्टी के कारनामों को भी ध्यान में रखना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हम पिछले लगभग पांच साल से किरन जी को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। हमने तो कभी इनको बीच में नहीं टोका। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बात कहने की होगी तो उसे मैं कहकर रहूंगी। मुझे मेरी बात रखने से कोई नहीं रोक सकता। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इन कांग्रेस के लोगों में कोई यूनिटी नहीं है और न ही अब इन पर कोई कंट्रोल रहा है। (शोर एवं व्यवधान) मैं दो मिनट के लिए बोलने के लिए क्या खड़ा हो गया किरण जी को मेरे बोलने से तकलीफ होने लगी। (शोर एवं व्यवधान) दो मिनट के लिए कोई विधायक बोलने के लिए क्या खड़ा होता है इनको उसी समय तकलीफ होने लगती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, अगर कोई गलत बात कहेगा तो उसको सुननी भी पड़ेगी। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। क्या समझ रखा है इन लोगों ने? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, किरण जी बड़ी भागी–भागी फिर रही थी कि इनको विपक्ष का नेता बनाया जाये। (शोर एवं व्यवधान) जो व्यक्ति किसी नये विधायक की बात दो मिनट के लिए भी सुनने को तैयार नहीं है वह किस प्रकार से विपक्ष के नेता का हकदार हो सकता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप तो सदन की एक बहुत ही अनुभवी सदस्या हो। एक नया विधायक कुछ कहना चाहता है तो एक बार उनको अपनी बात रख लेने दे। उनके बाद आप अपनी बात रख लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं किसी को बोलने से नहीं रोक रही हूँ लेकिन अगर कोई सदस्य गलत बात कहेगा तो फिर उसको सुननी पड़ेगी।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, अब बात खत्म हो गई है अब आप प्लीज बैठिए। गुप्ता जी अब आप अपनी बात रखें।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिन्हें देखकर हरियाणा प्रदेश की जनता आने वाले विधान सभा चुनावों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर मुहर लगाने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा और वह यह है कि आपने जिस दरियादिली के साथ इस सदन को चलाने का काम किया है वह वास्तव में एक सराहनीय कार्य है यही नहीं हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी ने पक्ष और विपक्ष के प्रति जो दरियादिली दिखाई है उसकी भी मैं प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। इसके बाद मैं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने लगातार पांच साल हरियाणा प्रदेश के लिए ओजस्वी बजट देने का काम किया और बड़ी ही दरियादिली के साथ सभी क्षेत्रों में बराबर नज़र रखते हुए फिस्कल डैफिसिट कंट्रोल में रखा वह भी बहुत ही सराहनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा): स्पीकर सर, आज का दिन वास्तव में आभार जताने व बधाई देने का दिन है। मैं समझता हूँ कि आज हमारे इस सत्र के आखिरी क्षणों में बहुत ज्यादा उलाहने देने का वातावरण नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 वर्षों तक सबने अपने–अपने क्षेत्रों में प्रयास किए, सबने काम किए और जिनकी बदोलत बहुत बड़े–बड़े कामों को किया गया। इन कामों की चर्चा सदन के सीमित समय में होना मुझे लगता है संभव नहीं है। स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से पांच वर्षों तक लगातार ईमानदारी से सरकार को चलाया, प्रदेश का विकास किया, प्रदेश को एक पारदर्शी शासन देने का काम करते हुए व्यवस्था को मजबूत बनाया, वह निःसंदेह एक सराहनीय कार्य है। हरियाणा प्रदेश में मैरिट के आधार पर नौकरियां देकर

उन्होंने हरियाणा प्रदेश में एक नई शुरूआत की है और इस शुरूआत को प्रदेश के सभी समाजों की तरफ से सराहना भी मिली है। स्पीकर सर, परीक्षा की घड़ी आने वाली है। इस परीक्षा का सेमीफाइनल हो चुका है और फाइनल मैच दो महीने में होने वाला है। इस फाइनल मैच में मूल्यांकन जनता ने करना है और निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों पर अपनी मुहर लगाने का काम करेगी। स्पीकर सर, आज मैं सदन के माध्यम से आपको भी बधाई देना चाहूंगा। आपने जिस सुचारू ढंग से लगातार पांच साल सदन के सत्र को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चलाने का काम किया है वह वास्तव में काबिले गौर है। स्पीकर सर, हम पहली बार विधायक बनकर इस सदन में आये थे। हमें सदन में बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। हल्की फुल्की नोक–झोंक से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सदन में बहुत सारी सार्थक और गम्भीर चचायें भी हमने सुनी और जटिल परिस्थितियों में शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा जी ने जिस तरह से सदन के गम्भीर माहौल को खुशनुमा माहौल बनाने का काम किया उसकी भी मैं सराहना किए बिना नहीं रह सकता। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त कल जो एक एतिहासिक फैसला पूरे देश के लिए हुआ जिससे न केवल कश्मीर बल्कि पूरे भारत वर्ष में एक नए बदलाव की बयार बहेगी अर्थात धारा 370 का हटाना, उसके लिए भी मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। स्पीकर सर, धारा 370 हटाना यह न केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, न केवल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था अपितु यह पूरे देशवासियों की एक सोच भी थी और यही कारण है कि धारा 370 को हटाने की कार्रवाई का पूरे देश ने स्वागत करने का काम किया है। स्पीकर सर, मैं आज इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे घरोंडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जोकि एक अति पिछड़े विधान सभा क्षेत्र की सूची में शामिल हुआ करता था, में इन पांच वर्षों के दौरान इतने ज्यादा काम किए कि जिन्हें देखकर निश्चित रूप से आज यहां के लोगों के अंदर खुशी व संतोष का वातावरण व्याप्त है। इन पांच सालों में यह पहली बार हुआ है जबकि किसी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के बारे में बहुत गम्भीरता से सोचा है और उनके लिए काम किया है। मैं आज अपनी बात समाप्त करने से पहले सदन के सभी सदस्यों को भी शुभकामनायें देना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शुभकामनायें इसलिए देना चाहूंगा कि उन्होंने 5 वर्षों तक प्रदेश के अन्दर एक नयापन लाने तथा राजनीति के नये आयाम स्थापित करने का काम किया है। मुझे

आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5 वर्षों में भी वे इसी तरीके से प्रदेश को नई उंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के बारे में जो उनका सपना है वह सपना हर हाल में पूरा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगल प्लान में न केवल हरियाणा के विकास और व्यवस्था पर अपितु पर्यावरण और जलसंरक्षण पर भी बहुत ज्यादा काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

सरदार बख्शीश सिंह विर्क (असन्ध) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे पता है कि समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कम शब्दों में ही अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में जितने भी विकास के काम पिछले 58 महीने में हुए हैं, उनकी सराहना जितनी भी कर लो उतनी ही थोड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे बड़ा और मुख्य काम गुरू गोविन्द सिंह जी का प्रकाशोत्सव पर्व मनाना, गुरू नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव मनाने का ऐतिहासिक फैसला लेना, गीता जयंती मनाना, रविदास जयंती मनाना और डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाना हरियाणा सरकार के सबसे बढ़िया प्रशंसनीय कार्य रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी पिछले 58 महीनों में विकास के कार्य हुए हैं उन सब की प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने इतने ज्यादा विकास के काम किए हैं, जिन्हें गिनना मुश्किल है। मैं एक ही बात सदन में कहता हूँ–

'नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला।'

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिन्द।

श्री सुभाष सुधा (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब पहले गीता जयंती महोत्सव कुरूक्षेत्र में मनाया जाता था तो प्रशासनिक स्तर पर केवल 5–10 हजार लोग ही शामिल हुआ करते थे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने का काम किया है और उसमें देश के कोने–कोने से लगभग 40 लाख लोग शामिल होते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से पहले कुरूक्षेत्र में दूर–दराज से टूरिस्ट्स आते थे तो उनको

धर्मक्षेत्र में 4–4 फीट के गड्ढे सड़कों पर मिलते थे। आज लगभग सभी रोड्स 6 लेन और 4 लेन के बने हुए हैं। इसके लिए मैं माननीय लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री का धन्यवाद करता हूँ। हमारे कुरूक्षेत्र में कोई भी राजकीय कॉलेज नहीं था, जिसके कारण हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए करनाल, पानीपत आदि शहरों में जाना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 16 एकड़ में पहला राजकीय कॉलेज खोला, इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूँ। कुरूक्षेत्र में केवल कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय ही हुआ करता था लेकिन अब हमारे कुरूक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय भी खोला गया है, इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुरूक्षेत्र को बहुत बड़ी सौगातें दी हैं। कुरूक्षेत्र में 5 रेलवे फाटकों पर एलीवेटिड पाथ के लिए रेलवे विभाग 100 करोड़ रुपये देगा और इस प्रोजैक्ट पर 224 करोड़ रुपये खर्च होंगे, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इन रेलवे फाटकों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इस तरह के अनेकों विकास के काम कुरूक्षेत्र में हुए हैं। कुरूक्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैंनेजमैंट प्लांट की व्यवस्था करना और सीवरेज ट्रीटमैंट के दो प्लांट लगने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यदि मैं सारे विकास की बात सदन में करने लग जाऊँगा तो बहुत ज्यादा समय लग जायेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब एक कार्यक्रम में हरिद्वार में गए तो वहां के मन्दिरों को देखकर कहा था कि हमारे हरियाणा के कुरूक्षेत्र में भी लगभग 5 एकड़ में 'भारत माता' का मन्दिर बनाया जायेगा। इसके फलस्वरूप ही कुरूक्षेत्र में तिरूपति बाला जी का मन्दिर, अक्षरधाम का मन्दिर आदि अनेकों मन्दिर बन रहे हैं। इसके साथ–साथ मैं एक बात और सदन में कहना चाहता हूँ कि कुरूक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है और एक सन्निहित छोटा सरोवर है। पहले दोनों सरोवरों के पास एक कच्चा नाला हुआ करता था और उसमें पशु नहाते और गंदगी फैलाते थे और धोबीघाट होने के कारण सारा गंदा पानी सरोवर में आता था। जब गीता जयंती, सूर्य ग्रहण का मेला या अमावस्या के दिन दूर–दराज से लोग नहाने आते थे तो वे लोग एक–दूसरे को कहते थे कि इस गंदे पानी में नहाना मत सिर्फ अपने शरीर पर पानी के छिंटे ही मार लेना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस गंदे पानी को रोकने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कम समय लेता हुआ सिर्फ आपके माध्यम से यही बात सदन में कहना चाहता हूँ कि 5 सालों के बाद सरकार डूबती हुई तो देखी है लेकिन पहली बार विपक्ष डूबता हुआ देखा है। अध्यक्ष महोदय, पिपली बस स्टैण्ड

का नवनिर्माण किया जाए। कुरूक्षेत्र में कई गर्ल्स स्कूल्ज में मार्निंग और इवनिंग की क्लासिज़ लगाने की प्रपोजल की फाइल माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास आई हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस काम को भी जल्दी से जल्दी अमलीजामा पहनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय मंत्रियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती बिमला चौधरी (पटौदी) : स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने इन पांच सालों में बहुत–से विकास कार्य किए । चाहे सड़कों की बात हो, नाली की बात हो, पंचायत अलग करने की बात हो, शिक्षा की बात हो उन्होंने बहुत–से काम किए हैं इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं । आपने भी हमको मौका दिया चाहे हम कम बोले चाहे ज्यादा बोले लेकिन सबको मौका दिया । मैं तो विपक्ष को भी यही कहती हूँ । कहते हैं कि भई जाते की पीठ दिखे आते का मुंह दिखे । सबका मंगल हो, सबकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो और हम यह कहते हैं कि सब मिलजुलकर रहें । (विघ्न) अगर हम सदन में मिलजुलकर नहीं रहते तो बाहर तो सब मिलजुलकर रह ही सकते हैं । मै किसी की कोई बुराई नहीं कर रही है मैं तो सबको धन्यवाद दे रही हूँ । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक बात कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले पटौदी में बाईपास की घोषणा की थी । मैं कहती हूँ कि इसी महीने में उसका शिलान्यास हो जाये, काम चालू हो जाये तो और भी अच्छा रहेगा । हमारे क्षेत्र के पहाड़ी गांव में एक फ्लाईओवर का काम अधूरा पड़ा है । मैं मंत्री जी से कहती हूं कि उसको पूरा करवाया जाये और उसमें ठेकेदार ने बहुत ही घटिया क्वालिटी की सामग्री लगा रखी है । अतः उसको भी चैक करवाया जाये । मैं सी. एम. साहब से एक बात और कहती हूं कि सी.एम साहब आपने धान की खेती को कम करने का बहुत अच्छा फैसला लिया है । इसके लिए आपने दो–दो हजार रूपये का इनाम भी रखा है । इसके लिए भी मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं । मैं आदरणीय सी.एम साहब से एक बात और कहती हूं कि हमारे पटौदी हल्के में पानी की बहुत ज्यादा कमी है । लोहारी गांव नहर के पानी को आगे नहीं आने देता है । ऐसे में मैं सी.एम साहब से कहती हूं कि उस पानी को भी थोड़ा और आगे पहुंचाने का काम किया जाये । आपने ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज को मंजूरी

देकर बहुत अच्छा फैसला किया है । आज के दिन जमीन में बहुत ज्यादा पानी की कमी है । हमारे क्षेत्र में दो–दो सौ फुट और हजार–हजार फुट तक जलस्तर गिर चुका है । अतः उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा फैसला लिया है । इसके लिए मैं सी.एम. साहब को बधाई देती हूं । मुझे खुशी है कि हमको इस महान सदन में आने का मौका मिला और हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय की टीम के सिपाही रहे हैं । अतः अगर हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूं । जय हिंद । जय भारत ।

डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद । मैं आज सदन में अपने हल्के के विषय में कोई मांग नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हल्के में विकास के लगभग सारे काम हो चुके हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा क्योंकि इनकी वजह से मेरे नौकरी छोड़कर राजनीति में आने का मकसद सफल हो गया है । मैं राजनीति में बिल्कुल नया था इसके बावजूद मुझे माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हुआ । इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं । विधायक बनने के बाद जब मैं पहली बार इस सदन में आया तो सबसे पहले मैंने उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद किया कि नौकरी छोड़ने के 6 महीने के बाद विधान सभा के चुनावों में मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे वोट देकर इस हाउस का मैम्बर बनवा दिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इस हाउस का मैम्बर बनने के लिए कई लोगों की पीढ़ियां निकल जाती हैं परन्तु वे फिर भी इस हाउस के मैम्बर नहीं बन सकते। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक डोमेन में माननीय सदस्यों के द्वारा किये गये कार्यों को जनता देखती है। मैं जब नौकरी से इसकी तुलना करता हूं तो पाता हूं कि नौकरी में अप्वॉइंटिंग अथॉरिटी एक ही होती है और चुनाव के क्षेत्र में लाखों की संख्या में अप्वॉइंटिंग अथॉरिटीज होती हैं। नौकरी तो इम्तिहान की तैयारी करके सफलता प्राप्त की जा सकती है लेकिन चुनावों में लाखों लोगों का इम्तिहान पास करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, नौकरी में ए.सी.आर.(एनुअल कांफीडैंशियल रिपोर्ट) एक अधिकारी लिखता है परन्तु चुनाव के क्षेत्र में लाखों मतदाता रिपोर्ट लिखते हैं। नौकरी में ए.सी.आर. खराब लिखी जाए तो उसको सीनियर अधिकारी ठीक कर देता है लेकिन चुनाव के क्षेत्र में रिपोर्ट ठीक करवाने के लिए 5 साल तक इन्तजार करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, हम

सभी माननीय सदस्य इस महान् सदन के सदस्य है और इस नाते से हमारी भी पब्लिक रेस्पॉसिब्लिटिज हैं। हमारे कार्यों को जनता बहुत नजदीकी से देख रही है और हम चाहे घर के 7 वें कोने में घुसकर कोई भी बेईमानी का काम कर लें, उसके बारे में प्रदेश की जनता को पता चल जाता है। इसलिए हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जनता कुछ नहीं जानती है। जनता हमारे कार्यों को बहुत बारीकी से देखती है और अगर एक काम भी गलत करेंगे तो उसके लिए जनता दण्डित भी करती है। अगर सरकार अच्छे कार्य करती है तो उस सरकार की वाहवाही होती है और जनता का प्यार भी मिलता है परन्तु कुछ विपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि यह झूठा प्रचार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की जनता के प्रति जो डैडिकेशन और कमिटमेंट होती है, उसके लिए जनता रिवार्ड देती है। जतना ताकत देती है जिसके कारण उसका जनता के प्रति भलाई के कार्य करने का साहस आता है। हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने जम्मू एवं काश्मीर में धारा 370 खत्म की है, उनका देश के प्रति डैडिकेशन और कमिटमैंट इतना था कि जनता को भी उनसे उम्मीद थी। देश की जनता की यह एक्सपैक्टेशन थी कि अगर श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे तो वे जो कह रहे है, उस बात को भी पूरा करेंगे। इसलिए उन्होंने कल एक ही झटके में धारा 370 को हटवा दिया। यह काम देश की आजादी से लेकर सालों साल तक नहीं हो सका परन्तु इस काम को उन्होंने एक ही पल में कर दिखाया। ऐसा नहीं है कि जम्मू एवं काश्मीर की समस्या को अधूरा छोड़ दिया बल्कि संबंधित समस्या का ऐसा हल कर दिया है जिसका आने वाली पीढ़ियां भी गुणगान करेंगी। जहां तक हमारी सरकार और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है तो कोई भी आदमी छत पर चढ़कर किसी का प्रचार कर ले या किसी की बड़ाई कर ले परन्तु जनता उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। प्रदेश की जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत भलाई के कार्य किये हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो नारे दिये थे जिसमें एक तो 'हरियाणा एक, हरियाणवी एक,' और दूसरा 'सबका साथ, सबका विकास,' का था। 'हरियाणा एक, हरियाणवी एक,' का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता कि वर्ष 2019 के लोक सभा चुनावों में पहली बार हरियाणा राज्य की राजनीति जातिवाद से बाहर निकल कर आयी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हर जाति के मतदाताओं ने वोट दिये हैं और

हर क्षेत्र ने वोट दिया है और उसका कारण यह था कि हमारी सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनायी गई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पहली बार जात–पात के आधार पर वोट डाले गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डा0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो बात कह रही हैं, वह बिल्कुल झूठी बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के इतिहास में पहले के चुनावों में कभी भी जात–पात के आधार पर वोट नहीं डाले गये थे।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश को जलाने वाले कौन लोग थे ? प्रदेश में जातिवाद का जहर कौन फैला रहा था ?

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं।

पंजाब विधान सभा के सदस्य एवं पंजाब विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर सर, आज हमारी विधान सभा की दर्शक दीर्घा में पंजाब विधान सभा के सदस्य श्री अमन अरोड़ा और पंजाब विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता सरदार हरपाल सिंह चीमा जी सदन की कार्यवाही देखने के लिए वी.आई.पीज. गैलरी में बैठे हैं। हम सदन की तरफ से उनका स्वागत करते हैं।

सदस्यों द्वारा विभिन्न मांगों को उठाना (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि यह तो क्षेत्र की जनता फैसला करती है कि वह किसे चुनकर इस सदन में भेजे ?

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जनता ने ही हमें चुनकर इस सदन में भेजा है।

श्री अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता ने ही हमें चुनकर भेजा है और दो महीने के बाद जनता दोबारा से वही फैसला देने वाली है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जनता से बड़ा दरबार और जनता से बड़ा फैसला करने वाला कोई नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें थीं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्षः नरेश कौशिक जी, आप अपनी बात शुरू करें।

श्री नरेश कौशिक (बहादुरगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं देश की सम्मानित जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे देश को एक ईमादार प्रधानमंत्री दिया और उसके साथ ही साथ मैं हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को भी 50 साल की राजनीति में पहली बार एक ईमानदार मुख्यमंत्री दिया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे हल्के से आता हूं, जो दिल्ली के साथ लगता है और हरियाणा प्रदेश की 50 साल की राजनीति में लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जात–पात, भाई–भतीजावाद और चौधर के नाम पर राजनीति की। यहां पर माननीय मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी भी बैठे हुये हैं, जब हम इस विधान सभा में चुनकर आये थे तो इस सदन में भी कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही थी रोहतक और झज्जर में काम कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों का पैसा वहीं पर लगा हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में मेरे हल्के में जितने विकास के कार्य हुये हैं, उतने पिछले 50 सालों की राजनीति में कभी नहीं हुये थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बहुत सारी समस्याएं थीं। उनमें पहली समस्या यह थी कि मेरे हल्के में पहले गुंडा–गर्दी का माहौल था और इस तरह का माहौल पिछले 20 सालों से लगातार चला आ रहा था। मेरे हल्के में वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक गुंडों के द्वारा वहां के व्यापारियों से सरेआम पैसा लिया जाता था और उन्हें तंग किया जाता था। मेरे हल्के में ऐसी–ऐसी सरकारों के शासन रहे थे, जिसके कारण वहां की सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थीं और वहां पर लोगों का सरेआम शोषण किया जाता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भय

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का नारा दिया था और ईमानदारी के साथ ''हरियाणा एक–हरियाणवी एक'' का भी नारा दिया था और हम सबको साथ लेकर हरियाणा प्रदेश में विकास करने की बात कही थी। (विघ्न)

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री नरेश कौशिक जी से कहना चाहूंगी कि यदि ये ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात करते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि किसानों की मौत क्यों हो रही है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शकुन्तला जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जायें, इसमें आपका कोई विषय नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कौशिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या श्रीमती शकुन्तला जी से कहना चाहूंगा कि मैं जानता हूं कि इनकी पार्टी कितनी ईमानदार है। (शोर एवं व्यवधान) मैं सब जानता हूं कि इनकी पार्टी के रिक्शा चलाने वाले सदस्य सी.एल.यू. करवाकर इतने बड़े–बड़े आदमी बन गये हैं।

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगी कि रिक्शा कौन चला रहा है ?

श्री नरेश कौशिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से कहना चाहूंगा कि मैंने इनका नाम नहीं लिया है। कृपया ये अपनी सीट पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि ये वही लोग हैं, जो बंदर की गोद में बैठकर लूट–पाट करके करोड़पति हुये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कौशिकः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्या का नाम नहीं लिया है। कृपया ये अपनी सीट पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से कहना चाहूंगा कि इस सदन में इस तरह से बात करने का यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्षः शकुन्तला जी, माननीय सदस्य ने आपका नाम नहीं लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कौशिकः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या से कहना चाहूंगा कि कृपया ये अपनी सीट पर बैठ जायें और मुझे अपनी बात रखने दें। मुझे सब के बारे में पता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शकुन्तला जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कौशिकः अध्यक्ष महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी तो विपक्ष के लोग यह कहते थे कि इस प्रदेश में नई पार्टी और नया मुख्यमंत्री बना है, इनसे सरकार नहीं चलेगी और 2.5 साल तक लोगों ने कोशिश भी की थी कि इस सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को फेल कर दें, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी का, इनके कुशल नेतृत्व का और मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ईमानदारी के साथ सरकार चलाई और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ समान विकास कराने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय मेरे हल्के में 10 साल तक कांग्रेस पार्टी के लोग चौधर का नाम लेकर वहां पर राज करते रहे लेकिन मेरे हल्के के 22 गांव ऐसे थे जिनमें कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करवाया था। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24 जुलाई, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हल्के में जनसभा की और इस जनसभा के माध्यम से एक नई परिपाटी की शुरूआत हुई। मुख्यमंत्री जी ने दरियादिली दिखाते हुए हल्के की जनता से कहा कि आपके हल्के की जितनी भी डिमांडज़ हैं, वे बतायें। अध्यक्ष महोदय, हल्के की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जितनी भी डिमांड्ज़ बताई, इन्होंने हमारी सभी डिमांड़ज को पूरा करने काम किया। इसके अलावा सरकार ने मेरे हल्के के सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध करवाया इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मार्किटिंग बोर्ड के सभी रोडज़ 12 फुट चौड़े थे, हमारी सरकार ने उनको 18 फुट चौड़े करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के चार गांवों के ऐसे स्कूल थे जिनकी बिल्डिंग्ज़ बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। आज इस महान सदन में हमारे पूर्व डिप्टी स्पीकर साहब भी बैठे हुए हैं, इनकी ससुराल का जाखोदा गांव है, इस गांव की बिल्डिंग भी बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पास करके इन बिल्डिंग्ज को भी नया बनाने का काम किया और इसके साथ ही मेरे गांव के दो स्कूलों को भी अपग्रेड करने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय

शिक्षा मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का इंडस्ट्रियल हल्का है जिसमें आज लगभग 4000 इंडस्ट्री काम कर रही है क्योंकि वहां पर मजदूर तबके की संख्या बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने मेरे हल्के में 100 बेड के अस्पताल को 200 बैड करने का काम किया। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस अस्पताल में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी लेकिन जब से हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, चाहे हम ट्रॉमा सैंटर की बात करें, चाहे बच्चों की नर्सरी की बात करें, चाहे डायलिसिस मशीनों की बात करें और चाहे एक्सरे मशीनों की बात करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में माननीय मंत्री श्री नरबीर जी ने सभी रोडज़ को नया बनवाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में एक बात और बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के के लोगों की उत्तरी बाईपास की एक बहुत बड़ी डिमांड थी परन्तु इसके लिए स्थानीय लोगों ने जमीन देने से इंकार कर दिया था। हमने उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तरी बाईपास बनाने की गुहार लगाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके रिगार्डिंग इरीगेशन विभाग से बात की और निर्णय लिया कि इरीगेशन विभाग की जो ड्रेन है, उसके ऊपर उत्तरी बाईपास बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री नरबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि मेरे हल्के में उत्तरी बाईपास को जल्द से जल्द बनाने का काम पूरा करे, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवादी रहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इस महान सदन में अपने हल्के से संबंधित डिमांड्ज़ गिनाने लग गया तो दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए मैं दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपका और पूरे सदन का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री श्याम सिंह राणा (रादौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्टूबर 2014 में हरियाणा प्रदेश में पहली बार बनी और आने वाले अक्टूबर 2019 में पूरे पांच साल हो जायेंगे। जब हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी तब कुछ पुराने विधायकों और पुरानी पार्टियों के माननीय विधायकों का ऐसा मानना था कि भारतीय जनता पार्टी को लीडरशिप का अनुभव नहीं है

लेकिन इन सभी साथियों की ये सारी बातें झूठ साबित हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन सभी विधायकों को कहना चाहता हूं कि जितना अनुभव इन पांच वर्षों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को रहा है वह शायद ही हरियाणा प्रदेश के किसी दूसरे मुख्यमंत्री जी को रहा होगा और यह बात इन पांच सालों में प्रदर्शित भी हो चुकी है। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में जितनी भी अनाउंसमैंट्स की थी, वह शायद ही हरियाणा प्रदेश के किसी अन्य मुख्यमंत्री ने की होगी। यही नहीं बल्कि उन सभी अनाउंसमैंट्स को पूरा करने का भी काम किया है और यह हरियाणा प्रदेश में रिकॉर्ड की बात है। इसके अलावा रादौर हल्के में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो–जो अनाउंसमैंट्स की थी उनको भी पूरा करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से इतनी उम्मीद नहीं थी कि वे हरियाणा प्रदेश में इतने ज्यादा विकास कार्य भी करवा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो यमुना नदी के नगली घाट पर बनने वाला पुल है, वह उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। यह किसानों की वर्षों पुरानी मांग थी जोकि यमुना नदी पर पुल बनाने की मांग क्षेत्र के लोगों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी और मैं समझता हूं कि इस पुल के बन जाने के कारण यहां के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि यमुना नदी के उस पार हमारे प्रदेश के गांव जठलाना, गुमथला और 10–15 गांवों के किसानों की हजारों एकड़ जमीन पड़ती है और वहां के किसानों को यमुना पार आने जाने में बड़ी कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमारे किसानों को यमुनानगर से होकर उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, जिसमें उनका पूरा दिन ही लग जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल को बनवाने के लिए बहुत प्रयास किया है। यमुना नदी से लगते रादौर के एरिया में पुल बनने से विकास की राह खुलेगी जिससे यहां के किसानों को सबसे बड़ा फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे यहां एक समस्या यह भी है कि बरसात के मौसम में यमुना नदी में बाढ़ आ जाती है जिसके कारण हमारे यहां जो 11000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन के खंबे हैं वह गिर जाते हैं जिसके कारण यहां पर काफी बार जान–माल की हानि उठानी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी कि यमुना नदी पर एक पुल बना दिया

जाये तो इसके लिए सरकार ने पुल के लिए एस्टीमेट पास कर दिया है । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि यमुना के साथ–साथ 11000 वोल्टेज की हाई टेंशन लाइन के पुराने पोल्ज को बदलकर नये पोल्ज लगाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, रादौर के गांव नाचरोंन में एक बहुत अच्छी आई.टी.आई. बनने जा रही है। जिससे वहां के बच्चों को ट्रेनिंग दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, पहले हमें अपने काम के लिए जगाधरी सब–डिवीजन में जाना पड़ता था, अब हमारी सरकार ने रादौर में ही सब–डिवीजन बना दिया है और यहां पर एस.डी.एम. की ड्यूटी भी लगा दी है, जिससे हमारे हल्के के लोगों को फायदा हुआ है। रादौर के अंदर पहले पंचायत होती थी लेकिन हमारी सरकार द्वारा रादौर में नगरपालिका का गठन किया गया है। हमारी नगर पालिका बहुत ही साफ–सुथरी है। सफाई के मामले में पूरे उत्तरी भारत में हमारी नगर पालिका पांचवें नम्बर पर है। हमारी सरकार द्वारा रादौर शहर में एक बहुत ही अच्छे बस–स्टैण्ड का निर्माण करवाया गया है। इसी प्रकार से रादौर में एक कॉलेज और एक स्टेडियम का निर्माण हमारी सरकार द्वारा करवाया गया है। इनसे हमारे बच्चों को पढ़ने और खेलने की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। हमारी सरकार द्वारा अंटावा में एक पी.एच.सी. का निर्माण करवाया गया है। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ऐसे ही काजीबांस और बकाना में हमारी सरकार द्वारा दो बड़े पॉवर हाउसिज का निर्माण करवाया गया है। कैल से लेकर कलानौर तक एक बहुत बड़े बाई–पास का निर्माण भी हमारी सरकार द्वारा करवाया गया है। इससे पर्यावरण में सुधार हुआ होगा और आस–पास के क्षेत्रों को प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। इसी प्रकार से अलीपुरा से यमुनानगर तक की सड़क को चौड़ा किया गया। कांग्रेस की सरकार के समय में जब यमुनानगर नगर निगम बना था तो उस समय इसमें आस–पास के 22 गांवों को भी सम्मिलित किया गया था। प्रत्येक दृष्टि से इन सभी 22 गांवों की हालत बहुत खराब थी। हमारी सरकार ने इन गांवों की हालत को सुधारकर इन गांवों के निवासियों के जीवन को बेहतर तरीके से सुविधासम्पन्न बनाने का काम किया है। इन 22 गांवों में साढ़े 32 करोड़ रूपये की लागत से सीवरेज सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे ही हमारी सरकार द्वारा 50 कालोनियों को रेगुलर करवाया गया। हमारी सरकार द्वारा रादौर के अंदर 50 बैड के हॉस्पिटल के निर्माण कार्य की शुरूआत भी करवा दी गई है। हमारी सरकार द्वारा ही रादौर में पार्क का निर्माण करवाया गया है। मेरे हल्के

14.00 बजे

रादौर के किसानों की सुविधा के लिए हमारी सरकार द्वारा खेतों के बहुत से कच्चे रास्तों को पक्का करवा दिया गया है। यह कार्य हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है। हमारी सरकार द्वारा ही प्रदेश के लोगों के बिजली बिल भरने के लिए एक विशेष स्कीम निकालकर एक लाख रूपये के बिलों का एक हज़ार रुपये में निपटान करवाया गया। हमारी सरकार के इस निर्णय से गरीबों और किसानों का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ऐसा हरियाणा प्रदेश के पहली बार हुआ है। यह हमारी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। इतना ही नहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र रादौर में 80 अम्बेडकर भवनों और अनगिनत हरिजन चौपालों का निर्माण करवाया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड की बहुत सी सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया। मेरे हल्के में पहली बार राक्षी, चतंग और सरस्वती इत्यादि बरसाती नालों पर किसानों की सुविधा को देखते हुए छोटे–छोटे पुलों का निर्माण करवाने का फैसला किया गया है जिनके टैण्डर लग चुके हैं और शीघ्र ही इनका निर्माण कार्य भी पूर्ण हो जायेगा। इन पुलों का निर्माण हो जाने से विशेषकर उन किसानों को बहुत फायदा हुआ जिनकी जमीन इन बरसाती नालों के दोनों ओर है। स्पीकर सर, हमारे यहां पर किसानों पर लाठीचार्ज़ हुआ था और उनके ट्रैक्टर्स को पुलिस प्रशासन द्वारा थाने में खड़ा करवा लिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों के ट्रैक्टर तो छुड़वा दिये गये थे। मेरी यह मांग है कि उन किसानों के अगेंस्ट जो केस दर्ज़ किये गये थे अगर उनको भी वापिस ले लिया जाये तो यह बहुत ही अच्छा होगा। मेरे हल्के के किसानों की एक डिमाण्ड यह है कि वे यह चाहते हैं कि उनके ट्यूबवैल्ज़ के बिलों का भी निपटान हो। इस मामले में मेरा यह सुझाव है कि इन बिलों के मामले में अगर सरचार्ज़ और ब्याज माफ हो जाये तो पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान बिल भरने में देर नहीं लगायेंगे। इस प्रकार से अगर सरकार किसानों के प्रति और ज्यादा उदारता दिखाये तो इन बिलों का भी निपटान हो सकता है। स्पीकर सर, जिस प्रकार से हमारी पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू–कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया है यह अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ साथियों द्वारा केन्द्र सरकार के इस ऐतिहासिक और जनहितकारी निर्णय का भी विरोध किया जा रहा है जोकि दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए मौका

दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, श्रीमती गीता भुक्कल सहित हरियाणा विधान सभा में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों द्वारा कल माननीय मुख्यमंत्री जी के जम्मू–कश्मीर से धारा 370 हटाने सम्बन्धी धन्यवाद प्रस्ताव का बाकायदा समर्थन किया गया। चौधरी दीपेन्द्र हुड्डा, भूतपूर्व सांसद ने भी केन्द्र सरकार के इस निर्णय का समर्थन किया है। इसी सम्बन्ध में श्री कुलदीप बिश्नोई जी ने भी बहुत अच्छा ट्वीट किया है। हम श्रीमान् जनार्दन द्विवेदी जी और श्रीमान् भुवनेश्वर कालिता के धन्यवादी हैं। राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप श्रीमान् भुवनेश्वर कालिता को यह कहा कि कांग्रेस के सांसदों को व्हिप जारी करें कि केन्द्र सरकार ने जम्मू–कश्मीर से जो धारा–370 हटाने का बिल पेश किया है उसका विराध करें। हम श्रीमान् भुवनेश्वर कालिता का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया और हमारे साथ आ गये। स्पीकर सर, हमारा देश बहुत महान है यहां कोई पता नहीं कि किसकी आत्मा कब जाग जाये? स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जो भी लोग भारतीय राजनीति की भारतीय जनता पार्टी नामक गंगा में शामिल हुए हैं उनको कभी भी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से डॉ. रघुवीर सिंह कादियान को पुनः –पुनः यही सुझाव है कि अभी भी समय है इसलिए वे भी भारतीय राजनीति की गंगा भारतीय जनता पार्टी में जल्दी से जल्दी शामिल होकर अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित कर लें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा था जब सभी ने उसको सर्वसम्मति से पास कर दिया तो मेरे ख्याल से माननीय सदस्य श्री श्याम सिंह राणा द्वारा ऐसी तलख टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी। यह गलत बात है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सन्दर्भ राष्ट्रीय स्तर पर था। व्यक्तिगत स्तर पर जिन लोगों ने धारा 370 को हटाने के लिए सपोर्ट किया है उनका स्वागत है, अभिनन्दन है तथा धन्यवाद है। मैं आपके माध्यम से

डॉ. कादियान को कहना चाहूंगा कि यह इनका बड़प्पन है कि ये इस विषय पर पार्टी से ऊपर उठ कर चले हैं

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय साथी श्री श्याम सिंह राणा जी की बात भी सुनी है। मैंने इस महान सदन में श्री भुवनेश्वर कालिता तथा श्री जनार्दन द्विवेदी का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि यह एक ऐतिहासिक घटना है। हमारे साथी डॉ. रघुवीर सिंह कादियान कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा इस महान सदन में इस प्रस्ताव का समर्थन करना भी एक ऐतिहासिक घटना है।

श्री मक्खन लाल सिंगला (सिरसा): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सिरसा की कुछ मांगें माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। सिरसा शहर में बरसाती पानी की निकासी और सीवरेज सिस्टम बहुत खराब है इसलिए इसका समाधान किया जाये। अनाज मंडी, कपास मंडी, सब्जी मंडी तथा काठ मंडी को बरनाला रोड पर शिफ्ट करने की हमारी बहुत पुरानी मांग थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं इसलिए इनको वहां पर यथाशीघ्र शिफ्ट किया जाये। चत्तरगढ़ पट्टी के पास डबवाली रोड पर रेलवे फाटक के पास जाम लगता है इसलिए वहां पर एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाये ताकि लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। सिरसा शहर की आबादी बहुत अधिक है इसलिए वहां पर एक बड़े अस्पताल का निर्माण करवाया जाये तथा मौजूदा अस्पताल में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाये ताकि लोगों को सुविधा हो सके। हमने शहर के बीचों बीच एक मल्टी स्टोरी पार्किंग की मांग की थी तथा उसके लिए तीन उपयुक्त स्थान भी सुझाए थे जिनमें पुराना सिटी थाना, पुराने सिटी थाना के सामने गर्ल्ज स्कूल के पास तथा मेहता मार्केट के पास खाली जगह पड़ी हुई है। हमारा यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है इसलिए जल्दी से जल्दी इस मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण करवाया जाये। शहर में टैक्सी स्टैंड तथा रेहड़ी संचालकों के लिए स्थाई जगह प्रदान की जाये। इसी प्रकार से शहर में ऑटो मार्केट के लिए जगह उपलब्ध करवा कर उनकी समस्या का समाधान किया जाये तथा अवैध कालोनियों को वैध किया जाये। इसके अतिरिक्त शहर के अन्दर भीड़ कम करने के लिए सिरसा शहर के चारों तरफ एक रिंग रोड का निर्माण किया जाये। सिरसा शहर में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी किया जाये ताकि वहां के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहरों में न जाना पड़े। सिरसा में थेड़ में 60 सालों से रह रहे लोगों के

लिए स्थाई मकान बनवा कर उनके नाम रजिस्ट्री करवाई जाये। सिरसा शहर के सभी पार्कों में बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाये तथा लोगों के बैठने के लिए सभी पार्कों में बैंचिज लगवाए जायें। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सभी चौंकों पर लाईट की व्यवस्था की जाये। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शहर में बहुत सी गलियां टूटी पड़ी हैं जिनका निर्माण करवाया जाये। शहर की जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत की जाये। इसी प्रकार से सिरसा विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों में वाटर वर्क्स की हालत बहुत जर्जर है उनकी रिपेयर करवाई जाये ताकि लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति की जा सके। गांव डिंग की आबादी 10 हजार से अधिक है इसलिए वहां पर सीवरेज की व्यवस्था की जाये। मेरे हल्के के गांव कुकड़ थाना गांव में वाटर वर्क्स नहीं है इसलिए वहां पर वाटर वर्क्स का निर्माण करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री तेजपाल सिंह तंवर (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस ईमानदारी तथा स्वच्छता से विकास के कार्य हुये हैं जब हम उनको गिनवाने लगते हैं तो कुछ साथियों को तकलीफ होती है। मेरा कहना यह है कि अच्छे कामों की प्रशंसा होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा मौका कभी–कभी मिलता है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक सरकार का गुणगान कर रहे हैं सरकार आगामी विधान सभा चुनाव में सभी के टिकट काटेगी।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री करण दलाल को एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी गली आवे नहीं और आवे तो जावे नहीं । आप बीच में हमारी पार्टी को छोड़ गए थे । अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हमने आपको उस मंच पर शामिल किया था । आप ये चिन्ता मत कीजिए ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए आदरणीय श्री राम बिलास शर्मा जी लेकर गए थे । वहां यह तय हुआ कि मैं चौटाला साहब का विरोधी हूं और बी.जे.पी का उनसे गठबंधन है तो आपने मेरी टिकट का क्या करना है ? फिर ये कहने लगे कि तेरी टिकट की हम जिम्मेवारी लेते हैं । जब चौटाला जी के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए और वह नहीं माने तो

इन्होंने मुझे बुलाकर यही कहा कि भाई करण हम तेरी टिकट नहीं दे पाएंगे । आपने जहां जाना है जा सकते हैं । शर्मा जी, मैं तो तब गया था । आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब तो बी.जे.पी. में आने के लिए अब भी तैयार हैं ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सदन कई बातों का चश्मदीद गवाह है परन्तु श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री पलवल की सभा में क्या बोलकर गए थे वह करण दलाल जानते हैं और मैं जानता हूं लेकिन आज श्री वाजपेयी जी इस दुनिया में नहीं हैं । पहले मेरी और करण दलाल की बात हुई थी उस समय मैंने इनको कहा था कि करण आप चिन्ता मत करो वाजपेयी जी वही बोलेंगे जो आप चाहते हैं ।

श्री तेजपाल तंवर : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय करण दलाल जी को मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार आपकी पार्टी की सरकार 10 साल रही है लेकिन गुरूग्राम में पांच किलोमीटर तक भी कोई रोड नहीं बना था। इसी के साथ हमारे क्षेत्र के लोग पिछले 50 साल से कॉलेजिज की मांग कर रहे थे इनकी सरकार के समय में वह कॉलेज नहीं बने और हमारे क्षेत्र की जो सड़कें टूटी पड़ी रहती थी, वे सड़कें 10 साल तक किसी ने रिपेयर भी नहीं की । आज हमारी सरकार के समय में आप हमारे क्षेत्र में मौके पर जाकर देख लें सारी सड़कें बिल्कुल अच्छी अवस्था में हैं । यह बात हम ही नहीं कह रहे हैं ये काम हरियाणा की ढाई करोड़ जनता देख रही है । हरियाणा की जनता ने ही काम के बदले लोक सभा के चुनाव में हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं । आज शहीदों का जो सम्मान हमारी सरकार ने किया है उतना पहले आपकी सरकारों ने नहीं किया था। इसके लिए मैं आपको उलाहना नहीं दे रहा हूं । हो सकता है आपके सामने वह परिस्थिति न हो । हमारे सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी व सभी मंत्रियों ने जिन–जिन पर जो–जो विभाग थे उनमें अच्छे कार्य किए हैं । चाहे वह पी.डब्ल्यू.डी. विभाग हो उसमें भाई राव नरबीर सिंह जी व माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से 26 हजार किलोमीटर तक सड़कें बनी हैं । इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में व हमारे स्कूलों में जहां पर हमारे कॉलेज पिछले 50–50 साल से नहीं बने, वहां आज शिक्षा के क्षेत्र में इतना अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इसी तरह से हमारे बिजली के कामों को देख लें जो तारें 50–50 सालों से जर्जर हुई पड़ी थी जिनको बदलने का कभी नाम नहीं लिया गया था । जब भी तेज हवा चलती थी तो वह तारें टूट–टूट

कर गिरती थी । अब हमारी सरकार ने उन सभी जर्जर तारों को बदलवाने का काम किया है और गांवों को जगमगाया गया है । जिन गांवों में पानी नहीं था उन गांवों तक पानी पहुंचाया गया है । हमारे महेन्द्रगढ़ में जो खालें वा नहरें थी वे बिल्कुल सूखी पड़ी हुई थी जिनमें कभी पानी नहीं गया था और न ही किसी ने उनकी कभी सुध ली थी । हमारी सरकार आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पानी पहुंचाने की सुध ली है । माननीय करण जी, हम इन कामों को ऐसे नहीं गिना रहे हैं, जो काम हुए हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए । अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपकी भी प्रशंसा होगी । विपक्ष कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी भी प्रशंसा होगी लेकिन जिन सरकारों ने काम ही नहीं किए उनकी प्रशंसा कैसे होगी । हमारी सरकार ने तो घुमक्कड़ जातियों के लोगों का भी सम्मान किया है । उनके बारे में भी सोचा गया है । आखिरी आदमी तक सोचा गया है । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष भी समझदार है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पता नहीं विपक्ष आएगा भी या नहीं ? आप सभी ने इन पांच साल में जिसके जैसे अच्छे विचार थे सभी ने अपने–अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब मैं आप सभी का दिल की गहराईयों से बहुत–बहुत स्वागत व धन्यवाद करता हूं । मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । जिस तरह से प्रदेश में उनकी देखरेख में चहुंमुखी विकास हुआ है । इसी के साथ सभी मंत्रियों का और दर्शक दीर्घा में बैठे सभी भाईयों का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। जयहिन्द ।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में कैग की रिपोर्ट रखी गई है। वास्तव में कैग की रिपोर्ट को बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जाना होताा है। खैर, आज जो कैग की रिपोर्ट टेबल की गई है उसको पढ़े तो पायेंगे कि कैग ने सरकार के हर डिपार्टमैंट को उसकी कार्यवाही के बदले एक तरह से धमकाने का काम किया है और डिपार्टमैंट्स की कारगुजारियों पर सवालिया निशान लगाये हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश एक प्रगतिशील प्रदेश हुआ करता था लेकिन इन पांच सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस हरियाणा प्रदेश को पीछे धकेलने का ही काम किया है। यह मैं नहीं कहता बल्कि जो कैग की रिपोर्ट आज सदन में प्रस्तुत की गई है उसमें यह सब लिखा हुआ है। कैग की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा का जो कर्जा पिछले वर्ष 1,22,617 करोड़ रूपये हुआ करता था, उसमें 12.39 परसैंट की बढ़ोतरी के साथ आज यह कर्ज 1,37,813 करोड़ रुपये हो गया है और 10578 करोड़ रुपये उस कर्ज के ब्याज

के रूप में देने पड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे सत्ता पक्ष के विधायक साथी सदन में इतनी झूठी वाहवाही कर रहे हैं कि यह हो गया–वह हो गया अगर इस कैग की रिपोर्ट को पढ़े तो पायेंगे कि कैग ने तो अपनी रिपोर्ट के माध्यम से प्रदेश के विकास के लिए चिंता ही प्रकट की है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में जो लिट्रेसी रेट होना चाहिए था वह लिट्रेसी रेट भी उतना आगे नहीं जा पाया है जितना कि हरियाणा के लोग उम्मीद करते थे। इसी के साथ–साथ बिलो पॉवर्टी लाइन की संख्या पर भी कैग ने चिंता प्रकट की है। यही नहीं प्रदेश की जिस जी. डी.पी. पर कैग द्वारा चिंता प्रकट की गई है वह भी मैं सदन के सामने रखता हूँ और जब मुख्यमंत्री जी अपना जवाब दें तो वे बतायें कि कांग्रेस की हुकूमत में आगे बढ़ती हुई इस स्टेट को इतना पीछे धकेलने का काम क्यों किया गया? वर्ष 2013–14 में हरियाणा प्रदेश में जो जी.डी.पी. 12.97 परसेंट हुआ करती थी वह अब घटकर मात्र 9.96 परसेंट रह गई है। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में जी.एस.डी.पी. का जो ग्रोथ रेट 15.5 परसेंट हुआ करता था आज वह मात्र 11.58 परसेंट रह गया है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कैग में जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स उत्तराखंड तथा पंजाब के संबंध में जानकारी दी गई है, उन स्टेट्स में निश्चित रूप से इस दिशा में ज्यादा बेहतर ढंग से संचालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट बहुत लंबी है लेकिन मैं ज्यादा समय न लेकर संक्षिप्त में ही अपनी बात रखूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी सदन में अभी बैठे नहीं है लेकिन वे जहां भी बैठे हुए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि the collection under tax receipts was only ₹ 48.397 crore against the anticipated receipt of ₹ 51.712 crores यानि कलेक्शन और टैक्स रिसीट का जो ₹51.712 करोड़ रूपये का एंटीसिपेटिड टारगेट था उसके अगेंस्ट कलेक्शन अंडर टैक्स रिसीट केवल ₹48.397 करोड़ रूपये है तो ऐसी परिस्थिति में सवाल उठता है कि यह पैसा जा कहां रहा है? इसके कारण के लिए या तो डिपार्टमैंट की कमी है या फिर अधिकारी द्वारा मिलीभगत करके टैक्स की चोरी जानबूझकर कराई जा रही है। इस तरह की हैडलाइन्ज अखबारों में रोज खबर के माध्यम से प्रकाशित हो रही हैं। इसी तरीके से वैट और जी.एस.टी. की बात करूं तो पायेंगे कि इसमें ₹30,500 करोड़ रूपये का जो एंटीसिपेटिड टारगेट था उसके अगेंस्ट रिसीट केवल ₹26,442 करोड़ रूपये है। इसी तरीके से State Excise में anticipated receipts of ₹6100 करोड़ रूपये के अगेंस्ट रिसीट केवल 4966 करोड़ रूपये दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, हजारों करोड़ रूपयों की अनियमितताओं को कैग

के माध्यम से इंगित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के पांच साल के कार्यकाल की सदन की यह आखिरी बैठक है। सत्ता पक्ष के हमारे मंत्री और विधायक साथी सरकार की झूठी वाहवाही करने में लगे हुए हैं लेकिन यदि वे एक बार भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो इन पांच सालों के लिए जनता से वायदे किए गए थे, उनको भी अगर पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के कर्जे को माफ करने, कर्मचारियों के वेतन–पद्धोन्नति जैसी विसंगतियों को दूर करना, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने, मध्य हरियाणा में पंजाब हरियाणा की बैंच बनाने, सभी बी.पी.एल. परिवारों के लिए मकान बनाने, प्रत्येक गांव में 24 घंटे बिजली देने, प्रत्येक घर को शुद्ध जल उपलब्ध कराने तथा किसानों की फसलों के लागत मूल्य पर 50 फीसदी लाभ देने जैसे झूठे वायदे करके भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार कायम की थी और स्पीकर सर न जाने कितने झूठे वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा की जनता से कर रखे हैं। अब विधान सभा के चुनाव में 75 प्लस सीटें जीतने का सपना देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणों के लोगों से किया है और उनके साथ झूठे वायदे किए हैं, जनता इस बार विधान सभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देगी। (विघ्न)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहूँगा कि हरियाणा की जनता से किए गए वायदों के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री अपना जवाब जरूर देंगे। कहीं ऐसा न हो कि सच्चाई को सुनकर कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण बीच में ही सदन से वॉक–आउट न कर जायें। (विघ्न)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं जिस फ्राख़दिली से आपने सभी सदस्यों को आखिरी सत्र में दो–दो मिनट बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज 13वीं विधान सभा के कार्यकाल का आखिरी सत्र है। इस नाते से आज सदस्यों को किसी प्रकार की नेगटिव सोच नहीं रखनी चाहिए क्योंकि आखिरी सत्र के आखिरी दिन सदस्यों द्वारा सरकार की कार्यप्रणाली पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आज सदन में सदस्यों की पॉजीटिव सोच होनी चाहिए लेकिन कई बार सदन में कुछेक

सदस्यों द्वारा ऐसी सोच नहीं हुई, इसलिए जो सदस्य बोलें हैं उनको इस चीज पर अमल करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, आप सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए थे और उस समय सभी सदस्यों की तरफ से मांग की गई थी कि आप सभी सदस्यों को एक आंख से देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने पूरे सदन को दोनों आँखों से बराबर देखा और बराबर ही बोलने का मौका दिया। सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सदस्यों का एक–दूसरे के प्रति कुछ खट्टी–मीठी बातों का भी जिक्र हुआ और विरोध के कारण वैल में भी आए। मुझे भी इस पद का अनुभव है और मैंने आपको देखा कि आप बड़े भारी दिल से किसी पार्टी के सदस्य को नेम करते थे। जब बात सदन के दायरे से बाहर हो जाती थी तो भी आपका मन नहीं करता था कि आप किसी भी पार्टी के सदस्य को नेम करे। इस बात के लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में कई ऐसी बातों पर चर्चा हुई, जिसे हमने भी ऑब्जर्व किया। वर्ष 1987 में मैं, श्री राम बिलास शर्मा, श्री मंगल सैन, श्रीमती सुषमा स्वराज आदि सदस्यों की बहुत बढ़िया टीम हुआ करती थी और हमारा एक ही लक्ष्य हुआ करता था कि हमें विकास के नाम पर हरियाणा को बहुत आगे लेकर जाना है। अध्यक्ष महोदय, अब विधान सभा में अलग–अलग पार्टियों के सदस्य हैं और आपस में बड़े प्यार–प्रेम और शालीनता से एक–दूसरे से मिलते हैं, इसलिए मैं 13वीं विधान सभा के हर सदस्य की क्वालिटी और हैसियत को बहुत–बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ है, जहां तक विधायकों के इस्तीफे देने की बात है इस मामले में कई विधान सभाओं का माननीय उच्चतम न्यायालय में भी टकराव हुआ है, लेकिन बिना किसी टकराव के सबसे ज्यादा इस्तीफे अगर किसी विधान सभा ने स्वीकार किए हैं तो केवल हरियाणा विधान सभा ने यानी अध्यक्ष महोदय आपने स्वीकार किए हैं, इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक पर्सनली बात भी सदन में कहना चाहता हूँ कि जब 13वीं विधान सभा का गठन हुआ तो उस समय स्व0 डॉ0 हरि चंद मिड्ढा सदन के सबसे उम्रदराज सदस्य थे और अब मैं हूँ। इस हैसियत से मैं सदन में ज्यादा लम्बी–चौड़ी बातें न करके केवल यही कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा आपके साथ या किसी अन्य सदस्यों के साथ कोई कहासुनी हुई है तो मैं अपने मन और अपनी आत्मा से खेद प्रकट करता हूँ और सभी सदस्यों के उनके सुन्दर भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूँ।

ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने जिस ढंग से इस सदन को चलाया है और मर्यादाओं को निभाया है उससे आपने इस चेयर के मान–सम्मान को और अधिक ऊँचा दर्जा प्रदान किया है । इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं ।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में एक बात को कहना बिल्कुल नहीं भूलना चाहता कि मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय मनोहर लाल की मनोहर, प्रिय और आदर्श सरकार के कमाल को सैल्यूट करता हूं क्योंकि मैं एक सैनिक रहा हूं । मैं आज अपने क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कोई डिमांड नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने बिना मांगे ही हमारे क्षेत्र के इतने विकास कार्य करवा दिए हैं । इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि –

'बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख ।'

हरियाणा सरकार ने हमारे क्षेत्र की नहरों की टेल तक पानी पहुंचाकर दक्षिण हरियाणा को जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पुनः धन्यवाद देता हूं । हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल देश हित में एक सख्त फैसला करने का जो कमाल किया है उसके विषय में मेरा कहना है कि इस तरह का चमत्कार केवल मोदी जी जैसी शख्सियत ही कर सकती है । मोदी जी और हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जोड़ी ने जो कमाल किया है वह कमाल एक बहुत ही शक्तिशाली, धैर्यवान, चरित्रवान, बहादुर, ओजस्वी, शालीन और अत्यंत पुरुषार्थी व्यक्ति ही कर सकता है । मैं इस महान कार्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री और उनके साथी रहे आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । इनके लिए पिछले सत्र में मैंने सदन में एक कविता सुनाई थी । उस कविता की लाइनों पर सभी माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई थी । वे लाइनें थी –

मोदी जी की जय बोलो मर्दानी भाषा बोली है ।
मोदी जी की जय बोलो मर्दानी भाषा बोली है ।
धन्यवाद है मोदी जी का, धन्यवाद है अमित शाह का ।
दृढ़ इच्छा–शक्ति दिखलाई है,
अब प्रताड़ित निर्दोषों को
भय व आतंक से मुक्ति दिलाई है ।
शत्–शत् नमन शहीदों को, खूब याचना झेली है ।
मोदी जी की जय बोलो मर्दानी भाषा बोली है ।
मोदी जी की जय बोलो मर्दानी भाषा बोली है ।
धारा 370 का भी कर दिया पक्का उपाय

अब सारे संकट कट जाएंगे चिंता कोई रहेगी ना ।
केन्द्र शासित प्रदेश बनाकर सभी बन्दिशें खोली हैं
मोदी जी की जय बोलो मर्दानी भाषा बोली है ।
एक ही झण्डा, एक ही डण्डा, एक ही होगा संविधान
कोई भेद–भाव नहीं होगा, सभी होंगे एक समान ।
सभी खतरों को सोच–समझकर कानून की राही टोह ली है ।
मोदी जी की जय बोलो मर्दानी भाषा बोली है ।

मैं ऐसी मर्दानी भाषा को शत्–शत् नमन करता हूं । आज इस सत्र का आखिरी दिन है और इस मौके पर आज माननीय सदस्य डॉ. कादियान ने भी बहुत अच्छी–अच्छी बातें कही हैं, इसलिए मैं भी सभी सभासदों को अपने दिल में बसाकर उन्हें धन्यवाद देता हूं । धन्यवाद । जय हिन्द । भारत माता की जय ।

श्री नगेन्द्र भडाना (फरीदाबाद) (एन.आई.टी.): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे मेरे हल्के (एन.आई.टी. फरीदाबाद) से चुनावों में जितवा कर भेजा है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। विपक्ष की पार्टी का सदस्य होने के नाते मुझे मेरे हल्के की जनता कहती थी कि हमारे हल्के में विकास कार्य नहीं हो जाएंगे। शुरू में तो मुझे भी ऐसा ही लगा लेकिन जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उनके सामने मेरे हल्के की समस्याएं रखी और मेरे हल्के में रैली के दौरान जो मांगे रखी गयी थी, उन सभी मांगों को पूरा किया गया है। मेरे हल्के की ज्यादातर कॉलोनीज में नौकरी करने वाले लोग ही रहते हैं और उनको पीने का पानी भी खरीदकर पीना पड़ता था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने एक रेनी वैल बनवाने की मांग रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित मांग को स्वीकार कर लिया और मंझावली गांव के रेनी वैल से 34 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाकर मेरे क्षेत्र की उन कॉलोनीज में पानी लाया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इससे आज मेरे एन.आई.टी. विधान सभा के 80 प्रतिशत क्षेत्र में पानी की पूर्ति हो गयी है लेकिन अभी भी 20 प्रतिशत ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी पहुंचाने की आवश्यकता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसके अतिरिक्त मंझावली गांव में जो 26 ट्यूबवैल्ज लगवाये गये थे उनको चालू करवाया जाए ताकि मेरे हल्के के बाकी कुछ क्षेत्र में जो 20 प्रतिशत पानी की कमी है, उसकी भी पूर्ति हो सके। घरोड़ा गांव में 33 के.वी. का सब स्टेशन है और वहां पर कभी–कभी बिजली की कमी हो जाती है और बिजली की कमी के कारण मेरे क्षेत्र में पानी की भी कमी हो जाती है। इसलिए इस घरौड़ा गांव के 33 के.वी. सब स्टेशन को ठीक करवाया जाए ताकि मेरे क्षेत्र में पानी की कमी न हो। पहले मेरे

एन.आई.टी. क्षेत्र की अधिकांश गलियों में पानी पहुंचाने लिए पाइपलाइन नहीं बिछायी गयी थी परन्तु अब वहां पर सी.एम. अनाउंसमैंट के तहत पाइपलाइन भी बिछायी जा चुकी हैं। जहां पर सीवर लाइन नहीं थी, वहां पर सीवर लाइन भी बिछायी गयी हैं। मेरे हल्के की गलियों में इन्टर लॉकिंग टाइल्ज और आर.एम.सी. रोड बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मूलभूत सुविधाए देने का काम किया है। इसी तरह से मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में 12 कम्युनिटी सैंटर बनाये गये जहां पर लोग शादियां और कुछ दूसरे फंक्शन भी कर सकते हैं। मेरे हल्के में पॉल्यूशन की समस्या भी बहुत ज्यादा है इसके समाधान के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने ग्रीन बैल्ट बनाने की डिमांड रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से एन.एच.–3 से लेकर अनाज गोदाम होते हुए प्याली गांव से सरल गांव तक तकरीबन 2 किलोमीटर तक बहुत ही बेहतरीन ग्रीन बैल्ट बनायी जा रही है। इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र के मुख्य चौराहों का सौंदर्यीकरण करके हाई मॉस्क लाईटें लगवायी गयी हैं और गलियों में एल.ई.डी. लाईटें लगवायी गयी हैं। मेरे हल्के के खेड़ी गांव में 10 एकड़ जमीन पर हैवी ड्राईविंग लाईसैंस का सैटर बनाया जाएगा और इसी गांव में नेशनल रिसर्च इंस्टीच्यूट (यूनानी मेडिसन फॉर एन.सी.डी.) बनाया गया है जिसमें 100 बैड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है इसलिए उसका शिलान्यास किया जाए ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। मेरे हल्के में सड़कों की भी दिक्कतें थी जिसको मेरे क्षेत्र की जनता 30–40 सालों से झेलती आ रही थी। उदाहरण के तौर पर डबवा पाली रोड जो पिछले 30–40 सालों से नहीं बना था परन्तु अब 24 करोड़ रूपये की लागत से बनवाया गया है। इसमें सीवर लाईनें बिछायी गयी हैं, पानी की लाईंने बिछायी गयी हैं और बीच में डिवाईडर बनाकर डबल रोड बनाया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरे हल्के के बीच से गोच्छी ड्रेन भी जाती है और इसके चारो तरफ लाखों लोग रहते हैं। इसके दोनों तरफ जो बिजली के अनियमित खंभे और ट्रांसफार्मर्ज लगे हुए थे, उनको ठीक करवाया गया है। इसके दोनों तरफ सीमेंटिड सड़कें बनवायी गयी हैं जिससे वहां पर पहले जो जाम की स्थिति बनी रहती थी, अब वह ठीक हो गयी है। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में एक साठ फुट का रोड था, उस रोड को भी चौड़ा करके साथ–साथ बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर लगवाये गये हैं। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में पानी की निकासी की समस्या थी, उसको ठीक करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इसी तरह से

मेरे विधान सभा क्षेत्र के शहर में 11 जिम और देहातों में 8 व्यायामशालाएं बनवायी गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस महान सदन के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम ''सबका साथ–सबका विकास'' और सबको साथ में लेकर चलेंगे और इसको वास्तव में अमलीजामा पहनाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधान सभा क्षेत्रों में एक समान विकास कार्य कराने का काम किया है, जिसका जीता–जागता प्रमाण मेरा एन.आई. टी. विधान सभा क्षेत्र है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बार–बार धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे एन.आई.टी. विधान सभा क्षेत्र में पानी की बहुत ही भारी समस्या है, इसलिए इस समस्या का परमानेंट समाधान करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे एन.आई.टी. विधान सभा क्षेत्र में पाली, मांगर, पावटा, गोठरा और मोहताबाद के जो पहाड़ हैं, जब वहां पर माइनिंग होती थी तो उसके कारण वहां पर सैकड़ों बड़ी–बड़ी खानें बन गई हैं, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि बारिश के समय में यमुना में शुद्ध पानी होता है और वह व्यर्थ में बहकर समुद्र में चला जाता है तो इसके लिए इस तरह का इंतजाम किया जाये ताकि उस पानी को उन माइन्स के अंदर भरा जा सके। ऐसा करने से हमारे विधान सभा क्षेत्र के साथ–साथ दिल्ली, फरीदाबाद, गुरूग्राम और सोहना के इलाकों को भी लाभ मिलेगा, इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल संचयन जल्दी से जल्दी कराने का काम करें। इसके साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं और इनको बधाई देता हूं, जिन्होंने जम्मू एवं काश्मीर से धारा–370 हटाकर राष्ट्रहित में एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसी तरह से अपना आशीर्वाद और प्यार इस विधान सभा में बनाये रखेंगे और इसी तरह से अपने क्षेत्र में विकास के कार्य कराने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्षः टेक चंद शर्मा जी, आप अपनी बात कहें।

श्री टेक चंद शर्मा (पृथला): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन

का आखिरी सत्र और आखिरी दिन है। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस विधान सभा में दिनांक 3 नवम्बर, 2014 को पहली बार शपथ ली थी। जब हम प्रदेश की जनता के द्वारा इस सदन में नये–नये चुनकर में आये थे तो हमने यहां पर आकर देखा कि इस सदन में हमसे बहुत ही ज्यादा तजुर्बेकार विधायक, पूर्व मंत्री और नये मंत्री थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में ज्यादातर विधायक नये थे और आपने उन सभी को यह महसूस नहीं होने दिया कि नये विधायक और पुराने विधायक में क्या फर्क है। अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी इस सदन में किसी भी विषय को लेकर समस्या आई तो आपने उसके हल के लिए आपस में मिल–बैठकर सुलझाने की कोशिश की। कई बार इस सदन में ऐसे मुद्दे भी आये, जिसे सर्व–सम्मति से पास करवाया गया, चाहे वह गो–संवर्धन का मुद्दा था, चाहे तरुण सागर जी वाला मुद्दा था या फिर 12 वर्ष से कम उम्र की छोटी बच्चियों के साथ जो अनैतिक कार्य होते थे, उसमें फांसी की सजा का मुद्दा था और इन सभी प्रस्तावों को इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने सर्व–सम्मति से पास करने का काम किया, इसके लिए भी मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं। यह निश्चय ही कहा जा सकता है कि पक्ष का काम अपने पक्ष को रखना होता है और विपक्ष का काम अपने पक्ष को रखना होता है। यह जरूरी नहीं है कि हर चीज में विपक्ष की भूमिका अलग ही रहे, क्योंकि सरकार के द्वारा जो अच्छे काम किये जाते हैं, विपक्ष को उसका भी समर्थन करना चाहिए। हमने काफी समय बाद इस सदन में देखा है कि हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य किसी भी विषय में जबरदस्ती कूद पड़ते थे। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई।)** उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें माननीय अध्यक्ष महोदय की दरियादिली यहां तक देखने को मिली कि इन्होंने कई बार हमारे माननीय सदस्यों को नेम किया और नेम करने के बाद उन सभी को इस सदन से बाहर का रास्ता भी दिखाया, लेकिन जब सदन के माध्यम से लीडर ऑफ दि हाउस के पास यह अपील गई तो उन्होंने अपनी दरियादिली दिखाते हुये, उन सभी को पुनः वापस बुला लिया और पूरे साल का उनका सस्पेंशन खत्म कर दिया। हमारे माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी ने कहा कि इस महान सदन में पूर्व की सरकारों में जब किसी माननीय सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ जाता था तो उसको वापिस नहीं लिया जाता था। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे श्री करण

दलाल जी, श्री कुलदीप शर्मा जी और श्री केहर सिंह रावत जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन सरकार लेकर आई थी लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए हाउस की सर्वसम्मति से इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन को भी वापस ले लिया गया था, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इस विषय पर कहा था कि पूर्व की सरकारों में ऐसे पहले कभी नहीं होता था। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सौहार्दपूर्ण विषय इस महान सदन के लिए और क्या हो सकता है? हम मानते हैं कि कई बार इस महान सदन में इस तरह का माहौल बन जाता है और माननीय सदस्यों से भी छोटी–मोटी गलतियां भी हो जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक विकास की बात है तो चाहे आप पिछली सदनों में बैठकों की कार्यवाहियों का पूरा रिकॉर्ड उठाकर के देख लें। जहां दो घंटे सदन का समय शेष रहता था उस समय पर भी माननीय सदस्यों द्वारा विकास की डिमांड्ज़ की जाती थी। इसके पीछे एक ही कारण रहा है कि ''सबका–साथ सबका–विकास और सबका–विश्वास''। उपाध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि इस बार प्रदेश की जनता ने सोच लिया है कि आने वाले समय में भी हरियाणा प्रदेश के यही मुख्यमंत्री रहेंगे। आज इस महान सदन में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की भी वहीं डिमांडज़ हैं जो 5 साल पहले हुआ करती थी। आज भी यही डिमांडज़ लगातार करते आ रहे हैं कि हरियाणा में अगर कोई विकास करवा सकता है तो सिर्फ श्री मनोहर लाल जी ही करवा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास की बात है तो वहां पर अब तक लगभग 2500 करोड़ रुपये के विकास कार्य हो चुके हैं। मेरे क्षेत्र में श्री विश्वकर्मा स्किल डिवैल्पमैंट यूनिवर्सिटी से लेकर, रैनीवाल स्कीम, गवर्नमैंट कॉलेज, नर्सिंग डिग्री कॉलेज और 3–3 आई.टी.आईज. आदि जबरदस्त विकास कार्य हुए हैं, शायद ही इतने विकास कार्य किसी अन्य सरकारों के कार्यकाल में हुए हों या यूं कहें कि ''सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी''। उपाध्यक्ष महोदया, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनता में ''विकास और विश्वास'' की अलख जगाई है। आज के दिन हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, हम उसके लिए वाकई दिल की गहराई से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं जो हमारे कैबिनेट और राज्य मंत्री हैं, सभी ने प्रदेश के सभी हल्कों में विकास के कार्यों को करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ रखी है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि श्रीमती कविता जैन के विधान सभा क्षेत्र की सीमा हालांकि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीमा के साथ नहीं लगती है परन्तु फिर भी मैं इनके पास कभी किसी काम के लिए

गया तो इन्होंने मुझे कभी भी काम के लिए मना नहीं किया। मैं इसके लिए सरकार का और सभी माननीय मंत्रियों का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस 13वीं विधान सभा के सत्र का आखिरी दिन है इसलिए हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें और इस विधान सभा में दोबारा से जीतकर भी आयें। उपाध्यक्ष महोदया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में किसी तरह का फर्क हुआ हो। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यह देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है और विकास के नये–नये आयाम भी स्थापित कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, समय का अभाव होने के कारण अब मैं अपनी वाणी को विराम देते इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मुझ से इन पांच सालों में किसी प्रकार की कोई गलती जाने अनजाने में हो गई हो तो उसके लिए मैं सदन से क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद । जय हिन्द।

श्रीमती प्रेम लता (उचाना कलां): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इस महान सदन को बताना चाहूंगी कि मैं उचाना हल्के से विधायक चुनकर आई हूं इसलिए मैं उचाना हल्के की ही बात करूंगी। जब मैं इस विधान सभा क्षेत्र से विधायक बनी थी तो मेरे सामने एक ही समस्या थी कि 15 साल पहले हरियाणा प्रदेश में जब चौटाला साहब का राज हुआ करता था और इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने भी 10 साल तक हरियाणा प्रदेश में राज किया। इन 15 सालों में इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। चाहे आप स्कूलों के अपग्रेडेशन की बात कर लें, चाहे गलियों की बात कर लें और चाहे सड़कों की बात कर लें। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि पिछले 15 सालों से उचाना हल्के को विकास के नाम पर अनदेखा कर दिया गया है लेकिन मैं जब आज अपने उचाना हल्के के विकास की तरफ निगाह दौड़ाकर देखती हूं तो आज उचाना हल्का पहले से बेहतर नजर आता है। मैं इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का करती हूं और इसके साथ ही साथ मैं सभी मंत्रीगण का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने तुरन्त फाइलों पर एक्शन लिया क्योंकि फाइलें तो इनके हाथों से ही अप्रूव होती हैं। उपाध्यक्ष महोदया, अधिकारियों के पास जो विकास की फाइलें होती हैं यदि वे माननीय मंत्रियों के पास समय पर फाइलें नहीं पहुंचाते हैं तो कोई काम सिरे नहीं चढ़ पाता है इसलिए मैं सभी अधिकारियों का भी विशेषतौर पर धन्यवाद करती हूं। उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक उचाना हल्के की बात है तो वहां पर पहले उप–तहसील

भी नहीं हुआ करती थी, उसको भी उप–तहसील से अब तहसील बनाया गया और तहसील से सब–डिवीजन भी बनाने का काम किया गया। जिसकी वजह से आज वहां पर एस.डी.एम., डी.एस.पी., तहसीलदार आदि बड़े अधिकारी/कर्मचारी बैठते हैं। इस नाते से स्थानीय लोगों की जो दिक्कतें थी, वे सब दूर हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पीछे 25 मार्च के आस–पास उचाना हल्के में आये थे और उन्होंने सिरसा ब्रांच हैड के माध्यम से हमारे 16 गांवों को पानी देने का काम किया, इसके लिए 16 गांवों के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट किया है। उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से गांव छात्तर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे। गांव छात्तर के बारे में इस महान सदन को अवगत करवाना चाहूंगी कि यह एक ऐसा गांव है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था। उपाध्यक्ष महोदया, अभी हाल ही में हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे तो उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने मत का प्रयोग किया। यहां से हम पहले लगभग 2700 वोटों से हार जाया करते थे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा किए गए विकास के कार्यों को देखते हुए आज के दिन यहां से हमें 300 वोटों की जीत मिली है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अकेले गांव छात्तर से हमारी भारतीय जनता पार्टी को 3000 वोटों से लोकसभा चुनाव में जीत मिली है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहती हूं कि छात्तर हमारे जींद जिले का सबसे बड़ा गांव है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहेदिल से धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर जाकर जो अनाउंसमैंट्स की थी अधिकारियों ने उन अधिकतर अनाउंसमैंट्स को निर्धारित समय–सीमा के अंदर पूरा करके दिखाया है। उनमें से जो थोड़ी बहुत रह गई हैं मुझे उम्मीद है कि वे भी जल्दी से जल्दी पूरी हो जायेंगी। इसी तरह से चार साल पहले कैप्टन पवन सिंह शहीद हुए थे उनकी शहादत को याद करते हुए बधाना गांव में हार्टिकल्चर सैन्टर का सब–स्टेशन बनने जा रहा है जिसकी चारदीवारी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि हार्टिकल्चर के इस सब–सैंटर का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जायेगा। इसी प्रकार से मैं अपने हल्के के 50 बैड के अस्पताल के बारे में कहना चाहूंगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में यह कहा गया था कि वहां पर 50 बैड का हॉस्पिटल बनाया जायेगा लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकार की यह घोषणा केवल मात्र कोरी घोषणा ही बनकर ही रह गई और वहां पर हॉस्पिटल के नाम पर एक ईंट तक भी नहीं लगी। हमारी सरकार आने के बाद ही वहां पर हॉस्पिटल का भूमि–पूजन किया गया और आज हमारा 50 बैड का हॉस्पिटल भी वहां पर तैयार

हो चुका है। ऐसे ही हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के 8–9 स्कूल्ज़ को अपग्रेड किया गया। हमारी सरकार आने के पहले के समय तक मेरा उचाना कलां विधान सभा क्षेत्र शिक्षा के मामले में पूरी तरह से पिछड़ा हुआ था क्योंकि वहां पर न तो स्कूल अच्छे थे और न ही टीचर्ज़ अच्छे थे। हमारी सरकार द्वारा ही अलेवा में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई जोकि अब फंक्शनल हो गया है। गांव नगूरा में हमारी सरकार द्वारा पी.एच.सी. का निर्माण करवाया गया और इसी प्रकार से अलेवा में स्थित पी.एच.सी. को अपग्रेड करके सी.एच.सी. बनाया गया। हमारी सरकार के इन कार्यों से मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति होगी। हमारी सरकार ने ही अलेवा को सब–तहसील का दर्जा दिया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 10 अम्बेडकर भवन बनने जा रहे हैं। जब हमारी सरकार सत्तासीन हुई थी तो उस समय सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा यह कहा गया था कि यह एक अनुभवहीन सरकार है लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने बहुत से ऐतिहासिक निर्णय लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में चहुंमुखी विकास की गंगा बहाई है। इससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री और पूरी सरकार अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों में और अब तक की सभी सरकारों में प्रदेश की तमाम जनता के सबसे चहेते बन गए हैं। अगर हम प्रदेश में किसी भी आयु और वर्ग के व्यक्ति से यह पूछें कि हरियाणा प्रदेश के अब तक आपने जितने भी मुख्यमंत्रियों को देखा है उनमें सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन हैं? उनकी जुबान पर केवल मात्र एक नाम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का ही होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भेदभाव के ग्रुप–घ सहित सभी सरकारी नौकरियों में जो भर्ती की वह अपने आप में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य है। हमारी सरकार के समय में प्रदेश के गरीब बच्चों को भी सरकारी नौकरियों की प्राप्ति हुई है जोकि हमारी सरकार के सत्तासीन होने से पहले पूर्ण रूप से असम्भव था। शुरू में इसके ऊपर कई तरह के सवाल उठे कि यह सब गलत हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी की भी गलत बात को न सुना और न ही माना। उन्होंने अपने कार्यों से लोगों के गलत अनुमानों को सही साबित करके दिया है। क्लास–4 की नौकरियों में बी.एस.सी. और एम.एस.सी. पास बच्चों का भी सिलैक्शन हुआ है। इससे उनमें खुशी की लहर है क्योंकि वे यह मानते हैं कि सरकारी

नौकरियों के मामले में अब हरियाणा में माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अब क्लास–4 की नौकरी मिली है और अगर वे मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में उन्हें इससे अच्छी नौकरी भी मिल जायेगी। इस प्रकार से प्रदेश की जनता में माननीय मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो गया है और भविष्य के लिए उन्हें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है कि उनका भविष्य बेहद उज्ज्वल होगा। मैं माननीय स्पीकर महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी माननीय सदस्य को बलपूर्वक उठाकर सदन से बाहर नहीं निकाला गया। उनका स्वभाव बेहद विनम्र है और उन्होंने किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को तुरंत सम्भालकर सदन के माहौल को खुशनुमा बनाने का काम किया है। कभी भी यहां पर किसी भी माननीय सदस्य को मार्शल की सहायता से बाहर निकलवाने की नौबत नहीं आई। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा समय–समय पर वॉक–आऊट तो किया जाता रहा है लेकिन वह अलग मैटर होता है। मेरा यही कहना है कि विपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य को कभी भी ज़ोर–जबरदस्ती करके सदन से बाहर नहीं निकाला गया। माननीय स्पीकर साहब के कार्यकाल के दौरान सभी सैशन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चले हैं। इस बात को विज साहब तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये पांच बार विधायक रह चुके हैं। इन्होंने तो अपनी आंखों से देखा है कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय में किस प्रकार से विपक्ष के माननीय सदस्यों को हाउस से बेइज्जत करके और धक्के देकर बाहर निकाला जाता था। हमारी सरकार के शासनकाल के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके लिए माननीय स्पीकर महोदय बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार से जहां तक स्पोर्टस की बात है स्पोर्टस में जितना नाम हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमारी सरकार के शासनकाल में कमाया है उतना पहले कभी नहीं कमाया था। इसका श्रेय हमारी सरकार की प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बनाई गई विशेष नीतियों और ईनामों की भारी–भरकम राशि निर्धारित करने को जाता है। हमारी सरकार द्वारा विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये के इनाम देने की घोषणा की जाती है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को अभी तक 420 करोड़ रूपये की राशि वितरित की जा चुकी है जो कि अपने आप में मिसाल है। ऐसा करके हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। इतना सब होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के माननीय साथियों द्वारा बार–बार ये आरोप

लगाये जाते हैं कि हमारी सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली इमानी राशि को कम कर दिया है। यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुकी है कि उनके इस प्रकार के सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को बहुत सी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करें और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष का नाम रोशन करें। हमारी सरकार की खेलों से सम्बंधित कल्याणकारी नीतियों के कारण ही खेलों के मामलों में हरियाणा प्रदेश देश के दूसरे सभी राज्यों से बहुत अग्रणी है। इसी कारण से एशियन गेम्ज़ में सबसे ज्यादा मैडल हरियाणा के खिलाड़ियों को ही मिले थे जिनमें साक्षी मलिक इत्यादि बहुत से खिलाड़ी शामिल थे। इसी के साथ मैं यह भी बताना चाहूंगी कि रोहतक रोड पर जींद के बाई–पास की सैंक्शन पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में हुई थी लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उस पर घास उग आई है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस बाई–पास का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाया जाये। मेरी एक डिमाण्ड यह भी है कि उचाना बाई–पास को भी जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। इस बारे में माननीय मंत्री राव नरबीर जी से मुझे जानकारी मिली है कि इस बाई–पास की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हो चुकी है। मैं बार–बार यही कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार के समय में पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास के अभूतपूर्व और एतिहासिक कार्य हमारी सरकार के समय में ही हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने अनेक मौकों पर हरियाणा सरकार की उनके द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों के लिए पीठ थपथपाई है। जहां तक विपक्षी पार्टियों का सम्बन्ध है उनका तो एकमात्र मकसद और एकमात्र एजेंडा यही है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना और बुराई की जाये। कांग्रेस पार्टी सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने ऐसा चश्मा पहन रखा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के अच्छे कार्य होते हुए भी दिखाई नहीं देते और कमियां न होते हुए भी दिखाई दे जाती हैं। मैंने बहुत से पक्ष और विपक्ष के माननीय विधायकों से बात की है उनमें से मुझे किसी ने भी यह नहीं कहा कि हमारी पार्टी की वर्तमान हरियाणा सरकार के शासनकाल में उनके यहां पर विकास के कार्य न हुए हों। मैं भी यह कहती हूं कि हमारे इलाके में पिछले 15 सालों से जो विकास नहीं हुआ था वह अब हुआ है। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करके एक सराहनीय काम

किया है। इसके साथ ही साथ शहीदों के परिवारों में अगर किसी का लड़का या लड़की नौकरी के लिए योग्य था तो वहां पर नौकरी भी प्रदान की गई है क्योंकि शहादत पाने वालों में हरियाणा अग्रणी राज्य रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, इस बार का लोकसभा चुनाव देशभक्ति के नाम पर लड़ा गया था। हमारे सैनिकों ने तिरंगे का मान रखते हुये सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसी प्रकार से अभी धारा 370 तथा 35–ए को हटाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। जो लोग इनके 56 इंच के सीने की बात कह कर मजाक उड़ाते थे यह काम उस 56 इंच वाले मोदी जी ने ही करके दिखाया है क्योंकि यह और किसी के बस की बात नहीं थी। अब मैं सर, छोटूराम के बारे में भी बोलना चाहती हूं। सर, छोटूराम देश के विभाजन से पहले भी मंत्री रहे हैं और मंत्री रहते हुये उन्होंने किसानों के हित के बहुत सारे काम किये थे। उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया था तथा उनके नाम से दीनबंधु ग्रामीण विकास की योजना चला कर उनका मान बढ़ाया है। इसी प्रकार से डॉ. मंगलसैन के नाम से शहरी विकास योजना चला कर शहरों के लिए पैसा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सर छोटूराम का मुकाबला सरदार बल्लभ भाई पटेल से करते हुये कहा था कि सर छोटूराम बहुत बड़े किसान नेता थे। मेरे लिए यह बहुत फख्र की बात है कि उस परिवार में मेरा विवाह हुआ है। अंत में मैं कहना चाहती हूं कि जितने भी मुख्यमंत्री आये उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को आगे किया केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ही सर छोटूराम जी को आगे किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश यादव (नारनौल): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आज से 5 साल पहले जब हम पहली बार विधायक बन कर इस सदन में आये तो हमें लगता था कि इस प्रदेश की राजनीति जिस प्रकार से पहले चलती रही है जिसमें क्षेत्रवाद तथा जातिवाद हावी रहे हैं क्या उससे मुक्ति मिल सकती है? आज जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दे कर सरकार को चलाने का जो नारा दिया उसके फलस्वरूप एक बहुत बड़ा अन्तर हमें देखने को मिला है। हमें यह भी देखने को मिला कि पहले जो आपाधापी से सरकारें चलाते थे तथा सभी प्रकार की रूह रियायतें होती थी, पिछले 10 साल तक जिनकी सरकार रही आज उसी पार्टी

के विधायक हाउस में बैठ कर शिकायतें करते हैं कि मेरे गांव में पीने का पानी नहीं है, कोई कहता है कि मेरे गांव के जोहड़ का मोगा नहीं लगा हुआ है। आज वे इन छोटी–छोटी बातों के लिए हाउस में शिकायत करते हैं। विकास के कामों से हम इतने संतुष्ट हैं कि पिछले 5 साल में हमने विकास कार्यों के लिए जो भी मांग की वह हमारी पूरी हुई है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूं। हम अपने क्षेत्र में विकास के सभी कार्य पूर्ण रूप से करवाने में सफल रहे हैं। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि बी.एस.पी.(बिजली, सड़क तथा पानी) मैं उससे भी आगे बढ़ कर कहता हूं कि बी.एस.एस.एस.पी. यानि बिजली और पानी तो है ही है लेकिन जो तीन एस.एस.एस. हैं उससे सड़क, शिक्षा तथा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हमने जो चाहा वही कार्य हुआ है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा उनके मंत्री मण्डल के सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल में हमने अपने क्षेत्र की जो भी मांग उठाई हमारी वे सभी मांगें पूरी हुई हैं। कुछ काम पूरे हो गये हैं तथा कुछ पर काम चल रहा है। आज हमारे क्षेत्र की जनता इन विकास के कार्यों से खुश है तथा आज मैं उन्हीं की आवाज बुलन्द करते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंत्री मंडल के सभी साथियों का फिर से अभिनन्दन करता हूं तथा आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं सदन के सभी सदस्यों तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष महोदया का भी धन्यवाद करता हूं कि हमने जब भी समय मांगा इन्होंने हमें बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द, जय भारत।

श्री घनश्याम सर्राफ (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदया, हम आपका व अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हैं क्योंकि इससे पहले हम विपक्ष में सामने वाले बैंचों पर बैठते थे और उस समय जो अध्यक्ष थे वह हमें बोलने का मौका नहीं देते थे । आपने और अध्यक्ष जी ने विपक्ष को बोलने का ज्यादा समय दिया है उसके लिए मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में जो विकास के पौधे लगाए हैं वे अब फल–फूलकर बड़े होने लग गए हैं । हमारे शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास जी ने मेरे क्षेत्र के दो स्कूलों को तो अपग्रेड किया है और लड़कियों का स्कूल बनवाने की मेरी एक डिमांड वर्ष 2009 से थी जिसके बारे में अभी मेरी मंत्री जी से बात हुई है जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाली 15 तारीख से पहले हम उस स्कूल का शिलान्यास कर देंगे । उसके लिए मैं मंत्री का धन्यवाद करता हूं । इसी तरह से अनिल विज जी ने हॉस्पीटल व खेलों के मामले में बहुत

सुधार किया है । पहले भिवानी के हॉस्पीटल की ओ.पी.डी. 650 व्यक्ति प्रतिदिन थी आज वह बढ़कर 2500–3000 व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है । इसी प्रकार से खेलों में खिलाड़ियों के इनाम की राशि बढ़ाई गई है । राष्ट्रीय मैडल खेलों में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने अव्वल स्थान प्राप्त किया और एशियन गेम्ज में भी हमारे खिलाड़ियों ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है । ओलम्पिक खेलों में हमारे प्रदेश से जो टीमें गई हैं उनमें भी हमारे प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने अच्छा स्थान प्राप्त किया है । इसी तरह से श्री ओमप्रकाश धनखड़ जो पहले हमारे सिंचाई व कृषि मंत्री थे अब ये किसान कल्याण मंत्री भी हैं । इन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अनेक काम किए हैं । जो यह दर्शाते हैं कि मंत्री जी ने स्वामीनाथन आयोग को लागू करने के जो वायदे किए थे उनमें हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और अगले पांच साल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के तहत जो किसानों की आमदनी डबल करने की बात कही गई थी वह पूरी हो जाएगी । इसी तरह से माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी अपने अन्दर हर तरह के कुबेर को छुपाए हुए हैं और इनका खजाना भरा रहता है । इनके पास किसी काम के लिए धन की कोई कमी नहीं है । इसी तरह से पंवार साहब मेरे साथ पिछली सरकार में भी विधायक थे । इन्होंने परिवहन के मामले में इनके अन्दर जो योग्यता है उसको दर्शाया है जिससे आज पूरा प्रदेश चकित है कि इन्होंने किस प्रकार से कार्य किए हैं । ये जेल मंत्री भी हैं और कई बार ये बिजली विभाग को भी देखते हैं । इसी तरह से हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती कविता जैन ने भिवानी नगरपरिषद में 125 करोड़ रुपये दिए हैं जोकि भिवानी को इतना पैसा पहली बार मिला है । इसके अलावा मंत्री जी भिवानी में अमृत योजना के तहत 163 करोड़ रुपये के काम करवा रही हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं । इसी तरह से पिछली सरकार ने जिन सड़कों को भिवानी से पहले ही रोक दिया था जैसे रोहतक वाली सड़क को खैरड़ी मोड़ पर, चांग वाली सड़क चांग और सिसर खास के बीच में जहां से भिवानी जिला शुरू होता था वहीं वह काम रुक जाते थे । अब उन सड़कों को बनाने के लिए भाई राव नरबीर सिंह जी ने लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है । इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । इसी तरह से श्री कृष्ण बेदी, श्री कर्ण देव कम्बोज, श्री मनीष ग्रोवर और श्री बनवारी लाल जी भी जो–जो विभाग संभाल रहे हैं उनमें वे भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं । उसके लिए मैं सभी राज्य मंत्रियों का स्वागत करता हूं ।

15:00 बजे

उपाध्यक्ष महोदया, यह हमारे प्रदेश के मंत्रियों की मेहनत का ही परिणाम है कि हमारे यहां स्थित खरकड़ी हैड पर बने एस्केप नाला से जो पानी व्यर्थ चला जाता था, आज उस पानी का सदुपयोग किया जाने लगा है। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने सदन में विकास के विभिन्न कार्यों के लिए जो सभी मंत्रियों के नाम लेकर बात की है वह इसलिए की है क्योंकि इन सभी मंत्रियों ने पूरी इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश के विकास में अपना अपूर्णीय योगदान दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, इन सबके अतिरिक्त अब मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। कथनी और करनी को एक समान करके प्रदेश के हित में कार्य करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदया, जैसाकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने तथा देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का जो काम किया है, इसके लिए मेरे क्षेत्र में बहुत खुशियां मनाई गई। लोग इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। मेरे क्षेत्र के दुकानदार भी इस कार्य में पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाई दी तथा आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी की तारीफ की। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे विपक्ष के साथी जो धारा 370 को हटाने का विरोध कर रहे हैं तथा जिन्हें भारत माता की जय के नारे से भी परहेज है, इनके इस तरह के कार्य से जनता को पता चल गया है कि इनके अंदर कौन सी देशभक्ति की भावना पनप रही है। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्रीमती संतोष चौहान सारवान (मुलाना) (एस.सी.): उपाध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करती हूँ और साथ ही यह भी कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान आपने तथा स्पीकर साहब ने सदन को निष्पक्ष और मर्यादित ढंग से चलाया है उसके लिए आप सराहना के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आज इस सदन के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी बहुत अभिनन्दन और वंदन करती हूँ जिन्होंने बहुत इमानदारी के साथ, विकासशीलता की भावना के साथ तथा पारदर्शितापूर्ण तरीके से सरकार को पोने पांच साल तक चलाया है। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने करीब चार साल नो महीने हो गए हैं और इस पूरे समय में हरियाणा में चहूंमुखी

विकास हुआ है और किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कथन के मुताबिक 'हरियाणा एक– हरियाणवी एक' की अवधारणा पर काम करके दिखाया है। मेरा हल्का मुलाना 100 प्रतिशत एक ग्रामीण हल्का हुआ करता था। 2 अक्टूबर, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री जी मुलाना विधान सभा क्षेत्र में एक विशाल रैली को संबोधित करने के लिए आए थे। यहां पर आते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुलाना विधान सभा क्षेत्र में कोई कस्बा शामिल नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि मुलाना विधान सभा क्षेत्र सारा का सारा ग्रामीण हल्का है। इसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि अकेले बराड़ा में 22 हजार की आबादी है लेकिन बावजूद इसके यहां पर अभी भी ग्राम पंचायत काम करती है। इसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से यहां पर नगरपालिका का गठन करने बारे अनुरोध किया और मेरे अनुरोध के सवा तीन महीने की समयावधि में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बराड़ा में नगर पालिका का गठन कर दिया। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आज इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगी कि विगत में बराड़ा को नगरपालिका बनाने के लिए दो बार नोटिफिकेशंज हो चुकी थी लेकिन यहां के जो पूर्व जनप्रतिनिधि थे उन्होंने दो बार बराड़ा को नगरपालिका बनने से रुकवाया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यहां पर कोई विकास का कार्य हो। जिस वक्त मैं पहली बार मुलाना से एम.एल.ए. बनी तो मैंने धरातल पर जाकर देखा तो पाया कि यहां पर विगत 15 सालों में विकास के कोई भी कार्य नहीं हुए थे। यहां के बाशिंदे बुरे हाल में जीने को मजबूर हो रहे थे। जब माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हमारे हल्के में आये तो मैंने उनके सामने 100 के करीब मांगे रखी थी और मुझे यह बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि उन 100 डिमांड्ज में से 97 डिमांड्ज कंप्लीट हो गई हैं और 3 मांगों पर काम चल रहा है। आज मेरी कोई भी डिमांड ऐसी नहीं बची है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी प्रकार की कोई मांग कर सकूं। मुख्यमंत्री महोदय से हमने जो कुछ मांगा इन्होंने उसे देने का काम किया। सबसे पहले मेरे हल्के में नगरपालिका बनाने का काम किया उसके बाद यहां पर 39 करोड़ रूपये की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने की मंजूरी दी और यही वजह है कि आज यहां पर 102 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन काम कर रही है। जहां तक मेरे हल्के में पी.एच.सी. की बात है तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने मुलाना और बराड़ा की दोनों पी.एच.सीज. को सी.एच.सीज. बनाने का काम किया जिसके लिए मैं उनका

धन्यवाद करती हूँ। हमारी सरकार ने मेरे हल्के के नौंनी गांव में आई.टी.आई. बनाने का फैसला लिया है। उपाध्यक्ष महोदया, पहले मेरे हल्के में सड़कों का बहुत बुरा हाल होता था, लेकिन हमारी सरकार ने सभी सड़कों की रिपेयर करते हुए 12 फीट चौड़ाई की जगह 18 फीट की चौड़ाई की सड़कें बना दी है और कुछ नई सड़कों का निर्माण भी किया है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे हल्के में 55 सामुदायिक केन्द्र बनाए गए हैं। इस प्रकार से अब गरीब आदमी को अपने बच्चों की शादी के लिए किसी मैरिज पैलेस को बुक करने की जरूरत नहीं है। मेरे हल्के में दो रेलवे ओवर व अंडर ब्रिज बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदया, बराड़ा में जो बीच की सड़क थी, वह 8.5 करोड़ रुपये की लागत से फोर लेन बनाई गई है। नहर से पानी की सप्लाई न होने की वजह से हम लोग टयूबवैल पर ही डिपैंड रहते हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अंदर 83 नये ट्यूबवैल्ज लगाने का ऐलान किया हुआ है। दो नये पॉवर हाउसिज का निर्माण किया गया है। मारकण्डे पर एक नया पुल बनाया गया है, जिससे हमारे 35 गांवों को सुविधा मिली है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं इतने विकास के काम होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। मेरे हल्के में सारे के सारे विकास के काम होने के कारण अब कोई भी विकास का काम पैंडिंग नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी सहयोगी टीम के साथ–साथ आपको और अध्यक्ष महोदय को बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य की शुभ कामनाएं भी करती हूँ। धन्यवाद ।

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से एक बात पूछना चाहता हूँ कि पहले हमारा हाउस करोड़ों रुपये खर्च करके चमचमाता हुआ आलीशान हुआ करता था लेकिन अब इसे तोड़–फोड़ दिया गया है। इसकी क्या वजह रही है? यह बात सदन में सदन के नेता को बतानी चाहिए। क्या इसमें हरियाणा सरकार की कोई नई शुरूआत हुई है या फिर किसी अन्य डिपार्टमैंट ने ऐसा करने का निर्देश दिया हुआ है, यह बात सदन को पता लगनी चाहिए। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : दलाल साहब, प्लीज आप बैठ जाइये क्योंकि सभी सदस्यों ने बोलना है। श्री कुलवन्त राम बाजीगर जी आप अपनी बात केवल दो मिनट में ही कंक्लूड कीजिए।

श्री कुलवन्त राम बाजीगर (गुहला) (एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम बड़े किस्मत वाले हैं कि हमें विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। पहले मेरा गुहला हल्का बहुत पिछड़ा हुआ करता था। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक विकास पुरूष ने इतने विकास के काम करवाएं हैं, जिसके बारे में कहना चाहूँगा कि–

'आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं,
लेकिन खुदा के नूर से, आदम जुदा नहीं।'

ऐसे विकास पुरूष ने जहां पर कोई दिक्कत देखी वहां पर बड़े ही सहज तरीके से काम करने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदया, यदि मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ तो गुहला हल्के में हमारी बेटियों के लिए कन्या महाविद्यालय बनवाया गया है। मेरे हल्के के 12 स्कूल्ज अपग्रेड किए गए हैं। लगभग 4.47 करोड़ रुपये की लागत से आई.टी.आई. की बिल्डिंग बनवाई गई। चार स्टेडियम मंजूर किए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदया, यदि में स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूँ तो दो पी.एच.सीज. एक अगोध गांव व दूसरी हरनोली गांव में खोलने के साथ–साथ शवगृह का भी निर्माण किया गया है। हमारी सरकार ने मारकण्डा, उरलाना, पहाड़पुर तथा पापशर माइनर का करोड़ों रुपये की लागत से निर्माण करवाया जो आखिरी टेल तक पानी पहुँचाने का काम करेगी। शहर में मारकण्डा माइनर को अण्डर ग्राउण्ड बना दिया गया है। पहले मारकण्डा माइनर अण्डर ग्राउण्ड न होने की वजह से पूरा शहर दो भागों में बंटा हुआ था, लेकिन अब अण्डर ग्राउण्ड होने पर शहर की सुन्दरता बढ़ी है। उपाध्यक्ष महोदया, यदि मैं सड़कों की बात करूँ तो लगभग 50 सड़कें ऐसी थी जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती थी उनको पक्का करने का काम किया है। शहर की अनेकों सड़कें रबड़ की बना दी गई हैं। यदि मैं बिजली के क्षेत्र की बात करूँ तो 33 के.वी.ए. के 11 पॉवर हाउसिज़ गुहला हल्के में चालू कर दिए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे हल्के में विकास के अनेकों काम करवाएं हैं, जिससे मैं तो यही कहता हूँ कि अगर यही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी 15–20 साल हरियाणा की बागडोर संभालते रहे तो गुहला हल्के को भविष्य में विकास के काम की कोई जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि अपने आप ही विकास के काम होते रहेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार को आबादकार और

पट्टेदारों की मांगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इतने काम करने के बाद अगर एक यह काम भी हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा । मेरा कहना है कि अभी हरियाणा बहुत ज्यादा बदलने वाला है । हमारी सरकार ने राजनीति के मायने बदल दिए हैं । मैं अपनी सीट पर बैठने से पहले एक शेर अवश्य पढ़ना चाहूंगा –

विकास की असली उड़ान अभी बाकी है,
हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है ।
अभी तो नापी है मुट्ठीभर जमीन हमने,
सारा आसमान अभी बाकी है ।

धन्यवाद । जय हिन्द ।

श्री रविन्द्र कुमार (समालखा) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे सदन में बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं सदन में बैठे हुए देख रहा था कि आप लेडी मैम्बर्ज को बोलने के लिए ज्यादा समय देते हो और जैंट्स मैंम्बर को कम समय देते हो । प्रदेश के विकास के विषय पर बोलने के लिए हमारे पास कोई बात नहीं बची है क्योंकि विकास के काम ही इतने ज्यादा हुए हैं । हरियाणा प्रदेश में एक समान विकास किया गया है । इस बात को तो माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल भी मानते हैं । मुझे यहां पर एक बात खराब लगी, वह यह कि सदन में कई सदस्य अंग्रेजी में बोलते हैं । यहां पर सदन की कार्यवाही देखने के लिए गांवों से लोग भी आते हैं और हमारे कार्यकर्त्ता भी आते हैं। उन बेचारों को अंग्रेजी नहीं आती है । अतः मेरा निवेदन है कि सदन में अंग्रेजी में बात न की जाए । माननीय मुख्य मंत्री महोदय की यहां पर सभी ने प्रशंसा की है और पूरा प्रदेश इनकी प्रशंसा कर रहा है । मैं आने वाले विधान सभा चुनावों के विषय में कहना चाहूंगा कि इनमें कोई भी झगड़ा मत करना क्योंकि सभी माननीय सदस्य केवल मोदी जी और मनोहर लाल जी के नाम से ही जीत जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इन 5 सालों में तो वे विधुर पैंशन लागू नहीं कर पाए लेकिन अगले प्लान में इसे जरूर लागू कर दें। जब कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसको विधवा पैंशन दी जाती है। इसी तरह जब किसी पुरूष की औरत मर जाती है तो बच्चे तो उसको भी पालने पड़ते हैं, इसलिए विधुर की भी पैंशन चाहिए । अगर मुख्य मंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनसे यह काम हंगे से करवाएंगे । इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि अब तो मोदी जी ने जम्मू–कश्मीर का भी रास्ता खोल दिया है । मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है कि अब हमें बहुएं लाने के लिए बिहार नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अब

हम जम्मू–कश्मीर से भी बहुएं ला सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती रोहिता रेवड़ी (पानीपत शहर): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मेरे पानीपत शहरी हल्के की जो भी समस्याएं थी, उनका समाधान करवाया गया है। मेरे हल्के में बहुत से विकास कार्य करवाये गये हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बात को बहुत गम्भीरता से सुना और धरातल पर कार्य भी करवाये हैं। इसका रिजल्ट यह निकला कि मेरा पानीपत शहरी हल्का एक नयी दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ ही साथ कैबिनेट के सभी मंत्रियों का भी धन्यवाद करती हूं। अन्त में, मैं यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ मेरा पानीपत शहरी हल्का ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा चहुंमुखी विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। हरियाणा प्रदेश में यह बदलाव माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ही हो पाया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूं।

श्री सुभाष बराला (टोहाना): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। इस 13वीं विधान सभा का 5 साल के कार्यकाल का अंतिम स्तर चल रहा है और जिस प्रकार से आपने और अध्यक्ष महोदय जी ने इस कार्यकाल में अपनी भूमिका निभायी है। वह बहुत ही सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री ने 'सबका साथ, सबका विकास,' के साथ–साथ सबका विश्वास जितने का काम किया है। उसी प्रकार से आप दोनों (उपाध्यक्ष महोदया और अध्यक्ष महोदय) ने इस विधान सभा में सत्ता पक्ष के साथ–साथ विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी बोलने के लिए पूरा समय दिया है। कभी–कभी तो हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से एक बात आती रही कि आपने विपक्ष के माननीय सदस्यों को बोलने के लिए ज्यादा समय दिया है। यह आपकी इस भावना का परिचायक है कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्वस्थ तरीके से व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष को अपनी बात कहने का बार–बार मौका मिलना चाहिए। इसके लिए आप दोनों ने विपक्ष के माननीय सदस्यों को बार–बार अपनी बात रखने के लिए मौका दिया है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी कुछ अपवाद को छोड़कर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां एक दूसरे पर की गयीं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार खुले दिल से माननीय

मुख्यमंत्री जी ने कार्य किये हैं और पूरी टीम को साथ लेकर चले हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता के मन में एक आशा थी कि प्रदेश में ऐसी सरकार बने जो विपक्ष को भी साथ लेकर चले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी भावना से अपनी टीम के साथ काम किया है। इसमें विधान सभा में रचनात्मक सहयोग मिला है। उसके लिए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं। इस सदन के माननीय सदस्यों का बेशक लोक सभा से सीधा नाता नहीं है लेकिन यह सभी माननीय सदस्यों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस समय सदन के सदस्य के रूप में चुनकर आएं हैं जब इस देश की राज्य सभा और लोक सभा में कई ऐतिहासिक बिल्ज पास करके एक नया इतिहास रचने का काम किया गया है। देश की राज्य सभा में कल एक नया इतिहास रचा गया है। खासतौर से राष्ट्रवादी ताकतें इस देश में आजादी के बाद से ही सालों से इसी मुद्दे को लेकर चल रही थी। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल को इस देश की एकता और अखंडता के लिए छोड़ दिया था और उसके संदर्भ में जम्मू एवं कश्मीर से धारा–370 को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक संकल्प राज्य सभा में लाया गया है। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि यह हम सभी माननीय सदस्यों के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य के रूप में चुनकर के आये हुये हैं। हम जब विपक्ष में थे तो उस समय भी हम जनता के बीच में जाते थे और जनता की भावनाएं सुनते थे कि हरियाणा की जनता प्रदेश में किस प्रकार की सरकार चाहती है। पहले हरियाणा प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्थायें ठीक प्रकार से नहीं चल पाती थीं और अलग–अलग सरकारों का अपना अलग–अलग सरकार चलाने का तरीका हुआ करता था और जन–भावनाएं दबकर रह जाती थीं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, हम जनता के बीच में जाते थे। जब हमारी नई–नई सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने माननीय सदस्यों के साथ काम करना शुरू किया तो उस समय विपक्ष के माननीय सदस्य कहा करते थे कि क्या अनुभवहीन लोग हैं, लेकिन उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ–साथ हम सभी माननीय सदस्य विपक्ष के माननीय सदस्यों को एक बात कहा करते थे कि हमें बेशक सरकार में रहने का और इस सदन में आने का हम में से बहुत ही कम सदस्यों को मौका मिला है, लेकिन जनता के बीच में रहकर के किस प्रकार से जन–मूल्यों की स्थापना करते हुये, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए, एक अच्छी सरकार

चलाई जा सकती है, इसका अनुभव हमें जरूर है। यह हमारे इस कार्यकाल का आखिरी सत्र है और मैं आज इस आखिरी सत्र में गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जितने भी चुनाव हुये, चाहे वह स्थानीय निकाय के चुनाव हों, चाहे पंचायती राज के चुनाव हों, चाहे नगर–निगम के अप्रत्यक्ष चुनाव हों, चाहे नगर–निगम के प्रत्यक्ष चुनाव हों, चाहे जींद के उपचुनाव हों या फिर लोक सभा का ऐतिहासिक चुनाव हो इन सारे ही चुनावों में जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने हमें मैंडेंट दिया और हमारे इस सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की जो कार्य प्रणाली थी, इनके मंत्रिमंडल की जो कार्य प्रणाली थी और माननीय मुख्यमंत्री जी को विपक्ष में रहते हुए जन भावनाओं को समझने का जो तजुर्बा था, उस तजुर्बे के ऊपर दोबारा से मोहर लगाने का काम इस प्रदेश की जनता ने किया और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बात भी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो चुनाव हुए, मुझे ऐसा लगता है कि यह शायद दूसरा ही मौका होगा कि किसी पार्टी की सरकार इस देश के अंदर रही हो और उसी नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया हो और उसने पहले से भी अधिक मत प्राप्त करके दोबारा से सत्ता हासिल की हो। संभवतः यह शायद दूसरा मौका इस देश के अंदर हुआ होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कारनामे को करके दिखाया और उन्हीं के पदचिह्नों पर चलते हुये, यह सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों से हरियाणा प्रदेश में चल रही है और इस दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम करके दिखाया है, उसके अनुसार इन्होंने ''सबका साथ–सबका विकास'' के नारे को सार्थक किया है और इसके साथ ही साथ इन्होंने सबका विश्वास जीतने का भी काम किया है। इसलिए मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में दोबारा से सत्ता में आकर के पिछले चुनाव से अधिक मत और सीटें प्राप्त करते हुये सत्ता में आयेगी और एक नया इतिहास बनाने का काम करेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वास्तव में प्रदेश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का एक सफल प्रयास किया है। इस सत्र के बाद यदि हम सभी माननीय सदस्य अगर मिलेंगे तो मैदान के अंदर मिलेंगे। हम सभी माननीय सदस्यों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। हमने अपने विपक्ष के साथियों से भी बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है और उसमें हम

सफल भी रहे हैं। हमारी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के लिए एक अच्छी बात यह होगी कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाते हम सभी माननीय सदस्य चुनाव में लड़ेंगे और दोबारा से जनता का मत हासिल करके इस सदन में वापिस आयेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत–बहुत धन्यवाद करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुखविन्द्र (बाढ़ड़ा) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधान सभा में उम्र में सबसे छोटा विधायक हूं। मुझे इन पांच वर्षों के दौरान सभी माननीय सदस्यों का बड़ा लाड–प्यार और सहयोग प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। इन पांच वर्षों के दौरान हरियाणा प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र बाढड़ा को भी विकास कार्यों में अन्य विधान सभा क्षेत्रों के मुकाबले में पिछड़ने नहीं दिया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, इस महान सदन के सभी माननीय सदस्यों ने बड़ी अच्छी–अच्छी बातें कही हैं। मैं भी उनकी बातों के साथ अपनी बात सम्मिलित करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री बिशम्बर सिंह बाल्मीकी (बवानी खेड़ा) (एस.सी.): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस महान सदन के आखिरी सत्र में सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने–अपने हल्कों से संबंधित बातें रखी। उपाध्यक्ष महोदया, जब आपने मुझे बोलने का मौका दिया तब आपने मुझे 2 अंगुलियों से इशारा किया कि मैं दो मिनट से ज्यादा न बोलूं तो उपाध्यक्ष महोदया मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मुझे अपनी बात समाप्त करने में 3 मिनट से भी अधिक का समय लग सकता है क्योंकि मुझे इन 5 वर्षों में इस महान सदन में बोलने का समय कम ही मिला है। आप चाहे तो रिकॉर्ड निकलवाकर देख सकती हो लेकिन आज इस महान सदन में मैं जो बातें कहूंगा वे उचित ही कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में ''हरियाणा एक हरियाणवी एक'' के नारे को लेकर सभी 90 के 90 हल्कों में ''समान काम समान विकास'' किया। यदि आप 90 के 90 हल्कों में जाकर देखोगे तो आपको असली धरातल का स्वयं ही पता लग जायेगा कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोलकर के जनता की भलाई के लिए पैसा दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और सदन का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष

महोदया, अब मैं इस महान सदन में अपने विधान सभा क्षेत्र बवानी खेड़ा की बात करना चाहूंगा। जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब भिवानी जिले को एन.सी.आर. में लिया गया था। उपाध्यक्ष महोदया, जो कांग्रेस सरकार ने सैप्पल से भिवानी तक का फोर लेन का काम बीच में ही छोड़ दिया था उसको हमारी सरकार ने लगभग 90 प्रतिशत पूरा कर दिया है। मैं इस महान सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इन्होंने उस वक्त मात्र 18–20 किलोमीटर के रास्ते को ऐसे छोड़ दिया जैसे मानो इसके साथ कोई वाघा बॉर्डर की सीमा लगती हो लेकिन उस रास्ते पर मेरे गांव खरक के साथ लगते हुए कलिंगा, बामला और नौरंगाबाद भी आते हैं। कांग्रेस सरकार ने यह रास्ता क्यों छोड़ दिया, इस बारे में मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि उनके मन में क्या था और क्या नहीं था, इस बारे में वे स्वयं ही जानते हैं। मैं इस कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और सदन का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, अब मैं अपने हल्के की बात करना चाहता हूं। मेरे हल्के के गांव प्रेम नगर में चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज दोनों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। अब इनकी चारदीवारी का कार्य शुरू हो चुका है। पिछले सप्ताह ही वहां पर 70 करोड़ रूपये की लागत से बने दो टीचिंग ब्लॉक्स का भी उद्घाटन हुआ है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 182 घोषणायें की थी जिनमें से 178 घोषणाओं का कार्य पूरा हो गया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि मेरे हल्के में कुल 182 में से 178 घोषणाओं का पूर्ण हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी और हिस्टोरिकल अचीवमैंट है। ऐसा करके हमारी सरकार निरंतर बहुत से नये–नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार की जितनी भी तारीफ की जाये वह बहुत कम होगी।

उपाध्यक्ष महोदया : विशम्बर जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए आप कृपा करके कंक्लूड करें।

श्री विशम्बर सिंह बाल्मीकी : उपाध्यक्ष महोदया जी, अपनी सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान जितने भी विधान सभा के सत्र हुए हैं उनमें मैं बहुत ही कम बार बोला हूं इसलिए आप आज तो मुझे बोल लेने दें ताकि मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बता सकूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने मेरे हल्के बवानी खेड़ा में विकास के

कितने अभूतपूर्व कार्य करवाये हैं। उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है चाहे मैं बवानी खेड़ा से बलियाली तक की सड़क की बात करूं और चाहे जमालपुर से रतेरा तक की सड़क की बात की जाये इन सड़कों सहित मेरे विधान सभा क्षेत्र की सभी सड़कों को चौड़ा और बहुत बढ़िया बना दिया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री राव नरबीर सिंह जी का बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसी प्रकार से बवानी खेड़ा शहर में सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है। ऐसे ही सभी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट्स भी लगाई गई हैं। हमारे बवानी खेड़ा में हमारी सरकार आने के पहले तक अग्नि शमन केन्द्र नहीं था। हमारी सरकार ने बवानी खेड़ा में अग्नि शमन केन्द्र की स्थापना करके एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्य किया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर बहन कविता जैन जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार मेरे विधान सभा क्षेत्र बवानी खेड़ा में लगभग 350 करोड़ रूपये की लागत से विकास के विभिन्न कार्य हमारी सरकार के शासनकाल में हुए हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है क्योंकि इतने विकास कार्य तो नवम्बर, 1966 से लेकर सितम्बर, 2014 तक के 48 साल के लम्बे समय में भी नहीं हो पाये थे। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)** माननीय स्पीकर सर, मुझे बातें तो और भी बहुत कहनी थी लेकिन समय के अभाव के कारण यह सम्भव नहीं हो पायेगा इसलिए आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री घन श्याम दास (यमुनानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से जनहितैषी और लोकप्रिय निर्णय लिये और विकास के नये आयाम स्थापित किये वह अपने आप में एक उदाहरण है। हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा के किसान को गन्ने का जो मूल्य दिया गया वह सारे देश में सर्वाधिक है। इसके लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। इसके साथ ही साथ जब हरियाणा प्रदेश का किसान पपलर की खेती को लेकर बहुत परेशान था तो नई लाईसैंस नीति लागू करके इच्छुक व्यक्तियों को लाईसैंस दिये गये जिससे प्रदेश में पपलर से जुड़ी हुई नई–नई इण्डस्ट्रीज़ की स्थापना हुई। हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार के सत्तासीन होने से पहले तक पपलर का मूल्य 400/– रूपये प्रति क्विंटल था लेकिन आज यह मूल्य 900/–

रूपये प्रति क्विंटल के आंकड़े को भी पार कर गया है इसलिए आज की तारीख में हरियाणा प्रदेश का पपलर उगाने वाला किसान माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार के गीत गा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और उनके सभी सहयोगी मंत्रियों ने "हरियाणा एक–हरियाणवी एक" का नारा देकर और पारदर्शी सरकार चलाकर सारे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और इसके साथ ही साथ योग्यता के आधार पर जो सरकारी नौकरी देने का काम किया यह उसी का परिणाम है कि हमारी सरकार आने के पश्चात् पंचायत से लेकर लोक सभा तक जितने भी चुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकार्ड तोड़ जीत हासिल की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 विधान सभाओं में विधान सभा विकास रैलियों के माध्यम से वहां के विकास के कार्यों को गति प्रदान की जिसके फलस्वरूप आज सारे का सारा हरियाणा निरंतर और बड़ी तेजी के साथ विकास और प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। हमारी सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत सी नई सड़कों का निर्माण करवाया और पुरानी सड़कों को बेहतर बनाया। ऐसे ही हरियाणा प्रदेश के लगभग सभी जिलों में 24 घंटे बिजली देने का काम किया वह भी अकल्पनीय है। इसी प्रकार से हमारी सरकार द्वारा उद्योग जगत को भी बहुत सी सुविधायें देने का काम किया गया है। हरियाणा प्रदेश के किसानों की भी सभी बातों को भी सुना गया है। हमारी सरकार द्वारा ही "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" तथा "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" इत्यादि योजनाओं के माध्यम से किसानों को उनके हितों के प्रति जागृत करने का जो काम किया गया है वह अपने आप में एक मिसाल है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाये वह कम ही होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान आपके कुशल नेतृत्व में जिस व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से इस सदन की कार्यवाही चली वह भी अभूतपूर्व है। इस महान सदन के जिन अधिकतर सभासदों ने इस सदन की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग देने का काम किया मैं उन सभी सभासदों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि हरियाणा प्रदेश की विधान सभा में जिस प्रकार से हमने इस कार्यकाल में नये मानदण्ड स्थापित किये हैं भविष्य में भी इससे अच्छे मानदण्ड स्थापित करते हुए हम हरियाणा प्रदेश की विधान सभा को अपने देश की सभी विधान सभाओं में नम्बर एक बनायेंगे। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्रीमती लतिका शर्मा (कालका): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यकाल में हम बहुत से नये विधायक थे उनमें मैं भी एक थी। शुरू में बहुत सा समय तो यह समझने में लग गया कि किसी काम को करवाने का क्या प्रोसीजर होता है। पहले न तो अधिकारियों का पता होता था और न ही विभागों की बहुत अच्छी जानकारी थी। इन सभी कामों को समझने में हमारे सभी विधायकों ने तथा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत साथ दिया है। इसके साथ–साथ हमारे सभी मंत्रियों तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने जो भी काम कहा वह करवा दिया गया तथा पैसे की भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। हमारे सभी अधिकारियों का भी सकारात्मक रुख रहा। इस प्रकार से हमें बहुत कुछ देखने और सीखने का मौका मिला। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार रही जिसने एक महिला विधायक होने के साथ–साथ हमारी जिला परिषद् की चेयरपर्सन भी महिला बनाई तथा बी.डी.पी.ओ. भी एक महिला को ही लगाया। इसी प्रकार से पहला महिला थाना भी पंचकुला में खुला तथा पहला ओ.डी.एफ. जिला भी पंचकुला ही बना। इस तरह से महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं। महिलाओं की आबादी आज के दिन 50 प्रतिशत है और हम जहां भी जाते हैं तो हम यह बात बहुत मजबूती के साथ कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शादीशुदा न होते हुए भी महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। इसी कारण उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से रसोई गैस महिलाओं को प्रदान की गई जो कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारा कालका विधान सभा क्षेत्र एक नम्बर पर आता है और हरियाणा की शुरूआत भी कालका से ही होती है। कालका का 80 प्रतिशत हिस्सा फोरैस्ट का है तथा यह म्युनिसिपल कारपोरेशन के 6 वार्डों में बंटा हुआ है। इसमें मोरनी हमारा पहाड़ी क्षेत्र रहा जहां पर पिछली सरकारों के कार्यकाल में कोई कार्य नहीं हुआ था लेकिन हमारी सरकार में चाहे सड़कों व पुलों की बात हो चाहे शिक्षा तथा स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र में अनेकों कार्य हुये हैं जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंत्री मंडल के सभी सदस्यों का तहेदिल से धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अब जो भारतीय जनता पार्टी का 75 पार का बिगुल बजा है उसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरूआत भी कालका से हो रही है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की आभारी हूं। धन्यवाद।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलने से पहले मैं सी.ए.जी. रिपोर्ट के बारे में कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा। आज सी.ए.जी. की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई थी। उस पर विपक्ष के हमारे माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल जी ने कुछ टिप्पणी की थी मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। वैसे तो सदन की परम्परा और नियमानुसार जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट रखी गई है उसको पी.ए.सी. एग्जामिन करेगी और इसमें जितने भी इशूज हैं उनके बारे में संबंधित विभागों से जवाब तलब करके तथा उनके साथ मीटिंग करके पी.ए.सी. अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेगी। इसके बावजूद भी चूंकि साथी विधायक ने प्रारम्भिक तौर पर कुछ रिस्पाँस किया था तो मैं यह अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि आपके माध्यम से उनकी संतुष्टि के लिए उनको जवाब दे दूं। इन्होंने सी.ए.जी. ने जी.डी.पी. की ग्रोथ रेट के बारे में कुछ कहा है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जब वर्ष 2014–15 में श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अक्तूबर, 2014 में हमारी सरकार बनी तो उस साल की हमारी जी.डी.पी. की ग्रोथ रेट 6.6 प्रतिशत थी तथा वर्ष 2013–14 की 6.97 प्रतिशत थी। मेरे पास उस समय के भी आंकड़े हैं। इसी प्रकार से वर्ष 2015–16 में हमारी जी.डी.पी. की ग्रोथ रेट 6.6 से बढ़ कर एक ही साल में सीधे 11.5 प्रतिशत हो गई। मान्यवर, आप जानते हैं कि जब एक ऊंचाई आ जाती है तो लगातार उस ग्रोथ रेट को मेनटेन करना अपने आप में एक चुनौती होती है लेकिन फिर भी उसके बाद भी लगातार वर्ष 2016–17 में 9.1 प्रतिशत, वर्ष 2017–18 में 7.9 प्रतिशत तथा वर्ष 2018–19 में 8.2 प्रतिशत ग्रोथ रेट हम मेनटेन कर पाये हैं। पिछले 5 वर्ष की जी.डी.पी. ग्रोथ रेट का जो एवरेज ग्रोथ रेट है ईयर ऑन ईयर वह पिछले 10 वर्ष की औसत जी.डी.पी. ग्रोथ रेट से ज्यादा है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हरियाणा की जो पूरी जी.डी.पी. ग्रोथ रेट रही है वह देश की एवरेज ग्रोथ रेट से 1 प्रतिशत ज्यादा ही रही है । बल्कि वर्ष 2013–14 में वह जी.डी.पी. ग्रोथ रेट देश की ग्रोथ रेट से नीचे चली गई थी । देश की जो जी.डी.पी. ग्रोथ रेट 7.4 प्रतिशत थी उसमें हरियाणा 6.6 प्रतिशत पर आ गया था । केवल एक साल ऐसा था जिसमें हरियाणा जी.डी.पी. ग्रोथ रेट में नीचे जा रहा था । उसके बाद हम निरन्तर हरियाणा को जी.डी.पी. ग्रोथ रेट पर लेकर आए हैं और निरन्तर नैशनल ग्रोथ रेट के एवरेज से 1 प्रतिशत ऊपर की ग्रोथ रेट को मेनटेन किया है । इसके अलावा करण दलाल जी ने शायद डैट के बारे में भी एक कमैंट किया है । मैंने एक चीज बार–बार इस सदन के पटल पर रखी है कि

यह जो पूरा डैट है उसमें पूरे हिन्दुस्तान में हरियाणा प्रदेश एक आदर्श राज्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है कि हरियाणा राज्य वित्त व्यवस्था व एफ.आर.बी.एम. एक्ट की जितनी भी मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का पूरा पालन करता है । मैंने इस बात को बार–बार सदन के पटल पर साबित किया है कि हमने जान–बूझकर, आंख बन्द करके अपने समय का बिजली कम्पनी से लिया हुआ 26 हजार करोड़ रुपये का कर्जा सरकार के खजाने में डाला है जिसके कारण से आज बिजली कम्पनियां प्रोफिट में और सुधार में आई हैं । कम्पनियों से जो वह 26 हजार करोड़ रुपये का कर्जा लिया गया है उसमें से हमने एक पैसा नहीं लिया है वह सारा पैसा सरकार के खजाने में जमा किया है ताकि सस्ता कर्ज हो जाए । उससे बिजली कम्पनियों की इंट्रस्ट के अन्दर 2800 करोड़ रुपये से लेकर लगभग 3000 करोड़ रुपये तक की सालाना बचत हुई है इसलिए मेरा निवेदन है कि कैग की रिपोर्ट आज सदन के पटल पर रखी गई है । मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर गम्भीरता से पी.ए.सी. भी विचार करेगी क्योंकि आगे आने वाले समय में इस सदन में पी.ए.सी. की रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है और जो कैग की रिपोर्ट आज इन्हीं के द्वारा टेबल हुई है उसमें वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम एफ.आर.बी.एम. एक्ट को फोलो कर रहे हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं । उसमें मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कैग की रिपोर्ट यह कहती है कि

> The State Government had not made necessary amendments in Haryana FRBM Act as per the guidelines of FFC. The State even failed to achieve the targets recommended by the F.F.C. in respect of Revenue Deficit and Outstanding Debts.

इसके अलावा जो आपने जी.डी.पी. के बारे में कहा (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बात को पढ़ा है और मैंने भी इस बात को पढ़ा है जिसमें सी.ए.जी. की रिपोर्ट में टोटल 26. कुछ प्रतिशत लायबिलिटी को प्रेजेन्ट करने की बात आई है । मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को स्पष्ट कर देता हूं कि महालेखाकार जो कैग की रिपोर्ट देते हैं वह अपने एक प्रारंभिक नजरिये से देते हैं । फिर उसमें विभाग जाकर कंटैस्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट के अन्दर आपने हमारे कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड से रिलेटिड जो

लायबिलिटी है वह उस रिपोर्ट में ऐड करके उसको कैल्कुलेट करके बताया है। यह आज हमारी सरकार ने नहीं किया है बल्कि शुरू से ही हरियाणा प्रदेश एफ.आर.बी.एम. एक्ट में इस प्रकार की जो लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज को इन्क्लूड नहीं करता रहा है और वही चीज फाइनली एक्सैप्ट होती रही हैं । वही सच्चाई है और वही तथ्य है । इस बार भी जो रिपोर्ट आई है वह कोई नई नहीं है, हर बार इस तरह के विषय आते रहे हैं और हर बार इन विषयों को कैग के सामने लाया जाता है क्योंकि भारत सरकार की 15 वीं फाईनैंस कमीशन की रिपोर्ट है उसकी रिक्मैंडेशन के आधार पर ही वह अपनी एक रिपोर्ट दे रहे हैं लेकिन हम पर जो एफ.आर.बी.एम. ऐक्ट अप्लाई होता है हम उसकी लाइट में जाकर उसको कंटैस्ट करके फिर टोटल 22.86 प्रतिशत लायबिलिटी बनती है । इसके साथ ही मैं एक बात और बता दूं कि वर्ष 2014–15 में जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना शुरू किया तो 4 लाख करोड़ रुपये की जी.डी.पी. थी जो आज बढ़कर 7 लाख 85 हजार करोड़ रुपये के करीब हो चुकी है । यह एक बहुत बड़ी वृद्धि है । इसके साथ मैं यह भी एड कर दूं कि एफ.आर.बी.एम. पर इसी रिपोर्ट में आगे पढ़ेंगे जिसको सभी माननीय सदस्यगण और पी.ए.सी भी देखेगी । कैग ने पिछले साल की रिपोर्ट में हरियाणा को एप्रीशिएट किया है । फिस्कल डैफिसिट, रेवैन्यू, प्राईमरी इन सभी में हरियाणा ने बहुत उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है और बहुत बेहतर काम किया है । अतः मैं करण दलाल जी से निवेदन करूंगा कि वह पूरी रिपोर्ट को पहले अच्छी तरह गहराई से पढ़ें और उसको पी.ए.सी. अध्ययन करे और उसके बाद पी.ए.सी. इस पर अपनी टिप्पणी दे तो फिर इस पर चर्चा करें तो अच्छी बात होगी।

श्री अध्यक्ष : अब मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखेंगे ।

शून्यकाल तथा विभिन्न मांगों के दौरान सदस्यगण द्वारा उठाए गए विभिन्न मद्दों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का पहला विधान सभा सत्र दिनांक 3.11.2014 को हुआ था। लगभग पांच सालों का यह दौर इतना सुखद रहा कि ऐसा लगता है कि जैसे कल ही 3.11.2014 को इस सरकार का पहला सत्र आयोजित किया गया था। जब समय आसानी से और बिना किसी विघ्न के बितता है तो समय का अंतराल छोटा दिखाई देने लग जाता है लेकिन जब यही समय कठिनाइयों से पूर्ण व पीड़ादायक होता है तो समय का अंतराल लंबा दिखाई देने

लग जाता है। विधान सभा के प्रथम सत्र में हमने घोषणा की थी कि हम एक ऐसी परंपरा बनायेंगे कि प्रत्येक वर्ष विधान सभा के तीन सत्र आयोजित हुआ करेंगे। पहले विधान सभा के दो ही सत्र हुआ करते थे हमने उस परिपाटी में एक अतिरिक्त सत्र जिसको मानसून सत्र के नाम से जाना जाता है, को जोड़ने का काम किया। हमने अपने तीन सत्र के कमिटमैंट को पूरा किया। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद विधान सभा के तीन सत्र आयोजित किए गए। यदि वर्ष 2014 में एक सत्र हुआ तो दो सत्र की कमी को हमने वर्ष 2019 में अब तक दो सत्र आयोजित करके तीन सत्र की कमिटमैंट को पूरा करने का काम किया है। 15वें सत्र के इस अवसर पर यदि हम हर वर्ष के तीन सत्रों की सीटिंग्ज की ओर ध्यान दें तो पायेंगे कि अब तक विधान सभा की कुल 84 सीटिंग्ज आयोजित हुई हैं। आज विधान सभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है। इस सीटिंग में जो हम बैठे हुए हैं, यह सीटिंग विधान सभा की 84वीं सीटिंग है। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पूरे कार्यकाल में आपने तथा उपाध्यक्ष महोदया ने जिस सफल निर्देशन के माध्यम से विधान सभा के विभिन्न सत्रों का संचालन किया है उसके लिए मैं आपका तथा उपाध्यक्ष महोदया का बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के बारे में बात करने से पहले तथा सत्र के विगत दो दिन के अंतराल में जिन विषयों पर चर्चा हुई, उन पर बात करने से पहले मैं सर्वप्रथम जम्मू एवं कश्मीर में धारा 370 हटाने के विषय पर जो सदन की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया है उस पर बात करते हुए पूरे सदन को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र भाई मोदी तथा देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में संविधान की धारा 370 के दुरूपयोग का एक विषय लगातार 70 साल से चला आ रहा था। अब केन्द्र सरकार ने इसकी समाप्ति की ओर कदम बढ़ाया और यही कारण है कि कल धारा 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने वाला बिल राज्य सभा में पारित हो गया है और आज लोक सभा में इस पर चर्चा चल रही है। मैं समझता हूँ कि सांयकाल तक लोक सभा में भी यह बिल पास हो जायेगा। धारा 370 का ऐसा दुरूपयोग किया गया कि वह जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का अभिन्न अंग होना चाहिए था, उसको एक प्रकार से अलग–थलग करने का कुप्रयास किया गया। धारा 370 हटने के पश्चात जम्मू कश्मीर प्रांत अब दो हिस्सों में बंट जायेगा। एक हिस्सा लद्दाख होगा जोकि शुद्ध केन्द्र शासित प्रदेश होगा और केन्द्र सरकार के अधीन

कार्य करेगा वही दूसरा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर होगा जोकि यूनियन टैरिटरी तो होगा लेकिन इसकी अपनी विधान सभा होगी। अध्यक्ष महोदय, 5 अगस्त, 2019 के इस ऐतिहासिक परिवर्तन के दिन को इतिहास में 15 अगस्त, 1947 के स्वतंत्रता दिवस के तौर पर याद किया जायेगा। देश की एकता व अखंडता के नाते से जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटाने की लगातार मांग उठ रही थी वह अब जाकर पूरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं भी जम्मू एवं कश्मीर से काफी वर्षों तक जुड़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पर कई वर्षों तक काम किया है। मैं जब वहां का प्रभारी होता था तो तीन वर्ष तक तो मेरा वहां पर लगातार आना जाना लगा रहा था। जब वहां पर वर्ष 2002 तथा 2008 में चुनाव हुए तो भी मैं वहां पर लगातार रहा था। पहले वहां पर छह साल की टर्म की एसेंबली होती थी लेकिन धारा 370 खत्म होने के पश्चात अब यहां की एसेंबली का चुनाव भी 5 वर्ष के बाद हुआ करेगा। अध्यक्ष महोदय, पहले यहां पर जो सरकारें चुनकर आती थी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी जिसके कारण वहां पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर होता था। मैं यह भी कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार अपनी सीमाओं को भी तोड़कर हुआ करता था। न वहां पर किसी प्रकार की कोई सी.ए.जी. की रिपोर्ट लागू होती थी न ही किसी प्रकार का कोई ऑडिट होता था। केन्द्र सरकार का कोई नियम तक भी वहां पर लागू नहीं होता था। हालत यह थी कि हमारी लोक सभा के सांसद जो नियम–कानून बनाते हैं वे भी जम्मू एवं कश्मीर में तभी मान्य होते थे जबकि वहां की विधान सभा उसे लागू कर देती थी। आजादी के बाद जब सभी रियासतों का भारत में विलय हुआ तो उस समय मात्र एक जम्मू एवं कश्मीर ही ऐसी रियासत थी जिसका भारत में पूर्ण विलय नहीं हो पाया था। यही कारण था कि यहां पर दो निशान थे, दो प्रधान थे और दो ही विधान थे। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका बलिदान हुआ था, उन्होंने इन तीन बातों को समाप्त करने के लिए मांग उठाई थी। उनकी शाहदत के समय एक बात तो मान ली गई कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा दो प्रधानमंत्री नहीं होंगे। लेकिन उनकी दो बातें रह गई थीं जो अभी तक चलती आ रही थीं कि विधान भी अलग और निशान भी अलग। अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी इस बात की है कि जब अनुच्छेद–370 हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित हो जायेगा तो अब दो विधान की बजाए एक विधान होगा और दो निशान की बजाए एक निशान होगा अर्थात् पूरे हिन्दुस्तान में तिरंगा फहराया जायेगा। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय

पर मैं पूरे देश को और इस हाउस के साथ–साथ हरियाणा प्रदेश की जनता को बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूँगा कि देश के नवनिर्माण में अभी तो 'यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है' जो हमकों मिलकर लड़नी है। देश के अंदर इस तरह के कई और विषय बाकी हैं जिनका देश की जनता इंतजार कर रही है कि कब पूरे होंगे? राज्य सभा में कुछ दलों ने अनुच्छेद–370 हटाने का समर्थन किया और कुछ दलों ने इसका विरोध भी किया है। अध्यक्ष महोदय, एक विडम्बना यह रही है कि जो देश का मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस पार्टी है उस पार्टी में दुविधा आ गई है और यह बात हमारे ध्यान में आ गई है। कांग्रेस पार्टी में बहुत से माननीय सदस्यों ने इस ऐतिहासिक निर्णय का समर्थन किया है, इसके लिए मैं उनका व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट करता हूँ। सामुहिक रूप से जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अनुच्छेद–370 हटाने का समर्थन किया है तो उसके लिए भी मैं हरियाणा कांग्रेस पार्टी का आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन केन्द्र में इस अनुच्छेद को हटाने बारे दुविधा खूब आई है। राज्य सभा में कांग्रेस पार्टी ने इस अनुच्छेद का विरोध किया लेकिन कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने समर्थन भी किया था। राज्यसभा में जैसे ही यह बिल पारित हुआ, हमें पता लगा कि कांग्रेस पार्टी के राज्य सभा में चीफ व्हिप (मुख्य सचेतक) ने तुरंत रिज़ाईन करते हुए कहा था कि मेरे द्वारा जबरदस्ती व्हिप जारी करवाया था कि राज्य सभा में सभी सदस्य बिल के पारित के समय मौजूद रहेंगे लेकिन इसके लिए मेरा मन नहीं करता है, इसलिए मैं अपने पद से रिज़ाईन देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस नाते से देश में यह बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है। बहुत लोग जो इधर–उधर की बातें करते हैं मैं उनको केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि–

'इधर–उधर की न बात कर, देश की अखण्डता का सवाल है,
इधर–उधर की न बात कर, यह शहीद शहादतों का सवाल है।'

अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा के अनेकों वीरों ने जम्मू–कश्मीर में अपनी शहादत दी है इस नाते से आज इन सभी शहीदों का सपना पूरा हुआ है। मैं उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। आज भी जम्मू–कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है लेकिन जिस प्रकार से अब केन्द्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है उसको देखते हुए हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी व माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी पर पूरा भरोसा है कि उसका भी कोई–न–कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और निश्चित रूप से वह भी एक दिन भारत

का हिस्सा होगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हरियाणा प्रदेश के विकास की बात है, उसे हमने 5 साल बखूबी निभाया है। हमने पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण भाव से और सेवा भाव से हरियाणा प्रदेश में विकास के काम किए हैं। विकास के मामले में मैं यह मानकर चलता हूँ कि 5 वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं चाहे वह क्वांटिटी में लगा लें, चाहे बजट के हिसाब से लगा लें या फिर चाहे वह व्यवस्था परिवर्तन के हिसाब से लगा लें। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास के कार्य पिछले सभी 5 वर्षों के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ेंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) व्यवस्था परिवर्तन में हमें बहुत सारे काम ऐसे ध्यान में आए हैं कि लोगों का जीवन कैसे सरल और सुखी बनाया जाये? सरकारी सिस्टम में पहले लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और दर–दर की ठोकरें खानी पड़ती थीं, अपने काम को करवाने के लिए नेताओं और अधिकारियों के चक्कर खाने पड़ते थे। पहले तो लोग अपना काम करवाने के लिए मंत्रियों और मुख्यमंत्री के निवास स्थान और कार्यालयों में बैठे रहते थे। श्री राम बिलास शर्मा जी तो यहां तक सुनाते थे कि जब हम पहले मंत्री हुआ करते थे और सुबह लोटा लेकर चलते थे तो लोग हमारे पीछे आकर बैठ जाते थे और कहते थे कि दादा मेरा मुहँ तो दूसरी तरफ है, हमारा काम जरूर कर देना। इस प्रकार से लोग पहले मंत्रियों और मुख्यमंत्री को घेरते थे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस बारे में सोचा कि लोग हमें क्यों घेरते हैं? यदि हम सही ढंग से सिस्टम बनायेंगे तो शायद लोग हमें घेरना बंद कर देंगे। इस प्रक्रिया को करने में बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ। मैं तो यह कहता हूँ कि बाहर के लोगों की बजाए अपने लोगों ने भी बहुत विरोध किया। हमारी सरकार की एक ट्रांसफर पॉलिसी है इसको हमने क्यों बनाया? अध्यापक वर्ग हरियाणा में सबसे बड़ा वर्ग है। इस वर्ग में से 10–20 अध्यापक ट्रांसफर के चक्कर में हमेशा शिक्षा मंत्री जी के आवास पर या फिर सचिवालय की चौथी मंजिल पर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर खड़े मिलते थे और अधिकारियों के आगे–पीछे घुमते रहते थे। अध्यक्ष महोदय, अब अधिकारियों से बात होती है तो वह कहते हैं कि जब से व्यवस्था परिवर्तन हुआ है तब से वह सुख की सांस लेने लगे हैं और अपने जरूरी सरकारी कामों को भी आसानी से कर लेते हैं, जबकि पहले सचिवालय में बैठकर काम करना दुभर हो जाता था। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था परिवर्तन से लोगों का समय भी बचा, साधन भी

बचे और फ्यूटाइल एक्सरसाइज भी नहीं करनी पड़ी । हमने इस प्रकार की नई पोलिसी बनाई है । मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पहले ही साल में 42 हजार अध्यापकों के ट्रांसफर्ज हुए और इनमें 93 परसैंट टीचर्स ऐसे थे जिनको पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर सलैक्ट किये हुए स्कूल्ज में ज्वायनिंग मिली । इससे सारे हरियाणा में एक अच्छा संदेश गया । इसके बाद इस पोलिसी को अब अन्य डिपार्टमैंट्स ने भी अडॉप्ट किया है । जहां पर कठिनाई आती है हमें उसे ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं है । किसी भी नये काम में शिकायतें आती ही हैं । इम्पलाइज के हित की कोई भी बात हो हम उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं । अगर इम्पलाइज प्रसन्न रहेगा तो उसका काम करने में मन लगेगा । वह समय गया जब नेता कहते थे कि मैं सड़क का मोड़ और मास्टर की मरोड़ काड दूंगा । मेरे विचार से ऐसे किसी की मरोड़ नहीं निकलती है । हर इम्पलॉयी का एक मानस होता है और उसको भी सुख की दरकार होती है । हमने जनता की खुशहाली के बहुत काम किये हैं और यह सुनिश्चित किया है कि लोगों के जीवन–यापन की व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए ? अब पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती । ऐसा नहीं है कि सब लोग एक समान हो जाएंगे । उद्यम करने वाले लोग ही आगे बढ़ेंगे लेकिन वे एक सीमा तक ही आगे बढ़ सकते हैं एक सीमा से नीचे रह गए तो उनको अवसर नहीं मिलता, वे मुख्यधारा में नहीं आ पाते और वे पीछे रह जाते हैं । उनको पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है । प्राइवेट उद्योगों में कैसे ज्यादा से ज्यादा इनवैस्टमैंट आए इसको लेकर हमारी सरकार ने इनवेस्ट्र्स सम्मिट्स भी करवाई हैं । एम.एस.एम.ई. के माध्यम से उद्योगों में युवाओं को जॉब भी दिलवाई गई हैं । हमने एच.एस.एस.सी. के माध्यम से 69 हजार युवाओं को और एच.पी.एस.सी. के माध्यम से 3–4 हजार युवाओं को जॉब दी हैं । इसके अलावा जो युवा प्रदेश के छोटे–बड़े उद्योगों में नौकरियों में लगे हैं उनके विषय में एक मांग उठती रहती है कि इनमें जो साढ़े तीन लाख लोग लगे हैं उनमें से कितने युवा हरियाणा के हैं और कितने युवा अन्य राज्यों के हैं । इस पर मेरा कहना है कि सरकार के पास अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि जिससे हम जानकारी ले सकें कि इनमें हरियाणा के इतने लोग लगे हैं और बाहर के इतने लोग लगे हैं । अब हमने सभी उद्योगपतियों से कहना शुरू कर दिया है कि अपने प्रदेश में उद्योग लगवाने का हमारा सिर्फ एक ही इंट्रस्ट है और वह है हरियाणा के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना । जी.एस.टी. के आने से पहले

हमारे दो प्रकार के इंट्रस्ट्स होते थे । उस समय हमारा पहला इंट्रस्ट वैट था । हमें जो वैट मिलता था उससे प्रदेश में साधन बढ़ते थे और विकास होता था तथा सरकार का रिवैन्यू बढ़ता था और दूसरा इंट्रस्ट ऐम्पलॉयमैंट था । जी.एस.टी. के आने से हमारा पहला इंट्रस्ट खत्म हो गया है क्योंकि जी.एस.टी. का लाभ उस स्टेट को होता है जहां पर उस प्रोडक्ट की कंजम्पशन होती है । अगर हरियाणा में लगे हुए किसी उद्योग के प्रोडक्ट की कंजम्पशन केरल में हो रही है तो जी.एस.टी. का लाभ केरल को होगा न कि हरियाणा को । अतः अब हरियाणा में उद्योग लगवाने का हमारे पास सिर्फ एक लाभ बच गया है । अब हमने हरियाणा प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए योजना बना ली है । हमने न्यू इनवेस्ट्र्स से हरियाणा के लोगों को रोजगार देने के संबंध में कहा है कि ब्लॉक 'ए' और 'बी' प्रकार के जो उद्योग–धंधे लगेंगे उनमें हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने पर हम प्रति वर्कर 3 हजार रूपये अपनी तरफ से 3 साल तक के समय के लिए देंगे । इस प्रकार से हम इन उद्योगपतियों को हरियाणा के लोगों को रोजगार देने के लिए प्रति वर्कर 1,08,000 रूपये 3 साल में देंगे ताकि वे हमारे युवाओं को आसानी से रोजगार दे सके । हमने हरियाणा के लोगों की खुशहाली के लिए और भी बहुत से काम किये हैं । न्यूनतम वेतन के संबंध में हमसे पूछा जाता है कि आपने अपने मैनीफेस्टो में क्या कहा था और क्या उसे पूरा कर दिया है ? मेरा कहना है कि हमने मजदूरों को न्यूनतम 300 रूपये प्रतिदिन दिहाड़ी देने की बात कही थी । आज के दिन हर मजदूर को न्यूनतम 9 हजार रूपये मासिक वेतन मिल रहा है । भिन्न–भिन्न स्थानों पर 9600, 9700 या और भी अधिक वेतन मिल रहा है । अतः हमने 300 रूपये प्रतिदिन वेतन के अपने वादे को पूरा किया है । हमने एक काम और किया है । समाज परिवर्तन के विषय और जो समाज निर्माण के कार्य हैं वे भले ही हमारे मैनिफैस्टो में नहीं थे फिर भी सरकार उन कार्यों को कर रही है। हमारी सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,' कार्यक्रम की घोषणा अपने मैनिफैस्टो में नहीं की थी। लेकिन यह एक सामाजिक समस्या थी इसलिए हमारी सरकार ने इस समस्या को सुधारा है। पूरे देश में पहले हमारा हरियाणा प्रदेश लिंगानुपात के मामले में बदनाम था परन्तु आज देश भर में हरियाणा प्रदेश की प्रशंसा हो रही है। हरियाणा प्रदेश में पहले 1,000 लड़कों पर 850 लड़कियां थीं लेकिन अब यह रेशो बढ़कर 1,000 लड़कों पर वार्षिक एवरेज में तो 915 लड़कियां हो गयी हैं परन्तु मासिक एवरेज में 1,000 लड़कों पर 933 लड़कियां हो गयी हैं।

16:00 बजे

इस प्रकार से प्रदेश में सैक्स रेशों में लगातार सुधार हो रहा है। सरकार चाहती है कि इसमें और सुधार किया जाना चाहिए लेकिन इसके लिए जनता को भी अवेयर करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हम शिक्षा विभाग, गृह विभाग, सामाजिक संस्थाओं, एन.जी.ओज., हैल्थ विभाग और डब्ल्यू.सी.डी. विभाग को साथ लेकर इस विषय को और भी आगे बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त पर्यावरण की भी बात आयी है कि पर्यावरण को कैसे सुधारा जाए ? उसमें चाहे पेड़ लगाने की बात हो, चाहे प्लॉस्टिक का कम यूज करने की बात हो, इन सभी चीजों में लगातार सुधार किया जा रहा है। प्लॉस्टिक यूज पर कागजों में तो पहले से ही बैन था परन्तु उस बैन को पिछले कई सालों से इनफोर्समेंट नहीं किया गया। हमारी सरकार के प्रयास से लोगों में प्लॉस्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूकता आनी शुरू हो गयी है। हम इस दिशा में और सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने सरकारी कार्यालयों में प्लॉस्टिक की बोतल के यूज पर बैन लगा दिया है। इसके अतिरिक्त पानी के विषय पर बहुत सी बातें आयी हैं। हमारी सरकार पानी बचाने की मुहिम पर भी काम कर रही है। प्रदेश में पानी की समस्या को कैसे सुधारा जाए, अंडर ग्राउंड पानी की रि–चार्जिंग कैसे की जाए? पानी के दुरूपयोग को कैसे रोका जाए, किस प्रकार पानी की वेस्टेज को रोका जाए ? इस सभी बातों पर भी काम किया जा रहा है। सरकार द्वारा समाज परिवर्तन और समाज निर्माण के कार्यों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसमें चाहे नशा मुक्ति की बात हो या संस्कार देने की बात हो, सरकार ने इन सभी चीजों में सुधार किया है। गीता के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करने की बात हो, राहगीरी कार्यक्रम की बात हो, मैराथन की बात हो, ये सभी ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे जनता में जागरूकता आती है कि अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम क्या–क्या कर सकते हैं ? हमारे माननीय मंत्री जी ने कल नशे की रोकथाम के बारे में जवाब देते हुए कहा था कि अगर सदन में किसी माननीय सदस्य के पास नशे की रोकथाम से संबंधित कोई जानकारी हो या कोई सुझाव हो तो उस पर सरकार कार्य करने के लिए तैयार हैं। नशा मुक्ति का विषय हरियाणा प्रदेश का ही नहीं है बल्कि पूरे उत्तरी भारत का है इसलिए हम सभी को इसमें साथ लेकर चल रहे हैं। अगर पूरे भारत की बात करें तो देश में दो ऐसे रीजन हैं, जहां पर ये समस्याएं बड़ी मात्रा में हैं जिसमें नोर्थ– ईस्ट और उत्तर भारत शामिल हैं। नोर्थ– ईस्ट की अपनी अलग प्रकार की समस्याएं हैं। उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर

प्रदेश और दिल्ली भी शामिल हैं। ये सभी राज्य मिलकर इस समस्या को ठीक करेंगे। नशा मुक्ति की पिछली मीटिंग में पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने स्वयं आगे बढ़कर मेजबानी की थी। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। उस मीटिंग में हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आये थे और बाकी राज्यों से अधिकारी ही आये थे। हम नशे की समस्या को समाप्त करने के लिए नशे की डिमांड को कम करेंगे और इसकी सप्लाई को भी रोकेंगे। इसके अतिरिक्त लोगों को नशा छोड़ने के लिए अवेयर भी करेंगे और लोगों को अंगेज भी करेंगे। ये बहुत बडे अभियान के हिस्से हैं जिसको हम सभी मिलकर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले जो छोटे–छोटे विषय हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं बाकी बड़े विषयों पर बाद में चर्चा कर लेंगे। मैं आज के विषयों में ऐसी बातें नहीं कहना चाहूंगा जिससे सदन में कोई तल्खी हो जाए। मैं सिर्फ तथ्यात्मक विषयों पर ही बातें कहूंगा और हो सकता है कि तथ्यात्मक विषयों में असहमति भी हो जाए। अगर किसी माननीय सदस्य को लगे कि संबंधित तथ्य ठीक नहीं है और कोई असहमति हो जाए तो उसको बाद में भी ठीक कर सकते हैं। कई बातें हमको बतायी जाती हैं, उनको हम कहते हैं और कई बातें हमें पहले से ही पता होती हैं, उनको भी हम कह देते हैं। आज चूंकि विधान सभा के सैंशन का आखिरी दिन है, इसलिए जो तथ्यात्मक बाते हैं वे ही संक्षेप में रख रहा हूं। हमारे विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्य तो अपनी बात सदन में कहकर चले गये हैं। मेरा उनसे निवेदन था कि वे सदन में ही रहें और सरकार की बातें सुनें। माननीय सदस्य श्री रणदीप सिंह सुरेजवाला जी अपनी दो–तीन बातें कहकर चले गये। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे आज सदन में ही नहीं आयेंगे। माननीय सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा जी तो यह कहकर गये थे कि उनको प्रोग्राम अटैंड करने के लिए जाना हैं परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप सदन को रात के 9:00 बजे तक चलायेंगे तो वे भी आ जाएंगे। मैंने कहा सदन रात को भी चला सकते हैं परन्तु प्रत्येक माननीय सदस्य की अपनी–अपनी व्यस्तताएं हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने जी.डी.पी. के बारे में कहा है। मैं इन्हें कहना चाहूंगा कि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मेरी ब्रोडर सेंस यह कहती है कि जी.डी.पी. की जो ग्रोथ है That is directly proportional to the inflation. इसका मतलब यह हुआ कि इन्फ्लेशन जितनी ज्यादा होगी, जी.डी.पी. की ग्रोथ उतनी ही ज्यादा होगी। मैं यही

बताना चाहूंगा कि उत्पादन की मात्रा को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके ही जी. डी.पी. बनती है। चूंकि इस साल हमारे प्रदेश में इन्फ्लेशन की दर पिछले सालों से कम हुई है इसलिए अगर इन्फ्लेशन की दर कम होगी तो स्वाभाविक है कि जी.डी. पी. की ग्रोथ कुछ कम जरूर होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे प्रदेश में इन्फ्लेशन की दर कम होते हुये भी जी.डी.पी. की दर कम नहीं हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे प्रदेश में उत्पादन बढ़ रहा है और हमारे प्रदेश में इन्फ्लेशन की दर कम होने के बावजूद जी.डी.पी की ग्रोथ बढ़ रही है। मैं आपको इन्फ्लेशन का एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि कर्मचारियों का जो डी.ए. होता है, वह सामान्यतः वेतन आयोग के साथ ही जुड़ता है। जो छठा वेतन आयोग आया था, वह वर्ष 2006 में आया था और उस समय हर 6 महीने के बाद डी.ए. की एक किस्त जुड़ती थी। इस तरह से 1 जनवरी, 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 तक 3.5 साल हुये और उन 3.5 सालों में जो डी.ए. का रेट आया था, वह 27 परसैंट था और वर्ष 2016 तक वह 156 परसैंट होकर समाप्त हुआ। उसके बाद उन सबको जोड़कर दिनांक 01.01.2016 को सातवां वेतन आयोग आया। अब सातवें वेतन आयोग आने के बाद भी हर 6 महीने के बाद डी.ए. की एक किस्त जुड़ती है। इसी तरह से 1 जनवरी, 2016 से लेकर 1 जुलाई 2019 तक 3.5 साल हुये और इन 3.5 सालों में डी.ए. का रेट 17 परसैंट चल रहा है यानी कि 1 जनवरी, 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 तक जो इन्फ्लेशन का रेट आया था, उसकी अपेक्षा 1 जनवरी, 2016 से लेकर 1 जुलाई 2019 तक जो इन्फ्लेशन का रेट आया है, उसमें टोटल 10 परसैंट की कमी आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2016 तक इन्फ्लेशन का रेट जो 156 परसैंट आया था, वह वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2026 तक 100 परसेंट से ज्यादा नहीं जायेगा। हम चाहते हैं कि महंगाई कम हो और जी.डी.पी. बढ़े, यह एक विरोधाभास बात है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जी.डी.पी. उत्पादन के कारण से भी बढ़ सकती है लेकिन इन्फ्लेशन के कारण उत्पादन न भी हो तब भी इन्फलेशन के कारण जी.डी.पी. बढ़ता रहेगा और हम खुश होते रहेंगे। इसलिए इस जी.डी.पी. का रेट अमेरिका का 2.5 या 3 परसैंट रहता है और हमारा जी.डी.पी. का रेट 6, 7 या 8 परसैंट चला जाता है, क्योंकि वहां रेट ऑफ इंट्रेस्ट 2. 5 या 3 परसैंट के करीब ही है, महंगाई दर भी 2.5 या 3 परसैंट के करीब ही है, लेकिन हमारे देश में महंगाई दर 6,7 या 10 परसेंट तक चला जाता है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि शुरू–शुरू में जब कोई भी देश विकास की राह पर चलता है तो

उसको इन्फ्लेशन रेट थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है ताकि लोगों को रोजगार मिले, उस देश में उत्पादन ज्यादा हो और लोगों की प्रगति हो। अब हम 70 सालों के बाद उस स्टेज पर आ चुके हैं कि हमको अपना इन्फ्लेशन अपग्रेड को भी रोकना पड़ेगा और जो साधन देश में उपलब्ध हैं, उसमें प्रोड्क्शन बढ़ाना पड़ेगा। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इन्फ्लेशन को कम कर सकें ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सही बनी रहे। मैं माननीय सदस्य को यही बताना चाहूंगा कि मैंने इन्फ्लेशन और जी.डी.पी. से संबंधित मोटी–मोटी बात इनको बताई है और हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, अगर वे इस संबंध में मुझे कुछ और समझना चाहते हैं तो वे मुझे समझा सकते हैं।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच सालों में....(विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मुझे सी.ए.जी की रिपोर्ट समझ नहीं आती है और मैंने अपनी सारी बात इनको बता दी है।

श्री अध्यक्षः दलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों का जवाब दे दिया है इसलिए आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य दलाल जी को कहना चाहूंगा कि मुझे केवल अपनी बात समझ में आती है और सी.ए.जी की रिपोर्ट समझ में नहीं आती है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इनको यह जरूर मानना चाहिए कि सी.ए.जी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच सालों में देश के अंदर साधन घटे हैं और रोजगार के साधन भी घटे हैं जिसके कारण हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी है।

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य करण दलाल जी को कहना चाहूंगा कि इन सारी बातों के ऊपर चर्चा हो चुकी है।

श्री अध्यक्षः दलाल जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने इन सबका जवाब विस्तार से दे दिया है, इसलिए कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जायें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इन सारे सवालों का जवाब हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने सी.ए.जी की रिपोर्ट के अनुसार दे दिया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो सी.ए.जी रिपोर्ट होती है, वह सी.ए.जी का अपना एक व्यू प्वायंट होता है और उस व्यू प्वायंट के

ऊपर सी.ए.जी कार्यालय के लोग अपना एतराज जाहिर करते हैं। उसके बाद वह रिपोर्ट पी.ए.सी. में जाती है, उसके बाद पी.ए.सी. में सब डिपार्टमैंट के अधिकारियों को बुलाया जाता है और इस तरह से सी.ए.जी रिपोर्ट के ऊपर 2 साल तक चर्चाएं चलती रहती हैं। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अगर ये पिछले 3 सालों की सी.ए.जी रिपोर्ट को उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि उन 3 सालों के बाद उस सी.ए.जी रिपोर्ट की एक्चुअल चीज आज फाइनल होकर क्या आई है, उसकी तुलना कर लेंगे तो इनको पता चल जायेगा कि सी.ए.जी रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि कैग रिपोर्ट में आज भी लिखा हुआ है कि हमारे प्रदेश का फिसकल रिसपोंसिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमैंट यानी एफ.आर.बी.एम. 26 परसैंट है, जबकि वास्तव में एफ.आर.बी.एम. 22.86 परसैंट है इसलिए हमारी और सी.ए.जी की रिपोर्ट में अंतर जरूर है। हम सी.ए.जी की रिपोर्ट को फाइनल मानेंगे और अपनी रिपोर्ट को फाइनल नहीं मानेंगे, यह तो कोई कारण नहीं बनता है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि कैग ने एफ.आर.बी.एम. का रेट कैटेगरीवाईज रखा हुआ है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एफ.आर.बी.एम. का रेट सालाना 3 प्रतिशत रखा है, अगर 3 प्रतिशत से 3.25 प्रतिशत हो जाये तब भी सी.ए.जी.को एतराज होता है। अगर एफ.आर.बी.एम. का रेट 3 प्रतिशत से 2.25 प्रतिशत हो जाये तब भी एतराज के रूप में सी.ए.जी. की रिपोर्ट में पैरा बन जाता है और सी.ए.जी. द्वारा यह कह दिया जाता है कि अगर एफ.आर.बी.एम. का रेट कम या ज्यादा हो जाए तो सरकार प्रदेश का विकास किस प्रकार करेगी? हमारा फिसकल डैफिसिट कम है, हम इस बात को मानते हैं और यह बात ठीक भी है। हमारा इस वर्ष एफ. आर.बी.एम. का रेट 3 प्रतिशत की बजाये 2.43 प्रतिशत आया है। सी.ए.जी. वाले चाहते हैं कि इस फिसकल डैफिसिट को और बढ़ाओ और इसे पूरा करने का भी प्रयास किया जाये। चाहे इसके लिए लोन ही क्यों न लेना पड़े लेकिन अगर हम लोन लेते हैं तो भी उनको एतराज होता है कि ज्यादा लोन क्यों ले लिया? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जी.डी.पी. की एक सीमा होती है अर्थात वार्षिक 3 प्रतिशत और टोटल अमाउंट का 25 प्रतिशत जी.डी.पी. होता है। उन्होंने आंकड़ों का एक सिस्टम बना रखा है और वे हमें समय–समय पर इस विषय के रिगार्डिंग गाईड भी करते रहते हैं। जो बातें हमें माननी होती है उन बातों को तो हमारी

सरकार मान लेती है। उसमें हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी नहीं होती है लेकिन फिर भी हमारे हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति बाकी प्रदेशों से अच्छी है। जिन प्रदेशों का माननीय सदस्य जी जिक्र कर रहे हैं, मुझे उन प्रांतों की आर्थिक स्थिति के बारे में पता नहीं है लेकिन मैं पंजाब प्रांत के बारे में बता सकता हूं कि पंजाब प्रांत की आर्थिक स्थिति से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से विनती करना चाहता हूं कि कई बार इस महान सदन में कई माननीय सदस्य मुझे कहते हैं कि हमें दो तीन महीने पहले फलानी जगह कुछ शिकायत मिली लेकिन मेरा इस विषय पर यह भी कहना है कि एक दो छोटे–मोटे इक्का–दुक्का विषय पर सिस्टम के रिगार्डिंग कोई शिकायत मिलती है तो सभी माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि जब विधान सभा का सैशन आयेगा तभी मैं अपने इस विषय की बात उठाऊंगा लेकिन मैं इन सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि विधान सभा के सैशन होने का इंतजार करने की बजाये सभी माननीय सदस्य इसकी शिकायत ग्राउंड लैवल पर जैसे पुलिस थाने हैं, सी.एम. विंडो है या इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं, वहां पर अपनी शिकायत करें। अगर वहां पर आपकी शिकायतों का निपटारा नहीं किया जाता है तब भी आप वहां पर बार–बार अपनी शिकायत बताते रहें लेकिन उसके बावजूद भी आपकी शिकायतों का निपटारा नहीं हो रहा है तब आप सरकार को अपनी शिकायत बतायें कि बार–बार शिकायत करने के उपरांत भी हमारी शिकायतों का निपटारा नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि एक दो माननीय सदस्यों ने बताया है कि हमारी शिकायतों का निपटारा नहीं किया जा रहा है। जब हमने इस बारे ग्राउंड लैवल पर पता किया तो पता लगा कि ऐसी कोई शिकायत ही नहीं आई थी। सबको सब बातें ग्राउंड लैवल पर अपने आप पता लग जाये ऐसी भी कोई बात नहीं है। शिकायतों को निपटाने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है। अगर वह सिस्टम हमें गलत जानकारियां देता है तो उसके बारे में भी सरकार को बताना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो सरकार भी चाहती है कि भ्रष्टाचार के मामले में हमारा प्रदेश जीरो टॉलरेंस पर हो। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि इस बात का सरकार दावा भी नहीं करती है कि जीरों प्रतिशत टॉलरेंस भ्रष्टाचार हो गया। सरकार तो यह चाहती है कि किसी भी सिस्टम में भ्रष्टाचार की कोई गुजांइश न हो। पूर्व की सरकारों के समय में सिस्टम के अंदर जो भ्रष्टाचार पनपता था उसको

एक प्रकार से कारपेट किया जाता था। अध्यक्ष महोदय, अब मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि इस महान सदन में मैं दो–चार बातें भ्रष्टाचार के संबंध में कह दूंगा तो विपक्ष के माननीय सदस्यों में तनाव और तल्खी का आलम शुरू हो जायेगा। मैं आज इस महान सदन में भ्रष्टाचार से संबंधित सभी आंकड़े लेकर आया हूं। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों के लिए दिक्कतें खड़ी हो जायेंगी। मैं केवल इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार से संबंधित जो–जो गड़बड़ियां हुईं हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उन गड़बड़ियों की अपने 10 साल के कार्यकाल में कितनी इन्क्वॉयरियां करवाईं हैं, यह बात भी माननीय विपक्ष के सदस्य आज सदन में बता दें। हम यह भी मानते हैं कि जो वर्तमान सरकार होती है वह पुरानी सरकारों के कार्यकाल की गड़बड़ियों की इन्क्वॉयरियां आसानी से करवा लेती हैं लेकिन जब अपनी सरकार यानी जो वर्तमान सरकार होती है तब वह भ्रष्टाचार से संबंधित कितनी गड़बड़ियों का पता लगाने में सफल होती है और कितनी गड़बड़ियों की कितनी बार इन्क्वॉयरियां करवाती हैं, इसके बारे में बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार यानी वर्तमान सरकार के समय में जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, उन सभी गड़बड़ियों की इन्क्वॉयरियां चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि पूर्व की सरकारों ने जो गड़बड़ियां की हैं अगर उन गड़बड़ियों को वर्तमान सरकार उजागर नहीं करेगी तो कौन उजागर करेगा? इसमें हमारी सरकार की कोई गलती नहीं है? अध्यक्ष महोदय, इसके रिगार्डिंग मैं इस महान सदन में एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में सरकार किसी भी पार्टी की आये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने एक नारा दिया है कि 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' लेकिन इस संबंध में हमारा यह कहना है कि 'न खाएंगे, न खाने देंगे और पिछला खाया–पिया भी निकालेंगे'। हमारी सरकार यह बात कतई बर्दाशत नहीं करेगी की भ्रष्टाचार की इन्क्वॉयरियां न हो। अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व की सरकारों ने गड़बड़ियां की हैं, उनकी इन्क्वॉयारियां तो हम करवाकर ही रहेंगे। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय *** (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : श्री करण सिंह दलाल जी ने जो *** शब्द कहे हैं वे सदन की कार्यवाही से निकाल दिए जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी को कहना चाहूंगा कि अगर ये इसी तरह से ही इस महान सदन में बोलेंगे तो मुझे मजबूरीवश होकर के इस महान सदन में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में हुए कई घोटालों की कहानी सुनानी पड़ जाएगी। (शोर एवं व्यवधान) अगर दलाल साहब इसी तरह बीच में बोलते गये तो मुझे इन्हीं का ही एक घोटाले का किस्सा सुनना पड़ जायेगा। दलाल साहब फिर आप बाद में मुझे बोलोगे कि यह आपने अच्छा नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, शायद दलाल साहब मान नहीं रहे हैं, इसलिए मैं इनके द्वारा किया गया एक घोटाले का किस्सा सदन में सुना देता हूं। वर्ष 2000 से पहले जब दलाल साहब वन मंत्री थे, उस समय इनके खिलाफ एक शिकायत आई थी कि इन्होंने बायो फर्टिलाईजर कंपनी लिमिटेड से 50 रुपये प्रति किलोग्राम खाद खरीदी है लेकिन उस समय खाद का वास्तविक मूल्य 17 रुपये प्रति किलोग्राम था। इसके बाद विजिलेंस इन्क्वॉयरी हुई और विजिलेंस इन्क्वॉयरी होने के बाद इनके ऊपर अभियोग चलाया गया। जब इनके ऊपर अभियोग चला था तो वर्ष 2010 में कांग्रेस सरकार ने उस अभियोग को वापिस लेने के लिए माननीय न्यायालय से निवेदन किया था। उसके बाद ही इस अभियोग को वापिस लिया गया था। यह मेरे पास रिकार्ड है। अगर श्री करण सिंह दलाल जी के पास तथ्य हैं तो वे इसको झूठा साबित कर दें। (शोर एवं व्यवधान) अगर इनका यह केस न्यायालय में होता तो झूठा केस होने की स्थिति में ये न्यायालय से बाईज्जत बरी हो जाते। अगर सरकार ने इनका यह केस वापिस ले लिया तो इसके ऊपर सबसे बड़ा प्रश्नचिन्ह तो यही लग गया कि सरकार द्वारा इनके खिलाफ जो केस था उसको वापिस क्यों लिया गया?

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण –

श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. द्वारा

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा एक केस का जिक्र करते हुए मेरा नाम लिया गया है इसलिए मैं उस बारे में अपनी पर्सनल एक्सपलेनेशन देना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि जिस सरकार के समय के ये केस हैं मैं उस समय की सरकार के बहुत से निर्णयों का विरोध करता था इसलिए उस समय मेरे खिलाफ 10–10 झूठे मुकद्दमें दर्ज़ करवाये गये थे। मैं यह हिम्मत रखता हूं कि किसी भी सरकार की कारगुजारी को विधान सभा के पटल पर रखा जाये।

शून्यकाल तथा विभिन्न मांगों के दौरा सदस्यगण द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, यह तो मैंने श्री करण सिंह दलाल का महज़ एक किस्सा ही बताया है जबकि मेरे पास तो इनके बहुत सारे किस्से हैं। ये यहां पर बार–बार बोलते हैं इसलिए मैं इनको याद करवा रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री करण सिंह दलाल को यह बात बताना चाहूंगा कि जिनके घर शीशे के हों उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए इसी में इनकी समझदारी है। श्री करण सिंह दलाल जी पर यह बात पूरी तरह से लागू होती है क्योंकि इनके घर शीशे के हैं इसलिए इनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिएं। हम इनकी सभी बातों का पूरा जवाब देंगे लेकिन उससे पहले इनको हाउस में आने से पहले साफ सुथरा होना पड़ेगा। अगर इनको कुछ कहना है तो पहले ये स्वयं पाक–साफ हो जायें उसके बाद ही यहां पर कुछ कहें। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के सभी सवालों का जवाब दूंगा। अभी तो यह शुरूआत हुई है लेकिन श्री करण सिंह दलाल जी ने अभी से बीच में बोलना शुरू कर दिया। यहां पर उनसे सम्बंधित इस प्रकार की बातों को रखने की मेरी बिलकुल भी मंशा नहीं थी लेकिन इनके व्यवहार को देखते हुए मज़बूरन मुझे यह सब कहना पड़ा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किलोमीटर स्कीम के बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप कृपया करके बैठ जायें। मुख्यमंत्री जी आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप बैठकर सुनने की कृपा करें।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, विपक्ष के साथियों की तरफ से यहां पर कुल मिलाकर पांच मुख्य विषय उठाये गये हैं। इन पांच विषयों में सबसे पहली बात घोटालों के बारे में हैं। मैं यहां पर यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम तो फाईल्स को सूंघते रहते हैं कि हमें हमारी सरकार के समय का भी कोई भ्रष्टाचार का किस्सा मिल जाये। अगर हमें थोड़ी सी भी भनक लग जाती है तो हम उसको अंदर घुसकर निकालते हैं और कभी भी उसके ऊपर पर्दा नहीं डालते हैं। सारे के सारे किस्से चाहे हरियाणा रोडवेज की किलोमीटर स्कीम से सम्बंधित मामला हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम से सम्बंधित मामला हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट में फर्जी आदेश दिखाकर अधिगृहित जमीन के एनहांसमैंट के

पैसे फर्जी तौर पर लेने का मामला हो इन सभी केसिज़ में हमने एफ.आई.आर. दर्ज़ कराई है। इसी प्रकार से फतेहाबाद के भूना ब्लॉक के भूंदड़ गांव में सरप्लस जमीन आबंटित करने का मामला हमारी सरकार के समय में हुआ है। जिन लोगों ने इस काम को अंज़ाम दिया है हम उन लोगों को पकड़ रहे हैं। ऐसे ही चाहे ओवरलोडिंग से सम्बंधित चरखी दादरी का मामला हो मैं यह मानता हूं कि ये मामले हमारी सरकार के समय के हैं। इस सम्बन्ध में हमने पांच केस ऐसे दर्ज़ किये हैं समय आने पर इनका जो रिजल्ट निकलेगा वह अपने आप में बेहद अप्रत्याशित होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय के ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर उस समय तत्कालीन सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। हमारी सरकार सत्तासीन होने के बाद हमने उन मामलों को उजागर किया और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन लिया। इस प्रकार के मामलों में हमने स्टेट विजीलैंस ब्यूरो या फिर सी.बी.आई. से इंक्वॉयरी करवाई। हमने इस प्रकार के किसी भी मामले को ऐसे ही रफा–दफा नहीं होने दिया। नीलम यूनिवर्सिटी, कैथल का मामला व पंचकूला और अम्बाला में 70 और 80 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ जिसके अंदर पात्र किसानों को मुआवज़ा राशि न देकर दूसरे लोगों को मुआवज़ा राशि का वितरण कर दिया गया। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाले पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में हमारे समय में एक घोटाला हुआ उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में भी वर्ष 2012 में एक घोटाला हुआ था इन दोनों घोटालों की हम इंक्वॉयरी करवा रहे हैं। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में यह घोटाला वर्ष 2012 से चल रहा है। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं यहां पर एक–एक करके सभी मामलों के बारे में बता रहा हूं। विपक्ष के माननी सदस्यों को मेरी बात धैर्यपूर्वक बैठकर सुननी चाहिए। स्पीकर सर, इसके बाद मैं यह बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में ही एच.एम.टी. घोटाला हुआ। हमारी सरकार द्वारा स्टेट विजीलैंस ब्यूरो से इसकी इंक्वॉयरी करवाई जा रही है। इसी प्रकार से सिंचाई विभाग में फर्जी डिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सैट्स घोटाला कांग्रेस पार्टी के शासन काल में हुआ। झज्जर जिले में सिंचाई के लिए अण्डरग्राउंड पाईप लगाकर गलत तरीके से सबसिडी जारी करने से सम्बंधित घोटाले की इंक्वॉयरी भी हम करवाने जा रहे हैं। ऐसे ही अम्बाला, रोहतक और गुरूग्राम में जमीन के सैक्शन–4 और 6 के बावजूद जमीन को अधिग्रहण से रिलीज करने का जो घोटाला हुआ है

इसकी जांच हम सीबी.आई. से करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से ये ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनकी जांच हम सी.बी.आई. से करवायेंगे। मानेसर घोटाला भी सी.बी.आई. को जांच के लिए दिया गया। इसी प्रकार से पंचकुला में इंडस्ट्रियल प्लाट्स की जिस प्रकार से अपने चहतों में बंदरबांट की गई उसकी भी सी.बी.आई. जांच कर रही है। इसी तरह से ए.जे.एल. के मामले में बिल्डिंग को भी कॉनफिसकेट कर लिया है तथा सी.बी.आई. जांच चल रही है। इस प्रकार से ये 4 विषय सी.बी.आई. में चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन को बताना चाहूंगा कि हम इन सभी विषयों की जांच करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे कृपया किलोमीटर स्कीम के बारे में भी बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अब मैं किलोमीटर स्कीम पर ही आ रहा हूं।

वॉक आउट

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनको अपना जवाब निष्पक्षतापूर्ण देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वे कोई ऐसी फिगर नहीं देंगे जिससे आपस में कोई मनमुटाव हो। Hon'ble Chief Minister, you must be true to the Chair, you must be true to the House. आज सदन का आखिरी दिन है। आप कह रहे थे कि हाउस की अब तक 84 सीटिंग हो चुकी हैं और आज सदन की आखिरी सीटिंग है। आप बिट्विन दा लाईन हैं और आप उसको तोड़ गये हैं। हम आपको सुनना चाहते थे लेकिन आप हमारी पार्टी के सदस्यों द्वारा उठाये गये विषयों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं सदन से वॉक–आउट करता हूं।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये जवाब से संतुष्ट न होने पर सदन से वॉक–आउट कर गये।)

शून्यकाल तथा विभिन्न मांगों के दौरा सदस्यगण द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, उस लाईन को मैंने नहीं तोड़ा, उस लाईन को करण सिंह दलाल जी ने तोड़ा है। मैं इस विषय को उठाना ही नहीं चाहता था लेकिन इसको दलाल साहब ने उठा दिया। अगर मैं उसका जवाब नहीं दूंगा तो मैं

कलप्रिट हो जाऊंगा। जहां तक हरियाणा रोडवेज की किलोमीटर स्कीम की बात है तो हरियाणा रोडवेज में लगातार बसों की कमी चल रही है और बसों का बेड़ा बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की है लेकिन किन्हीं कारणों से नई बसें खरीदने में दिक्कत होती रही है। बाद में एक योजना यह बनी कि अपनी बसें जितनी आयेंगी वे तो आयेंगी ही साथ ही इस बेड़े को बढ़ाने के लिए हम रोडवेज के अन्तर्गत ही किलोमीटर स्कीम के आधार पर लोगों से बसें ले लेते हैं। जो कंसैसनेयर आयेगा वह किलोमीटर स्कीम के आधार पर अपनी बसें देगा। हमने अध्ययन किया है कि देश भर में सिर्फ 5 प्रांत ऐसे हैं जिनमें किलोमीटर स्कीम नहीं है। इन 5 प्रांतों को छोड़ कर बाकी सब प्रांतों में किलोमीटर स्कीम है। ये 5 प्रान्त कर्नाटक तमिलनाडु, बंगाल, बिहार और उड़ीसा हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया के जितने भी प्रांत हैं उनमें अभी तक हरियाणा को छोड़कर बाकी सभी जगह पर किलोमीटर स्कीम चल रही है। किलोमीटर स्कीम का अध्ययन किया गया कि हम अपनी बसें न लेकर लोगों से कहेंगे कि बसें लाओ और बसों पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्जिज हैं वे आप ले लो। कंडक्टर हमारा होगा, रेवेन्यू हमारा होगा केवल बस की जो टूट फूट, रिपेयर तथा मलकियत है वह मालिक की होगी और ड्राईवर भी मालिक का ही होगा। हमने इस स्कीम का अध्ययन किया तो हमने पाया कि अच्छी स्कीम है। जो बात आई थी कि मुख्यमंत्री ने इस किलोमीटर स्कीम की सराहना की है तो मैंने फाइल पर इस स्कीम की सराहना की है। मैंने कहा है कि किलोमीटर स्कीम अच्छी स्कीम है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आखिर सरकार के साथ पब्लिक मिलकर काम करती ही है। सारे काम सरकार स्वयं करेगी ऐसा कोई विधान नहीं है। सरकार स्वयं भी काम करती है और कहीं–कहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप में भी काम करती है। इस किलोमीटर स्कीम के दो अलग–अलग पार्ट हैं। एक पार्ट है किलोमीटर स्कीम को लागू करना तथा दूसरा पार्ट है स्कीम लागू होने के बाद टैंडर करना तथा दूसरी प्रक्रिया लागू करना। यहां जो ऐतराज है वह टैंडर वाली प्रक्रिया में है। कुछ लोग इन दोनो भागों को मिला कर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इसकी सराहना की है। मैंने सराहना किलोमीटर स्कीम की की है, मैंने टैंडर खुलने के बाद की सराहना नहीं की है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि विभाग ने फाइल पर गलत तथ्य पेश किये हैं। विभाग हरियाणा रोडवेज को घाटे में दिखा रहा था और उसके मुकाबले किलोमीटर स्कीम

को कम कीमत पर आंका जा रहा था। मुख्यमंत्री जी, आपने जो सही आंकड़े थे उनको नहीं मंगवाया, जो फजिंग ऑफ फैक्ट्स हैं उसको उजागर नहीं किया गया है। आपके विभाग के अधिकारी तथा मिनिस्टर जान बूझ कर फैक्ट्स को छिपा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह किस लेवल पर हो रहा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं दलाल साहब को सारी बातें बता रहा हूं। मैं वे सभी फैक्ट्स मंगवा लूंगा और यदि दलाल साहब देखना चाहें तो दिखा भी दूंगा। अभी वे ध्यान से सुन तो लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपने बजिंग ऑफ फैक्ट्स को एप्रिशिएट किया है, आपने किलोमीटर स्कीम को एप्रिशिएट नहीं किया है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में जब यह किलोमीटर स्कीम आई तो हमें हरियाणा रोडवेज के बारे में बताया गया कि हमारा एक बस का खर्च 48 रुपये प्रति किलोमीटर आता है । प्राईवेट बिडर्ज ने हमें बाद में कहा कि आपको ये खर्च 40 रुपये प्रति किलोमीटर से कम मिल जाएगा । अब तथ्य यह आ रहा है कि हरियाणा रोडवेज में एक बस का खर्च 48 रुपये प्रति किलोमीटर आ रहा है और प्राईवेट बिडर्ज कहता है कि एक बस 40 रुपये प्रति किलोमीटर से कम खर्च में मिल जाएगी । अब हम तो बसें चलाते नहीं इसलिए हमें तो पता नहीं कि कितना खर्च आ सकता है ?

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो इसी बात का है कि जो 53 रुपये प्रति किलोमीटर बनना चाहिए था हरियाणा रोडवेज ने उस खर्च को 53 रुपये ना दिखाकर कम दिखाया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण दलाल जी, प्लीज आप बैठ जाईए ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, आप दलाल साहब को कहें कि वह मेरी पूरी बात सुनें और उसके बाद इनको बोलने का मौका मिल जाएगा । जब ये मेरी पूरी बात सुनेंगे तभी इनकी समझ में आएगी । कोई भी स्कीम अप्रूव करने के लिए पहले उसका प्रारूप बनाया जाता है । प्रारूप बनने के बाद हमने उसका डील तो कर लिया लेकिन यह फाईनल नहीं होता है । प्रारूप तो यह है कि अगर हम अपनी रोडवेज की बसों के अलावा बाहर से बसें लेंगे तो हमें कम रेट में मिलेंगी । अब प्राईवेट बिडर्ज ने वह रेट 5 रुपये कम दिखाया, 10 रुपये कम दिखाया या 20

रुपये कम दिखाया । वहां कोई एग्रीमैंट नहीं हुआ है । परिवहन विभाग ने कहा कि यह स्कीम बढ़िया है हम प्राईवेट बिडर्ज से कम रेट में बसें ले लेते हैं उससे हमें फायदा भी होगा और बसें भी बढ़ जाएंगी तो हमने कहा कि आप किलामीटर स्कीम फाईनल कीजिए । अब किलोमीटर स्कीम फाईनल होती है तो वहां रेट क्या दिखाया, क्या नहीं दिखाया उसका कोई अर्थ नहीं है । अर्थ एक ही है कि हरियाणा रोडवेज का अपना जो रेट है उससे कम पड़ेगा । हमने कहा कि इसका टैंडर कर दीजिए । अब यहां शुरू होती है टैंडर की कहानी । टैंडर हो गया । अब जब टैंडर होता है तो यह मानकर चला जाता है कि जब टैंडर होगा तो पब्लिक एट लार्ज टैंडर में आएगी और उसमें जो एल–1 होगा हम उसको लेंगे । यह टैंडर का नियम होता है । जब टैंडर हुआ और उस टैंडर में जो रेट आए उसमें कम से कम रेट 31 रुपये आया और उसके बाद 36 रुपये आया । इस प्रकार के रेट आए । इससे पहले भी एक कहानी हो चुकी है पहले जब एक बार टैंडर किया तो उस समय रेट आया 16–17 रुपये और जब 16–17 रुपये रेट में टैंडर लेने के लिए कहा तो फिर एक भी आदमी टैंडर लेने नहीं आया । सभी अपना डिपोजिट छोड़कर चले गए । हमने कहा कि यह क्या हुआ ? फिर हमें बताया गया कि यह 16–17 रुपये रेट तो किसी ने इस स्कीम को फेल करने के लिए डाला है क्योंकि 16–17 रुपये रेट में कोई टैंडर लेने आता नहीं है । हमने कहा कि रेट दोबारा से इससे नीचे आ जाए उसकी बजाए हरियाणा रोडवेज का जो नॉर्मल रेट बनता है या जितना खर्चा आता है या बाकी प्रांतों में देखकर उसका कोई मीनिमम रेट तय कर दीजिए । फिर हरियाणा रोडवेज ने 21 रुपये रेट तय कर दिया । उन्होंने कहा अगर कोई 21 रुपये से कम रेट वाला टैंडर आएगा तो वह कहीं न कहीं इस स्कीम को फेल करने के लिए आएगा इसलिए इसका मीनिमम रेट 21 रुपये है । अगर कोई प्राईवेट बिडर्ज इससे ऊपर रेट देगा तो हम ले लेंगे । उसके बाद 31 रुपये रेट आ गया । उस समय हमें लगा कि यह रेट ज्यादा है लेकिन जो टैंडर पहले आया हुआ है तो उसका कैसे करें ? अब टैंडर में 31 रुपये और बाद में 36 रुपये रेट आ गया । फिर वही चक्कर पड़ गया क्योंकि 31 रुपये में तो 5 बसें और बाकी बसों में 36 रुपये रेट आ गया। अतः इस समय इसमें कहीं न कहीं शक होता है इसलिए हमने कहा कि अभी इस टैंडर को रोक लीजिए । इस समय इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें भी 700 बसों का टैंडर था जिसमें से 510 बसों का टैंडर आया और 190 बसों का टैंडर नहीं आया । हमने

हरियाणा रोडवेज को उसी समय कहा कि आप 190 बसों का टैंडर अलग लगाईए । उसमें हमें टैंडर लगाने वाली कम्पनी की शिकायतें भी मिली थी लेकिन हरियाणा रोडवेज को नैक्स्ट टैंडर कम्पनी की फॉरजिंग ध्यान में आ गई । फिर हमें किसी ने बताया कि वह कम्पनी 10 मिनट के लिए अपनी साईट खोलती है और 10 मिनट के बाद वह उस साईट को बन्द कर देती है जबकि उनको अपनी साईट पूरा समय खोलनी चाहिए उसकी वह साईट हैंग हो जाती है और उसके बाद वह साईट खुलने का मौका ही नहीं मिलता था। इसको देखते हुए हमने सबसे पहले नैक्स्ट टैंडर कम्पनी को बाहर किया और उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया । हमने कहा कि अब जो ये 190 बसों का टैंडर आएगा वह नैक्स्ट टैंडर कम्पनी से नहीं बल्कि ओपन टैंडर कम्पनी से होकर आएंगी । चाहे वह टैंडर बैंक का लें, चाहे एन.आई. सी. का लें, चाहे हरट्रॉन का लें । बहुत सी ऐसी कम्पनियां हैं जो टैंडर को ओपन कर सकती हैं । फिर ओपन टैंडर में उन 190 बसों को डाला गया । जिसमें लोगों ने यह कहा कि रेट सस्ता आ जाएगा, शायद 26–27 रुपये रेट आ जाएगा । हमने उसकी विजिलेंस इंक्वायरी करवाई । हमने कहा कि अगर वह 26–27 रुपये रेट आ रहा है तो फिर ये 31 व 36 रुपये रेट क्यों आ रहा है ? यह मान कर उस समय विजिलैंस इंक्वायरी मार्क कर दी गई । इसी बीच दोनों बातों को लेकर रोडवेज में स्ट्राईक हो गई । जिसमें एक तो यह कहा गया कि किलोमीटर स्कीम में रेट ज्यादा आ रहा है और दूसरा यह कि हम किलोमीटर स्कीम स्वीकार नहीं करेंगे । हमने कहा कि किलोमीटर स्कीम तो लागू रहेगी लेकिन जो रेट ज्यादा की शिकायत है उस पर हमें शंका है । उस समय हमने कहा कि हम इस रेट में 190 बसों का टैंडर लगाकर देख लेते हैं । उस समय रेट क्या आएंगे उसके बाद हम इसका निर्णय लेंगे । इसी बीच यह केस कोर्ट में चला गया और इसकी विजिलैंस इंक्वायरी भी हो गई जिसमें पता लग गया कि इसमें गड़बड़ है । वह इंक्वायरी कोर्ट में दे दी गई । उसके बाद कोर्ट ने भी यही कहा कि यह टैंडर गलत है आप इसको छोड़ दीजिए । उसके बाद 190 बसों के रेट 26 रुपये या जो भी कुछ आया, उसका मुझे पूरा पता नहीं है लेकिन उसमें भी नैगोशिएशन की गई कि और कितना कम हो सकता है । उस नैगोशिएशन की बात अभी चल रही है वह भी अभी फाईनल नहीं हुई है । अब कल ही लगभग 123 बसें नैगोशिएशन के माध्यम से इस स्कीम के तहत दी गई हैं । बाकी और बसें हायर रेट की थी हमने उनको मना कर दिया । अगर वह बसें एल–1 या एल–2 रेट पर आएंगी तो उस पर

क्या–क्या झगड़े होते हैं कैसे मैनुप्लेट होते हैं, वह मैं सदन को बताता हूं । जब किलोमीटर स्कीम के तहत बसों को लगाने के लिए प्राइवेट बिडर्ज, टैंडर्ज के लिए आवेदन करते हैं तो वे जानबूझकर रेट्स खराब करने के लिए कुछ बसों के लिए लिए टैंडर रेट्स बहुत कम कर देते हैं और उसके बाद अन्य बसों के लिए रेट्स ज्यादा डाल देते हैं ताकि सरकार एल–1 के बाद एल–2 पर आगे ही न बढ सके और सरकार के लिए एल–1 को लेना मजबूरी हो जाये। जब हमारे सामने ऐसी स्थिति आई तो हमने अन्यों को कहा कि देखिए एल–1 और एल–2 में बहुत गैप है इसलिए आप भी एल–1 पर आ जाओ लेकिन एल–1 पर आने से उन्होंने मना कर दिया तो हमने उस समय एल–1 के तहत आने वाली 15 बिडर्ज की की बसों को ले लिया। इसके बाद चूंकि और बसों की जरूरत थी और टैंडर प्रक्रिया में क्वॉटिटी पूरी करने का यह भी एक प्रावधान है कि यदि किन्हीं कारणों से क्वॉटिटी पूरी न हो तो क्वॉटिटी पूरी करने के लिए एल–2, एल–3 तथा एल–4 तक भी जाया जा सकता है तो हमने कैबिनेट में एल–1 से आगे बढ़ने का फैसला किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, किलोमीटर स्कीम का यह मामला माननीय हाई कोर्ट में गया था और उसके निर्देश पर इसमें विजिलैंस जांच भी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, किलोमीटर स्कीम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी से जो फाइल एप्रूव हुई थी उस फाइल में असली तथ्यों को जानबूझकर छिपाने का प्रयास किया गया था। जैसाकि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि रोडवेज की बसों का प्रति किलोमीटर 48 रूपये खर्च आता है। इस फाइल में प्राइवेट किलोमीटर स्कीम के बिडर्ज की तरफ से दिए गए 31 से 37 रूपये का खर्च दिखाकर यह दिखाने का प्रयत्न किया गया कि यह रेट्स रोडवेज के वर्तमान रेट्स के खर्च से कम है लेकिन बिडर्ज को फायदा पहुंचाने के लिए इस फाइल में जानबूझकर कंडक्टर की सेलरी और दूसरे खर्चों को कैलकुलेट करके नहीं दिखाया गया। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह फाइल निकलती है उस दिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब छुट्टी पर थे इसलिए इस फाइल पर लिखा दिया जाता है कि the Minister has been apprised of the matter और इसके बाद रॉंग फैक्ट्स पर आधारित यह फाइल 18 तारीख को सी. एम. साहब के पास चली जाती है और सी.एम. साहब के पास से यह फाइल उसी दिन निकल भी जाती है और बाकायदा इस फाइल पर लिखा जाता है कि approved and appreciate the good work done. अध्यक्ष महोदय, कौन सा गुड

वर्क किया गया था बताइये तो सही? इस फाइल में बिडर्ज को फायदा पहुंचाने के लिए गलत फैक्ट्स डाले गए थे, अगर उन गलत फैक्टस की पड़ताल और कैलकुलेशन सी.एम.साहब तथा इनका कार्यालय नहीं कर सकता तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? अध्यक्ष महोदय, इस पूरे मामले में 1600 करोड़ रूपये का स्कैम बनता है। जब पानी सिर से उपर चला गया तब जाकर विजिलैंस इंक्वॉयरी की बात कही गई। विजिलैंस ने मुझे भी बुलाया था। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ। करण दलाल जी ने जो अभी स्टेटमैंट दी है वह बिल्कुल गलत है क्योंकि जब कोई चीज प्रोसेस में होती है तब तक उनका कोई कांट्रैक्ट वगैरह नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अगर करण सिह दलाल गलत स्टेटमैंट दे रहे हैं तो इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाये। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, समस्या तो फिर वही आ गई। करण सिंह दलाल अभी–अभी विधान सभा के इस आखिरी सत्र में पहले वाले प्रिविलेज मोशन से निकले हैं। अगर कोई ऐसा प्रावधान होता कि जो गलत स्टेटमैंट करण दलाल जी दे रहे हैं उसके लिए अगर इन पर जो प्रिविलेज मोशन लाया जाये वह नैकस्ट एसेंबली में अगर यह दोबारा चुनकर आते हैं तो इन पर लागू रहेगा और नैकस्ट एसेंबली के पांचों साल यह रगड़े जाये तो ऐसा किया जा सकता था लेकिन ऐसा कोई प्रावधान है नहीं इसलिए इस बात को यही रहने दे तो अच्छा है। अब मैं विषय पर बात करता हूँ। करण सिंह दलाल ने गलत स्टेटमैंट दी है क्योंकि कोई चीज जब प्रोसेस में है और फाइनल नहीं हुई है तो स्वाभाविक सी बात है कि फ्रॉड की तो कोई संभावना ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हाउस में बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि सभा में या तो प्रवेश न किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए क्योंकि वहाँ न बोलने से या गलत बोलने में दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। अतः सरकार को सदन में लिखी गई इस शब्दावली पर खरे उतरने का काम करना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, सदन में लिखे गए तथ्य, वर्तमान संदर्भ के तथ्यों से एकदम परे है इसलिए अभय जी को बैठकर मेरी पूरी बात सुननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, फ्रॉड तब हो सकता है जबकि कोई चीज फाइनल हो जाती है। कोई चीज प्रोसेस में थी और उसमें हमें कोई कमी ध्यान में आई तो हमने उसकी इंक्वॉयरी

करवा दी और इंक्वॉयरी में वह चीज गलत पाई गई तो उस गलत चीज को हमने कोर्ट में पेश कर दिया तो बताओ किस प्रकार से फ्रॉड हो गया? जब कोई चीज एग्जिक्यूट हो जाये और उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो उस अवस्था में फ्रॉड माना जाता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ इसलिए फ्रॉड की संज्ञा देना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात आकर खड़ी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को वास्तविक तथ्यों के बारे में बताया नहीं जा रहा है।(विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, दलाल जी को चिंता करने की जरूर नहीं है मुझे सब तथ्यों की भलीभांति जानकारी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः दलाल जी, जब किलोमीटर स्कीम सिरे ही नहीं चढ़ी है और उसकी इंक्वॉयरी भी करवा दी गई है तो ऐसी स्थिति में फ्रॉड कैसे हो गया? जब कोई स्कीम चालू ही नहीं हुई है तो उसके लिए घोटाला शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किलोमीटर स्कीम के बारे में विस्तार से करण सिंह दलाल को बताया है अतः मैं आपके माध्यम से दलाल जी को अनुरोध करता हूँ कि अब इस बारे में ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को बैठकर ध्यान से सुनना चाहिए और व्यर्थ का बहाना बनाकर सदन से भागने की कोशिश नही करनी चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से एक चीज साफ कर देना चाहता हूँ कि किलोमीटर स्कीम को फेल करने का प्रयत्न चाहे किसी का भी हो, इस बारे में जो झूठा एजेंडा चलाने का काम किया जा रहा है उसको किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जायेगा। किलोमीटर स्कीम चालू होगी और जरूर होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, विजिलैंस ने अपनी इंक्वॉयरी में साफ लिखा है कि किलोमीटर स्कीम में तमाम अधिकारी शामिल हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसमें संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाये लेकिन सरकार द्वारा ऐसा नही किया गया। न किसी अधिकारी के खिलाफ एफ.

आई. आर. दर्ज की गई और न ही किसी मिनिस्टर के खिलाफ ही कोई एफ.आई. आर दर्ज हुई है। कारण यही है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो कहीं न कहीं सरकार इसमें फंसती है। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्माः स्पीकर सर, दलाल साहब तथ्यों को बिल्कुल तोड़ मरोडकर पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः दलाल जी, संबंधित मामले में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी बातें बता दी गई हैं। यहां तक की इस मामले में विजिलेंस इंक्वॉयरी तक हो गई है। अतः अब आपको तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पेश नहीं करना चाहिए।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, यह विषय मुख्यमंत्री जी तक भी जा सकता है? (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, यह विषय मेरे तक जब आयेगा तो तब मैं इसका जवाब भी दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. तब लिखी जाती है जबकि कोई काम हो चुका होता है। एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद में जहां तक अपराध की जड़े होती है, उन जड़ों तक जांच–प्रक्रिया पहुंचती है। उस एफ.आई.आर. में यदि सरकार का कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, मंत्री होगा या फिर मुख्यमंत्री होगा, जो भी उस एफ.आई.आर. में शामिल होगा उसको किसी को भी नहीं बख्शा जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मनोहर लाल मैं अलग हूँ और मुख्यमंत्री अलग हूँ। यदि मैंने गलती की है तो मनोहर लाल के नाम से की होगी, मुख्यमंत्री के नाम से नहीं की होगी अर्थात् यदि मेरे ऊपर भी कोई आरोप सिद्ध होता है तो मुझे भी जेल में डाल दिया जाये, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। (विघ्न)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के नेता से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मैटर की जांच चल रही है?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूँ कि एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है और जांच चल रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, माननीय सदन के नेता ने क्लीयर शब्दों में जवाब दे दिया है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता विजिलैंस की रिपोर्ट पर यकीन नहीं कर रहे हैं। एफ.आई.आर. में सरकार के अधिकारी शामिल हैं। फिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार इसी बात की तो जांच करवा रही हैं कि कौन–कौन से अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं। जांच रिपोर्ट में यदि अधिकारी दोषी पाए जायेंगे तभी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो मेरे अधीन लगभग 750 बड़े अधिकारी काम करते हैं, तो क्या मैं 750 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश कर दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, घोटाले के मामले में सरकार को चाहे 1000 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पड़े वह करनी ही चाहिए। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ ही एक्शन लिया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, *** ।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, दलाल साहब ने अभी जिस व्यक्ति के बारे में बात की है उसको रिकॉर्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, असली बात तो यह है कि विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। यह जनता के बीच में जाने के लिए अनाप–शनाप के मुद्दे की तलाश में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से जनता का जो आज मूड है, उसमें से विपक्ष के साथी कैसे बाहर निकले यह उसकी कोशिश कर रहे हैं और इन्हें करते भी रहना चाहिए, हमको इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। (विघ्न)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, सदन में बात तो स्पष्ट होनी ही चाहिए।

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में बात स्पष्ट कर दी है कि इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है और जांच चल रही है। उस जांच के दौरान जहाँ–जहाँ तक आंच जायेगी किसी को भी छोड़ा नहीं जायेगा। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट बसों को हॉयर करने के लिए किलोमीटर स्कीम में सामने आए घोटाले में अफसरों की संलिप्तता को लेकर रोडवेज कर्मियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या सरकार इस स्कीम को कैंसिल कर रही है? यह बात भी माननीय सदन के नेता सदन को बताएं। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम किलोमीटर स्कीम को कैंसिल नहीं करेंगे। स्कीम तो लागू रहेगी। अगर उस स्कीम में टैंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली और जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने गड़बड़ की हैं जांच रिपोर्ट के हिसाब से उनको दण्डित किया जायेगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, किलोमीटर स्कीम तो लागू ही रहेगी। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट आने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप बैठ जाइये। माननीय सदन के नेता ने बिल्कुल क्लीयर कर दिया है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, *** ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, ने जो कुछ कहा है, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी को कहता हूँ कि जो सदस्य उनका हौंसला बढ़ा रहे हैं उन पर भरोसा न करें। यदि करण सिंह दलाल अपने आप को काबू में रखेंगे तो उनका राजनीति का भविष्य ठीक रह सकता है, नहीं तो जनता विधान सभा के चुनाव में उनको सबक सीखा देगी कि क्या करना होता है। (विघ्न)

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अच्छा काम करने से हौंसला बढ़ता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप बैठ जाइये। आप बार–बार सदन के नेता के बीच में न बोलें। इस तरह तो मुझे मजबूरन होकर आपको नेम करना पड़ेगा। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या आप मेरे बोलने पर मुझे नेम करने की धमकी दे रहे हैं? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, मैं कोई आपको धमका नहीं रहा हूँ। आप ठीक ढंग से सदन में आवाज नहीं उठा रहे हैं। आपने जो जवाब सदन के नेता से पूछ लिया तो पूछ लिया। इसका मतलब यह तो नहीं है कि सदन के नेता को आप बार–बार बीच–बीच में टोकते रहेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। (विघ्न)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, कोई भी मसला सदन में चल रहा हो तो सदन के नेता को उसको स्पष्ट रूप से बताने का धर्म होता है। (विघ्न)

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें सुनने में पता नहीं माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल को क्या दिक्कतें आ रही हैं? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें क्योंकि सदन के नेता जवाब दे रहे हैं। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जल का विषय है। कल श्री अभय सिंह चौटाला जी ने पानी बचाने का विषय सदन में उठाया था। यह बात ठीक है कि पानी का बहुत बड़ा संकट हम सबको सामने दिख रहा है। कम से कम लम्बी सोच रखने वाले लोगों के ध्यान में आता है कि इस मामले में अगली पीढ़ी को भी जवाब देना है। सामान्यतः सामान्य व्यक्ति को यह यह चिन्ता नहीं होती है उसे तो सिर्फ अपने लाभ की ही चिंता होती है । आज स्थिति यह है कि पानी का जलस्तर बहुत नीचे जा रहा है । रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि हर साल जल स्तर 5–15 फुट तक नीचे जा रहा है । कहीं–कहीं पर तो 100–150 फुट तक जल स्तर नीचे चला

गया है । जल स्तर के नीचे जाने से पानी की क्वालिटी भी खराब हो रही है । वह पानी पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां बढ़ रही हैं । आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 'जल बचाओ अभियान' का आह्वान किया है । जल बचाने के जो तौर–तरीके हैं वे हमें अपनाने पड़ेंगे । हमने किसनों से आह्वान किया था कि धान की बुआई में पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप इसकी बजाय अन्य फसल ले लें । आंकड़े बताते हैं कि एक किलोग्राम चावल उगाने में 3000–5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है । अगर खेत में पानी की बहुतायत है तो ठीक है लेकिन अगर पानी की कमी है तो फिर हमें धान की बिजाई को कम कर देना चाहिए । हमने अन्य फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक स्कीम बनाई और किसानों को कहा कि इसमें आपको कुछ–न–कुछ कंपनशेट किया जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा तो कंपनशेट नहीं किया जा सकता । हमने किसानों को कहा कि हम आपको धान की फसल न बोने के एवज में 2000 रूपये प्रति एकड़ मुआवजा, दूसरी फसल का मुफ्त बीज, 'फसल बीमा योजना' के तहत दी जाने वाली किस्त सरकार स्वयं भरेगी और उस फसल की प्रोक्योरमैंट भी सरकार सुनिश्चित करेगी । इस पोलिसी के तहत हमारा टार्गेट था कि हम इस साल 50 हजार हैक्टेयर भूमि पर धान की फसल कम बुआएंगे । आंकड़ों के मुताबिक इस साल अन्य सालों की अपेक्षा 52–53 हजार हैक्टेयर भूमि पर धान की फसल कम बोई गई है जोकि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमैंट है । जिन किसानों ने इस पोलिसी को अडॉप्ट किया है उन पर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी और न ही उन पर किसी तरह की कार्रवाई करने की बात कही थी । हमने उनको सिर्फ एक अपील की थी । अध्यक्ष महोदय, उनको भी पता था कि हमारे क्षेत्र का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। शुरू में इसके लिए हमने सिर्फ 7 ब्लॉक्स चिन्हित किये थे लेकिन इसके बाद 7 जिलों को इस योजना के तहत कवर किया गया । अब 7 जिलों में यह योजना सफल हो चुकी है । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने उनको दण्डित करने का कोई प्रावधान किया था । भविष्य में लोगों को इस योजना के प्रति और जागरूक किया जाएगा । हमने जिस समय यह स्कीम निकाली उस समय फसलों की बुआई शुरू हो चुकी थी और उस समय लोगों को यह स्कीम समझने का समय भी कम मिला था । तब लोगों ने हमसे कहा कि अगर यह स्कीम 1–2 महीने पहले आ जाती तो इसके और भी अच्छे परिणाम हो सकते थे । हम वाटर रिचार्जिंग के सिस्टम पर भी ध्यान दे रहे हैं । इसके लिए बरसात के पानी को खेतो में इकट्ठा

किया जा सकता है, नदी–नालों के पानी से भी वाटर रिचार्जिंग होता है और हमने अर्बन लोकल बोडीज डिपार्टमैंट और टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट को भी इसके लिए नियम बनाने का कहा है । कहीं पर पानी की उपलब्धता की कमी होने की बात है तो हम वहां के लिए बाहर से पानी ले रहे हैं । एस.वाई.एल. नहर का मामला भी सभी को मालूम है, इसलिए उसके बारे में आज सदन में कोई कमिटमैंट करने की आवश्यकता नहीं है । इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में 3 सितम्बर की डेट लगी हुई है । सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया था कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को साथ बिठाकर इस मामले में निर्णय लिया जाए । इसके लिए हमने ए.सी.एस., इरीगेशन की अध्यक्षता में 3 व्यक्तियों की एक कमेटी बना दी है । इस मामले में पंजाब ने क्या किया है वह मुझे मालूम नहीं है । हमने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि इस मामले में कोई रास्ता निकाले । एस.वाई.एल. नहर पर हमारा स्टैण्ड केवल इतना ही है कि एस.वाई.एल. नहर के बचे हुए हिस्से की खुदाई करवाकर हमें हमारे हिस्से का पानी दिया जाए । इसके अलावा हमारा और कोई स्टैण्ड नहीं है और न कोई समझौता है । हाँसी–बुटाना नहर का विषय भी सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है । उसकी डेट लगने वाली है । हमें हाँसी–बुटाना नहर से एक हजार क्यूसिक पानी मिल जाएगा । इसके बाद उस पानी को जहां–जहां भी आवश्यकता होगी वहां पर दे दिया जाएगा । सुरजेवाला जी ने एक मुद्दा उठाया था कि इस नहर का पानी साउथ हरियाणा में जा सकता है । हमको समझ नहीं आया कि उन्होंने कौन–सी भूगोल पढ़ी है । इस नहर का पानी दादरी, भिवानी तक तो जा सकता है लेकिन दक्षिण हरियाणा के जिलों जैसे रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, मेवात आदि में नहीं जा सकता । (शोर एवं व्यवधान) ऐसा हो सकता है कि इस नहर की वजह से यमुना नदी का जो पानी बचेगा वह पानी दक्षिण हरियाणा में जा सकता है ।

वाक आउट

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा के परिवहन विभाग में प्राइवेट बसिज की किलोमीटर स्कीम के टैंडर में 1600 करोड़ रूपये के घोटाले के विषय पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय की रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं सदन से वॉक आउट करता हूं ।

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य श्री करण सिंह दलाल परिवहन विभाग में प्राइवेट बसिज की किलोमीटर स्कीम के टैंडर में हुए कथित

घोटाले के विषय पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉक आउट कर गये ।)

शून्यकाल तथा विभिन्न मांगों के दौरान सदस्यगण द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर (पुनारारम्भ)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने इस पोलिसी के तहत जीरी लगाए जाने वाले एरिया को अडॉप्ट किया है । प्रदेश के 7 जिले डॉर्क जोन में हैं इसलिए यह काम प्रयोग के रूप में किया है क्योंकि पूरे हरियाणा में पानी की एक जैसी स्थिति नहीं है।

श्री आनंद सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार धान के एरियाज को एडॉप्ट करेगी तो उससे फायदा है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसके बारे में बड़ी प्लान बाद में बनायी जाएगी। सरकार ने इस इशू को अभी तो इन्ट्रोड्यूस किया है ताकि यह विषय जनता तक पहुंचाया जा सके और किसानों के ध्यान में आ जाए कि उनको धान की बजाय दूसरी फसलों की बिजाई करनी चाहिए। हमारे देश में धान की ज्यादा रिक्वायरमैंट नहीं है बल्कि धान तो कई–कई सालों का एफ.सी.आई. के गोदामों में एक्सट्रा पड़ा हुआ है। इसलिए धान की खेती कम करेंगे तो देश में अनाज का कोई संकट नहीं आएगा। किसानों को धान की बजाय दलहन/तिलहन की बिजाई करने की आश्यकता है क्योंकि आज वे हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही हैं।

श्री आनंद सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, धान की बिजाई न करने से किसानों को बहुत ज्यादा लॉस होगा।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, इस समय संबंधित फसल को लेकर ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके बारे में बताया जा सकें। हमने किसानों पर कोई दबाव नहीं डाला है और न ही कोई एक्शन लिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जल संरक्षण बहुत जरूरी है। यह बात ठीक है कि जहां पर पानी का संकट आया है उसको दूर करके लोगों तक पानी पहुंचाया जाना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार ने एस.वाई.एल. नहर के बारे में तो कह दिया कि इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। दादूपूर नलवी नहर का मकसद अंबाला और कुरूक्षेत्र जिलों में बारिश के समय में इस नदी के माध्यम से अंडर

ग्राउंड वॉटर को रिचार्ज किया जाना था। इसके लिए 350 करोड़ रुपये से भी ज्यादा पैसे खर्च हो गये हैं। इस नहर से कम से कम 5 लाख एकड़ जमीन का अंडर ग्राउंड पानी रि–चार्ज किया जाता था जिससे जमीन के पानी की मात्रा बढ़ जाती थी। इस नहर में डायरेक्ट बरसात का पानी जाना था। सरकार ने इसको बन्द क्यों किया ? सरकार को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि 52 हेक्टेयर जमीन में किसान अपनी मर्जी से धान न बोये। कोई भी किसान अपनी मर्जी से धान की बिजाई नहीं करता। सभी माननीय सदस्यों को खेती करने का अनुभव है। धान की फसल तो 1 एकड़ में 50–70 हजार रूपये तक हो सकती है और छोटे–छोटे किसान तो 70,000 रुपये से भी ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। सरकार कहती है कि धान की जमीन पर दलहन की पैदावार की जाए परन्तु धान की जमीन पर दलहन की बिजाई नहीं हो सकती। अगर संबंधित किसान ने धान की फसल नहीं बोयी तो वह मारा जाएगा। सरकार का यह फैसला गलत है ? अगर कोई किसान फसल की बिजाई करने के लिए पंचायत की जमीन ठेके पर लेता है या उसकी अपनी जमीन है और वह उसमें धान की बिजाई नहीं करेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किया है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात अखबारों में पढ़ी है। मैंने पहले भी ये बातें बतायी हैं और आज फिर बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात का जवाब दे देता हूं।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दादूपूर नलवी नहर के द्वारा 5 लाख एकड़ जमीन में अंडर ग्राउंड वॉटर रिचार्ज होना चाहिए था और इस नहर पर 350 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे फिर अब सरकार ने इस नहर को बन्द क्यों किया ? सरकार को इस सदन में जल सरंक्षण करने के लिए क्यों कहना पड़ रहा है ?

श्री महीपाल ढांडा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हर बार इसी बात को उठाते रहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने केवल मुर्गियां ही पाली हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि दादुपूर नलवी नहर के ऊपर पहले भी विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, आप खुद इस बात के गवाह हैं और मैं आज दोबारा से कह रहा हूं कि कागजों में कुछ था और वास्तविक रूप में कुछ और था। काश कि कागजों में लिखी हुई सारी बातें धरातल पर होतीं। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस नहर से 5 लाख एकड़ भूमि का पानी रिचार्ज होने की बात कही गई थी, लेकिन उस 5 लाख एकड़ भूमि में माइनर भी नहीं बन पाये और उन माइनर को बनाने वाले जमीन के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया गया था कि अब ये माइनर नहीं बनाये जायेंगे। इस नहर के संबंध में फाइल के ऊपर भी यह ऑर्डर है कि अब ये माइनर नहीं बनाये जायेंगे, क्योंकि किसानों ने इस बारे में विरोध किया था इसलिए उस ऑर्डर को विदड्रा कर लिया गया था।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि माइनर बनाने की बात तो बाद में आई थी, उससे पहले पानी की रिचार्जिंग स्कीम बनाने की बात आई थी। जो स्कीम बनाई गयी थी, वह केवल पानी की रिचार्जिंग के लिए ही बनाई गयी थी। माइनर बनाने का फैसला तो बाद में हुआ था कि यदि पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी पानी को आगे पूरे वर्ष किसानों को दिया जायेगा।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह तब संभव है जब यमुना नदी में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध हो। जो बरसात के तीन महीने होते हैं, उन तीन महीनों में ही यमुना नदी में पानी उपलब्ध होता है और उन तीन महीनों में यमुना नदी के पानी को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि यमुना नदी के पानी से फ्लड आ जाती है। बरसात के तीन महीनों में यमुना नदी में बहुत ही ज्यादा पानी आता है। मैं खुद यमुना, अम्बाला और घाड़ के एरिया में रहा हूं और यमुना नदी का पानी उन तीन महीनों में उस एरिया में इतना भर जाता है कि उस पानी को निकालना मुश्किल हो जाता है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि उन तीन महीनों में यमुना नदी में से सिंचाई के लिए पानी आ सकता है। मैं

माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि अभी भी इन तीन महीनों के बावजूद हर साल ढाई सौ एकड़ की सिंचाई यमुना नदी के पानी से की जा रही है। मेरा कहना है कि अगर भविष्य में यमुना नदी में पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है तो उससे सिंचाई तो जरूर की जायेगी, लेकिन आज के समय में यह संभावना बिल्कुल ही नहीं है। यह सब ख्याली पुलाव पकाना है कि यमुना नदी में पानी आयेगा, लखवार डैम और रेणुका डैम बनेगी। अगर यमुना नदी में लगातार पानी आता है तो उस पानी को लेने के लिए राजस्थान भी तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें उनका भी हिस्सा बंटा हुआ है। आज के समय में यमुना नदी में जितना पानी है, हम उसमें से उनको पानी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यमुना में आज के समय में पर्याप्त पानी उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यमुना में पानी नहीं है और हमें ऐसे ही ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां के किसानों को इससे कोई एतराज नहीं है और अगर भविष्य में यमुना नदी में पानी आ जाता है और किसानों को पानी की जरूरत होगी तो हम वहां पर विकास के कार्य जरूर करेंगे।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये मुझे इस बात का भी जवाब दे दें कि 10 नवम्बर, 2016 को एस.वाई.एल. नहर का जो फैसला आया था, उसके बाद इन्होंने एस.वाई.एल. नहर के संबंध में केन्द्र सरकार से कितनी दफा बातचीत की और इन्होंने कितनी दफा इस बात का प्रयास किया कि यह नहर बने और उसका पानी हमें मिले ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि अगर एस. वाई.एल. नहर बन जायेगी तो क्या हमारी सरकार हरियाणा के लोगों को पानी दे देगी, जबकि यह प्रश्न ही नहीं बनता है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये हमारी बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इन से यही पूछा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवम्बर, 2016 को एस.वाई.एल. नहर से संबंधित फैसला हमारे हक में दे दिया था तो उस फैसले के आने के बाद सरकार ने अपनी तरफ से इस संबंध में माननीय राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्री और राजनाथ सिंह जी से मिलने का प्रयास किया था। उसके बाद अभी तक आगे की क्या प्रक्रिया रही और आपने इस संबंध में अब तक क्या प्रयास किये ? मेरा कहना यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर 3 सितम्बर, 2019 को हीयरिंग होनी ही है तो आपको इसके

लिए कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको केन्द्र की सरकार से समय लेकर उनसे मिलना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो ..... (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इन्होंने इस संबंध में अभी तक क्या–क्या प्रयास किये हैं, उसके बारे में इन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि कृपया ये नाराज न हों। हमें राजनीतिक ड्रामेबाजियां करनी नहीं आती हैं कि कस्सी उठाकर नहर खोदने चलेंगे।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन्होंने केवल और केवल राजनीतिक ड्रामेबाजी की बात की है। इस सदन में जब भी कोई माननीय सदस्य किसी बात के ऊपर चर्चा करता है तो उसमें श्री राम बिलास शर्मा जी खड़े हो जाते हैं और उस विषय को जलेबी की तरह बनाकर छोड़ देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा आपसे होती है और श्री राम बिलास शर्मा जी बीच में खड़े हो जाते हैं और गीता तथा गाय के ऊपर चर्चा करने लगते हैं। (शोर एवं व्यवधान) क्या हमने श्री राम बिलास शर्मा जी से हमारी हरियाणा प्रदेश की जो जीवन रेखा है उसके बारे में पूछा है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप हमें कम से कम इतना तो बता दीजिए कि सरकार ने एस. वाई एल. नहर से संबंधित मामले में लगभग पौने तीन साल तक क्या काम किये हैं? (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अभय सिंह चौटाला जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार एस.वाई.एल. नहर से संबंधित मामले पर पूरी कोशिश कर रही है और इनको भी सरकार की कोशिशों पर भरोसा करना पड़ेगा। मैं समय आने पर इसी विषय के बारे में जरूर जवाब दूंगा। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन में बोलने लगता हूं तो माननीया मंत्री श्रीमती कविता जैन जी बैठे–बैठे ही आपकी तरफ इशारा करती हैं कि मुझे बैठा दिया जाये। (विघ्न) इनको पानी की अहमियत के बारे में क्या पता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह चौटाला जी, पानी के बारे में तो हरेक आदमी को पता होता है। (विघ्न)

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं। मैंने इस तरह का कोई इशारा नहीं किया है (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीया मंत्री जी को आपकी तरफ इशारा करते हुए देखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौटाला जी को बताना चाहूंगा कि 12 साल तक प्रैजिडेंशियल रैफरेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट की फाइलों में दबा पड़ा था। अगर किसी सरकार ने अर्ली हियरिंग का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और अर्ली हियरिंग करके एक दिन फैसला भी हो जायेगा। उसी फैसले के लिए ही वर्तमान सरकार अभी भी प्रयास कर रही है। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं)** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि ऐसे मेजें पीटने से काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर पिछले 12 साल का जिक्र नहीं कर रहा हूं। हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2002 में इंडियन नैशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की सांझी सरकार थी। उस समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस.वाई.एल. नहर के रिगार्डिंग फैसला दिया था लेकिन उस वक्त यह फैसला लागू नहीं हुआ। इस फैसले को लागू करवाने के लिए कई कारण सामने आये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अभय सिंह चौटाला जी को बताना चाहूंगा कि उस वक्त पंजाब की गवर्नमैंट ने यह मामला लटका दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह चौटाला जी, प्लीज आप बैठ जाईये। माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज, आप बैठ जाईये मुख्यमंत्री जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अभय सिंह चौटाला जी को कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ईमानदारी के साथ पानी के लिए जितने भी

प्रबंध हो सकते थे, उनको करने का काम किया है। चाहे इसमें एस.वाई.एल. नहर का मामला हो, चाहे वह हांसी–बुटाना का मामला हो और चाहे वह लखवार डैम का मामला हो। मैं स्वयं लखवार डैम देखने गया था, इसके लिए मैं सदन में बताना चाहूंगा और यह बात किसी के भी ध्यान में भी नहीं आई कि लखवार डैम का मामला और भी आगे बढ़ जायेगा। एक दिन मेरे मन में लखवार डैम को देखने का विचार आया था और मैंने एक दिन का स्पैशल लखवार डैम को देखने के लिए प्रोग्राम बनाया। अध्यक्ष महोदय, मैंने अधिकारियों को यह कहा कि इसकी जानकारी किसी भी स्टेट को या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को न दी जाये क्योंकि हम अकेले ही लखवार डैम को देखना चाहते थे। जिस दिन मैं लखवार डैम को देखने गया उस दिन समाचार–पत्रों में इस बात की खूब चर्चा हुई। मैं इसके रिगार्डिंग केन्द्र सरकार में केन्द्रीय मंत्री श्रीमती उमा भारती जी से मिला। मैंने उनसे कहा कि लखवार डैम, रेणुका डैम और किसाऊ डैम के मुद्दे को क्यों लटका रखा है? अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे को लगभग 40 वर्षों से लटकाकर रखा हुआ है। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि आज इसका एक ऐतिहासिक एम.ओ.यू. भी हो गया है और उसका निर्माण भी शुरू हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने बहुत प्रत्यन किए हैं। उन्होंने यह घोषणा भी की कि पाकिस्तान को जाने वाले पानी को भी रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के लिए रावी और उज्ज दोनों नदियों पर डैम बननी शुरू हो गई हैं। जब यह पानी आयेगा तो पानी के संबंध में ये आपसी झगड़े भी खत्म हो जायेंगे। आज पंजाब और हरियाणा का झगड़ा क्या है? झगड़ा यही है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है कि हमारे पास पानी की कमी है और हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे हिस्से का जो पानी देने का पंजाब सरकार ने वादा किया था, वह पानी दिया जाये। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला कर दिया है लेकिन फैसला करने के बाद उसके ऑर्डर की एग्जिक्यूशन होती है। एग्जिक्यूशन का मतलब हमारे माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी जानते होंगे क्योंकि वह वकील है। उनको इस बात की पूरी जानकारी है और वे इस बारे में अच्छी तरह से जानते भी है और सदन में बता भी सकते हैं कि एग्जिक्यूशन क्या होता है? मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि निर्णय के बाद हरेक कोर्ट एग्जिक्यूशन का ऑर्डर देती है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि हमारी कोशिशों पर भरोसा कीजिए। गवाही तो अदालतें मांगा करती हैं और जब अदालत लगेगी तो उस समय देख लेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मेरी कही गई किसी बात का जवाब नहीं है और बीच में ही शेरो शायरी जैसी बातें करने लग गये हैं। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि यह शेरो शायरी नहीं है। जब आप जनता के बीच जाओगे तो वहां हमसे जवाब मांगने लग जाओगे, इसलिए आज ही मैं आपको सही जवाब दे रहा हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : श्री अभय सिंह चौटाला जी, आप प्लीज बैठ जायें। (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी को कहना चाहता हूं कि बीच–बीच में ऐसी मनोरंजक शेरो शायरी वाली बातें जरूर होनी चाहिए ताकि कुछ तल्खी कम हो।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, सदन में हमारी बहन किरण चौधरी जी ने ग्रामीण चौकीदारों के बारे में एक विषय रखा था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन किरण चौधरी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ग्रामीण चौकीदारों के लिए आपकी स्टेटमैंट ठीक नहीं थी। इन्होंने सदन में स्टेटमैंट यह दी थी कि सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय 10200 रुपये प्रति माह देने का तय किया है लेकिन उनको यह दिया नहीं जा रहा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय 3500 रुपये की जगह 7000 रुपये प्रति माह किया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से अब इनको 7000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जायेगा। इसके अलावा बहन किरण चौधरी जी ने सीवरमैन की बात कही थी कि इनकी मृत्यु हो जाने पर सरकार ने इनको राहत देने के लिए 5 कैटेगरी बनाई है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात का जवाब देने के बजाये दूसरे इशू पर चर्चा करनी शुरू कर दी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह चौटाला जी, आपकी बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लीयर शब्दों में दे दिया है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी को कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार पानी के लिए ईमानदारी के साथ प्रयत्न कर रही है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों को गोलमाल कर दिया है इसलिए हम सदन से वॉक–आउट करने जा रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह चौटाला जी, मुझे लगता है कि आप वॉक–आउट करने के लिए ही बैठे थे। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अभय सिंह चौटाला जी को बताना चाहूंगा कि हमने इनकी बातों का जवाब देने में किसी प्रकार का कोई गोलमाल नहीं किया है। (विघ्न) एस.वाई.एल. नहर के मामले की अगली सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 सितम्बर, 2019 को होगी। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने नवम्बर, 2016 से लेकर अब तक एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए क्या एफर्टस किए हैं। (विघ्न) मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है। हमने उस समय यह कहा था कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखी गई थी उसको सदन के पटल पर रखा जाये। हमने यह भी पूछा था कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच में इस विषय पर क्या बातचीत हुई उसके बारे में भी हमें बताया जाये।

17:00 बजे

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं यहां पर यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने सतलुज–यमुना सम्पर्क नहर के विषय के बारे में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को इससे सम्बंधित चिट्ठी भी लिखी थी। हमने उस चिट्ठी में यही लिखा था कि सतलुज–यमुना सम्पर्क नहर के सम्बन्ध में हरियाणा प्रदेश का एक प्रतिनिधिमण्डल आपसे मिलना चाहता है। हमारी उस चिट्ठी के जवाब में हमें यह कहा गया कि हम इस मामले में श्री राजनाथ सिंह जी से मिल लें जो कि उस समय गृह मंत्री थे। इस प्रकार से हमारे प्रतिनिधिमण्डल ने श्री राजनाथ सिंह, तत्कालीन गृह मंत्री जी से बात कर ली थी।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अब आप बैठ जायें क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आपके सवाल का कम्पलीट जवाब दे दिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं आया है क्योंकि जो जवाब अभी मुख्यमंत्री जी ने दिया है वह गोलमोल है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, हमने यहां पर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से मिलने की बात कही थी। यह विषय गृह मंत्री जी से सम्बंधित था इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि हम गृह मंत्री जी से मिल लें। इसके बाद हमारी गृह मंत्री जी से बात हो गई थी।

वॉक–आऊट

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एस.वाई.एल. नहर व दादुपुर–नलवी नहर के निर्माण के सम्बन्ध में सवाल पूछे थे लेकिन माननीय मुंख्यमंत्री जी द्वारा मेरे इन दोनों सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है इसलिए मैं इसके प्रोटैस्ट में सदन से वॉक–आऊट करता हूं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोक दल के एक सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनके द्वारा एस.वाई.एल. नहर व दादुपुर–नलवी नहर के निर्माण के सम्बन्ध में पूछे गये सवालों के संतोषजनक जवाब न मिल पाने के विरोध में सदन से वॉक–आऊट कर गये।)

शून्यकाल तथा विभिन्न मांगों के दौरान सदस्यगण द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर (पुनारारम्भ)

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, इसी प्रकार से कुछ माननीय सदस्यों ने सीवरेज़ के अंदर उतरकर काम करने वाले कर्मचारियों का जीवन बीमा सरकार के खर्च पर करवाने की बात कही थी। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि न केवल सीवरेज के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों बल्कि उनके साथ–साथ सभी सफाई कर्मचारी, फॉयर मैन, फॉयर ड्राईवर, लाईन मैन, असिसटैंट लाईनमैन और बॉयलर अटैंडैंट इन सभी कैटेगरीज़ के कर्मचारियों में से अगर किसी भी कर्मचारी की काम करते समय मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 10 लाख रूपये की धनराशि का बीमा कवर सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान कर दिया गया है। इस प्रकार से कोई भी रिस्क का काम करने वाले जो कर्मचारी हैं ऐसे कर्मचारियों के साथ अगर काम करते हुए कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उनके लिए सरकार के स्तर पर यह योजना बना दी गई है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से माननीय सदस्यों द्वारा कर्मचारियों का रेगूलराईजेशन और पैंडिंग झगड़ों से सम्बंधित विषय भी यहां पर उठाया गया था। इस बाबत मेरा यह कहना है कि जितने भी कर्मचारियों के पिछले समय के पैंडिंग झगड़े हैं और खास करके आऊटसोर्सिंग से सम्बंधित, डी.सी. रेट से सम्बंधित, प्राईवेट सेवा से सम्बंधित या

गैस्ट टीचर्ज़ से सम्बंधित जो झगड़े हैं, उनके बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि ये बहुत सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनमें तत्कालीन सरकारों द्वारा कर्मचारियों से बैक–डोर एंट्री करवा रखी है। यह बात मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि पिछली सरकारों की बहुत सी नाकामियों को हमें सुलझाना पड़ रहा है। यह बात भी सही है कि पिछली सरकारों की नाकामियों को सुलझाने का दायित्व आने वाली सरकारों का ही होता है इसलिए हम भी अपने इसी दायित्व को निभा रहे हैं। इसी के तहत हमने विभिन्न कैटेगरीज़ के कर्मचारियों को कभी भी सरकारी सेवा से बर्खास्त करके घर भेजने का काम नहीं किया है। हमने सभी को सरकारी सेवा में कंटीन्यू रखने के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकाला है। इसी प्रक्रिया में अतीत में अतिथि अध्यापकों के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आ गया था कि ये आगे एक मिनट के लिए भी सरकारी नौकरी पर नहीं रह सकते। यह बाकायदा तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिटन डिसीज़न है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन अतिथि अध्यापकों से सम्बंधित वर्ष 2014 की पॉलिसी को ही रद्द किया जा चुका था इसलिए उनको पक्का तो किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता था। हमने उनको कहा कि हम आपको सरकारी सेवा से बाहर नहीं जाने देंगे इसलिए हमने उनके लिए नया एक्ट बनाया। उस एक्ट के मुताबिक हमने उनको यह कहा कि हम आपको आपकी रिटायरमैंट की आयु तक सरकारी सेवा में रखेंगे और आपको लम्प–सम पैसा सैलरी के तौर पर दिया जाता रहेगा। इस प्रकार से आज भी हमने उन अतिथि अध्यापकों को सरकारी सेवा में रखा हुआ है। इसी प्रकार से वर्ष 2004 के दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा 102 एच.सी.एस. अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी तो उन्होंने उनकी भर्ती के ऊपर एक प्रश्नचिन्ह् लगा दिया था कि इस भर्ती में गड़बड़ी हुई है इत्यादि, इत्यादि। हमने इन अधिकारियों के पक्ष में कोर्ट में केस लड़ा और वहां पर उनकी दो सूचियां बनवाई जिनमें एक टेंटिड हैं और एक नॉन–टेंटिड है। जो नॉन–टेंटिड सूची है उसमें 38 व्यक्ति हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया को हमने वर्ष 2016 में पूर्ण किया है। इस प्रकार से तत्कालीन सरकारों की गलत नीतियों की वजह से वर्ष 2004 से वर्ष 2016 तक लगभग 12 वर्ष तक उन एच.सी.एस. अधिकारियों को घर बैठना पड़ा। हमारी सरकार 2014 में सत्ता में आई। पिछली सरकारों ने इन एच.सी.एस. अधिकारियों के केस को इतना पेचीदा बना दिया था कि उसको सुलझाने में हमारी सरकार को भी लगभग दो साल का समय लग गया। ऐसे ही

इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार के समय का हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एच.एस.आई.एस.एफ.) का केस है। हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में तत्कालीन सरकार द्वारा पांच हज़ार युवाओं को भर्ती कर दिया गया था लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय की सरकार इनको ड्यूटी ज्वाईन नहीं करवा पाई। उसके बाद हरियाणा प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई कांग्रेस की सरकार ने उनकी भर्ती को ही रद्द कर दिया था और यह कह दिया कि इनको हम ड्यूटी ज्वाईन नहीं करवायेंगे। इस प्रकार से राजनीतिक विरोध के कारण कर्मचारियों की गर्दन पर तलवार लटकाने का काम हमारी सरकार हरगिज़ नहीं कर सकती। यह बात भी सच है कि हरियाणा प्रदेश का अतीत इस प्रकार के अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की जनकल्याणकारी सरकार की इसी विचारधारा के तहत हमने हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के उन सभी जवानों को एस.पी.ओ. के रूप में भर्ती किया और उनको सेवा में लगातार एक्सटैंशन दे रहे हैं। इस मामले में भी हमारी सरकार का यही निर्णय है कि इनको भी रिटायरमैंट की आयु तक सरकारी सेवा में बरकरार रखा जाये। पुलिस बल के रूप में जितना उन सभी का उपयोग सम्भव होगा वह हमारी सरकार करती रहेगी। ऐसे ही एक केस 2189 कम्प्युटर अध्यापकों का है। इनको भी हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी में बनाये रखने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से 2315 प्रयोगशाला सहायकों को भी सरकारी सेवा में बनाये रखने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इनको भी हमारी सरकार ने सेवा से बर्खास्त नहीं किया है। इनका मामला भी हमारी सरकार के समय का न होकर पूर्ववर्ती सरकारों के समय का ही है। हमारी सरकार का यही प्रयास है कि जो भी कर्मचारी एक बार सरकारी नौकरी में आया है किसी तरीके से उसके परिवार का पालन–पोषण होता रहे। जहां तक रेगूजराईजेशन का सम्बन्ध है वह तो सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है लेकिन रेगूजराईजेशन के अलावा जो भी अधिकार हमारे पास हैं उनका प्रयोग करके हमने इन सभी कर्मचारियों को सेवा में बरकरार रखा हुआ है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में एक बात यह लाना चाहूंगा कि कुछ समय पहले जब हरियाणा राज्य परिवहन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई थी उस समय रोडवेज़ की बसों को चलाने के लिए जो ड्राईवर भर्ती किये गये थे आज वे अपने फैमिली मैम्बर्स के साथ पंचकूला में धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कोई भी मंत्री उनके साथ बात

करने को तैयार नहीं है। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उनकी भी सुध ली जाये और उनकी समस्या का भी कोई न कोई सर्वमान्य हल निकाला जाये ताकि उनका जीवनयापन भी सम्मानजनक ढंग से हो सके।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमसे मुलाकात की है तथा उनको हमने समझा दिया है, उनको एक पत्र भी दिया है जिसमें लिखा है कि नई बसें आने के बाद आगे जब भी कभी हमें टैम्पोरेरी की जरूरत पड़ेगी तो उनको प्राथमिकता के आधार पर रखा जायेगा। आज के दिन जितनी बसें हैं उन बसों की संख्या के हिसाब से हमारे पास ड्राईवर और कंडक्टर्स की संख्या पहले से ही ज्यादा है। उस ज्यादा संख्या होने के कारण सरप्लस होने के कारण, अभी उनको नहीं रखा जा सकता है लेकिन यदि भविष्य में आवश्यकता हुई तो सरकार की आउटसोर्सिंग नीति के तहत इन कर्मचारियों को लगाने में प्राथमिकता दी जायेगी। यह उनको कह दिया है। वे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट–1 के तहत लगाये गये थे। यह बात ठीक है कि उस समय आवश्यकता थी तो हमने उनको लगाया लेकिन उनको कोई पक्की सर्विस देने की बात उस समय नहीं कही गई थी और न हमें आगे आवश्यकता है। आज भी कम से कम 1000–1200 तो ड्राईवर ज्यादा हैं और इतने ही कंडक्टर ज्यादा हैं। नई बसें जब जायेंगी तब देख लिया जायेगा। हम खुद अपनी बसें भी खरीद रहे हैं, उनका शायद टैंडर हो गया है या होने वाला है। जब हम नई बसें खरीदेंगे तथा कुछ किलोमीटर स्कीम के तहत बसें आयेंगी तो कंडक्टर्स उसमें काम आ जायेंगे। इसलिए उन सबका भी ध्यान रखा जायेगा। सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन सरकार अपनी तरफ से बैस्ट कर रही है। उसके बावजूद भी जिनकी इच्छा होगी वे धरने भी देंगे और डिमांड भी करेंगे। धरने और डिमांड का संज्ञान हम लेते हैं लेकिन हमारी जितनी लिमिटेशन्ज हैं वह आपको पता है कि हम कितने लोगों को लगा सकते हैं। स्थायी कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा लगें हमारा यही प्रयास रहता है। हमने अपने शासनकाल में इस प्रकार का कोई भी वर्ग खड़ा नहीं किया कि वह बाद में सरकार पर दबाव बनाए कि हमें रेगूलर करो। यह सब पिछली सरकारों के समय के अस्थायी कर्मचारी चले आ रहे हैं और उनको यह उम्मीद भी है कि अगर कोई उनका कल्याण कर सकती है तो यह वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। अगर इसका उदाहरण लिया जाये तो यह है कि मैंने एक विडियो देखी है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष

श्री अशोक तंवर जे.बी.टी. टीचर्स के धरने पर गये थे, उन टीचर्स ने उनसे कहा कि आप किस मुंह से हमारे पास आये हो? यह आपकी सरकार का ही किया हुआ काम है। वह शायद लो मैरिट पात्र अध्यापकों का विषय है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब जो बात कहते हैं तंवर साहब के कानों में तो वह भी नहीं घुस रही है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी दलाल साहब को कहना चाहता हूं कि हम वह विडियो इनको भी भिजवा देंगे। तंवर साहब को हुड्डा साहब के हिस्से की गालियां सुननी पड़ रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब और तंवर साहब में आपस में कितना प्रेम है यह जगजाहिर है, यह सबको पता है। हमारे लिये तो हुड्डा साहब भी ऐसे ही हैं, तंवर साहब भी ऐसे ही हैं तथा दलाल साहब भी ऐसे ही हैं। हम तो सबके लिए दिल बिछा कर बैठे हैं।

"मुट्ठी भर बीज बिखेरे थे हमने दिलों की जमीन पर,
बारिश का मौसम आया सामने बैठे सभी,
कुछ में अपनापन पनप गया
कुछ और पनपाने को तैयार बैठे हैं।

दलाल साहब आपका स्वागत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि हम आपकी पार्टी की नियत को जानते हैं आप अपने कम से कम 30 विधायकों के टिकट अवश्य काटेंगे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अब हमारे पास रास्ता खुल गया है। 90 विधायक तो हरियाणा में लड़ायेंगे और अब तो जम्मू कश्मीर का भी रास्ता खुल गया है। पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ सकते थे लेकिन अब जो बचेंगे उनको वहां पर भी लड़ा सकते हैं।(हंसी) अध्यक्ष महोदय, एक विषय यह भी आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी कितने चुनावी वायदे पूरे किये हैं। मैंने कल रिकॉर्ड मंगवा कर देखा तो पता चला कि हमारे किए हुए इतने काम सामने आ गये कि अगर मैं उन सभी को गिनवाने लग जाऊं तो शायद कल सुबह के पांच बज जायेंगे। उन सभी को यहां पर बता पाना सम्भव नहीं है। अब चूंकि चुनाव आ गया

है तो वे सभी बातें हम जनता के सामने लेकर जायेंगे कि ये हमारे वायदे थे और ये हमने पूरे किये हैं। अगर किसी में कोई कमी रही होगी तो वह भी हम जनता के सामने बतायेंगे। हम कथनी और करनी में अन्तर नहीं रखते हैं। हमने जो–जो काम किये हैं हम उसकी एक किताब छपवायेंगे। यहां पर हमारे अध्यक्ष बैठे हुये हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो, सभी को उसकी एक प्रति अवश्य भिजवाएं।

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने रोहतक के निन्दाणा गांव को गोद लिया था। उस गांव को जैसा गोद लिया था आज भी वह वैसा ही है, उसमें कोई काम नहीं हुआ है।

श्री मनोहर लाल : दांगी साहब, अब गांव की बात नहीं हो रही है । बात है मैनीफेस्टो की। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं उस गांव में भी 40 से 50 करोड़ रुपये तक के काम हुए हैं । आज तक उस गांव में इतना पैसा कभी नहीं लगा था जितना हमारे समय में लगा है । आप कहें तो मैं उस गांव में किए हुए कार्यों की लिस्ट आपके पास भिजवा दूंगा आपको पता चल जाएगा कि वहां कितना पैसा लगा है। अध्यक्ष महोदय, जैसे हमने फसल बीमा योजना की बात की थी, वह बात हमारी पूरी हुई है । वैसे तो ये सभी बातें हमें बताने की जरूरत नहीं है लेकिन जो हमारे 10–20 महत्वपूर्ण काम हैं जिसके बारे में सबको पता भी है और जिसको कोई मना नहीं कर सकता है, उनको तो हम बताएंगे ही । जैसे हमने कहा था कि हम गौ निषेध कानून को सख्ती से लागू करेंगे । उसको हमने पूरा किया । इसी प्रकार से किसानों की फसलों का 48 घण्टे के अन्दर तुरंत भुगतान करने बात हमने कही थी वह भुगतान आज भी किया जाता है । कोई किसान ऐसा नहीं है जिसके खाते में पैसा नहीं पहुंचता है । (शोर एवं व्यवधान) हमने कहा था कि हम भूतपूर्व सरपंचों को मानदेय देंगे । हमने वह भूतपूर्व सरपंचों का मानदेय देने का वायदा भी लागू किया । हमने तो भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, भूतपूर्व नगरपालिका के चेयरमैन इन सभी का मानदेय लागू किया है । ये तो मैं मोटे–मोटे काम बता रहा हूं । हमने कहा था कि ग्राम पंचायतों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे । हमने इंटर जिला परिषद बनाया जिसमें जिला परिषदों व पंचायत समितियों को और अधिकर व बजट दिए हैं । हमारे आने से पहले जिला परिषदों को ऐवरेज मात्र एक करोड़ रुपये का बजट जाता था । अब इन पांच सालों में

उनको 20 से 25 करोड़ रुपये का बजट जा रहा है । हमारा इस बजट को और ज्यादा बढ़ाने का विचार है । हम चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा उनकी क्षमता बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा उनके कर्मचारी बढ़ाए जाएं ताकि हम जिला परिषदों को भी इतना अधिकार दें सकें कि जो छोटे–मोटे काम हैं वह बजाए प्रदेश सरकार के सीधे वहीं से हों, जहां से वे होने चाहिए ।

श्री करण सिंह दलाल : मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह विधान सभा बिल्डिंग की रैनोवेशन जो पहले की गयी थी, उसको क्यों उखाड़ दिया ? इसकी आज इतनी बुरी हालत क्यों बना दी है, ऐसा क्यों हुआ है ?

श्री मनोहर लाल : दलाल साहब, इसके बारे में आपको स्पीकर साहब बताएंगे ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप हमारे चैंबर में आ जाना, हम आपको चाय भी पिलाएंगे और आपको इसके बारे में भी बता देंगे ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने छात्र संघ के चुनाव करवाने के बारे में भी कहा था वह हमने करवा दिए हैं और इस बार फिर होंगे । इसलिए हमने उस वायदे को भी पूरा किया । हमने 10वीं–12वीं कक्षा के प्रतिभावान छात्रों को लैपटॉप देने की बात की थी वह भी इस बार सबको बांटे जा रहे हैं । हमने बुढ़ापा व विधवा पैंशन दो हजार रुपये मासिक देने की बात की थी । आज बुढ़ापा व विधवा पैंशन दो हजार रुपये मासिक मिल रही है । हमारा जो पांच साल का कार्यकाल है ये उसी का एजेंडा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, पांच साल बाद अब दो हजार रुपये मिले हैं ।

श्री मनोहर लाल : दांगी साहब, हमने यह दो हजार रुपये कब की है इसका सवाल नहीं है । सवाल ये है कि आज उनको दो हजार रुपये मासिक पैंशन मिल रही है ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : स्पीकर सर, उस समय यह क्लीयर नहीं था कि कब दो हजार रुपये देंगे लेकिन घोषणा यह थी कि हमारी सरकार दो हजार रुपये बुढ़ापा पैंशन देगी ।

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, लोग तो बहुत खुश हैं ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार प्रतिदिन न्यनतम मजदूरी 300 रुपये देने के बारे में मैंने पहले बता ही दिया है जिसमें 100 घण्टे काम के बदले 12वीं,

ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को सक्षम योजना के माध्यम से काम मिलेगा । इसमें हम लगभग 66 हजार युवाओं को काम दे चुके हैं इसके अलावा जो अपना नाम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं और जैसे–जैसे हमारे पास काम आता है हम उन सबको काम दे रहे हैं । तीन साल के अन्दर–अन्दर वह अपना कोई रोजगार करें या कोई प्राईवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी में आते हों तो उनको सरकारी नौकरी में भी शामिल कर रहे हैं । ऐसे लगभग 22 हजार लोग हैं जो पक्का इम्प्लाईमैंट लेकर उनमें से बाहर निकल चुके हैं । अध्यक्ष महोदय, हमने जितने काम किए हैं हम उन सभी कामों के बारे में जरूर बताएंगे । जो काम हमने नहीं भी कहे थे वह भी हमने किए हैं क्योंकि सारे काम घोषणा पत्र के समय ध्यान आते हैं ऐसा नहीं है । बाद में सरकार चलाते समय बहुत सारे काम ध्यान में आते हैं । जैसे पढ़ी–लिखी पंचायतों की बात है । क्या यह काम हमने घोषणा पत्र में लिखा था ? नहीं लिखा था लेकिन हमारे ध्यान में आया कि नेतृत्व मजबूत व जिम्मेवार होना चाहिए और उसके मन में एक भाव होना चाहिए ताकि वह कोई न कोई जिम्मेवारी से काम कर सके । इसमें पांच कंडीशन लगाकर इस काम को किया गया था । इस काम को करवाते समय विपक्षी दलों, हाई कोर्ट व अन्य सभी के एतराज भी आए लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करवा कर इसको लागू करवाया गया । सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि दot only in Haryana but other States also this should be implemented. यह सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सारा हरियाणा हड़ताल पर बैठा हुआ है । मुख्यमंत्री जी उस हड़ताल को खत्म करवाईए । वह अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं । आप उन लोगों को बुलाकर उनसे बात करके उनका समाधान कीजिए । हमने अखबारों में पढ़ा है कि सरकार ने उनसे अभी तक बात ही नहीं की है । आप उनसे बात करके इस हड़ताल को खत्म करवाईए क्योंकि इससे हरियाणा के लोग परेशान हो रहे हैं ।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हमने कर्मचारियों की मांग पर ही चार साल पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने की कार्यवाही शुरू की थी। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने के लिए जो रिकमंडेशन जारी की गई थी उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकार भी शामिल थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, चाहे कुछ भी हुआ हो लेकिन आज जो वकील स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने के विषय पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सरकार को उन्हें बुलाकर बात करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं दलाल जी को बताना चाहूंगा कि वकीलों के प्रतिनिधियों से सरकार की बात हुई है। उन्होंने मात्र एक ही बात कहकर अपनी बात खत्म कर दी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया जाये और हमने साफ कह दिया कि यह खत्म नहीं हो सकता। इतनी बात तो हो गई है इससे अलग यदि वे बात करना चाहेंगे तो सरकार भी बातचीत की दिशा में आगे बढ़ेगी परन्तु वे इससे आगे बढ़ते नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है इतने गम्भीर मसले पर मैं न मानू वाली बात कभी लागू नहीं हो सकती क्योंकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकार इन सभी चारों स्तरों ने मिलकर इसको बनाने का निर्णय लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, जिन डिमांड्ज पर ज्यादा जद्दोजहद हो, उन डिमांड्ज पर किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी लगाकर हड़ताल खत्म करवाई जा सकती है क्योंकि लंबी हड़ताल चलने की वजह से ज्यूडिशियल प्रोसेस से जुड़े तमाम प्रकार के कामों में रूकावट आ रही है और इससे किसी न किसी स्तर पर नुकसान भी तो हो रहा है?(विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं गीता जी को बताना चाहूंगा कि नुकसान हो रहा है यह विषय सबको सोचना है। उनको भी सोचना है और हमें भी सोचना है। किसी बात को खत्म करने के लिए कईं रास्ते होते हैं लेकिन चूंकि इन लोगों ने एक जिद पकड़ ली है इसलिए हड़ताल लंबी खिंच रही है। यह जिद सबकी ओर से है ऐसा भी नहीं है क्योंकि जब कोई हड़ताल होती है तो हड़ताल का सारा काम काज नेतृत्व कर रही यूनियन/मैंनेजमैंट के लोगों के हाथों में आ जाता है। जहां तक गीता जी जिम्मेदारी की बात कर रही हैं तो अगर यह जिम्मेदारी आप ले लें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिद के आगे रास्ता निकालना बहुत मुश्किल होता है। किन्हीं विषयों पर परिणाम पर तभी पहुंचा जा सकता है जबकि दोनों पक्ष बातचीत की दिशा में कुछ आगे बढ़े। खैर, अब मैं फिर विषय पर आता हूँ। कई विषय ऐसे होते हैं जो हमारे घोषणा पत्र का भाग नहीं होते परन्तु

बावजूद इसके उन विषयों पर भी काम किया जाता है। इसका साक्षात उदाहरण यह है कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहीं भी यह मैंशन नहीं किया था कि हम हरियाणा को कैरोसीन मुक्त करेंगे लेकिन बावजूद इसके हमने हरियाणा को कैरोसीन मुक्त करने का काम किया है। कारण यह था कि जब सरकार के ध्यान में आया कि वर्तमान संदर्भ में अब कैरोसीन ऑयल का कोई भी यूज घरों में नहीं हो रहा है और यह मात्र ब्लैक मार्किट का एक जरिया बन गया है। कैरोसीन ऑयल के ट्रक, डिपो से चलकर सीधे पैट्रोल पम्प पहुंच जाते है और पैट्रोल की अंडरग्राउंड टंकियों पर ट्रकों में लोड कैरोसीन ऑयल को पाइप के माध्यम से भर दिया जाता है और आगे चलकर यही खराब पैट्रोल हमारी गाड़ियों, स्कूटर, कारों, बसिज तथा ट्रैक्टरों के इंजन खराब करने का काम करता है तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रदेश को कैरोसीन मुक्त करने का बीड़ा उठाया। कहने का भाव यही है कि अगर घोषणा पत्र से अलग भी कोई विषय हमारे संज्ञान में आया तो भी हमने उस विषय पर काम करने से कभी परहेज नहीं किया और यदि भविष्य में भी कोई ऐसा विषय आयेगा जिस पर काम करने की जरूरत होगी तो निःसंदेह हमारी सरकार उस विषय पर काम करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। अध्यक्ष महोदय, भावांतर भरपाई योजना हमारे घोषणा पत्र का भाग नहीं थी लेकिन हमने इस योजना को भी अपनाने का काम किया। आरम्भ में हमें बताया गया कि भावांतर भरपाई योजना मध्य प्रदेश में सफल नहीं हुई थी तो भी हमने कहा कि कोई बात नहीं वहां सफल नहीं हुई लेकिन हम इसको हरियाणा प्रदेश में सफल करके दिखायेंगे। हमने इस योजना के तहत पहले बाजरा खरीदा उसके बाद सरसों खरीदी और इसके बाद सूरजमुखी को भी खरीदने का काम किया गया। यही नहीं अब हम गोबी, आलू, प्याज तथा टमाटर इन चार प्रकार की सब्जियों को भी इस योजना के तहत खरीदने का काम कर रहे हैं। भाव यही है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक मनोबल की आवश्यकता होती है और वह मनोबल हमारी सरकार में है और यही कारण है कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में नित रोज नए–नए प्रयोग करती जा रही है और हमारे चित में जो बात है वह यह है कि समाज का जो अंतिम गरीब आदमी है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले फिर चाहे कोई केन्द्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो यह कोई महत्व नहीं रखता। गरीब आदमी को सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ दिलाना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। हमारे चित में एक चीज यह भी थी कि ऐसे

केन्द्र बनाये जायें जहां एक छत के नीचे लोग बैठकर विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसके लिए अंतोदय केन्द्र तथा सरल केन्द्र खोले गए जोकि वर्तमान में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग एप्लीकेशंज के माध्यम से यहां आकर अपने कामों को करवा रहे हैं और उनको घर बैठे–बैठे ही मैसेज पहुंच जाता है कि उन्होंने जिस काम के लिए एप्लाई किया था वह फाइल फलां लैवल पर पहुंच गई है और इतने दिनों को बाद उनका यह काम हो जायेगा या सरकारी स्कीम का पैसा मिल जायेगा अर्थात यदि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वह इन केंद्रो की सहायता लेकर अपना काम करवा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब हम एक नई चीज और करने जा रहे है। इसके बारे में आप सबने समाचार पत्रों में तो पढ़ा होगा लेकिन विधान सभा में बताने का मौका अब मिला है। सब जानते हैं कि एक व्यक्ति की पहचान उसके आधार कार्ड से होती है लेकिन किसी परिवार की पहचान क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। अब हमारी सरकार परिवार की पहचान के नाते से परिवार पहचान–पत्र के रूप में एक पत्रक बनाने जा रही है। इसको बनाने का कार्य आजकल एक–एक कैटेगरी के हिसाब से शुरू किया हुआ है। हमने कहा है कि इसके लिए सब लोग फार्म भरें और उसे अपलोड करें और जो वेरिफिकेशन की बात है वह बाद में होती रहेगी ताकि सरकार की जो योजनायें हैं उनको हर जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के पास पूर्ण आंकड़े हों। प्रदेश या देश में कितने परिवारों में सदस्यों की संख्या कितनी है, परिवार की आमदनी क्या है, उसका एड्रैस क्या है, उसके पास अपना मकान है या नहीं। यह जानकारी ऐसी होंगी जोकि परिवार पहचान पत्र से मिलेंगी और इनके आधार पर ही भविष्य में सरकार अपनी योजनाओं को बनाकर देश के लोगों की सेवा करने का काम करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, अब आधार कार्ड व परिवार पहचान पत्र से जुड़ी बात हो रही है तो मैं भी इस संदर्भ में जानना चाहती हूँ। जैसाकि सदन में कहा गया था कि बहुत से लोग अपनी फैमली मैम्बर्ज का आधार कार्ड देने से बचते हैं तो सरकार की ओर से जो यह परिवार पहचान पत्र के संदर्भ में पत्र जारी किया गया है, जिसके लिए सरकारी कर्मचारियों से कहा गया कि यदि आप अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी नहीं देंगे तो आपकी सेलरी रोक दी जायेगी और जब सरकारी कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो इस पत्र को वापिस ले लिया गया,

इसलिए मैं इस संदर्भ में जानना चाहती हूँ कि क्या परिवार पहचान पत्र के लिए परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड देना कंप्लसरी हैं?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आधार कार्ड कंप्लसरी नहीं है लेकिन परिवार पहचान पत्र बनवाना कंप्लसरी है। जहां तक परिवार के सदस्यों की जानकारी न देने के कारण सैलरी रोक देने की बात है तो यह बिल्कुल गलतफहमी पैदा करने वाली ही बात है। सरकार की ओर से जो पत्र जारी किया गया था उसका भाव यह था कि चूंकि हर महीने की 30–31 तारीख तक कर्मचारियों को सैलरी मिल जाती है। अगर सैलरी के डिस्बर्सल के दिन ही परिवार पहचान पत्र के लिए जरूरी फार्म भरवा लिया जाये तो इससे परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य आसान हो जायेगा। इसके पीछे सरकार की केवल यही मंशा थी लेकिन इसका अर्थ यह ले लिया गया कि अगर कोई परिवार पहचान पत्र से संबंधित फार्म नहीं भरेगा तो उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। यह किसी भी सूरत में सच बात नहीं थी और यही कारण है कि हमने उसी दिन शाम को इस पत्र को चेंज करवाया और सैलरी वाले कॉलम को हटवाकर इसमें यह बात जोड़ दी कि इस फार्म को जल्द से जल्द भरकर दे दिया जाये। यह रिवाइज्ड लैटर उसी दिन या अगले दिन सबको भेज दिया गया और अब किसी को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं है। यदि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली होती तो महीने के आखिरी तीन दिन में सैलरी का हल्ला मच जाता। जितना जल्दी हो सका हमने इस चीज पर संज्ञान लेते हुए सभी कर्मचारियों को समय पर सैलरी दे दी है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि यदि कर्मचारी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखकर नहीं देगें तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको आज भी हम लागू कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह भी पूछना चाहता हूँ कि सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर्ज सम्मिट के दौरान कितना एफ.डी.आई. हरियाणा में लेकर आयी है? इस बात की जानकारी भी आखिरी सत्र को देखते हुए माननीय सदन को आज सदन में बतानी चाहिए। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के सदस्यों ने जो इस बार प्रश्न पूछे हैं मुझे पहले उनका जवाब देने दीजिए। यदि भाई करण सिंह दलाल को जनता ने दोबारा से विधान सभा में आने का मौका दे दिया तो फिर यही बात माननीय सदस्य एक तारांकित प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं उस समय माननीय सदस्य के इस प्रश्न का जवाब अवश्य दे दूंगा कि कितना निवेश हरियाणा में आया है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो पहली बार चुनकर सदन में आए हैं और मुझे विधान सभा में आते हुए लगभग 25 साल हो गए हैं। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, 25 साल माननीय सदस्य को विधान सभा में आते हो गए हैं और कोई काम जनता का नहीं किया है, इसलिए तो हरियाणा की जनता आगे विधान सभा में आने के लिए रोक लगायेगी। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राईक करके वोट हासिल कर लिए और अब यह अनुच्छेद–370 हटाने की आड़ में हरियाणा की जनता से वोट ले लेंगे। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि अभी तो अनुच्छेद–370 हटाने जैसे ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए लोकसभा के सत्र की अवधि को एक सप्ताह के लिए ही बढ़ाया है अगर एक–आधा सोमवार तक और लोकसभा का सत्र बढ़ गया तो चौथे सोमवार देख लेना क्या होगा। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल ने एक विषय को उठाते हुए कहा था कि तत्काल स्कीम में जिन लोगों को टयूबवैल के कनैक्शन नहीं मिले हैं उन्हें जरूर दें। अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि तत्काल स्कीम में जितनी भी कनैक्शन लेने के लिए एप्लीकेशंज आई थीं, उन सबके कनैक्शन रिलीज़ हो गए हैं। केवल उनमें 9 केस कोई न कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम के कारण पैंडिंग हैं, जैसे ही टैक्नीकल प्रॉब्लम दूर हो जायेगी वैसे ही कनैक्शन रिलीज़ कर दिये जायेंगे। इस हिसाब से तत्काल स्कीम में कोई केस पैंडिंग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आगे के लिए हम जरूर एक योजना बना रहे हैं कि बिजली कैसे बचाई जाए अर्थात् एनर्जी इफिश्न्ट पम्प सेट्स लगाए जायें। अभी तक फोर स्टार पम्प सेट लगाने की एक पद्धति थी। हमारे ध्यान में यह बात आई है कि हमारे किसान

भाई फोर स्टार पम्प सेट लगाने की बजाए देसी किस्म के पम्प सेट ही लगाते हैं क्योंकि उनको देसी पम्प सेट सस्ते मिल जाते होंगे या फिर उनको कोई लालच रहता होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहता हूँ कि अब लेटैस्ट टैक्नोलजी फाइव स्टार पम्प सेट की आ गई है इसमें पहले वाले फोर स्टार पम्प सेट से 30 प्रतिशत की बिजली की बचत होती है, इसलिए अब फाइव स्टार पम्प सेट लगाने की योजना है। हम यह भी चाहते हैं कि किसान भाई स्वयं बाजार से यह न खरीद कर, सरकार द्वारा अच्छी कंपनियों के टैंडर के माध्यम से फाइव स्टार पम्प सैट खरीदे। हमें बाजार के भाव पर भरोसा नहीं है। हमें यह भी नहीं पता कि असली और नकली पम्प सेट कितने का है? बिजली विभाग ही उसको लगवायेगा और पांच वर्ष की उसकी वारंटी भी होगी। अध्यक्ष महोदय, नॉर्मली मोटर की खरीद में किसानों का जितना पैसा लगता है उसका पता लगाकर उस हिसाब से सब्सिडी वगैरह देकर रेट के अंतर को तय कर लेंगे। (विघ्न)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, सरकार पुरानी मोटरों का क्या करेगी?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, पुरानी मोटरों को भी रिप्लेस कर देंगे। अभी तक तो मैं सिर्फ जो नये कनैक्शन रिलीज़ करने की बात है उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। अब जो नये कनैक्शन देने हैं वे फाइव स्टार पम्प सेट के ही दिए जायेंगे। बाजार में जो फोर स्टार व देसी किस्म के पम्प सेट्स हैं उनके रेट से थोड़ा कम पैसा किसानों से लिया जायेगा और बाकी पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यदि हम अच्छी कम्पनी से टैंडर के माध्यम से अधिक मात्रा में फाइव स्टार पम्प सेट्स खरीदेंगे तो ज्यादा महंगें भी नहीं मिलेंगे और उन मोटरों की पांच वर्ष की वारंटी भी होगी। पांच वर्ष की वारंटी मिलने पर यदि कोई मोटर खराब हो जाती है तो मुफ्त में ठीक करने की जिम्मेवारी कम्पनी की होगी। इस प्रकार से बिजली की बचत होनी शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, किसान से तो नाम मात्र ही शायद 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ही पैसे लिए जाते हैं लेकिन इस प्रोसैस को करने से सरकार को 30 प्रतिशत ज्यादा बिजली की बचत होगी। इसका सीधा–साधा लाभ सरकार जो किसानों को बिजली पर सब्सिडी देती है उस पर पड़ेगा। इस प्रकार का सिस्टम बनाकर हम जल्दी ही लागू करने जा रहे हैं। नये कनैक्शन रिलीज़ होने के बाद फिर हम पुराने कनैक्शनों को भी बदल देंगे। अध्यक्ष महोदय, बिजली बचाने के इस प्रोसैस में किसानों के ऊपर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है लेकिन सरकार बिजली के ऊपर जो सब्सिडी लोगों

को शायद 7–8 हजार करोड़ रुपये के करीब देती है उसके ऊपर जरूर पड़ेगा। इस प्रकार से यह लाभ हम सबको हो जाएगा । सदन में एक विषय फरीदाबाद का आया था कि वहां बड़खल रोड पर बैंक्वेट हॉल्स और फार्म आउसिज की कुछ दीवारें बनी हुई हैं । यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018–19 में 13 मैरिज प्लेसिज को चलने की इजाजत दी थी और बाकियों को पैंडिंग रखा था । वहां 60 फार्म हाउसिज में कोई काम नहीं चल रहा है । वहां पर केवल उनकी चारदीवारी हुई रहेगी । उन पर आगे कोई भी काम नहीं हो पाएगा । जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक इन पर यथास्थिति रहेगी । सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इनमें कुछ हो पाएगा । यह इलाका जंगल और पहाड़ का इलाका है और यहां पर पी.एल.पी.ए. एक्ट के कारण भी बहुत–सी चीजें उलझी हुई हैं । अध्यक्ष महोदय, मुझे सदस्यों द्वारा सदन में उठाए गए विभिन्न विषयों पर यही जानकारी देनी थी । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

विधान कार्य

(i) दि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब खेल एवं युवा मामले मंत्री हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय, विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा खेल–कूद विश्वविद्यालय, विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

> कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय, विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय, विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, अभी ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बिल पेश किया है । यह बहुत ही वैलकमिंग स्टैप है । माननीय मंत्री जी पिछले 5 साल से कह रहे थे कि हम राई स्पोर्ट्स स्कूल को स्पोट्स यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे । आज सदन में जो बिल पेश हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं । हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश–दुनिया में

अपने खेल से हरियाणा का नाम रोशन किया है । मेरा इस बिल के बारे में सुझाव है कि इस यूनिवर्सिटी में जब वी.सी. नियुक्त किया जाए तो वह स्पोर्ट्सपर्सन हो ताकि वह खिलाड़ियों की जरूरतों को समझ सके और यूनिवर्सिटी को अच्छे ढंग से चला सके । इसके अतिरिक्त भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय के अंडर जो कॉलेजिज चल रहे हैं मैं उनके बारे में भी क्लैरीफिकेशन चाहती हूं । सरकार ने कहा था कि इस यूनिवर्सिटी के तहत कॉलेज और रीजनल सैंटर्स खोलने का भी प्रावधान किया जाएगा तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या झज्जर में भी ऐसा कोई रीजनल सैंटर खोला जाएगा ? इससे पहले जब हमने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनाई थी तो उसको भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहा गया था लेकिन इस सरकार के आने के बाद कोई भी नये स्कूल या कॉलेज नहीं बने जो उस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हों । अतः मैं जानना चाहती हूं कि इस नई यूनिवर्सिटी के अंडर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल या कॉलेजिज को लाया जाएगा या फिर इसके लिए नये कॉलेजिज बनाए जाएंगे ? इसके अलावा मैं जानना चाहती हूं कि इस यूनिवर्सिटी में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमैंट भी रहेगा या फिर इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स एण्ड यूथ अफेयर्स डिपार्टमैंट ही काम करेगा ? हरियाणा के जो खिलाड़ी अपनी मेहनत से मेडल लेकर आते हैं उनके लिए यदि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टैक्नोलॉजी और रिसर्च वर्क भी होगा तो मेरा कहना है कि इससे आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा और हमारा प्रदेश खेलों में काफी तरक्की करेगा ।

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, श्री सुभाष कात्याल, भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा जो सदन की वी.आई.पीज. गैलरी में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं, मैं सदन की तरफ से उन का अभिनन्दन करता हूँ ।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश है । उनके खेल को और संवारने के लिए हमें स्पोर्ट्स साइंस की जरूरत थी । इसके लिए खिलाड़ियों को बार–बार विदेशों में जाना पड़ता था, इसलिए हमने एक उच्चस्तरीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय किया है। इसमें स्पोर्टस साइंस, स्पोर्टस टैक्नोलॉजी, स्पोर्टस मेडिसन, स्पोर्टस साईक्लोजी, स्पोर्टस न्यूट्रिशन, स्पोर्टस जर्नलिज्म, स्पोर्टस मार्केटिंग, स्पोर्टस कोचिंग और स्पोर्टस फिजियोलॉजी टाईप के

कोर्सिज रखे जाएंगे और कोचिज तैयार करवाये जाएंगे। आज खिलाड़ी को जरूरत है कि उसे किस न्यूट्रिशन के भोजन की जरूरत होती है लेकिन हमारे पास उसके टैक्नीकल्ज नहीं है। आज अगर खिलाड़ी को साईक्लोजिकल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है तो हमारे पास साईक्लोजिस्ट नहीं है। आज स्पोर्टस जर्नलिज्म के प्रोपर तरीके से पढ़े हुए लोग नहीं है और हमारे पास कोचिज भी नहीं हैं। मैंने हर जिले में 20–20 नर्सरी एजूकेशन संस्थांओं को दी हैं परन्तु वे कई स्थानों पर किन्हीं कारणों से शुरू नहीं हो पायी क्योंकि क्वालिफाईड कोच नहीं मिल रहे हैं। उनको खेलना तो आता है परन्तु वे क्वालिफाईड नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में क्वालिफाईड कोच और अम्पायर भी तैयार किये जाएंगे और सैंटर ऑफ एक्सिलैंसी भी बनाया जाएगा। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बुलाकर ट्रेनिंग दी जा सके, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सैंटर ऑफ एक्सिलैंसी बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने चांसलर और वाइस चांसलर की नियुक्ति के बारे में बात की है तो उसके लिए हमने एक्ट में लिखवा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, खेल प्रशासक या नामी खेल शिक्षक को ही चांसलर/वाइस चांसलर बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो राई स्पोर्टस स्कूल है, वह कैंपस स्कूल ही रहेगा। जैसे यूनिवर्सिटी में कैंपस स्कूल होते हैं, वैसे ही रहेगा।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज (2) ऑफ क्लॉज– 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> कि सब क्लॉज (2) ऑफ क्लॉज– 1 विधेयक का पार्ट बनें।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

क्लॉजिज 2 से 43

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉजिज 2 से 43 विधेयक का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि शिड्यूल विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज (1) ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज (1) ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बनें।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाईटल हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्षः अब खेल एवं युवा मामले मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधयेक पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

(ii) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नंबर 3) बिल, 2019

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री, हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे और यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज –2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज– 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–3

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज– 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि शिड्यूल विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें कि विधेयक पारित किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

(iii) दि हरियाणा गोवंश संरक्षण एण्ड गोसंवर्धन (अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब पशु पालन एवं डेयरिंग मंत्री, हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज 2 से 4

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 4 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब पशु पालन एवं डेयरिंग मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

(iv) दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैकंड अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करती हूं और मैं आपकी अनुमति से इस विधेयक के क्लॉज–20 (ii) में एक संशोधन करना चाहती हूं कि ''निगम'' शब्द के स्थान पर ''पालिका'' शब्द होना चाहिए। इसलिए मैं प्रस्ताव करती हूं –

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 के क्लॉज–20 (ii) में पहली पंक्ति में ''निगम'' शब्द के स्थान पर ''पालिका'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अब मैं यह प्रस्ताव करती हूं –

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 के क्लॉज–20 (ii) में पहली पंक्ति में ''निगम'' शब्द के स्थान पर ''पालिका'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए और हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का रवैया इस तरह का रहा है कि 'खांदी छोले ते डकार बादामां दे'। इसका मतलब यह है कि काम कोई करना नहीं और दिखावा इतना करना कि कोई काम करने की जरूरत ही न पड़े। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से सरकार Municipal Councils के अंदर three days continuously sittings का प्रोविजन करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल काउंसिल्ज़ के लिए चाहे सरकार जितने भी सैशन करवायें लेकिन जो चेयरपर्सन और पार्षद होते हैं उनको अधिकार जरूर दिए जायें। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में म्युनिसिपल काउंसिल्ज़ में ऐसे हालात पैदा हो गये हैं कि जो चेयरपर्सन और पार्षद हैं, उन बेचारों को काम करवाने के लिए विधायकों और मंत्रियों के पीछे–पीछे घूमना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनको सरकार ने क्या अधिकार दिए हैं? जहां तक दूसरी स्टेट्स की बात है, जैसे पश्चिम बंगाल और इसके अलावा कई अन्य स्टेट्स भी हैं, उन्होंने उनको अधिकार दे रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम भी अपने म्युनिसिपल काउंसिल्ज़ के चेयरपर्सन और पार्षद को अधिकार देते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे सरकार का बोझ हल्का होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के जितने भी शहर हैं उनमें जो प्राइमरी स्कूल्ज़ और डिस्पैंसरीज़ बनी हुई है, जो पहले आवारा पशुओं के लिए जो अलग से डिपार्टमैंट हुआ करता था, इन सभी को भी अब अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमैंट से बाहर कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा तो सरकार से यही कहना है कि सरकार इनको फाइनैंशियल पावर दें तभी इसका फायदा है, वरना तो ये बेचारे मीटिंग्स के लिए तीन–तीन दिन तक इंतजार में बैठे ही रहेंगे क्योंकि इनके पास वहां पर बैठने के लिए बिल्डिंग भी उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए अक्ल मार प्रोग्राम शुरू कर रही है, यह तो वही बात हुई कि 'खांदी छोले ते डकार बादामां दे'।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी के शब्दों पर आपत्ति करते हुए सदन के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा है कि काम कोई करना नहीं और दिखावा इतना करना कि कोई काम करने की जरूरत ही न पड़े। इसके लिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ऑलरेडी पहली बार हरियाणा प्रदेश में स्टेट फाईनैंस कमीशन के माध्यम से डैवोल्यूशन फार्मूला तैयार किया है। हमारे म्युनिसिपल काउंसिल्ज़ में थर्ड टियर और सैंकिंड टियर हैं। उनके लिए डायरैक्ट डैवोल्यूशन फार्मूले के तहत स्टेट के बजट से ग्रांट मुहैया करवाई जाएगी।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की बात से सहमत हूं और हमें इसमें कोई एतराज भी नहीं है लेकिन मेरा सरकार से निवेदन यह है कि इनको कोई न कोई पावर दी जाये ताकि सरकार का बोझ भी कम हो और इसके साथ–साथ वहां इनको काम करने के अधिकार भी मिलें। अगर ऐसा होगा तो शहरी लोगों को भी राहत मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : करण दलाल जी, मंत्री जी ने सदन में जानकारी दे दी है कि इस बिल के माध्यम से सरकार चेयरपर्सन्ज़ और पार्षदों को पावर देने का काम करने जा रही है।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी को कहना चाहती हूं कि हरियाणा सरकार चुने हुए प्रतिनिधि को सही मायनों में किस तरह अधिकार देने हैं, ऐसा पहली बार हरियाणा प्रदेश में करने जा रही है। अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में कहा जाता है कि ये अपने आप में पूरी सरकार है, अर्बन लोकल बॉडीज को कर लगाने, इन्कम जैनरेट करने और एक्सपैंडीचर करने का भी अधिकार होता है। माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने एक बात बिल्कुल सच कही कि पहले किस तरह से पाषर्दों को ऊँगलियों पर नचाने का काम किया जाता था, किस तरह से काम करवाये जाते थे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में 'सुशासन और विकास'' का एक संकल्प लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि बिगड़ती हुई व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने का बीड़ा अगर किसी सरकार ने उठाया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है और इसी को सुशासन कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

से सदन में यह भी कहना चाहती हूं कि हरियाणा प्रदेश में म्युनिसिपल कारपोरेशन्ज़ में बिगड़ती हुई व्यवस्थाओं को देखते हुए ही मेयर के डायरैक्ट इलैक्शन हुए थे। जब किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो कैसे प्रदेश में डिवैल्पमैंट वर्क्स किए जायेंगे, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखकर सरकारें अपने प्रोग्राम बनाती हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले यह होता था कि अगर सरकार अल्प बहुमत के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती थीं तो म्युनिसिपल कारपोरेशन्ज़ को इस बात डर सताता रहता था कि न जाने कब हमारे सारे कामों पर तलवार लटक जायें क्योंकि सरकार गिरने का डर हमेशा लगा रहता था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि उनको इस बात का भी डर सताता रहता था कि अब हाउस की मीटिंग कैसे होगी और डिवैल्पमैंट वर्क्स कैसे अप्रूव होंगे? इन बातों को लेकर पूरा साल बीत जाता था, मीटिंग नहीं होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट लैवल फाईनैंस कमीशन और इंटर डिस्ट्रिक्ट फाईनैंस कमीशन बनाया है ताकि वित्तीय प्रावधान किए जा सकें और ग्राउंड लैवल तक की जो शक्तियां हैं, वो ग्राउंड स्तर तक पहुंचाई जा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि अर्बन लोकल बॉडीज के साथ–साथ, जिला परिषद् को भी स्ट्रैंग्थन कर दिया गया है और सी.ई.ओ. को जिला परिषद के चेयरमैन के अंडर किया गया है ताकि सभी हरियाणा प्रदेश की संस्थाओं को सशक्त किया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले वर्ष अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर डायरैक्ट मेयर के इलैक्शन करवाये और जनता ने भी इस बात को सराहा तथा स्वीकार किया। दलाल साहब को भी इस बात का भलीभांति ज्ञान है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पांचों मेयर के चुनाव पूर्ण बहुमत से जीते थे। इसके साथ हमारी सरकार इस बिल में संशोधन के माध्यम से यह भी प्रावधान करने जा रही है कि नगर निगमों के अलावा जो दूसरी संस्थाएं हैं जैसे म्युनिसिपल कमेटीज और म्युनिसिपल काउंसिल्ज़ हैं उनके प्रैजीडैंटस के चुनाव भी हमारी सरकार डायरैक्ट करवाने का प्रावधान करेगी। आज इस महान सदन में इसके रिगार्डिंग बिल भी पास हो जायेगा। जहां तक नगर निगम की बात है तो मैं बताना चाहूंगी कि जो नगर निगम की जो बैठकें होती हैं, हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से इसमें यह भी प्रावधान करने जा रही है कि साल में कम से कम दो बार इन संस्थाओं में मीटिंग्स जरूर हुआ करे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी को यह भी बताना चाहूंगी कि इन संस्थाओं का हाउस

कितने दिन चलेगा, इन सबका एक खाका तैयार किया जा रहा है ताकि विकास के एजेंडे पास किए जा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दलाल साहब को कहना चाहूंगी कि आप दूसरों को ज्ञान तो बहुत बांटते फिरते हैं परन्तु खुद असलियत में ऐसी ज्ञान की बातें कुछ नहीं करते हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए इस महान सदन में बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जब यह बिल पास हो जायेगा तब छह महीने के बाद इन संस्थाओं में एक बार मीटिंग जरूर हुआ करेंगी और वह मीटिंग भी तीन दिन तक लगातार चला करेंगी। इसके अगले छह महीने के बाद भी इसी तरह की मीटिंग बुलाने का प्रावधान होगा यानी साल में इन संस्थाओं में हाउस की मीटिंग 6 दिन चला करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि इससे हरियाणा प्रदेश नई बुलन्दियों को छू सकेगा और हरियाणा प्रदेश की जनता को सही मायनों में विकास दिया जा सकेगा। यही हमारी सरकार का उद्देश्य तथा संकल्प है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 के क्लॉज – 20 (ii) में पहली पंक्ति में 'निगम' शब्द के स्थान पर 'पालिका' शब्द प्रतिस्थापित किया जाये और हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉजिज–2 से 21

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज–2 से 21 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं–

कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक यथासंशोधित पारित हुआ।)

(V) दि हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगी तथा यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : स्पीकर सर, मैं हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं –

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(विधेयक पारित हुआ।)

(vi) दि हरियाणा ग्रुप डी इम्प्लॉईज़ (रिक्रूटमैंट एण्ड कंडीशंज़ ऑफ सर्विस) अमैंडमैंट बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

सब क्लॉज (2) ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज (2) **ऑफ** क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज (3) ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज (3) ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉजिज–2 से 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज–2 से 4 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज (1) ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज (1) ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

(vii) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रेगूलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज 2 से 5

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 5 विधेयक का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

(viii) दि पंजाब इलैक्ट्रिसिटी (इमरजेंसी पॉवर्स) हरियाणा रिपील बिल, 2019

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब परिवहन मंत्री, पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) हरियाणा निरसन विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार): अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) हरियाणा निरसन विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) हरियाणा निरसन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) हरियाणा निरसन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) हरियाणा निरसन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब परिवहन मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

(ix) दि हरियाणा कंट्रोल ऑफ आर्गेनाईज्ड क्राइम बिल, 2019

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, वक्त के मुताबिक सरकार जो यह कानून लेकर आ रही है इसकी वाकई में जरूरत है । जो इस बिल में प्रोविजंस दिए गए हैं उनको मैंने पढ़ा है । सरकार ने इस बिल के अन्दर कहा है कि हम यह कानून महाराष्ट्र, गुजरात और यू.पी. के पैटर्न पर हरियाणा में बनाना चाहते हैं । इसमें जहां तक मुझे पता लगा है कि इन स्टेट्स में जो गैंग या इस तरह के असामाजिक तत्व हैं वह जो भी एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज का उनके बिल में बाकायदा जिक्र किया गया है कि फलां–फलां गैंगस्टर एक्टिविटीज करने

वालों के खिलाफ इस कानून का प्रयोग किया जाएगा । अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि सरकार को भी इस बारे में विचार करना चाहिए । स्पीकर सर, इसी तरह से आज हरियाणा में भी गांवों में जो नाजायज हथियार होते हैं जिन्हें देशी पिस्तौल भी कहते हैं, वह पूरे हरियाणा के तकरीबन हर गांवों में हैं लेकिन इन नाजायज हथियारों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है । इन हथियारों को भी रखना एक बहुत बड़े गैंगस्टर्स का ही काम है । यह काम भी इसमें आना चाहिए । इससे सरकार के खजाने को भी हानि होती है । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में नम्बर दो का शराब बेचने का भी बहुत बड़ा गैंग है क्योंकि इतनी शराब ठेकों पर नहीं बिकती जितनी शराब गलियों में, मौहल्लों में व घरों में आती है । वह शराब जो नम्बर दो में निकलती है वह शराब हरियाणा के एक्साइज विभाग के जो अधिकारी हैं या जो राजनेता हैं उनकी मदद से सस्ती होकर जाती है । उनके गैंग बने हुए हैं और उनमें आपस में झगड़े भी होते हैं । (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने एक विषय ऑर्गनाईज्ड क्राईम के बारे में उठाया है वह ठीक है । इसकी परिभाषा में जो–जो आएंगे वह आने चाहिएं । माननीय साथी एक विषय को ही जिस प्रकार से घुमाकर और गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं वह ठीक नहीं है । हमने पहले भी कहा है कि इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल के बाद हमारा एक्साइज विभाग का रेवैन्यू लगभग डबल हुआ है जबकि कोई जनसंख्या नहीं बढ़ी है, कोई शराब पीना नहीं बढ़ा है फिर भी इस प्रकार से रेवैन्यू डबल हुआ है । इसका मतलब उस समय कहीं न कहीं रेवैन्यू की चोरी थी । आज रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग डबल रैवेन्यू खजाने में आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी यह बात सही है कि लगातार इस प्रकार से इल्लीगल तरीके से गांव–गांव से अगर हमें शराब के कारोबार की सूचना मिलती है तो उस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी होती है । जिनकी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं उन गाड़ियों पर भी कार्रवाई होती है । यह भी एक रिकॉर्ड की बात है कि हरियाणा के इतिहास में पहले इतने बड़े स्तर पर कभी भी उतनी धर–पकड़ नहीं हुई जितनी धर–पकड़ अब की जाती है । आप अखबारों में लगातार पढ़ते होंगे कि एक्साइज व पुलिस विभाग दोनों के अधिकारी मिलकर उनको पकड़ कर उनके ऊपर सख्त पैनल्टी लगाते हैं । यहां तक कि डिस्टलरी के लाईसेंस को सस्पैंड करने तक का एक्शन लेने का काम भी हुआ है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस तरह के गैंग्स को रोकने की यहीं जरूरत है क्योंकि जो भी इस तरह का धन्धा करते हैं मान लो एक ट्रक शराब का पकड़ लिया या इन्होंने सैंकड़ों हजारों बोतलें पकड़ ली तो वह क्रिमनल एक्ट में न जाकर के एक्साइज एक्ट में पहुंच जाते हैं और वह केवल जुर्माना भरकर ही निकल आते हैं । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केवल आपके विभाग के हित में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के हित में है । आज इल्लीगल शराब का धन्धा करने वाले लोग नौजवान पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं । स्पीकर सर, आपको तो इसके बारे में बहुत चिन्ता है क्योंकि नशे के बारे में आपके पास जितने भी प्रस्ताव आए हैं उनको आपने हमेशा तरजीह दी है । अतः जब तक शराब का नम्बर दो का धन्धा करने वाले गैंग्स को इस एक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी । स्पीकर सर, इसी तरीके से आपके हल्के से लेकर पलवल होडल तक सारी रात अवैध खनन की ओवर लोडिड गाड़ियां चलती हैं और उनके आगे–आगे पुलिस की गाड़ियां होती हैं जो उन्हें सुरक्षित निकालकर ले जाते हैं । इससे सरकार के खजाने का नुकसान होता है । अध्यक्ष महोदय, पत्थरों की अधिकतर खदानें भिवानी, दादरी तथा नारनौल की साइड में हैं और वहां पर भी इस अवैध खनन माफिया का अवैध धंधा जोरों पर होता है। (विघ्न)

18:00 बजे

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र की चिंतायें ठीक हैं लेकिन जो यह बिल अब सदन में पेश किया गया है और इसमें जो आर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन दी गई है, वह इतनी ब्रॉड है कि जो क्राइम से जुड़ी अलग–अलग बातें करण सिंह दलाल जी ने बताई हैं, उन सभी बातों का इस बिल में अलग–अलग उल्लेख करने की मुझे नहीं लगता, कोई आवश्यकता है। इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं उनको महाराष्ट्र राज्य के मकोका कानून की तर्ज पर एज इट इज अर्थात शब्दशः उतारकर इस बिल में डालने का प्रावधान किया गया है। मकोका कानून के जिस एक क्लॉज पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की आब्जर्वेशन आई हुई है, केवल उस आब्जर्वेशन से संबंधित क्लॉज को निकालकर बाकी सारे के सारे मकोका कानून के प्रावधानों को इस बिल में शामिल किया गया है। यही नहीं इस बिल में हर क्राइम को अलग–अलग मैंशन करने से भी परहेज किया गया है क्योंकि जितना ज्यादा लिखा जायेगा उतना ही कानून एक तरह से लूज होता चला जायेगा। इसलिए इस बिल में किन्हीं अलग–अलग क्राइम्ज के लिए अलग–अलग उल्लेख न

करने की बजाए आर्गेनाइज्ड क्राइम की ब्रॉड डेफिनेशन देकर सब क्राइम्ज को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है और माननीय सदस्य यदि इस डेफिनेशन को पढ़ेगे तो उनकी सभी चिंतायें दूर हो जायेंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि मुख्यमंत्री जी को जो जैसा बता दे वे वैसे ही चल पड़ते हैं। इस बिल में लिखा गया है कि जिन जुर्म की सजा तीन साल से ज्यादा होगी केवल वहीं जुर्म आर्गेनाइज्ड क्राइम में कवर होंगे। इस तरह से मैं समझता हूँ कि आर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत हर तरह के जुर्म को शामिल नहीं किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, यदि आप बिल को पढेंगे तो इसमें लिखा हुआ पायेंगे कि जिस जुर्म में तीन साल से ज्यादा की सजा होगी केवल वही जुर्म आर्गेनाइज्ड क्राइम में कवर होंगे। अध्यक्ष महोदय, जो गैंग्स हैं उन्होंने ज्यादातर ऐसे जुर्म किए हुए होते हैं जिनके अंदर तीन साल से कम की सजा का प्रावधान है इस प्रकार वे तो इस आर्गेनाइज्ड क्राइम में कवर होंगे ही नहीं? अतः जैसाकि मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा था कि यह बिल एक तरह से महाराष्ट्र राज्य के मकोका कानून का शब्दशः रूपांतरण है, मैं समझता हूँ कि सरकार को उनका यह बिल मंगवाकर फिर से देख लेना चाहिए ताकि यदि मेरे द्वारा बताई गई परिस्थिति पैदा हो जाये तो ऐसी अवस्था में सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाये जा सकते हैं, उनके बारे में सरकार पहले से ही सचेत हो जाये? अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त इस बिल के तहत जो इंटरसैप्शन ऑफ टेलीफोन काल्ज का अधिकार दिया गया है उससे निजी लोगों की आजादी बाधित होगी क्योंकि सी.आई.डी. वालों का तो यह धंधा ही बन जायेगा और वे तो हमारे जैसे लोगों के टेलीफोन काल्ज भी इंटरसैप्ट करने लगेंगे। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं फिर करण सिंह दलाल जी को बताना चाहूंगा कि टेलीफोन काल्ज केवल उन्हीं के इंटरसैप्ट होंगे जोकि आर्गेनाईज्ड क्राइम के दायरे में आयेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहे आर्गेनाइज्ड क्राइम के दायरे में आयें चाहे न आयें लेकिन आर्गेनाइज्ड केसिज के दायरे में हम जैसे लोगों को लाने में सरकार को कोई देर थोड़ा ही लगती है। अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन इंटरसैप्ट करने का काम एक तरह से गैर कानूनी ही होगा। अगर सरकार इसको करना ही चाहे तो यह कार्य बड़े ही अच्छे तरीके से व जिम्मेदारी के साथ बहुत ही

जिम्मेवारान हाथों में दिया जाना चाहिए और बाकायदा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि अगर कोई आदमी इसका गलत इस्तेमाल करता है तो संबंधित अधिकारी बहुत सख्त कार्रवाई का पात्र होगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं नकली दवाइयों से जुड़े विषय पर बात करूंगा। आज हरियाणा में नकली दवाइयों को बेचने का स्कैम पूरे जोर–शोर से चल रहा है लेकिन बावजूद इसके इस अपराध के लिए जो सजा का प्रावधान किया गया है वह बहुत ही कम है। मेरा सरकार से निवेदन है कि नकली दवाइयों का काम करने वाले गैंग्ज की सूची बनाइये और उन पर आर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। अध्यक्ष महोदय, आर्गेनाइज्ड क्राइम में व्हाइट कॉलर क्रिमनल्ज को भी शामिल किया जाये। आज के दिन सबसे ज्यादा जो क्रिमनल्ज हैं वे व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं। चाहे वे अधिकारी हैं, चाहे वे राजनेता हैं या फिर चाहे वे कॉमन मैन हैं मेरा विचार है कि व्हाइट कॉलर क्रिमनल्ज के कार्यों को भी आर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन में शामिल करके इनका इलाज करने का भी काम किया जाये। अगर इनका इलाज हो जाता है तो फिर आपके प्रधानमंत्री जी की न खायेंगे–न खाने देंगे की अवधारणा को मूर्त रूप मिल जायेगा। अतः सरकार से मैं फिर कहना चाहूंगा कि व्हाइट कॉलर क्रिमनल्ज को भी आर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल किया जाये। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस बिल के द्वारा एक और गैर जिम्मेवाराना काम करने जा रही है। इसके लिए मैं इस बिल के पेज नम्बर 16 पर क्लॉज 23 relating to Cognizance and investigation of offence को पढ़कर सुनाता हूँ:–

"23 (1) Notwithstanding anything contained in the Code,-

(a) no information about the commission of an offence of organised crime under this Act, shall be recorded by a police officer without the prior approval of the police officer not below the rank of the Deputy Inspector General of Police; "

अध्यक्ष महोदय, इसमें आर्गेनाइज्ड क्राइम के संबंध में जो पुलिस ऑफिसर की प्रॉयर एप्रूवल की अनिवार्यता बताई गई है वह भी एक तरह से दूसरे के हाथ में अपना हथियार देने के समान है। हो सकता है कि डी.आई.जी. इस बिल के मूल भाव को समझे या न समझे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं उसी व्यक्ति के किसी गैंग से तार जुड़े हों क्योंकि सबको पता है कि बिना पुलिस के सहयोग के गैंग नही चला करते। अध्यक्ष महोदय, बिल के माध्यम से जो इस प्रकार की

जिम्मेदारियां दी जा रही हैं वह एक तरह से पुलिस को उनकी दुकान चलाने के रास्ते खोलने का ही काम करेगी और निःसंदेह इस तरह के प्रावधानों से वे अपनी दुकानदारी चलायेंगे भी। जब प्रदेश में हरियाणा विकास पार्टी सत्ता में थी तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी आप तो विधायक नहीं थे लेकिन मैं उस सरकार में मंत्री था और हमने जब हरियाणा प्रदेश में शराब बंदी लागू की तो उस समय कुछ ऐसे वाक्ये पेश आये जिनकी बदौलत मैं आज सदन में यह बात कह रहा हूँ। मैं एक वाक्या सदन के सामने रखना चाहूंगा। जब हमारी सरकार ने शराब बंदी की तो उन्हीं दिनों एक दिन एक नौजवान लड़का मेरे पास आता है और कहता है कि उसे मुझसे अलग में बात करनी है। मैंने पूछा कहिए क्या बात है तो वह बोला कि वह पहले शराब बेचने का काम किया करता था लेकिन अब उसने वह छोड़ दिया है परन्तु थाने का थानेदार डी.एस.पी. की मौजूदगी में ही उसको कहता है कि कि तू दारू बेच या न बेच मुझे तो इतने पैसे चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात अपने कानों से सुनी ही सदन को बता रहा हूँ। इस प्रकार से सरकार को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए। अगर हम कोई अच्छा कानून ला रहे हैं तो उसका फायदा सभी लोगों को होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार पुलिस अधिकारियों के जितने लैवल बना देगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उतने ही लैवल्ज पर धंधा तय हो जायेगा। मैं यह भी नहीं कहता कि सारे के सारे पुलिस अधिकारी ऐसे हैं लेकिन ऐसा अक्सर होता है। इस प्रकार से सरकार को इस क्लॉज के बारे में विचार करना चाहिए । इसी तरह से अब मैं इस बिल के सैक्शन 23 (1) (b) के बारे में कहना चाहूँगा। इसमें लिखा है कि–

> "no investigation of an offence under the provisions of this Act shall be carried out by a police officer below the rank of the Deputy Superintendent of Police."

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा पुलिस में कितने डी.एस.पीज. हैं? न्सपैक्टर्ज की भर्ती सरकार ने की हुई है जो इन्सपैक्टर की क्वालिफिकेशन और सैलरी है वह डी.एस.पी. रैंक के बराबर है। इस प्रकार से सरकार को डी.एस.पी. रैंक की भर्ती करनी पड़ेगी। अगर सरकार ठीक समझे तो इसमें इन्सपैक्टर रैंक पर सोच सकती है जिससे कि इनके काम में कोई बाधा न आए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैं इस बिल के सैक्शन 23 (2) के

बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सैक्शन 23 (2) में लिखा है कि–

> "No Special Court shall take cognizance of any offence under this Act without the previous sanction of the police officer not below the rank of Additional Director General of Police."

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से एक और घातक दरवाजा खुल गया है। इन्होंने माननीय कोर्ट को भी जो ए.डी.जी.पी. रैंक है, उनके अधीन कर दिया है, अगर वे इजाजत देंगे तो वे उनके अंदर कार्यवाही कर सकते हैं वरना माननीय कोर्ट भी कार्यवाही नहीं कर सकती है। इस प्रकार से सरकार को नये कानून बनाने की बजाए धंधा चलाने का नया कानून नहीं बनाना चाहिए। इससे हरियाणा में गैंग को रोकने की बजाए गैंग को बढ़ावा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस बिल की सैक्शन–24 जो कि Punishment for public servants से संबंधित है, में लिखा है कि– ..... (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं but he is saying contradictory things in one sentence. इन्होंने शुरू में इस बिल का समर्थन किया था। कल चौधरी अभय सिंह चौटाला के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उसके ऊपर भाई करण सिंह दलाल, बहन गीता भुक्कल, बहन नैना चौटाला आदि माननीय सदस्यों ने भी अपने–अपने विचार व्यक्त किए थे। बहन नैना चौटाला ने तो नशे के बारे में डबवाली का भी जिक्र किया था। अध्यक्ष महोदय, नशे के इस संवेदनशील मुद्दे पर सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का आयोजन सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किया था। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री मनोहर लाल जी को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा था कि हमारा पंजाब नशे के सेवन से बर्बाद हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब भाई करण सिंह दलाल जी की पार्टी सत्ता में होती है तो इन्हें कभी पुलिस का इन्सपैक्टर अच्छा लगता है, कभी ए.डी.जी.पी. अच्छा लगता है और कभी कोई और अच्छा लगने लगता है। अब के एन.एस.ए. (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) श्री अजीत डोभाल आई.पी.एस. ऑफिसर थे, उन पर कोई भी शक नहीं कर सकता था। अध्यक्ष महोदय, उस आई.पी.एस. ऑफिसर ने 10 साल पाकिस्तान में रिक्शा चलाई, नमाज पढ़ी और मस्जिद में रहा। दिनांक 28 सितम्बर, 2016 को जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राईक की तो हमारे प्रधानमंत्री श्री

नरेन्द्र भाई मोदी ने उसके ऊपर गर्व महसूस किया। उस वक्त रात के करीब 12:00 बजे हमारे फौजी पाकिस्तान की सीमा में करीब 10 किलोमीटर तक अंदर गए और लगभग 90 आंतकवादियों को मौत के घाट उतार कर सुबह 5:00 बजे के करीब वापिस आए थे। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि विपक्ष का काम सवाल पूछना होता है और भाई करण सिंह दलाल की काबिलियत को हम मानते हैं। वे हर बिल पर बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज भाई करण सिंह दलाल को बहन गीता भुक्कल जी से सीखना चाहिए क्योंकि आज बहन गीता भुक्कल जी ने अपनी स्पीच समर्थन देने के नाम से प्रारम्भ की है। अध्यक्ष महोदय, आई.पी.एस. की सेवा हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी श्रेष्ठ सेवाओं में से एक है, इसलिए इस बिल में हमने प्रावधान किया है। यह बात भी ठीक है कि कई बार प्रावधान करने पर दुरूपयोग हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमने कर्नाटक में जो आर्गेनाइज्ड क्राइम होता है उससे संबंधित कानून देखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और सदन को बताना चाहता हूं कि डॉ. ओम प्रकाश धनखड़ कनाडा में मैडिकल डिपार्टमैंट के मुखिया हैं उनका मुझे फोन आया और मैं एक घंटे में ही रोहतक पहुंच गया । मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रोहतक के नशामुक्ति केन्द्र की सारी बातें रखी और तत्काल उस नशा मुक्ति केन्द्र की घटना को वहां के पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया गया । स्पीकर सर, इस तरह से कोई भी बात यदि हमारे संज्ञान में आती है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं । हमारी सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है । हमारी ईमानदारी से यह कोशिश रहती है कि हम अपनी जवान पीढ़ी को बर्बाद करने वाले लोगों पर एक्शन लें । इसके लिए हमें चाहे उनके टैलीफोन ही टेप क्यों न करने पड़ें । यदि किसी व्यक्ति का किसी गिरोह से संबंध पाया जाएगा तो उसका फोन टेप किया जाएगा । स्पीकर सर, आतंकवाद की आग इसलिए ही भड़की थी क्योंकि उन लोगों को संरक्षण मिलता था । अतः जो लोग नशामुक्ति केन्द्र चलाते हैं और जिनका संबंध अपराधियों से, गैंगस्टर्स से मिलता है इंटैलीजैंस एजेंसीज उनके फोन टेप करती हैं । इसमें डर किस बात का है ? बिल में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक आई.पी.एस. रैंक के अधिकारी के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और उसके बाद भी वह पुलिस पर यह आरोप लगाता है कि मुझे तो डंडे मारकर जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था तो इस बिल में यह प्रावधान है कि इसके बाद उसको सी.जे.एम. के सामने पेश किया जाएगा । किसी आई.पी.एस. अधिकारी या ए.डी.जी.पी. स्तर के कम रैंक के

अधिकारी के सामने जुर्म कबूल करने पर भी वह अपनी बात से मुकरता है तो यह आदरणीय न्यायाधीश के अपने विवेक पर निर्भर करेगा कि वे उसका विश्वास करते हैं या नहीं और क्या वे हमारे आई.पी.एस. अधिकारी की बात को निरस्त करते हैं ? वे चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं । अतः हमने इसमें कहीं पर भी ज्यादती होने की गंजाइश नहीं छोड़ी है । यह कार्य जनहित में है । हमने यह बिल महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर कर्नाटक और गुजरात के कानूनों में से जितने अच्छे प्रावधान थे, उन सबका इसमें समायोजन करके इसको एक सख्त कानून बनाया है ।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं इस बिल पर वह सुझाव दे रहा हूं जो बहुत जरूरी हैं और उनको लागू करना चाहिए । अभी माननीय मंत्री श्री राम बिलास कह रहे थे कि हमने इस कानून में ऐसा प्रावधान किया है कि व्यक्ति की एक पुलिस ऑफिसर के सामने स्टेटमैंट ली जाएगी और वही उसका बेस मानी जाएगी फिर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा । हमें इसमें इण्डियन ऐविडैंस एक्ट की धाराओं को देखना पड़ेगा क्योंकि इण्डियन ऐविडैंस एक्ट हमें इसकी इजाजत नहीं देता । सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. के भी अपने दायरे हैं । इस तरह की चीजें इण्डियन ऐविडैंस एक्ट में एडमिसिबल नहीं हैं । अगर आपको यह ठीक लगता है तो 164 सी.आर.पी.सी. है उसमें जज के सामने बयान होते हैं । यह प्रोविजन बहुत अच्छा है लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी गलती है । इसमें प्रावधान किया है कि अगर कहीं भी कोई गलत कार्यवाही करता है तो उसको भी दोषी मानेंगे लेकिन उसको सिर्फ 3 साल की सजा का प्रावधान किया है लेकिन उनके लिए भी उतनी ही सजा का प्रावधान करना चाहिए जो जुर्म करने वाले के लिए किया गया है । जो उन्हें असिस्ट, हैडिंग और कांस्पीरेट कर रहे थे, उन पुलिस अधिकारियों के लिए भी उतनी ही सजा का प्रावधान होना चाहिए ।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य करण सिंह जी ने लॉ की पढ़ाई मेरठ यूनिवर्सिटी से की है । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की है।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, वहां पर प्रत्येक सर्टिफिकेट की कीमत है। पी.एच.डी. की डिग्री की अलग कीमत है। I am a Law Graduate in 1st Class from the Panjab University. इस बिल को सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सीज. को पढ़कर ही बनाया है इसलिए माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल को सरकार की बात और नियत पर भी विश्वास करना चाहिए। सरकार ने संगठित अपराध के लिए

एक बहुत ही सख्त कानून बनाया है। इसमें माननीय सदस्य को सरकार का समर्थन करना चाहिए। मैंने सदन में पहले भी कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर भी किसी अधिकारी के बारे में या कोई बड़ा आदमी अपराध में शामिल मिले तो 8195811111 पर फोन करें, we will do that.

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा सुझाव है कि जो भी अधिकारी किसी गैंग की मद्द करता है तो जो सजा उन गैंगस्टर्ज की होती है लेकिन मेरा कहना यह है कि वही सजा संबंधित अधिकारी की भी होनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश में यह जो बी.जे.पी. की सरकार बनी है, वह माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नाम पर नहीं बल्कि माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी के नाम पर बनी थी। प्रदेश के सभी ब्राह्मणों ने बी.जे.पी. का झंडा थाम लिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और कहीं पर तो दांव चला नहीं परन्तु उन्होंने एक **** ऑफिसर की छुट्टी कर दी। दूसरी तरफ एक भ्रष्ट अधिकारी **** को बिजली विभाग में नियुक्त कर दिया है।

श्री अध्यक्षः अभी माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल ने जो आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, उनको रिकार्ड न किया जाए।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी की बातें सरकार सुनना चाहती है लेकिन वे बीच–बीच में ऐसी आपतिजनक बातें कहते हैं जो अमर्यादित होती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अच्छे आई.पी.एस. अधिकारी को बर्खास्त कर दिया और भ्रष्ट अधिकारी को बिजली विभाग में लगा दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का किसी से भी व्यक्तिगत विरोध हो सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, भ्रष्ट अधिकारी को किसी पद पर नियुक्त करना कहां का न्याय है ?

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य व्यक्तिगत विरोध के लिए किस सीमा तक इस महान् सदन का उपयोग करेंगे ? यह असभ्य और अमर्यादित भी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया जाए।

श्री अध्यक्षः ठीक है। मैंने पहले ही सदन की कार्यवाही से आपत्तिजनक शब्दों को निकलवा दिया है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

.....

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज (2) ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज (2) ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बनें।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

सब क्लॉज (3) ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज (3) ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बनें।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

क्लॉजिज 2 से 29

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉजिज 2 से 29 विधेयक का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज (1) ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज (1) ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बनें।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाईटल हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधयेक पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

(x) दि मोटर व्हीकल्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2019

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब परिवहन मंत्री मोटर यान (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर यान (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि मोटर यान (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि मोटर यान (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि मोटर यान (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्षः अब परिवहन मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

संसदीय कार्यमंत्री हरियाणा विधान सभा के अधिकारिों तथा कर्मचारियों को मानदेय के रूप में एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने के संबंध में दिया गया सुझाव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा विधान सभा में लगभग 300 से अधिक अधिकारी/कर्मचारी काम करते हैं और वे विधान सभा के हर सत्र में दिन–रात काम करते हैं। मैंने देखा है कि अनेक विधानसभाओं में विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगन से किए गए कार्य की एवज में एक महीने का अतिरिक्त वेतन ऑनरेरियम के रूप में उनको दिया जाता है। अतः मैं आज इस सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि हरियाणा विधान सभा के

अधिकारियों/कर्मचारियों को भी एक महीने की अतिरिक्त तनख्वाह देकर पुरस्कृत किया जाये।

श्री अध्यक्षः ठीक है, इस दिशा में जरूर कार्य किया जायेगा।

हरियाणा के मृतक एम.एल.ए. की पत्नियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का मामला उठाना

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले दिनों कुछ दिक्कतें ऐसी देखी हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। जो हमारे एक्स एम.एल.एज. हैं, उनको विधान सभा के नियमों के अनुसार पैंशन दी जाती है। जब किसी मैम्बर की डैथ हो जाती है तो वह पैंशन उनकी वाईफ को मिलने लग जाती है लेकिन अगर किसी मृतक मैम्बर की वाईफ को मैडीकल संबंधी कोई समस्या आ जाती है तब उसको मैडीकल सुविधा नहीं दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार को कोई न कोई इस मामले में भी विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : करण दलाल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मृतक मैम्बर की वाईफ को मैडीकल संबंधी समस्या आने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

संसदीय कार्य मंत्री, श्री करण सिंह दलाल, एम.एल.ए. तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि जो विदाई के क्षण होते हैं, वे बड़े ही भावुक होते हैं और दिल के ऊपर भावनाओं का ज्वार हावी हो जाता है। स्पीकर सर, इस सदन में हम सभी माननीय सदस्यों का पिछला जो पांच साल का समय गुजरा है, उसमें हमें पता ही नहीं चला कि कब माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार शुरू हुई ? आज इस सरकार का पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। स्पीकर सर, आपने बहुत ही शालीनता, गरिमा और मर्यादा के साथ इस सदन को चलाया है। स्पीकर सर, इस सदन में आपका बहुत ही कठिन काम है, लेकिन उसके बावजूद आपने बड़े संयम और गरिमामयी तरीके से अपने काम को निभाया है। मैं माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी को समझाता रहता हूं, लेकिन श्री करण सिंह दलाल जी को समझाना बहुत ही कठिन काम है। स्पीकर सर, संसदीय प्रणाली (पार्लियामैंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी) में विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है।

इस सदन में कई माननीय सदस्य पिछले 5 सालों से हैं तो कई माननीय सदस्य पिछले 10 सालों से हैं, लेकिन यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस सदन में पिछले 35 सालों से हूं। स्पीकर सर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य देश और प्रदेश के लिए काम करते हैं इसलिए हमारे लिए Nation is first होना चाहिए। कल पार्लियामैंट में जो हुआ है, उसके लिए वहां माननीय सदस्यों ने अपनी पार्टी के घेरे से बाहर निकलकर अपनी देशभक्ति के जज्बात को सबसे ऊपर का स्थान दिया है। स्पीकर सर, कल राज्य सभा के माननीय सदस्य श्रीमान जनार्दन द्विवेदी जी ने जम्मू एवं काश्मीर से संविधान की धारा–370 के प्रभाव को कम करने का समर्थन किया था और श्रीमान भुवनेश्वर कालिता जी ने जम्मू एवं काश्मीर से धारा–370 के प्रभाव को कम करने का समर्थन करते हुए राज्यसभा की सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया था। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के द्वारा इस सदन में जम्मू एवं काश्मीर से केन्द्र सरकार द्वारा धारा–370 के प्रभाव को समाप्त करने पर जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था, उसका हमारी हरियाणा विधान सभा के कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने भी समर्थन किया था। स्पीकर सर, केन्द्र सरकार ने यह जो निर्णय लिया है, उस निर्णय से पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मैं भी इस सदन के सभी माननीय सदस्यों और अपने भाइयों–बहनों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका और बहन श्रीमती संतोष यादव जी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इस सदन में बहुत से तल्खी के अवसर भी आये, लेकिन आपने उन्हें बहुत ही सुखद तरीके से निपटाया। हमारे लिए इन पांच सालों का जो कार्यकाल था, वह बहुत ही सुखद रहा है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाली अगली विधान सभा में भी हम सब ज्यों के त्यों बने रहें। (हंसी)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी ने जो कहा है, उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि मुझे भी यह सौभाग्य मिला है कि जिस तरह से श्री राम बिलास शर्मा जी 5 दफा चुनाव जीतकर इस विधान सभा में आये हैं, उसी तरह से मैं भी 5 दफा चुनाव जीतकर इस विधान सभा में आया हूं। हमें लाखों लोग चुनाव में जिताकर इस सदन में भेजते हैं और इस महान सदन में बैठने का मौका देते हैं इसलिए हमारा इन लाखों लोगों के प्रति धर्म और कर्त्तव्य बनता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात इस महान सदन में बताना चाहूंगा कि देश की किसी भी विधान सभा में यह नहीं लिखा हुआ है जो हमारी विधान

सभा में लिखा हुआ है कि ''सभा में या तो प्रवेश न किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहाँ स्पष्ट और सच बात कही जाए क्योंकि वहाँ न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है''। अगर हम यहां आकर चापलुसी और जी हजुरी करने लगे और वह भी गलत नियत से तो यह पाप है, गुनाह है। हमें हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों की वजह से और परमपिता परमात्मा की कृपा से इस ऊंचे स्थान पर बैठने का मौका मिला है तो हमारा भी प्रदेश के लाखों लोगों के प्रति फर्ज बनता है। यह प्रजातंत्र की पहली मर्यादा भी है और जो कि सच भी है, उसको हमेशा सच ही बोलना चाहिए। मैं अपने जीवन काल में इस विधान सभा में 5वीं बार चुनकर आया हूं। मुझे इन 5 वर्षों में जो प्यार और स्नेह मिला है, वह शायद ही पिछले 25 वर्षों में किसी को मिला हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके मन में सदस्यों के प्रति दर्द महसूस किया है, जो हमेशा आपके चेहरे पर झलकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए अपनी तरफ से और अपनी पलवल विधान सभा चुनाव क्षेत्र के लोगों की तरफ से आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस 13वीं विधान सभा में मुझे विधान सभा के अध्यक्ष के पद की जिम्मेवारी संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान आप सब के सहयोग से मैंने अपने कर्त्तव्यों का निर्वाहन पूरी सत्यनिष्ठा से करने का प्रयास किया जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी विधान सभा सदस्य चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिक से अधिक मौका दिया गया। यदि आप हरियाणा विधान सभा के पिछले 25 वर्षों के आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इस सदन की सर्वाधिक बैठकें आयोजित की गई जिसका श्रेय मैं मौजूदा सरकार को देता हूं। इसके साथ ही मुझे हरियाणा प्रदेश के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर हरियाणा विधान सभा के सभी मौजूदा व पूर्व विधायकों को सम्मानित करने का अवसर भी मिला। इन जनप्रतिनिधियों को सम्मानित कर मुझे अति हर्ष का अनुभव हुआ। इसके साथ ही मैं आप सभी सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सब ने इस गरिमामय सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए इस सदन की विभिन्न बैठकों में जनहितैषी विषयों पर चर्चाएं की, जन–साधारण की समस्याओं को उठाया तथा सरकार के द्वारा भी विभिन्न जनहितैषी योजनाएं लागू की गई व लोकहित में अनेक विधेयक पारित किए गए। इन सभी कार्यों के लिए मैं आप सभी सदस्यों व

हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं। माननीय सदस्यगण, प्रत्येक सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र का तो प्रतिनिधित्व करता है साथ ही साथ पूरे प्रदेश की भी विभिन्न समस्याओं व मांगों को इस सदन के माध्यम से हल करवाने का प्रयास करता है। जिसके चलते इस सदन में चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों में कई बार आपसी नोक–झोंक भी हो जाती है या कुछ ऐसी टिप्पणियां भी हो जाती है जिसको इस सदन की गरिमा के अनुसार अमर्यादित कहा जा सकता है। किसी भी सदस्य द्वारा यदि ऐसी टिप्पणी की गई हो तो कोई भी सदस्य कृपा उसे निजी तौर पर ना लेकर सदन तक ही सीमित रखते हुए एक अच्छी स्वच्छ राजनीतिक सोच वाले राजनेता, जनप्रतिनिधि व समाजसेवी होने का संदेश दे ताकि हम हरियाणा की इस पवित्र धरा पर और नये विकास के आयाम स्थापित कर सकें। मैं, एक बार फिर से आप सभी सदस्यगणों का अपने हृदय की गहराईयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महान सदन की गरिमा को बनाये रखने व जनहित कार्यों हेतू अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही मैं पत्रकार बंधूओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस सदन की कार्यवाही को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। मैं हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व हरियाणा विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस महान सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद।

माननीय सदस्यगण, अब यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है।

*6.30 बजे

(तत्पश्चात् सदन अनश्चितकाल के लिए *स्थगित हुआ।)